

•

•  
•

•

•

•  
•

•

•

•

•

## भूमिका

राष्ट्र की सम्पन्नता का आधार शिक्षा का सर्वाङ्गीण विकास है। आधुनिक युग में प्रगति के पथ पर अभियान करने के लिये लातायित सभी देश शिक्षा की समस्याओं का समाधान करके उसके मार्ग को प्रशस्त बनाने के कार्य में संलग्न हैं। 'समाजवादी आदर्श के समाज' की स्थापना को अपना लक्ष्य मान कर आज हमारा देश भी शिक्षा की विविध समस्याओं का निराकरण करके उसके पुनर्संगठन तथा विस्तार के लिये गवीनतम योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत में शिक्षा की ऐसी अनेकों समस्याएँ हैं जिन पर देश के नेताओं और शिक्षाविदों द्वारा यत्नीय चिन्तन एवं विचार-विमर्श किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा के इतिहास के छात्रों और शिक्षा-नीका के कर्णधार के रूप में अध्यापकों के लिये शिक्षा की समस्याओं और उनके समाधान के उपायों का अध्ययन अनिवार्य हो गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह पुस्तक प्रस्तुत की जा रही है।

गत कुछ वर्षों से प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के छात्राध्यापकों को एक ऐसी पुस्तक का अभाव खटक रहा था जिसमें भारतीय शिक्षा की समस्याओं का सरल एवं सुन्दर ढङ्ग से विवेचन किया गया हो। इस विचार-बिन्दु को समझ रख कर इस पुस्तक की रचना की गई है। समस्याओं के साप-साथ शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले महत्वपूर्ण परीक्षणों का भी आलोचनात्मक विवरण पुस्तक में दिया गया है।

इस पुस्तक के लेखन में श्री रामबाबू शर्मा, एम० ए० एवं भाषा के परि-मार्जन में श्री विनोदकुमार अग्रवाल, एम० ए० से जो विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिये हम उनके आभारी हैं।

दयालबाग

१-६-६०

डॉ० पी० जी० हरी

पी० डी० पाठक

प्रकाशक—  
राजकिशोर धप्रवाल  
विनोद पुस्तक मन्दिर  
हॉस्पिटल रोड, भागरा

प्रथमावृत्ति  
१९९१  
मूल्य ९.००

मुद्रक—  
राजकिशोर धप्रवाल  
बंगाल विनिर्माण संस्थान  
बागमती रोड, भागरा ।

# भूमिका

राष्ट्र की सम्पन्नता का आधार शिक्षा का सर्वाङ्गीण विकास है। आधुनिक युग में प्रगति के पथ पर अभियान करने के लिये लालायित सभी देश शिक्षा की समस्याओं का समाधान करके उसके मार्ग को प्रशस्त बनाने के कार्य में संलग्न हैं। 'समाजवादो भावार्थ के समाज' की स्थापना को अपना लक्ष्य मान कर आज हमारा देश भी शिक्षा की विविध समस्याओं का निराकरण करके उसके पुनर्संगठन तथा विस्तार के लिये नवीनतम योजनाओं को कार्यान्वित किया आ रहा है। भारत में शिक्षा की ऐसी अनेकों समस्याएँ हैं जिन पर देश के नेताओं और शिक्षाविदों द्वारा गम्भीर चिन्तन एवं विचार-विमर्श किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा के इतिहास के छात्रों और शिक्षा-नौका के कर्णधार के रूप में अध्यापकों के लिये शिक्षा की समस्याओं और उनके समाधान के उपायों का अध्ययन अनिवार्य हो गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह पुस्तक प्रस्तुत की जा रही है।

गत कुछ वर्षों से प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के छात्राध्यापकों को एक ऐसी पुस्तक का अभाव खटक रहा था जिसमें भारतीय शिक्षा की समस्याओं का सरल एवं सुन्दर ढङ्ग से विवेचन किया गया हो। इस विचार-विन्दु को समक्ष रख कर इस पुस्तक की रचना की गई है। समस्याओं के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले महत्वपूर्ण परीक्षणों का भी प्रालोचनात्मक विवरण पुस्तक में दिया गया है।

इस पुस्तक के लेखन में श्री रामशास्त्रु शर्मा, एम० ए० एवं भाषा के परि-मार्जन में श्री विनोदकुमार भट्टवाल, एम० ए० से जो विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिये हम उनके आभारी हैं।

दयालनाथ

१-६-६०

डॉ० पी० जोहरी

पी० डी० पाठक





# विषय-सूची

## अध्याय १

### ✓✓ घनिवार्य शिक्षा ✓

१ प्राथमिक शिक्षा, घनिवार्यता से पूर्व २, घनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ५, घनिवार्य शिक्षा की समस्याएँ १०, घनिवार्यता-प्रसार सम्बन्धी सुझाव १८, उपसंहार २४, सारांश २४।

## अध्याय २

### ✓ अपव्यय एवं अवरोधन

अपव्यय का अर्थ एवं परिभाषा २८, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय २९, अपव्यय के कारण ३०, अपव्यय निवारण के उपाय ३४, अवरोधन का अर्थ एवं परिभाषा ३९, प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन ३९, प्राथमिक कक्षाओं में परोक्षा-कलों का प्रतिघात ४०, अवरोधन के कारण ४१, अवरोधन निवारण के उपाय ४४, सारांश ४६।

## अध्याय ३

### ✓ स्त्री-शिक्षा

हिन्दू-युग में स्त्री-शिक्षा ४९, मुस्लिम युग में स्त्री-शिक्षा ५०, आधुनिक युग में स्त्री-शिक्षा ५१, स्त्री-शिक्षा का विकास ५२, स्त्री-शिक्षा की समस्याएँ ५६, समस्याओं का समाधान ६२, सरकार के कर्तव्य ६३, जनता के कर्तव्य ७२, स्त्रियों के कर्तव्य ७४, सारांश ७६।

## अध्याय ४

### ✓ समाज-शिक्षा ✓

राष्ट्रीय जीवन में समाज-शिक्षा का स्थान ७९, प्रौढ़-शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा ८०, प्रौढ़-शिक्षा की नवीन धारणा ८१, प्रौढ़-शिक्षा तथा समाज-

शिक्षा के उद्देश्य २३६, वैज्ञानिक शिक्षा की विशेषतायें २४१, वैज्ञानिक शिक्षा के दोष २४८, उपसंहार २४६ ।

## २. विश्व-भारती

विश्व-भारती की स्थापना २५०, टैगोर के शैक्षिक विचार २५०, विश्व-भारती का वातावरण २५३, विश्व-भारती के उद्देश्य २५४, विश्व-भारती की संस्थायें २५४, विश्व-भारती के विभाग २५६, विश्व-भारती का कार्यक्रम २५७, विश्व-भारती का विवरण एवं विशेषतायें २५८, उपसंहार २६० ।

## ३. भरविन्द-प्राथम

श्री भरविन्द घोष २६१, श्री भरविन्द के धर्म तथा संस्कृति-सम्बन्धी विचार २६२, श्री भरविन्द के शिक्षा-सम्बन्धी विचार २६४, श्री भरविन्द के शिक्षा-सिद्धान्त २६६, भरविन्द-प्राथम २६६, प्राथम स्कूल २७०, श्री भरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र २७२, उपसंहार २७५ ।

## ४. गुरुकुल

प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली २७५, आधुनिक काल में गुरुकुलों की स्थापना २७७, गुरुकुलों के लिये मान्योपेक्षा २७७, गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की रूपरेखा २७८, गुरुकुल-संस्थानों का निर्माण २७६, गुरुकुल कागड़ी २७६, गुरुकुल वृन्दावन २७६, कन्या-गुरुकुल २८०, गुरुकुल-शिक्षा के उद्देश्य २८०, गुरुकुल-शिक्षा की विशेषतायें २८१, उपसंहार २८२,

## ५. बनस्पती विद्यापीठ

विद्यापीठ की स्थापना एवं स्थापना २८२, छात्रायें तथा भवन २८३, विद्यापीठ के शिक्षा-विभाग २८३, विद्यापीठ के मध्य एवं उद्देश्य २८४, विद्यापीठ की विशेषतायें २८५, पंचमुखी शिक्षा २८६, शारीरिक शिक्षा २८७, नैतिक शिक्षा २८७, प्रायोगिक शिक्षा २८७, कला की शिक्षा २८८, वैज्ञानिक शिक्षा २८८, विद्यापीठ के विविध शैक्षिक कार्यक्रम २८८, उपसंहार २८९, शारीरिक २८९, (वैज्ञानिक शिक्षा २८९), (विश्व-भारती २९१), (भरविन्द-प्राथम २९२), (गुरुकुल २९४), (बनस्पती विद्यापीठ २९५) ।

## अध्याय १

### ‘अनिवार्य शिक्षा’

अपने युग के महान् अंग्रेज लेखक रस्किन (Ruskin) के अप्रतिष्ठित शब्द शिक्षा-जगत को सदैव आलोकित करते रहेंगे : “शिक्षा का अभिप्राय व्यक्तियों को उन बातों की शिक्षा देना नहीं है, जिन्हें वे नहीं जानते हैं; शिक्षा का अभिप्राय है उनको इस प्रकार का व्यवहार करने की शिक्षा देना जैसा कि वे नहीं करते हैं।”<sup>१</sup> हम भने ही अपने को प्रगतिशील, आधुनिक तथा सम्यक् हैं, परन्तु हमारे नैतिक आदर्शों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज का मानव उसी प्रकार की समस्या उपस्थित करता है, जैसा कि प्राचीन मानव करता था। उसने अपने बाह्य आवरण को परिवर्तित कर लिया है, परन्तु उसका स्वभाव वही है। वह अधिक सुन्दर और आकर्षक वस्त्र धारण करता है, परन्तु फिर भी वह प्राचीन मानव से भिन्न नहीं है। अपनी सम्यता की चरम सीमा पर पाश्चात्य देशों के पुरुषों ने गत दो विश्व-युद्धों में ऐसे जघन्य प्रदर्श किये हैं, जिनकी समानता इतिहास में प्राप्त होना असम्भव है।<sup>२</sup> अतः आज के प्रजा-

1. Compulsory Education.

2. “Education does not mean teaching people to know what they do not know; it means teaching them to behave as they do not behave.”—John Ruskin, Quoted by Sir Richard Livingstone : *Some Tasks for Education*, p. 24.

3. “In the last years the West, at the height of its civilization has seen human nature guilty of crimes to which history has no parallel.”—Sir Richard Livingstone, *op. cit.* p. 27.

तन्वीय युग में सर्व महान् आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा द्वारा मानव को मानवता का पाठ पढ़ाया जाय और उसे प्रजातन्त्र राज्य का सुयोग्य नागरिक बनाया जाय। एक उत्तम नागरिक के रूप में उसे दूसरों के साथ रहना और उनके अधिकारों तथा भावनाओं का धाँवर करना सीखना है। उसे समाज की प्रगति में योग देना है, अन्यथा समाज का जीवन रहना असम्भव है। समाज के विनाश में हमारा विनाश भी अवश्यम्भावी है।

आज हमारा देश भी एक प्रजातन्त्र राज्य है और उसको सफल बनाने के लिये उत्तम एवं धाँदस नागरिकता की शिक्षा देना अनिवार्य है। इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि भारत की केवल १६.६१% जनसंख्या शिक्षित है।<sup>१</sup> भारतीयों को एक विशेष स्तर तक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके ही उन्हें देश के योग्य नागरिक बनाने की आशा की जा सकती है और भारत की सफल प्रजातन्त्र बनाने का स्वांल्ल स्वप्न पूर्ण हो सकता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भारतीय संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है : "राज्य इस संविधान के कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्तर्गत सभी बच्चों के लिये जब तक वे चौदह वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

इस स्थान पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के इतिहास पर विहंगम दृष्टिपात कर लेना अनुपयुक्त न होगा।

### प्राथमिक शिक्षा—अनिवार्यता से पूर्व

१७१७ से १८१३ तक

१७१७ में प्लासी के युद्ध के उपरान्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में राज्य-प्रसार के पथ पर अपना अभियान प्रारम्भ किया और उसी समय से भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारम्भ हुआ। उस समय तक देश में व्यापक अशिक्षा और अराजकता के परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा-व्यवस्था की काया पर्याप्त रूप से जीर्ण और जर्जर हो चुकी थी, फिर भी सम्पूर्ण देश में शिक्षा-संस्थाओं का जाल बिछा हुआ था, जो जनता में

१. भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ), १९६०, पृ० ७३।

२. "The state shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution for the free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years."—Article 43 of the Constitution adopted by Free India on January, 26, 1950.

कारण व्यक्तियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का भङ्ग न हो सके।

१८३५ के आसपास केवल बंगाल में एक लाख पाठशालायें थी।<sup>१</sup> परन्तु ब्रिटिशों ने अपने व्यापारिक एकाधिकार एवं राजनीतिक स्वामित्व को चिरस्थायी बनाये रखने की अभिलाषा से देशी शिक्षा का गला घोट दिया। "यदि किसी देश को दास बनाए रखना है, तो उसके साहित्य और संस्कृति का विनाश कर देना चाहिए।" अपनी शिक्षा-नीति के निर्माण में भारत के ब्रिटिश शासकों ने इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया। इसी के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा-व्यवस्था निष्प्राण होती चली गई और पारम्परिक सम्प्रदाय तथा संस्कृति से बौद्धिक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पनपने लगी।

१८१३ से १८५४ तक

आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था पर आधारित शिक्षासंस्थायें स्थापित करने का श्रेय मिशनरियों को प्राप्त है। उन्होंने ही भारतीयों की प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये शिक्षा-संस्थाओं का निर्माण किया। कम्पनी के शासनकाल में इसकी निश्चित रूप से व्यवहृतता की गई क्योंकि कम्पनी के संचालकों को व्यापार द्वारा धनोपार्जन में ही प्रमुख रुचि थी, न कि भारतीयों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करके धन व्यय करने की। १८१३ के आस-पास (Charter) के अनुसार भारतीय साहित्य के पुनर्स्थापन एवं विज्ञानों के प्रसार के लिये कम से कम एक लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने का आदेश दिया गया। परन्तु इस घोड़े से घन का, जो देश की इतनी विशाल जन-संख्या के लिये कदापि भी पर्याप्त नहीं था, दस वर्ष तक समुचित प्रयोग नहीं किया गया। १८२४ से शिक्षा के लिये घल्प धन-राशि व्यय की जाने लगी, परन्तु भ्रष्ट होने के कारण वह करोड़ों भारतीयों की शिक्षा की आवश्यकता को पूर्ण न कर सकी।

१८५४ से १८५७ तक

१८५४ के वुड के शिक्षा-घोषणा-पत्र (Wood's Despatch) में यह स्वीकार किया गया कि जन-साधारण की शिक्षा की पूर्ण रूप से व्यवहृतता की गई थी। अतः घोषणा-पत्र में कहा गया कि जन-साधारण को व्यावहारिक एवं सामुदायिक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय, प्राथमिक

1. A. N. Basu : *Education in Modern India*, p. 5.

2. *Ibid*, p. 5.

विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाय और सहायता-धनुदान (Grant-in-aid) द्वारा देशी विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाय। परन्तु भारत स्थित कम्पनी के कर्मचारियों ने प्राथमिक शिक्षा की उद्देश्य करके, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के प्रसार में ही अधिक धन व्यय किया। फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की प्रगति न हो सकी। १८५७ की क्रान्ति के उपरान्त ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कम्पनी की राजनैतिक शक्ती का अन्त करके भारतीय शासन की भागदोर अपने हाथ में सम्हाली।

१८५७ से १८८२ तक

१८५६ के स्टैनले के घोषणा-पत्र (Stanley's Despatch) में भारत-सरकार से प्राथमिक शिक्षा का भार अपने ऊपर लेने के लिये कहा गया और उसका व्यय-भार वहन करने के लिये स्थानीय कर लगाने का परामर्श दिया गया। फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की द्रुत गति से उत्पत्ति हुई। १८८२ के अन्त तक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ८२,६१६ और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या २१ लाख हो गई। परन्तु इन आंकड़ों से प्राथमिक शिक्षा के विकास को अनुपम स्वीकार कर लेना अस्वाभाविक होगा, क्योंकि १८८२ में भारत में साक्षरता का प्रतिशत केवल १.२ था।

१८८२ से १९०५ तक

१८८२ में भारतीय शिक्षा-आयोग (Indian Education Commission) की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस नवीन व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा की कुछ प्रगति तो अवश्य हुई, पर उसको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अथर्व आयोग ने यह स्पष्ट शब्दों में बतपूर्वक कहा था कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिये, तथापि सरकार ने इसकी अवहेलना की। वास्तविकता यह है कि सरकार ने स्थानीय संस्थाओं पर प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व डालकर उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा का उचित विस्तार नहीं हुआ। इसका प्रमाण इस बात से प्राप्त होता है कि १९०२ तक प्राथमिक विद्यालयों की छात्र-संख्या में केवल ६ लाख ६० हजार की वृद्धि हुई। स्थानीय संस्थाओं के प्रयास के बावजूद भी राज्य से पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा का विकास अवकट हो गया। प्राथमिक शिक्षा की सरकार द्वारा अवहेलना की गई थी, उसे भारत के गर्वनर-जनरल, लार्ड कर्जन (Lord

Curzon) ने इन शब्दों में स्वीकार किया : "प्राथमिक शिक्षा से मेरा अभि-  
प्राय जन-साधारण को मातृ-भाषा की शिक्षा देना है । मैं उन व्यक्तियों में से हूँ,  
जो समझते हैं कि सरकार ने इस विधा में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया  
है ।" १९०४ के "शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव" (Government  
Resolution on Educational Policy) में कर्जन ने स्वीकार किया :  
"प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न पर सामान्य रूप से विचार करने पर सरकार इस  
निष्कर्ष पर पहुँचे बिना नहीं रह सकती है कि अब तक प्राथमिक शिक्षा के प्रति  
अपर्याप्त ध्यान दिया गया है, और उसे सार्वजनिक कोष से अपर्याप्त धन-राशि  
प्राप्त हुई है ।"<sup>१</sup>

लार्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने और उनके  
शिक्षण-स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सराहनीय कार्य किया । परन्तु उसकी  
बंग-भंग (Partition of Bengal) की मूर्खतापूर्ण एवं निष्प्रयोजन नीति ने  
उसके सभी शिक्षा-कार्यों पर पानी फेर दिया । जनता उसकी सेवाओं की ओर  
रुचिमान भी ध्यान न देकर, उसके भ्रष्टाचार के कारण क्रोधान्वित हो  
उठी । १९०५ में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय आन्दोलन  
प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया । इस आन्दोलन ने भारतीयों को अपने  
अधिकारों के प्रति जागरूक कर दिया । अन्य अधिकारों के साथ-साथ उन्होंने  
विदेशी सरकार से शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की भी बलपूर्वक माँग में  
मौन थी । यहीं से प्राथमिक शिक्षा में एक मोड़ आता है, और वह अनिवार्य  
शिक्षा की दिशा में अग्रसर होती है ।

## अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

### प्रारम्भिक प्रयास

यद्यपि वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ तक अनिवार्य शिक्षा के लिये कोई  
ठोस कदम नहीं उठाया गया था, तथापि कतिपय शिक्षा-प्रेमी व्यक्तियों ने

1. "Primary Education—by which I understand the teaching of the masses in vernacular—opens a wider and more contested field of study. I am one of those who think that Government has not fulfilled its duty in this respect."  
—Curzon's Speech at the Simla Conference, 1901.
2. "On a general view of the question the Government of  
India cannot avoid the conclusion that primary education  
received insufficient attention and an inadequate share  
of the public funds." —Government Resolution on  
Educational Policy, 1904.





जांच करने के लिए १९०६ में एक समिति की नियुक्ति की। परन्तु प्राप्त के दुर्भाग्य से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करना उचित न होगा, क्योंकि जनता इसके लिए तैयार नहीं थी।<sup>१</sup>

### बड़ौदा का सर्वप्रथम प्रयोग

भारत में अनिवार्य शिक्षा का सर्वप्रथम सफल प्रयोग बड़ौदा-नरेश, महाराज सायाजीराव गायकवाड ने किया। उदार मस्तिष्क एवं शिक्षा-प्रेमी नरेश ने १८९२ में घोषित किया कि उनके राज्य के धमरेली नगर के एक ताल्लुका के ६ ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। ७ से १२ वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों और ७ से १० वर्ष तक की आयु की सब बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी थी। नवम्बर, १८९३ में अनिवार्य शिक्षा का यह कार्य प्रारम्भ किया गया और इसमें इतनी आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई कि उपरोक्त ताल्लुका के ५२ ग्रामों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। १९०६ में अधिनियम बनाकर राज्य के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया।<sup>२</sup>

### गोखले के असफल प्रयास

राष्ट्रीय भावनाओं से सराबोर शिक्षा के मर्मज्ञ गोपाल कृष्ण गोखले ने बड़ौदा—नरेश के उत्कृष्ट उदाहरण से अनुप्राणित होकर केन्द्रीय धारा-सभा (Imperial Legislative Council) में १६ मार्च १९१० को यह प्रस्ताव रखा: "यह सभा सिफारिश करती है कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाय।"<sup>३</sup> सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार किये जाने का आश्वासन प्राप्त होने पर गोखले ने प्रस्ताव को वापिस ले लिया, परन्तु सरकार ने अपने आश्वासन को साकार रूप देने का स्वप्न में भी विचार नहीं किया।

प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता देख कर गोखले ने १६ मार्च १९११ को केन्द्रीय धारा-सभा में प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी अपना विधेयक (Bill) प्रस्तुत किया। "इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा-

1. D. M. Desai : *Universal Compulsory and Free Primary Education in India*, pp. 42-48.
2. *The Gazetteer of the Baroda State*, pp. 310-312
3. "That this Council recommends that a beginning should be made in the direction of making elementary education free and compulsory, throughout the country."—Gokhale; *op. cit.*, p. 609.

राज्य में अनिवार्यता के सिद्धान्त को क्रमशः लागू करना था।" इस विधेयक के अनुसार स्थानीय परिषदों द्वारा सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त करके उन क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की जा सकती थी, जहाँ ६ से १० वर्ष तक की आयु के बालकों की एक निश्चित संख्या शिक्षा प्राप्त कर रही थी। परन्तु गोखले का अनिवार्य शिक्षा का शीघ्रगोचर करने का यह लक्ष्य तथा शुद्ध प्रयास सफल न हो सका। घारा-सभा में विधेयक का घोर विरोध हुआ और १६ मार्च १९१२ को इसे १३ वोटों के विरुद्ध ३८ वोटों से गिरा दिया गया।

### अनिवार्य शिक्षा-अधिनियम

गोखले के कार्य से प्रेरणा प्राप्त करके भारत के एक अग्र्य महान् नेता विठ्ठलभाई पटेल ने बम्बई की प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य प्रान्त के नगरपालिका क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना था। विधेयक ने १९१८ में 'बम्बई प्राथमिक अधिनियम' का रूप धारण किया। यह प्रथम अधिनियम था जिसके द्वारा एक प्रान्त की सरकार ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त की स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम शिक्षा-जगत में क्रान्ति का प्रसूत था। इसके परिणाम स्वरूप १९३० तक प्रायः सभी प्रान्तों में अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम पारित कर दिये गये।

अनिवार्य शिक्षा के इन अधिनियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया गया। अधिनियमों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भी इन्हीं संस्थाओं पर रखा गया। शिक्षा के व्यय की पूर्ति के लिए इन्हे 'शिक्षा-कर' (Education Cess) लगाने का अधिकार दे दिया गया। प्रान्तीय सरकारों ने इस व्यय के लिये आर्थिक सहायता देने का वचन दिया। अनिवार्य शिक्षा का लाभ वे ही बालक और बालिकाएँ उठा सकते थे, जिनकी आयु साधारणतः ६ वर्ष से १० वर्ष तक की थी।

### अनिवार्यता का प्रसार

अनिवार्य शिक्षा-अधिनियमों और राष्ट्रीयता की भावना की व्यापकता के फलस्वरूप अनिवार्य शिक्षा का प्रसार क्रमशः तीव्र होता गया। राष्ट्रपिता के पथ-प्रदर्शन में स्त्रियों ने अपने अधिकारों की माँग की। उन्होंने १९२७ में 'प्रखिल भारतीय स्त्री-शिक्षा सम्मेलन' आयोजित करके पुरुषों के अनुरूप शिक्षा की अधिकारिणी होने का नारा बुलन्द किया। महारत्ना गाँधी जी का ४० धन्देद्वार के अथक प्रयास से हरिजनों में न केवल जागृति, अपितु शिक्षा का प्रसार भी प्रारम्भ हुआ। इन सभी कारणों के फलस्वरूप जनता प्राथमिक शिक्षा में अधिक रुचि लेने लगी। परिणामस्वरूप उसकी प्रगति होना स्वाभाविक

था। भारत के सौभाग्य से १९२१ में प्रान्तीय शिक्षा का संचालन-सूत्र भारतीय मंत्रियों के हाथ आ जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को राजकीय योग की प्राप्ति हुआ।

अनिवार्य शिक्षा की यह प्रगति १९३० तक होती रही, परन्तु तत्पश्चात् १९३१ से १९३७ तक इसका विकास प्रायः अवरुद्ध हो गया। इसके दो प्रमुख कारण थे। प्रथम, यह काम विश्वव्यापी आर्थिक-अवसाद (Economic depression) का था जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। अतः अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था योजनाओं को स्थगित कर दिया जाना स्वाभाविक था। द्वितीय, १९२७ में नियुक्त की गई हार्टोग-समिति (Hartog Committee) ने इस बात पर बल दिया था कि प्राथमिक शिक्षा को अधिक लाभप्रद बनाने के लिये प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि न की जाय, अपितु उनकी गुणात्मक उत्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाय और शिक्षा को ठोस (Consolidation) बनाने की नीति का अनुसरण किया जाय। जनता का विरोध करने पर भी सरकार ने समिति के इस सुझाव को क्रियान्वित किया जिससे अनिवार्य शिक्षा पर बजट प्रहार हुआ और उसका प्रसार अवरुद्ध हो गया।

१९३७ में प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना के समय ११ प्रान्तों में से ६ में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का निर्माण हुआ। उन्होंने अपने प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रचलित करने के प्रयास किये। उन्होंने उन ग्रामों में स्कूल स्थापित किये जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं थे। स्थानीय संस्थाओं को प्रतिरिक्त सहायता-प्रनुदान दिया, जिससे वे प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में होने वाले व्यय का भार सहन कर सकें। जिन स्थानों में जनता की माँग थी, वहाँ बालिका-विद्यालय निर्मित किये। इन प्रयासों के फलस्वरूप अनिवार्य शिक्षा की प्रति द्रुत गति से उत्थिति हुई। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय बालकों के लिये २२९ नगरों तथा १०,०१७ ग्रामों और बालकों एवं बालिकाओं के लिये १० नगरों तथा १,४०४ ग्रामों में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जा चुकी थी।<sup>१</sup>

**स्वतंत्र भारत में अनिवार्य शिक्षा**

स्वतंत्र भारत ने अपने नवनिर्माण के लिये शिक्षा-प्रसार की आवश्यकता का अनुभव किया। इसीलिये राष्ट्रीय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क, सार्वभौमिक तथा अनिवार्य बनाने का निर्णय किया। भारतीय संविधान की ५५ वीं धारा में अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त की घोषणा की गई। यह शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा के प्रकार की होगी। इसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा का मदन

व्यक्त है। संयोजन ने निष्ठा है कि भारत की राजनीतिक स्थिति अनिवार्य शिक्षा योजना का कार्यान्वयन धीमे ही चाहती है परन्तु देश के राजनीतिज्ञ इसके लिये न तो उत्सुक ही हैं और न वे ऐसा करने की स्थिति ही में हैं।<sup>१</sup> कारण यह है कि सत्ता हस्तान्तरण के समय से लेकर आज तक उनके समक्ष कितनी ही कठिन समस्याएँ उपस्थित रही हैं और अब भी हैं, यथा-देशी राज्यों की समस्या, घरेलू विवादों की समस्या, काश्मीर की समस्या, चीन की समस्या, विभिन्न भाषा-भाषी राज्यों की समस्या, खाद्यान्न की समस्या इत्यादि। इन समस्याओं ने सरकार के इतने धन और ध्यान पर अधिकार रखा है कि अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी सरकार को शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्य पालन का अवकाश नहीं प्राप्त हुआ है।

#### ४. बोपपूर्णा शिक्षा-प्रशासन

भारत के अधिकांश राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर-पालिकाओं तथा जिला परिषदों पर है। जब यह बतें उन्हें सौंपा गया था, तब यह धारा थी गई थी कि इससे शिक्षा का प्रसार अधिक तीव्र गति से होगा। परन्तु समय की गति ने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं हुआ है। साधारणतः इन स्थानीय संस्थाओं में कार्य-क्षमता, धनिकता तथा धन का अभाव है। वे अनिवार्य शिक्षा का व्यवहार करने के लिये स्थानीय कर से सज्जी हैं, परन्तु ऐसा करने से पद-लोभुष सदस्य धानायी निर्वाचन में अपना पद रक्षित करने के विचार से सशक्त हो उठते हैं। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सभी अधिनियम समायोजन न होकर प्राचीन हो गये हैं। फिर ऐसी कोई केन्द्रीय संस्था या शक्ति नहीं है, जो स्थानीय संस्थाओं को इन्हें कार्यान्वित करने के लिये बाध्य करे। ऐसी स्थिति में वे अधिनियम केवल पुरनकों में लिखे हुए ही रह गये हैं। इनके प्रतिष्ठित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में तो कृद्धि की गई है, परन्तु उनके अनुदान में शिक्षा-निरीक्षकों की कृद्धि नहीं की गई है। शिक्षा-प्रशासन की ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में महान् बाधक निम्न हो रही है।

#### ५. शिक्षकों की समस्या

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में शिक्षकों की बाधित संख्या उत्तम न होने के कारण सरकार के लक्ष्य एक प्रति प्रतिशत समस्या उत्पन्न है। अनुमान लगाया गया है कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये २५ लाख

शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु इनमें से केवल ६२३,२५५ शिक्षक ही उपलब्ध हैं।<sup>१</sup> १९५५-५६ में प्रति शिक्षक के पास औसत रूप में शिक्षा देने के लिये ३३ छात्र थे।<sup>२</sup> नगर-विद्यालयों की अपेक्षा ग्राम विद्यालयों में शिक्षकों का अधिक अभाव है। शिक्षकों की वाञ्छित संख्या प्राप्त न होने तथा विद्यालयों में उनका अभाव होने का प्रमुख कारण यह है कि नवयुवकों के लिये अध्यापन कार्य आकर्षक नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन इतना निम्न है कि किसी योग्य तथा सुशिक्षित नवयुवक का ध्यान उधर आकृष्ट ही नहीं होता है। नगरों में तो उनको मनोपार्जन के अन्य साधन प्राप्त रहते हैं, परन्तु ग्रामों में इस बात की आशा करना असम्भव है। इसके अतिरिक्त ग्रामों की अपेक्षा नगरों में सुखद जीवन व्यतीत करने के अधिक उत्तम साधन उपलब्ध होते हैं। इन्हीं सब बातों का विचार करके युवक अध्यापक ग्राम-विद्यालयों में कार्य नहीं करना चाहते हैं। जहाँ तक अध्यापिकाओं का प्रश्न है, वे ग्राम-विद्यालयों में कार्य करने का विचार ही नहीं करती हैं, जब तक कि उनका निवास-स्थान उसी ग्राम में न हो जिसमें कि विद्यालय है। ऐसी स्थिति में अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं का प्राथमिक विद्यालयों में स्थायी अभाव होना स्वाभाविक है। इस अभाव की उपस्थिति में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य बनाया जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता है।

#### ६. शिक्षण का निम्न स्तर

प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की ग्यूनता है। १९५५-५६ में इन विद्यालयों में ६,९१,२४६ व्यक्ति अध्यापन कार्य कर रहे थे, जिनमें से २,६८,०५७ अध्यापक तथा अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित थे।<sup>३</sup> प्रशिक्षित अध्यापक शिक्षण-विधियों से परिचित नहीं होते हैं। समस्त शिक्षकों में से ५ प्रतिशत से भी कम हाईस्कूल अथवा मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण हैं। शेष सभी प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं। अभाव के कारण प्राथमिक विद्यालय शिक्षण के उपकरणों को प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इन समस्त कारणों के फलस्वरूप शिक्षा अक्षवर्धक तथा निम्न स्तर पर है। अतः वह बच्चों तथा उनके अभिभावकों को पाहट्ट करने में असफल रहती है।

1. S. N. Mukerji : *Education in India Today and Tomorrow*, p. 102.

2. *Education in India*, 1955-56, p. 71.

3. *...*



प्रतिष्ठित विद्यालय-भवन ही ऐसे हैं, जिन्हें उपयुक्त कहा जा सकता है। ऐसी सभी विद्यालय किराये के मकानों, मन्दिरों, धनी धार्मिकों के गृहों, अध्यापकों के निवास-स्थानों आदि में चल रहे हैं। इनमें जगह का अभाव है और छात्रों के बैठने तथा खेतने के लिये उचित व्यवस्था नहीं है। अनेकों विद्यालय कोला-हलपूर्ण अथवा अवाञ्छनीय वातावरण में स्थित हैं तथा उनके भवनो में धूप एवं वायु का प्रवेश न हो सकने के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि शिक्षा को अनिवार्य करके छात्रों की संख्या में वृद्धि कर दी जाय तो उन्हें शिक्षा कहाँ दी जाय। निःसंदेह, उत्तर होगा कि नवीन भवनों का निर्माण किया जाय। पर इसके लिये धन जुटाना जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, अत्यन्त कठिन है।

## १०. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम

प्राथमिक विद्यालय का पाठ्य-क्रम संकीर्ण तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। इसमें पुस्तकीय शिक्षा पर बल दिया जाता है और छात्र की अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास करने तथा कार्य करके सीखने के सिद्धान्त को अवहेलना की जाती है। पाठ्य-क्रम के इन दोषों का निराकरण करने के लिये सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा का रूप प्रदान करने का निश्चय किया है। इससे पाठ्यक्रम के दोष तो अनिवार्य रूप से दूर हो जायेंगे, परन्तु बेसिक शिक्षा की व्यापक योजना को सम्पूर्ण देश में एक साथ न तो क्रियान्वित किया जा सकता है और न किया जा सका है।

## ११. अपव्यय एवं अवरोधन

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अत्यधिक अपव्यय (Wastage) एवं अवरोधन (Stagnation) है। प्रत्येक १०० छात्रों में से जो १९५२-५३ में बसा १ में थे, केवल ४३ छात्र १९५५-५६ में कक्षा ४ में पहुँचे।<sup>१</sup> इस प्रकार ५७ प्रतिशत छात्र परीक्षाओं में असफल होने अथवा अपने अभिभावकों को कार्य करके तथा धनोपार्जन करके सहायता देने के लिये विद्यालयों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर गये। दुर्भाग्य से विद्यालयों की उपकरण हीनता, अवाञ्छनीय स्थिति तथा आकर्षण रहित भवन उनको सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रत्यक्षोत्थित न कर सके। इस बात की परम आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को दूर किया जाय, अन्यथा अनिवार्य शिक्षा-योजना अथवा शिक्षा-असार की अन्य किसी भी योजना का सफल होना असम्भव है।

1. *Education in India, 1955-56, p. 64.*



७. **प्राथमिक समस्या**  
प्राथमिक विद्यालयों के समस्त प्राथमिक समस्या घनिष्ठ विचारों रूप में उपस्थित रहती है। हम ऊपर निम्न युक्त हैं कि प्राथमिक शिक्षा का उत्तर-दायित्व नगरपालिकाओं तथा विद्यालयों पर है। सरकार ने ऐसा व्यवस्थापन तो उन पर रखा दिया, परन्तु उनके लिये धन की कोई व्यवस्था नहीं की। उनके स्वयं के धन-साधन सीमित हैं, जिनमें वे प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर उसका व्यवस्थापन करने में संबंधी प्रत्यक्ष हैं। ब्रिटिश शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय का ३० प्रतिशत सरकार द्वारा दिया जाता था। स्वतंत्र भारत में इस धन-राशि को ३३ प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस न्यून प्राथमिक सहायता को शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये किसी प्रकार उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः देश के नागरिकों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व राज्य पर होता है, न कि स्थानीय संस्थाओं पर। फिर यदि प्राथमिक समस्या में प्रत्यक्ष स्थानीय संस्थाएँ शिक्षा को अनिवार्य बनाने का विचार नहीं करती हैं, तो इसके लिये उन पर दोषारोपण करना संबंधी अनुचित है।

#### ८. विद्यालय स्थापना की समस्या

अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में एक अन्य कठिनाई विद्यालयों की स्थापना की समस्या है। नगरों में तो नहीं, परन्तु ग्रामों में इस कठिनाई पर विचार प्राप्त करना दुष्कर प्रतीत होता है। भारत ग्राम-प्रधान देश है, परन्तु दो-तिहाई ग्राम ऐसे हैं, जिनमें विद्यालय नहीं हैं, १९५१ की जन-गणना के अनुसार भारत में ५५,००,००० ग्राम हैं। इनमें से ३,८०,०२० ग्राम ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या ५०० से कम है। शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये लगभग ५ लाख ग्रामों में, जिनमें ५०० से कम जनसंख्या वाले भी ग्राम सम्मिलित हैं, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना आवश्यक है। परन्तु इतने विद्यालयों के निर्माण के लिये धन एकत्रित करना सरल नहीं है। फिर ५०० से कम की जनसंख्या वाले ग्रामों में विद्यालय निर्मित करना अधिक बालकों की शिक्षा के लिये हितकर सिद्ध नहीं होगा। यह एक ऐसी समस्या है जिसने देश के प्रशासकों तथा शिक्षाविदों के समक्ष एक जटिल प्रश्न उपस्थित कर दिया है।

#### ९. विद्यालय-भवन की समस्या

विद्यालय-भवनों की एक अन्य समस्या है। प्रायः हमारे देश में केवल ३०

1. Education in India, 1952-53, Vol. I, p. 27.
2. भारत, १९६०, पृष्ठ १३

प्रतिष्ठित विद्यालय-मवन ही ऐसे हैं, जिन्हें उपयुक्त कहा जा सकता है। देश सभी विद्यालय किराये के मकानों, मन्दिरों, घनों, व्यक्तियों के गृहों, मध्यापकों के निवास-स्थानों आदि में चल रहे हैं। इनमें जगह का अभाव है और छात्रों के बैठने तथा खेलने के लिये उचित व्यवस्था नहीं है। अनेकों विद्यालय कोला-हलपूर्ण भयवा अवाञ्छनीय आवावरण में स्थित हैं तथा उनके भवनों में वर्ष एवं वायु का प्रवेश न हो सन्ने के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि शिक्षा को अनिवार्य करके छात्रों की संख्या में वृद्धि कर दी जाय तो उन्हें शिक्षा कहाँ दी जाय। निःसंदेह, उत्तर होगा कि नवीन भवनो का निर्माण किया जाय। पर इसके लिये घन जुटाना जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, अत्यन्त कठिन है।

## १०. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम

प्राथमिक विद्यालय का पाठ्य-क्रम संकीर्ण तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। इसमें पुस्तकीय शिक्षा पर बल दिया जाता है और छात्र की अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास करने तथा कार्य करके सीखने के सिद्धान्त की अवहेलना की जाती है। पाठ्य-क्रम के इन दोषों का निराकरण करने के लिये सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा का रूप प्रदान करने का निश्चय किया है। इससे पाठ्यक्रम के दोष तो अनिवार्य रूप से दूर हो जायेंगे, परन्तु बेसिक शिक्षा की व्यापपूर्ण योजना को सम्पूर्ण देश में एक साथ न तो क्रियान्वित किया जा सकता है और न किया जा सका है।

## ११. अपव्यय एवं अवरोधन

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अत्यधिक अपव्यय (Wastage) एवं अवरोधन (Stagnation) है। प्रत्येक १०० छात्रों में से जो १९५२-५३ में कक्षा १ में थे, केवल ४३ छात्र १९६५-६६ में कक्षा ४ में पहुँचे।<sup>१</sup> इस प्रकार ३७ प्रतिशत छात्र परीक्षाओं में असफल होने अथवा अपने अभिभावकों को कार्य करके तथा अनौपचारिक करके सहायता देने के लिये विद्यालयों से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर गये। दुर्भाग्य से विद्यालयों की उपकरण हीनता, अवाञ्छनीय स्थिति तथा आकर्षण रहित भवन उनको सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रेरित नहीं कर सके। इस बात की परम आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को रोककर जाय, अतः अनिवार्य शिक्षा-योजना अथवा शिक्षा-प्रसार की अन्य किसी भी योजना का सफल होना अत्यन्त आवश्यक है।

## १२. भौगोलिक कठिनाइयाँ

घनिवार्य शिक्षा के प्रसार में भौगोलिक कठिनाइयाँ अत्यन्त बाधक सिद्ध हो रही हैं। हिमाचल-प्रदेश, काश्मीर, गढ़वाल और अल्मोड़ा आदि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने के कारण ग्राम दूर-दूर पर स्थित हैं। यही बात राजस्थान के रेतीले प्रदेश के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। फिर मध्य-प्रदेश, मध्य भारत तथा दक्षिण में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जो जंगलों से ढके हुए हैं और जहाँ की जनसंख्या छोटे एवं सुदूर ग्रामों में बिखरी हुई है। उपरोक्त सभी प्रदेशों में आवागमन के साधनों का अभाव है और शीत, उष्णता अथवा भारी वर्षा यात्रा के मार्गों में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित करते हैं। क्योंकि भारत के प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, अतः इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके दूसरे ग्राम-विद्यालयों में ऐसा शानाजंन करने के लिये जाना, जिसका वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है, छात्रों एवं उनके अभिभावकों द्वारा बुद्धिमानों की बात नहीं समझी जाती है।

## १३. सामाजिक समस्याएँ

धर्माश्रयता, अन्धविश्वास, दृष्टिवादिता, अधिशासिता तथा प्राचीन परम्पराओं में, अस्था रहने के परिणामस्वरूप भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, जहाँ के निवासी नाना प्रकार की सामाजिक समस्याओं में अस्त न हों। उदाहरणार्थ, बाल-विवाह, अस्पृश्यता, पर्दा-प्रथा, धार्मिक सिद्धान्त आदि ऐसी अनेकों बातें हैं जिन्होंने घनिवार्य शिक्षा के मार्ग में अड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। बाल-विवाह-नियम अधिनियम की चिन्ता न करके मात्र भी प्राचीन विचारों के अनेकों व्यक्ति बालकों तथा बालिकाओं का अल्प आयु में विवाह करके उन्हें शिक्षा से वंचित कर देते हैं। विधान द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार दिये जाने पर भी मात्र अनेकों हरिजन छात्रों को किसी न किसी बहाने से विद्यालयों में प्रवेश करने से निषेध कर दिया जाता है। मात्र भी अनेकों हिन्दुओं तथा मुसलमानों का हड़ विरवास है कि बालिकाओं को या तो शिक्षा दी ही नहीं जानी चाहिये या यदि दी भी जाय तो अति ग़ुन। पर्दा-प्रथा के कारण मात्र भी ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है, जो प्राथमिक विद्यालयों में भी सह-शिक्षा के विरोधी हैं। जब जनता का दृष्टिकोण ऐसा है, तब शिक्षा की घनिवार्य बनाना निःसंदेह एक गम्भीर समस्या है।

## १४. अभिभावकों की धार्मिक स्थिति एवं अधिशासिता

अभिभावकों की धार्मिक स्थिति एवं अधिशासिता भी शिक्षा के मार्ग में अड़ी दीवारें खड़ी कर रही हैं। अनेक गाँव के लोगों के अतिरिक्त सभी लोग

अधिक संकट में प्रस्त है। वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों ने उनकी कठिनाई को कई गुना अधिक बढ़ा दिया है। भारत में ऐसे करोड़ों व्यक्ति हैं जिन्हें पेट भरने के लिए भोजन तथा तन ढकने के लिये कपड़े भी नसीब नहीं हैं। इन दयनीय दशा में वे यह अधिक उत्तम समझते हैं कि उनके बालक तथा बालिकाएँ या तो कुछ धनोपार्जन करें या उनके कार्य में हाथ बँटा कर उन्हें अधिक धन का प्रजन करने के योग्य बनाएँ, जिससे वे अपना तथा उनका भरण-पोषण कर सकें। अतः वे अपने बच्चों को शिक्षा देने का स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते हैं। फिर भारत में अधिशा के दानव का भयंकर साम्राज्य है। यहाँ की केवल १९.६१ प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है।<sup>१</sup> अधिशा के ऐसे वातावरण में अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा देने के लिये बहना संव्या विरमक है। जो अभिभावक स्वयं ही शिक्षित नहीं हैं, वे अपने बच्चों की शिक्षा द्वारा सामान्वित होने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं।

## १५. भाषा की समस्या

अनिवार्य शिक्षा की अन्तिम समस्या भाषा की है। १९५१ की जनगणना के अनुसार देश में ८४५ भाषाएँ समझा बोलिमाँ बोली जाती हैं।<sup>२</sup> देश के प्रशासकों के साथ समस्या यह है कि इनकी विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले बच्चों को शिक्षा किस भाषा के माध्यम द्वारा दी जाय। भारतीय संविधान में जिन १४ भाषाओं का उल्लेख किया गया है, वे ऐसी हैं जिनकी शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है, परन्तु ऐसी अनेक भाषाएँ हैं जिनको इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, ऐसी अनेकों अनुसूचित तथा आदिम जातियाँ हैं, जिनका न तो कोई साहित्य है और न कोई वर्णमाला। फिर उनकी संख्या भी ७.७८ करोड़ है।<sup>३</sup> इनके अतिरिक्त ४० लाख निरक्षरों के आदिम जातीय लोग और हैं।<sup>४</sup> इन विप्लवी हुई जातियाँ में अभी तक अनिवार्य शिक्षा का प्रवेश बहुत ही कम हो पाया है।

उपरिनिर्दिष्ट समस्याओं एवं कठिनाइयों में अनिवार्य शिक्षा के प्रचार-कार्य का निर्वाह उन्नयन नहीं होने दिया है। परन्तु इसमें हतोत्साहित न होकर देश के कुशल शिक्षा-विशेषज्ञ राज्य के सहयोग से उनके अपरोक्षण में क्रियाशील हैं। हम इन समस्याओं के निराकरण तथा कठिनाइयों के उन्मूलन के सम्बन्ध में कुछ विचार पत्रित शुभाव निष्क्रिय पत्रियों में दे रहे हैं।

१. भारत, १९६०, पृष्ठ, ७७

२. वही, पृष्ठ १२

३. वही, पृष्ठ, ११६

४. वही

## अनिवार्यता-प्रसार सम्बन्धी गुम्नाव

हमने अनिवार्य शिक्षा की त्रिन समस्याओं एवं कठिनाइयों का विवरण ऊपर दिया है, उन पर विजय प्राप्त करने के लिये कुछ भावहारिक गुम्नावों को प्रयोजित पंक्तियों में संक्षिप्त किया जा रहा है :—

### १. अनिवार्य शिक्षा की निश्चित नीति

सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपनी अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी नीति को पूर्ण रूप से निश्चित कर ले। सरकार घोषित कर चुकी है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा बेसिक शिक्षा के प्रकार की होगी। परन्तु इसके साथ-साथ सरकार इस बात को भी स्वीकार कर चुकी है कि कुछ ही समय में सम्पूर्ण देश में बेसिक शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करना असम्भव है। इस प्रकार सरकार एक भावदर्श को तो अपने समक्ष रखना चाहती है, परन्तु उसको प्राप्त करने में स्वयं ही अपनी असमर्थता को स्वीकार करती है। ऐसी दशा के सर्वोत्तम नीति यही हो सकती है कि अनिवार्य शिक्षा की नीति को भावदर्शवाद पर आधारित न करके मर्याद परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाय। अनिवार्य शिक्षा और बेसिक शिक्षा का प्रसार दृष्टि रूप से किया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालयों में जो भी शिक्षा दी जा रही है, उसी को अनिवार्य बनाया जा सकता है, चाहे उसका रूप कुछ भी हो। उस शिक्षा को सन्तानों और सुविधानुसार बेसिक शिक्षा का रूप प्रदान किया जा सकता है। यदि सरकार ने इस सिद्धान्त पर अपनी अनिवार्य शिक्षा-सम्बन्धी नीति का निर्माण नहीं किया, तो यह निःसंकोच रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि निकट भविष्य में अनिवार्यता की प्राप्ति करना व्यर्थ है।

### २. शिक्षा-प्रशासन में सुधार

इस समय प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं के ऊपर है। परन्तु जैसा कि हम लिस चुके हैं, इन संस्थाओं की उदासीनता तथा असमर्थता के कारण अनिवार्य शिक्षा के प्रसार की गति अत्यन्त मन्द है। नागरिकों को शिक्षित करने का भार राष्ट्र के ऊपर होता है। अतः यह आवश्यक है कि अनिवार्य शिक्षा के पुनीत कार्य का भार सरकार स्वयं अपने ऊपर ले। यदि किन्हीं कारणों वश सरकार कुछ समय के लिये इस उत्तरदायित्व को नहीं सम्हाल सकती है, तो उसे एक ऐसी शक्तिशाली केन्द्रीय संस्था स्थापित कर देनी चाहिये जो एक निश्चित अवधि में जिला-परिषदों तथा नगर-शासिकाओं को अपने क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने के लिये बाध्य करे। परन्तु इसके साथ-साथ

आवश्यकता इस बात की होगी कि इस शिक्षा से सम्बन्धित जो भी व्यय हो, उसको सरकार पूर्ण करे।

### ३. शिक्षकों की समस्या

शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये शिक्षकों की वाञ्छित संख्या उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। प्रारम्भ में न्यूनतम वेतन पर आवश्यक योग्यताओं के शिक्षकों को चुना जा सकता है, चाहे वे अप्रशिक्षित ही क्यों न हों। उनमें से प्रति वर्ष एक निश्चित संख्या को विद्योपार्जन करके अपनी योग्यताओं को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है, भयवा उन्हें राज्य-व्यय पर प्रशिक्षण विद्यालयों में दीक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ करने के लिये उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक कि उचित शिक्षकों की उचित संख्या उपलब्ध न हो जाय, विवेकपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता है। सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों को अधिक वेतन, अधिक सुविधायें तथा अधिक सम्मान प्रदान करके अभ्यापन-कार्य के प्रति आकर्षित किया जाय।

### ४. आर्थिक समस्या

घनभाव के कारण अनिवार्य शिक्षा का प्रसार अबाध गति से नहीं हो रहा है। यदि सम्पूर्ण देश में अनिवार्य बेसिक शिक्षा की योजना को ६ से १४ वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों के लिये क्रियान्वित कर दिया जाय, तो प्रतिवर्ष २६६.५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।<sup>१</sup> शिक्षा पर इतना घन व्यय करना इस निर्धन देश की शक्ति से परे की बात है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर ६३ करोड़ रुपये व्यय किया गया, परन्तु अन्य विज्ञान कार्यों के लिये धन की आवश्यकता होने के कारण द्वितीय योजना में इस राशि को बढ़ा कर ८६ करोड़ कर दिया गया।<sup>२</sup> घनभाव की ऐसी दशा में हमारा ध्येय प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि पर नहीं होना चाहिये, अपितु हमें इस बात का प्रयास करना चाहिये कि कम धन व्यय करके अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित किया जा सके, जिससे वे अज्ञानता के मार्ग में न भटकें। इस सम्बन्ध में गोपाल कृष्ण गोखले के ये शब्द उत्तेजनीय हैं : "जन-शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अशिक्षा का नाश करना है। शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि महत्वपूर्ण अवश्य है, पर उस पर अभी बल दिया जाना चाहिये जब अज्ञानता

1. Education in India, 1953-54, Vol I, p. 116.

2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ ४६८

का विनाश हो जाय।<sup>१</sup> इस कथन के निर्विवाद सत्य को ध्यान में रखकर जो धन प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक स्कूलों में परिणत करने में व्यय किया जा रहा है, उसे पूर्ण रूप से तो नहीं पर अधिकांश रूप से समाप्त कर देना वांछनीय होगा। सर्व प्रथम अनिवार्य शिक्षा पर न कि बेसिक शिक्षा के रूप में अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिये। कुछ भारतीय शिक्षा-विदों का मत है कि प्राथमिक शिक्षा की अवधि को चार वर्ष करके भी व्यय को कम किया जा सकता है। आस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, मिश्र, चीन और रूस ने प्राथमिक शिक्षा की अवधि को चार वर्ष रख कर ही जन-साधारण में शिक्षा का प्रसार किया।<sup>२</sup> देसाई का सुझाव है कि अनिवार्य शिक्षा के व्यय को कम करने के लिये धनी व्यक्तियों के बच्चों से शुल्क लिया जाय और व्यक्तिगत प्राथमिक विद्यालयों को बच्चों से शुल्क लेने की अनुमति दे दी जाय।<sup>३</sup> यदि इन सभी सुझावों को सरकार द्वारा मांग्यता प्रदान कर दी जाय, तो अनिवार्य शिक्षा की आर्थिक समस्या का समाधान सम्भव हो सकता है।

#### ५. विद्यालयों की समस्या

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की समस्या अति जटिल है। नये विद्यालयों के निर्माण के लिये धन का अभाव है। फिर अनेकों ग्राम दूर-दूर तथा छोटे हैं। यदि विद्यालयों के निर्माण के लिये धन प्राप्त हो सकता है, तो उन्हें ऐसे ग्रामों में पहिले निर्मित किया जाय, जहाँ उनकी आवश्यकता अधिक है। जो ग्राम छोटे हैं, उनके मध्य में विद्यालय निर्माण के लिये ऐसे ग्राम को चुना जाय, जो सभी ग्रामों के बच्चों के लिये सुविधाजनक हो। परन्तु यदि धन उपलब्ध नहीं है, तो अनिवार्य शिक्षा का कार्य इसलिये स्थगित नहीं कर देना चाहिये कि छात्रों के लिये विद्यालयों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। बच्चों को जब शिक्षित ही किया जाना है तो मन्दिरों, मसजिदों, धर्मशालाओं, सरायों, जमींदारों की चौपालों अथवा अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इंग्लैण्ड में तो विद्यालयों के अभाव में बच्चों को रेल के पुनो के नीचे बैठकर शिक्षा दी जाती थी।<sup>४</sup> फिर प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति अथवा

1. "Primary purpose of mass education is to banish illiteracy. The quality of education is a matter of importance that comes only after illiteracy has been abolished." Gokhale : *op. cit.*, p. 651.
2. Dinker Desai : *Primary Education in India*, pp. 31-32.
3. D. M. Desai : *op. cit.*, p. 337.
4. *Ibid.*, p. 84.

शान्तिनिकेतन की प्रणाली के अनुसार बूझों की छाया में बच्चे विद्यार्जन कर सकते हैं। आयरलैण्ड में तो कुछ समय पूर्व तक इसी पद्धति को अपनाया गया था।<sup>१</sup> भारत को भी विद्यालयों के निर्माण पर अपना ध्यान केन्द्रित न करके, देश के भावी नागरिकों को ज्ञान के पथ पर अग्रसर करने का श्रेय अपनाना चाहिये।

#### ६. पाठ्यक्रम की समस्या

प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम एक-भागीय तथा अर्धचक्र है। स्थानीय पर्यावरण से सम्बन्धित न होने के कारण उसमें किसी प्रकार की उपादेयता नहीं है। यह ठीक है कि सरकार बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कार्यान्वित करके शिक्षा को रोचक बनाने का प्रयास कर रही है, परन्तु इस कार्य में अति दीर्घ समय लगेगा। अतः उस समय तक के लिये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में किसी कला-कौशल की शिक्षा दी जाय। इससे बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ेगी और वे अपने अर्जित ज्ञान से कुछ लाभ भी उठा सकेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि हस्त-कौशल की शिक्षा देने के लिये कोई विद्वान तथा प्रशिक्षित अध्यापक ही रखा जाय। इस कार्य के लिये किसी भी स्थानीय तथा अनुभवी व्यक्ति की सेवाओं से लाभ उठाया जा सकता है।

#### ७. पारि-विधि का प्रचलन

पारि-विधि (Shift System) के प्रचलन द्वारा अध्यापकों तथा विद्यालय भवनों के अभाव पर पर्याप्त मात्रा में विजय प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि इस विधि को आदर्श रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तथापि अध्यापकों एवं विद्यालय-भवनों के अभाव की वर्तमान स्थिति में इसको अपनाना ही श्रेयस्कर होगा। पारि-विधि के अनुसार एक ही भवन में विभिन्न छात्रों की दो अधिवेशनों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये बुलाया जा सकता है—प्रथम प्रातः ७.३० बजे से ११.३० बजे तक और द्वितीय १ बजे से ५ बजे तक। पारिविधि को विश्व के अनेकों देशों ने शिक्षा-प्रसार की प्रारम्भिक दशाओं में अपनाया है। इन देशों में जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि हैं। आज भी इस प्रथा का आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, टर्की, मिस्र, चीन, लंका, डेनमार्क आदि देशों में प्रचलन है।<sup>२</sup> भारत में इस प्रणाली का प्रचलन किया जाना चाहिये। यदि ऋतुधी, कुचकी तथा भूमिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विद्यालयों के अधिवेशनों का समय निर्दिष्ट कर

1. Dinker Desai : *op. cit.*, p. 88

2. S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 103.



दिया जाय, तो इस प्रणाली से भारत के बच्चों में ज्ञान का प्रसार यदि सर-  
सता पूर्वक किया जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि शिक्षकों को कुछ  
अधिक कार्य करना पड़ेगा। पर यदि उनको कुछ अधिक वेतन दे दिया जायगा,  
तो उनको अधिक कार्य करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

## ८. कक्षाओं में छात्र-संख्या की वृद्धि

मनिवार्म शिक्षा के तीव्र विकास के लिये कतिपय भारतीय शिक्षा-मर्मज्ञों  
का मत है कि कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि कर दी जाय। इस समय  
प्रत्येक शिक्षक को औसत रूप से एक कक्षा में ३३ छात्रों को शिक्षा देनी पड़ती  
है।<sup>१</sup> अनेको पाश्चात्य देशों में प्रति शिक्षक को शिक्षा देने के लिये ३३ से  
कहीं अधिक छात्र थे। उदाहरणार्थ, १९२२ तक इंग्लैन्ड में प्रत्येक कक्षा में  
छात्रों की संख्या ६० तक थी और १९३२ तक इटली में भी यही संख्या थी।  
राष्ट्र संघ ने चीन के प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं के लिये भी ६० छात्रों  
की सिफारिश की थी। अतः जिन भारतीय प्राथमिक विद्यालयों में एक अध्या-  
पक एक ही कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, वहाँ छात्रों की संख्या में  
निश्चय रूप से वृद्धि की जा सकती है। हाँ, जिन विद्यालयों में एक अध्यापक  
एक से अधिक कक्षा को एक ही समय में शिक्षा देता है, वहाँ इस योजना को  
क्रियान्वित करना उचित नहीं होगा।

## ९. विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना

उन देशों में जहाँ आदिम, अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जातियाँ निवास  
करती हैं विशिष्ट स्कूलों की स्थापना आवश्यक है। स्वतंत्र भारत में इस ओर  
पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। सरकार इन जातियों के छात्रों के लिये विशिष्ट  
स्कूल स्थापित कर रही है और उन्हें निःशुल्क पढ़ाई, छात्रवृत्तियों, पुस्तकों,  
लेखन-सामग्री आदि की सुविधायें दे रही है।<sup>२</sup> द्वितीय पंचवर्षीय योजना के  
अवधि में आदिम जातीय क्षेत्रों में ३,१८७ और अनुसूचित जातियों के लि-  
६,००० स्कूल और छात्रावास स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह  
सराहनीय है, परन्तु जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि अनुसूचित त-  
आदिम जातियों की संख्या प्रमथाः ५.५३ करोड़ तथा २.२५ करोड़ है,  
हमें कुछ निराशा प्रतीत होने लगती है। शिक्षा द्वारा शताब्दियों से पद-ब-

1. *Education in India, 1955-56, p. 71.*

२. भारत, पृष्ठ १२०

३. वही, पृष्ठ १२२

इन शक्तियों की शिक्षा का भार केवल सरकार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिये, अपितु जनता को भी इस पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान करना चाहिये ।

## १०. जनता का सहयोग

धनिवार्य शिक्षा के प्रसार के लिये देश-व्यापी प्रयास की आवश्यकता है । जब सरकार के साथ-साथ इस देश के निवासी प्रत्येक बाधा का उन्मूलन करके, प्रत्येक कठिनाई का व्ययरोपण करके और प्रत्येक समस्या का समाधान करके, भारत के कोने-कोने में सरस्वती देवी को बरासन पर प्रतिष्ठित करने के लिये कटिबद्ध हो जायेंगे, सभी ४० करोड़ से अधिक निवासियों के इस विस्तृत भूभाग में शिक्षा का प्रवाह अनवरत गति से प्रवाहित हो सकेगा । देश के विकास में शिक्षा का विकास सन्निविष्ट है । पंचवर्षीय तथा सामुदायिक विकास योजनाओं से जितने शीघ्र भारत का विकास होगा, उतने ही शीघ्र शिक्षा अपने मार्ग पर अग्रसर होगी । यातायात एवं परिवहन के साधनों का विकास बालकों के मार्ग में आने वाली भौगोलिक कठिनाइयों का अन्त कर देगा । देश का औद्योगीकरण तथा कृषि-सुधार की योजनायें भारत के निवासियों के आर्थिक स्तर को उच्च कर देंगी और वे धनाभाव के कारण अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे । फलस्वरूप शिक्षा में होने वाला अपव्यय समाप्त हो जायगा । सरकार द्वारा समाज-शिक्षा की जो योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, उनसे जनता का दृष्टिकोण संकुचित न रह कर विस्तृत हो जायगा और वह शिक्षा के महत्त्व तथा मूल्य को समझ सकेगी । परन्तु सरकार द्वारा देश, समाज तथा जनता की उन्नति के हेतु जो भी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं, उनकी सफलता अथवा असफलता इस देश के निवासियों पर निर्भर है । कोई भी सरकार चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली तथा धन एवं साधन सम्पन्न क्यों न हो, देश की प्रगति के पथ पर तब तक नहीं अग्रसर कर सकती है, जब तक उसकी जनता निस्स्वार्थ भाव से उसे पूर्ण सहयोग न प्रदान करे । अतः प्रत्येक भारतीय का यह एक परमावश्यक कर्तव्य हो जाता है कि वह सरकार के कार्यों में हाथ बटा कर देश के कल्याण की योजनाओं को सफल बनाये । इन योजनाओं की सफलता पर ही शिक्षा-विस्तार की सफलता आधारित है ।

५६१५

७८



ने प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की है। १९०५ में काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय चान्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया। तभी से जनता का ध्यान प्राथमिक शिक्षा द्वारा जन-शिक्षा की ओर आकृष्ट हुआ।

**अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा**—१८१८ में ऐडम ने, १८५२ में विनगेट ने और १८५८ में टी० सी० होप ने अनिवार्य शिक्षा के प्रस्ताव रखे, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने उनको स्वीकार नहीं किया। १९०६ में बड़ौदा नरेश ने अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। १९११ में गोसले ने केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य शिक्षा का विधेयक प्रस्तुत किया, परन्तु उनको मफज्जा न मिला। १९१८ में 'बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम' पारित किया गया। १९३० तक प्रायः सभी प्रान्तों में अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम बना दिये गये। १९३७ में ६ प्रान्तों में काँग्रेसी मंत्रिमंडलों का निर्माण हो जाने के कारण प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार सरकार ने अनिवार्यता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है।

**अनिवार्य शिक्षा की समस्याएँ**—ये समस्याएँ अवलिनित हैं—(१) ब्रिटिश सरकार की उदासीनता, (२) भारतीय सरकार की होपपूर्ण नीति, (३) राजनीतिक कठिनाइयाँ, (४) होप-पूर्ण शिक्षा-प्रशासन, (५) शिक्षकों की समस्या, (६) शिक्षण का निम्न स्तर, (७) आर्थिक समस्या, (८) विद्यालय-स्थापना की समस्या, (९) विद्यालय-सबन की समस्या, (१०) अनुपयुक्त पाठ्य-क्रम, (११) आरोग्य तथा अवरोधन, (१२) भौगोलिक कठिनाइयाँ, (१३) सामाजिक समस्याएँ, (१४) अभिभावकों की आर्थिक स्थिति एवं अनिच्छा, और (१५) भाषा की समस्या।

**अनिवार्यता-प्रसार सम्बन्धी मुद्दाएँ**—ये मुद्दाएँ अवलिनित हैं—(१) अनिवार्य शिक्षा की निश्चित नीति, (२) शिक्षा-प्रशासन में सुधार, (३) शिक्षकों की समस्या, (४) आर्थिक समस्या, (५) विद्यालयों की समस्या, (६) पाठ्य-क्रम की समस्या, (७) वारि-विधि का प्रचलन, (८) कक्षाओं में छात्र-संख्या की वृद्धि, (९) विविष्ट विद्यालयों की स्थापना, और (१०) जनता का सहयोग।

**सहायक पुस्तकों की सूची**

1. Sir Richard Livingstone : *Some Tasks for Education*.
2. A. N. Dasu : *Education in Modern India*.
3. G. K. Gokhale : *Speeches*.





4. J. P. Naik : *History of Local Fund Cess in the Province of Bombay.*
5. D. M. Desai : *Universal Compulsory and Free Primary Education in India.*
6. K. G. Saiyidain : *Compulsory Education in India.*
7. S. N. Mukerji : *Education in India Today and Tomorrow.*
8. Dinker Desai : *Primary Education in India.*
9. *Constitution adopted by the Free India on January, 26, 1950.*
10. *Government Resolution on Educational Policy. 1904.*
11. *The Gazetteer of the Baroda State.*
12. *Progress of Education in India, 1937-47, Vol. I.*
13. *Education in India, 1955-56.*
14. *Adam's Reports*
15. दूसरी पंचवर्षीय योजना (प्रारम्भिक स्तरों में)
16. भारत (वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ), १९६०

### TEST QUESTIONS

1. Give a brief history of compulsory education in India.
2. Discuss the special difficulties that have stood in the way of the adoption of compulsory primary education in India.
3. Outline the history of compulsory primary education in India laying greater emphasis on recent developments in the field.
4. What, in your opinion, are the major problems of compulsory primary education in India? What suggestions can you offer to tackle them?
5. Describe the system of compulsory primary education which has been adopted in your state.
- /6. Discuss the causes of slow progress in the spread of primary education in India. How could these be removed?

## अध्याय २

### अपव्यय एवं अवरोधन ✓

हम गत अध्याय में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का विवरण देते समय अपव्यय (Wastage) एवं अवरोधन (Stagnation) का उल्लेख कर चुके हैं। "प्राथमिक शिक्षा, जैसा कि स्वयं इसके नाम से विदित है, वह आधार है जिस पर शिक्षा की सम्पूर्ण संरचना का निर्माण किया जाता है।" परन्तु भारत में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्याएँ इतनी गंभीर तथा व्यापक सिद्ध हो गई हैं कि वर्तमान और निकट भविष्य में इन समस्याओं को पूर्ण रूपेण व्याख्यात्मक स्वीकार किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में भारत सरकार सक्रिय पग उठा रही है, विद्यालयों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रही है, अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रही है और सामान्य पाठ्यक्रम को बेसिक पाठ्यक्रम में परिवर्तित करके शिक्षा को अधिक उपयोगी बना रही है, परन्तु फिर भी इन समस्याओं की स्थिर प्रकृति के कारण सरकार प्राथमिक शिक्षा के आधार को दृढ़ बनाने में अमिलहित सफलता प्राप्त करने में निराशा का भातिगन कर रही है। इन समस्याओं का रूप क्या है और इनका समाधान किन प्रकार किया जा सकता है, यही प्रस्तुत पाठ को प्रमुख विषय-वस्तु है। अतः हम इनका इस स्थान पर अध्ययन करेंगे।

1. Wastage and Stagnation.
2. "Primary education, as its very name implies, constitutes the foundation on which the entire superstructure of education is built."—*Education in India, 1955-56, p. 47.*



## अपव्यय

प्राथमिक शिक्षा के इतिहास में अपव्यय एक प्राचीन समस्या है, यद्यपि यह समस्या जन-शिक्षा के प्रकार में अति दीर्घ काल में घेरा जाने हुए थी, तथापि भारतीय शिक्षा के विकास की ठेकेदारी का दावा रखन वाली विदेशी सरकार हमसे मिल होकर भी अनभिज्ञ बनी रही। १९२६ में हार्टोग समिति (Hartog Committee) ने शिक्षा के विभिन्न चरणों की तुलना का मे औष करके सरकार का ध्यान अपव्यय एवं अवरोधन की घोर घातविन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा : “अपव्यय से होने वाली हानियाँ कुछ छात्रों के अतिरिक्त प्रायः सभी की साक्षरता के मार्ग में बाधक है।”<sup>१</sup> हम नीचे की पंक्तियों में अपव्यय के अर्थ तथा परिभाषा और उसमें सम्मिलित अन्य बातों का उल्लेख कर रहे हैं।

### अपव्यय का अर्थ एवं परिभाषा

‘अपव्यय’ शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है। शिक्षा में ‘अपव्यय’ शब्द का सम्बन्ध अर्थ है उन छात्रों पर समय, धन और शक्ति का अपव्यय जो सफलता पूर्वक अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं करते हैं। जो बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, उससे यह धागा की जानी है कि वह पाँच वर्ष में अपनी प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर लेगा और धन में बचा ५ में उत्तीर्ण हो जायगा।<sup>२</sup> इस प्रकार के छात्र के सम्बन्ध में समय, धन और शक्ति का किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होता है। परन्तु व्यावहारिक रूप में हमें ऐसे अनेकों छात्र मिलते हैं जो अति उत्साह से प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, किन्तु वे कुछ ही समय के उपरान्त और कभी-कभी तो ३ या ४ वर्ष के पश्चात् विद्यालय से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर देते हैं। इस प्रकार के छात्र प्राथमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम को समाप्त नहीं करते हैं। अतः इन छात्रों पर समय, धन और शक्ति का अपव्यय होता है। इस प्रकार ‘अपव्यय’ से हमारा अभिप्राय है उन विद्यार्थियों पर व्यय किया हुआ समय, धन और शक्ति जो किसी न किसी कारणवश प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने से पूर्व ही अपना अध्ययन

1. “The losses due to wastage prevent all but few pupils from becoming literate.”—*Report of the Hartog Committee*, p. 49.
2. भारत के अधिकतर राज्यों में प्राथमिक शिक्षा की अवधि ५ वर्ष की है, परन्तु बम्बई, मध्यप्रदेश, विजयप्रदेश आदि में ४ वर्ष और छात्ताम में ३ वर्ष है।  
—*Education in India*, 1955-56, p. 54.

स्थगित कर देते हैं। 'अपव्यय' के अर्थ को हर्टग समिति की रिपोर्ट में इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है : "अपव्यय में हमारा अभिप्राय है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बच्चों को विद्यालय की किसी भी कक्षा से हटा लेना।"<sup>१</sup> इसे अपव्यय इसलिये कहा गया है क्योंकि जो शिक्षा इस प्रकार के छात्र प्राप्त करते हैं, वह उनको स्थायी रूप से साक्षर बनाने में असफल होती है। इसकी पुष्टि में हम हर्टग समिति के इन शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं : "जब तक प्राथमिक शिक्षा कम से कम साक्षरता न प्रदान कर दे, वह व्यर्थ है। सामान्यतः कोई भी बच्चा जिसने कम से कम चार वर्ष का प्राथमिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम पूर्ण नहीं किया है, स्थायी रूप से साक्षरता नहीं प्राप्त कर सकता है।"<sup>२</sup>

### • प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय

यद्यपि प्रगति के इस युग में भारतवासी प्राथमिक शिक्षा के द्वारा देशव्यापी साक्षरता के महत्त्व को पूर्णतः हृदयंगम कर चुके हैं, तथापि अब भी प्राथमिक शिक्षा में अत्यधिक अपव्यय है। आज भी कितने ही अभिभावक ऐसे हैं जो कठिन परिस्थितियों के शिकंजे में पड़े होने के कारण अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम पूर्ण करने से पूर्व ही विद्यालयों से पृथक् कर देते हैं। १९५२-५३ में कक्षा १ में शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रत्येक १०० छात्रों में से १९५३-५४ में कक्षा २ में ६४, १९५४-५५ में कक्षा ३ में ५१ और १९५५-५६ में कक्षा ४ में ४३ छात्र थे।<sup>३</sup> इन आँकड़ों से सिद्ध हो जाता है कि हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा में अति महान् अपव्यय है। इसके साथ ही ५७ प्रतिशत बच्चे जो पूर्ण प्राथमिक शिक्षा के लाभ से वंचित रह गये, वे जैसा कि उपरिर्कथित हर्टग समिति का मत है, साक्षर न हो सके। इन विद्यार्थियों की शिक्षा पर व्यय किया गया समय, धन और शक्ति व्यर्थ ही गये। वास्तविकता यह है कि प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले धन का आधे

1. "By 'wastage' we mean the premature withdrawal of children from school at any stage before completion of the primary course."—*Report of the Hartog Committee* p. 47.
2. "Primary education is ineffective, unless it at least produces literacy. On the average, no child who has not completed a primary course of at least four years will become permanently literate."—*Ibid*, p. 48.
3. *Education in India*, 1955-56, p. 64.

से अधिक भाग इन छात्रों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करने में व्यर्थ ही नष्ट हो गया। यह अप्रव्यय करोड़ों रुपये का था, जिसका अनुमान सहज ही इस बात से लगाया जा सकता है कि १९५५-५६ में प्राथमिक विद्यालयों के सम्पूर्ण छात्रों की संख्या २,४५,११,३३१ थी<sup>१</sup> और प्रत्येक छात्र पर औसत रूप से २३.४ रुपये व्यय किये गये।<sup>२</sup> इस महान् अप्रव्यय को रोककर ही सार्वजनिक शिक्षा द्वारा साक्षर भारत की कल्पना की जा सकती है।

### अप्रव्यय के कारण

अप्रव्यय के कतिपय प्रमुख कारण हैं, जिन पर हम नीचे प्रकाश डाल रहे हैं :

#### १. दोष-पूर्ण शिक्षा-प्रशासन

प्राथमिक शिक्षा का दोष-पूर्ण प्रशासन अप्रव्यय के लिये बहुत-कुछ उत्तरदायी है। यदि प्रशासक इस बात पर बल देने लगे कि कोई भी छात्र प्राथमिक शिक्षा का पाठ्य-क्रम समाप्त करने से पूर्व विद्यालय से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकता है, तो अप्रव्यय पर पर्याप्त अंकुश लगाया जा सकता है। परन्तु हमारे शिक्षा-प्रशासक अपने इस कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं। बालकों पर विद्यालय से प्रेषण न होने का प्रतिवन्ध लगाने के लिये उन्हें अभिभावकों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ेगा और सम्भवतः अपनी सेवा की वर्तमान दशाभो में शिक्षा-प्रशासक तथा निरीक्षक इस दिशा में क्रियाशील होने के लिये अपने को असमर्थ पाते हैं।

प्राथमिक शिक्षा-प्रशासन का एक अन्य प्रमुख दोष यह है कि छात्रों के विद्यालय प्रवेश की योग्यता, आयु तथा वर्ष में उपस्थिति के दिवसों के सम्बन्ध में निश्चित नियम नहीं है। फलस्वरूप पर्याप्त योग्यता वाले विद्यार्थी उच्च कक्षा में प्रवेश ले लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे वार्षिक परीक्षा में असफल होने के उपरान्त या उससे पूर्व ही अपना अध्ययन स्थगित कर देते हैं। विद्यालय प्रवेश की आयु निर्धारित न होने के कारण कोई भी बालक कि भी आयु में किसी भी कक्षा में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों में आयु की पर्याप्त समानता दृष्टिपोषक होती है। छोटे तथा बड़े बच्चे के बच्चों पर इसका घनिष्ठ प्रभाव पड़ता है। दोनों प्रकार के बच्चे कक्षा के वातावरण को अपने अनुकूल नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप उन

1. *Education in India*, 1953-56, p. 63.  
2. *Ibid*, p. 79.

कतिपय छात्र शिक्षा की ओर से अपना मुँह मोड़ लेते हैं। वर्ष में उपस्थिति के दिवसों की निश्चित संख्या न होने के कारण बालक स्वेच्छा से विद्योपार्जन के लिये जाते हैं। प्रायः उन्हें धमिमावकों द्वारा किसी कार्य के हेतु घर पर रोक लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में छात्रों की अनियमित उपस्थिति विशेषतः घबलोक्ति की जाती है क्योंकि ग्रामीण कृषक वृद्धि-कार्य की अधिकता के समय अपने बच्चों को स्वयं ही विद्यालय जाने से रोक लेते हैं। इस यदा-कदा कक्षा-उपस्थिति से बालक न तो सफलता पूर्वक ज्ञान का भर्जन ही कर पाते हैं और न उनकी शिक्षा में रुचि ही उत्पन्न हो पाती है। फलतः उनका मन शिक्षा से दूर होने लगता है और उनकी शिक्षा का कार्यक्रम भागे नहीं बढ़ पाता है।

प्राथमिक शिक्षा-प्रशासन का एक प्रमुख दोष यह है कि विद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में शिक्षा-निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है। परिणामस्वरूप एक विद्यालय-निरीक्षक के अधीन इतने विद्यालय हैं कि वह उनका कुशल तथा उपयुक्त निरीक्षण नहीं कर पाता है। यदि कोई कर्तव्यनिष्ठ शिक्षा-निरीक्षक ऐसा करने का संकल्प भी करता है, तो यातायात, परिवहन तथा निर्दिष्ट स्थान पर रात्रि-विश्राम की उचित व्यवस्था के अभाव में उसे अपने संकल्प को छोड़ देना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में न तो शिक्षा-निरीक्षक अव्यय के कारणों का ही अध्ययन कर पाते हैं और न उनको दूर करने के उपाय ही सोच सकते हैं।

## २. दोषपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था

प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतया दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता है। ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अति नगण्य है, जो बालक के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास करने का दावा कर सकें। अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का स्तर निम्न है, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है, शिक्षा-उत्तरण की अनुपस्थिति एक विशेषता है और स्वस्थ वातावरण में निमित्त विद्यालय भवन की कमी है। शिक्षा-व्यवस्था की ऐसी दशा में न तो छात्र ही विद्यालय का संकल्प ले पाते हैं और न शिक्षक ही पूर्ण उत्साह से निपुण अध्यापन के कार्य का बीड़ा उठा पाते हैं। फलस्वरूप दोनों ही शिक्षा प्राप्त करने तथा शिक्षा प्रदान करने के कार्य के बोझ से लदे हुए व्योन्वों करके अपने दिन काटते हैं। जब शिक्षा की ऐसी व्यवस्था है, तब उसमें सजीवता तथा भावपूर्ण की भाषा करना व्यर्थ है और फलस्वरूप यह कल्पना करना भी पड़ता है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्र अपने पाठ्य-क्रम को समाप्त करके ही विद्यालय से विदा लेंगे।

निशा की इन व्यवस्थाओं के कारण जो घणघन हो रहा है, उसे मारन-मारमार में स्वयं स्वीकार करते हुए निशा है : "विद्यालयों के धूलूँ निशा-उत्तरण, सर्वोपनीय भवन और मीरन तथा उगाह-हीन वातावरण दुर्भाग्य ने छात्रों को घणघन करते रहने के लिये प्रभावपूर्ण प्रेरणा न प्रदान कर सके।"<sup>१</sup>

## ३. दोष-पूर्ण पाठ्यक्रम

प्राथमिक निशा में घणघन का एक अन्य कारण दोष पूर्ण पाठ्य क्रम है। पाठ्य क्रम एक-मार्गीय तथा बडोर है और उसमें विषयों का माधिव्य है। नगर तथा ग्राम के समस्त बालक-बालिकाओं को एक ही पाठ्य-क्रम का घणघन करना पडता है, चाहे उन्हें उसमें रुचि हो घणघन नहीं। माप ही पाठ्य-क्रम में किसी हस्तकाय को समाविष्ट करके उसे रोचक बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। यद्यपि बेसिक पाठ्य-क्रम के अनुसार इन निशा में सक्रिय पण उठाया जा रहा है, तथापि घण भी ऐसे घनेकों प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें यह योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी है। पाठ्य-क्रम में विषय इतने अधिक हैं कि घण घणु के बालकों के लिये उन सब का घणघन करना सरल तथा सम्भव नहीं होता है। बम्बई राज्य में किये गये एक घणघण से ज्ञात हुआ है कि छात्र गणित, कृषि तथा सामान्य विज्ञान में रुचि न लेने के कारण साधारणतः इन विषयों में निर्बल होते हैं।<sup>२</sup> इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि छात्र परीक्षा में घणुत्तीर्ण हो जाते हैं और उनमें से घनेको विद्या-देवी की घाराघना करना समाप्त कर देते हैं।

## ४. अभिभावकों की अधिक्षा

बम्बई राज्य में किये गये एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि पिछड़ी हुई जातियों के बच्चों में अधिक घणघन्य है।<sup>३</sup> इसका प्रमुख कारण यह है कि इन बच्चों के अभिभावकों में शिक्षा का घभाव है। स्वयं शिक्षित न होने के कारण ये अपने बच्चों की शिक्षा का भी सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व समझने में विफल रहते हैं। अतः शिक्षा को घणघन समझकर वे यदि अपने बच्चों को शिक्षा उप-

1. "The schools being ill-equipped, poorly housed and with dull and depressing environment unfortunately could not exercise effective counter-acting influence."—*Education in India, 1955-56, p. 64.*
2. *Report on Wastage and Stagnation in Primary Schools, Bombay.*
3. *Ibid.*

लब्ध करने के लिये विद्यालयों में प्रविष्ट भी करा देते हैं, तो भी कुछ समय उपरान्त वे उन्हें वहाँ से हटाकर उनके तथा अपने दृष्टिकोण से हितकर किसी कार्य में लगा देते हैं। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न करने से अप्रत्यक्ष होना स्वाभाविक है। जो बात धन विछड़ी हुई जातियों के अभिभावकों के सम्बन्ध में कही जा सकती है, वही भारत की अधिकांश जनता के विषय में भी सत्य है, क्योंकि आज भी हमारे देश के मस्तक पर निरक्षरता की कसक कालिमा लगी हुई है। इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि अभी तक भारत में लगभग ८५ प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं।<sup>१</sup>

## ५. आर्थिक कारण

आर्थिक कारण भी अप्रत्यक्ष के लिये उत्तरदायी है। नमन सत्य यह है कि प्राथमिक शिक्षा में होने वाले ६० प्रतिशत अप्रत्यक्ष का कारण भारतीय जनता की प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियाँ ही हैं।<sup>२</sup> हमारे देशवासी निर्धनता के कारण ऐसी असहाय दशा में हैं कि यदि उनके बच्चों के लिये शिक्षा निःशुल्क भी कर दी जाय, तो वे उनके लिये कापी-किताबों तथा शिक्षा से अन्य सम्बन्धित व्यय के लिये धन जुटाने में अपने को असमर्थ पाते हैं। फिर उनके समक्ष निरन्तर यह प्रश्न उपस्थित रहता है कि बालकों को विद्याध्ययन के लिये भेजा जाय अथवा उन्हें आर्थिक विचार बिन्दु से लाभप्रद किसी कार्य में संलग्न कर दिया जाय। जैसा कि स्वाभाविक है वे द्वितीय विचार का ही निर्वाचन करते हैं क्योंकि इससे न केवल बच्चों की अपितु परिवार के सदस्यों की सुधा शान्त करने में योग प्राप्त होता है। बालक भी इस बात को समझते हैं और उपयुक्त कार्य मिलने पर शिक्षा को तिलांजलि दे देते हैं। जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न है, उनको अधिक से अधिक अ, ब, स का ज्ञान कराने के उपरान्त विद्यालयों से पूछकू कर लिया जाता है। ऐसा किये जाने के समय अभिभावक उचित विचार नहीं करते हैं कि बालिकाओं को शिक्षित करने से परिवार का कोई आर्थिक हित नहीं होगा। इसके लिये अभिभावकों पर दोषारोपण करना व्यर्थ है, क्योंकि जिस सामाजिक वातावरण में वे पले और बड़े हुए हैं, उसमें उन्होंने ऐसा ही देखा और सुना है।

१. भारत, १९६०, पृ० ७७

२. K. G. Salyidain : *Compulsory Education in India*, p. 56.

## ६. सामाजिक कारण

रूढ़िवादिता पर आधारित भारतीय समाज अपव्यय में प्रतिशय योग दे रहा है। आज के आधुनिक युग में भी इस देश के प्रत्येक कोने में अनेकों हास्यप्रद सामाजिक कुरीतियों का बोल-बाला है। अल्प-आयु के बालकों तथा बालिकाओं की सह-शिक्षा को संशंकित दृष्टि से देखा जाता है। फलस्वरूप यदि एक स्थान पर बालिकाओं की शिक्षा के लिये पुण्य व्यवस्था नहीं है, तो उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है और यदि सीमाय से वे किसी विद्यालय में प्रवेश पा चुकी हैं, तो थोड़ी सी आयु अधिक हो जाने पर ही उन्हें सरस्वती की भाराघना समाप्त करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। फिर बाल-विवाह की एक ऐसी दूषित प्रथा है जो अनेकों बालिकाओं को ही नहीं, अपितु कुछ बालकों को भी प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व ही उसकी ओर से मुख मोड़ लेने के लिये अधिकार पूर्ण धादेन देती है। इन कारणों के फल-स्वरूप जो अपव्यय होता है वह उच्चवर्ग के हिन्दुओं में तो कम है, पर मध्य तथा निम्न श्रेणी के हिन्दुओं और साधारण मुसलमानों में प्रति-शोचनीय है।<sup>१</sup>

## अपव्यय-निवारण के उपाय

- \* प्राथमिक शिक्षा में होने वाले अपव्यय का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर हम अधोलिखित धक्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं :

### १. शिक्षा-प्रशासन में सुधार

प्राथमिक शिक्षा के दोष-पूर्ण प्रशासन के कारण जो अपव्यय हो रहा है, उसका एकमात्र उपाय यही है कि प्रशासन की निर्बलताओं तथा त्रुटियों का उन्मूलन किया जाय। यह तभी सम्भव हो सकता है जब सरकार और स्थानीय संस्थाएँ इस ओर अपना ध्यान दें और शिक्षा-प्रशासन की एक निश्चित नीति का निर्धारण करें। इसके अन्तर्गत छात्रों के विद्यालय-प्रवेश की योग्यता, आयु तथा वर्ष में उपस्थिति के दिवसों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाय। जब तक उचित योग्यता के छात्र बच्चाओं में प्रविष्ट नहीं होंगे, प्रत्येक बच्चा में प्रवेश आयु निश्चित नहीं की जायगी और उपस्थिति के दिवस स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किये जायेंगे, तब तक इन कारणों के फलस्वरूप होने वाले अपव्यय की रोकना सम्भव नहीं होगा। धार्यव्ययता इस बात की भी है कि

1. Report on Wastage and Stagnation in Primary Schools, Bombay.

शिक्षा-निरीक्षकों की संख्या में उचित वृद्धि की जाय, उनको निरीक्षण की सुविधायें प्रदान की जायें और उनके निरीक्षण को कठोर, कुशल तथा फलोत्पादक बनाया जाय ।

## २. शिक्षा-व्यवस्था में सुधार

अपभ्रम का निराकरण करने के हेतु शिक्षा-व्यवस्था में त्वरित सुधार किया जाना अनिवार्य है । प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा-स्तर को ऊँचा उठाया जाय, अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाय, शिक्षा-उपकरणों में वृद्धि की जाय, स्वस्थ पर्यावरण में विद्यालय-भवनों का निर्माण किया जाय, विद्यालयों के वातावरण को आकर्षक बनाया जाय और छात्रों के मनोरंजन तथा खेल-कूद की उचित व्यवस्था की जाय । जब तक विद्यालयों को इस प्रकार से संगठित नहीं जायगा, तब तक वे शिक्षा के वास्तविक केन्द्र न बन सकेंगे और परिणामतः वे शिक्षा-प्रसार का कार्य सफलता पूर्वक न कर सकेंगे ।

प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का एक प्रमुख दोष यह है कि भारत में ऐसे अनेक प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें समस्त कक्षाओं के छात्रों को शिक्षा देने के लिये केवल एक अध्यापक है । १९५५-५६ में इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या १,११,२२० और उनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या ३९,१९,७१२ थी ।<sup>१</sup> इस सम्बन्ध में मत विभिन्नता नहीं हो सकती है कि एक अध्यापक विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का कुशलता पूर्वक अध्यापन नहीं कर सकता है । फिर सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे कभी न कभी किसी कार्य वश विद्यालय से अवन्यास लेना आवश्यक हो जाता है अथवा अन्य मनुष्यों के सहण वह किसी रोग से पीड़ित हो सकता है । तनिक अपने मानस-पटल पर उस दिवस या उन दिवसों का चित्र अंकित कीजिये, जब छात्र तो विद्यालय में उपस्थित है परन्तु अध्यापक अदृश्य है । वर्ष में ऐसे अनेक अवसर हो सकते हैं । ऐसी परिस्थिति में छात्र एवं अभिभावक दोनों विद्यालय-भाग्यमन निष्प्रयोजन समझने लगते हैं । फलस्वरूप अपभ्रम से बचने का कोई उपाय नहीं रह जाता है । स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है : "एक अध्यापक वाले प्राथमिक विद्यालयों ने इस अपभ्रम में अद्भुतपूर्व योग दिया है ।"<sup>२</sup> यह जानते हुए भी भार्गव इस बात का है कि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जा रही है । १९५५-५६ में एक अध्यापक वाले प्राथमिक

1. *Education in India*, 1955-56, p. 66.

2. "Single-teacher primary schools contributed a good deal to this wastage." *Education in India*, 1955-56, p. 64.



विद्यालयों की संख्या गम्भीर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या की १६.६ प्रतिशत थी, जब कि यह संख्या १९५४-५५ में १८.४ थी।<sup>१</sup> यदि यह तर्क उपस्थित किया जाय कि सरकार विद्यार्थी के घमाव के कारण इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना कर रही है, तो इसके विपक्ष में यह बलपूर्वक कहा जा सकता है कि जिस धन का अपभ्यस्य इन विद्यालयों के कारण हो रहा है, उस धन के कुछ भाग को अधिक वेतन देकर व्यक्तियों को अभ्यापन कार्य के प्रति आकर्षित किया जा सकता है और शेष धन से उनको प्रशिक्षित किया जा सकता है।

### ३. पाठ्य-क्रम में सुधार

अपभ्यस्य का उन्मूलन करने के लिये पाठ्य-क्रम में सुधार किया जाना आवश्यक है। किसी भी पाठ्य क्रम को एक अनिश्चित काल के लिये निश्चित नहीं माना जा सकता है। इसमें अनुभव तथा परीक्षण के माध्यम पर परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। अतः प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थानीय वातावरण तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर परिवर्तन किया जाय, नगर तथा ग्राम के छात्रों के लिये पृथक् पाठ्य-क्रम तैयार किये जायें और बालकों एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं तथा रुचियों पर ध्यान केन्द्रित करके विषयों का निर्धारण किया जाय। सर्वोपरि प्रयास इस बात का किया जाना चाहिये कि पाठ्य क्रम रोचक, सरल एवं व्यावहारिक हो और उसमें स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला कला-कौशल का कोई ऐसा हस्तकार्य अवश्य हो जो बालक की निर्माणकारी एवं सामप्रद कार्य करने की आन्तरिक मनोभावना को संतुष्ट कर सके।

### ४. अभिभावकों की शिक्षा

अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के महत्त्व को तभी हृदयंगम कर सकेंगे और तभी वे उनको कम से कम प्राथमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम को पूर्ण करने की अनुमति प्रदान करेंगे, जब वे स्वयं शिक्षित होंगे। शिक्षित अभिभावकों को शिक्षित करने के लिये रात्रि-पाठशालाओं, वयस्क विद्यालयों और अंशकालिक शिक्षालयों (Part-time schools) की स्थापना की जानी चाहिये। हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। १९५५-५६ में ४,६१,२१४ पुरुषों और ५३,९८७ स्त्रियों को साक्षर बनाया गया और

उनकी शिक्षा पर १६,८६,५६२ रुपया व्यय किया गया।<sup>१</sup> द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को अधिक प्रोत्साहन देने के लिये १५ करोड़ रुपया व्यय किया जा रहा है।<sup>२</sup>

## ५. आर्थिक कठिनाइयों का निवारण

अभिभावकों की आर्थिक कठिनाइयों का निवारण अति आवश्यक है क्योंकि इनके कारण प्राथमिक शिक्षा में अत्यधिक अपभ्यय हो रहा है। भारत-सरकार इस दिशा में प्राण-प्रण से चेष्टा कर रही है। देश का औद्योगीकरण किया जा रहा है और अन्न तथा कृषि सम्बन्धी अन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। आशा है कि देश के आर्थिक विकास का जो अनवरत प्रयास किया जा रहा है उसके परिणामस्वरूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति की आय में लगभग १८ प्रतिशत की वृद्धि होगी, और १९५५-५६ की २८१ रुपये की आय से बढ़ कर १९६०-६१ में ३३१ रुपये की हो जायगी।<sup>३</sup> निस्सन्देह आय की इस वृद्धि से जनता की आर्थिक कठिनाइयों का बहुत कुछ निवारण हो सकता है, परन्तु विचारणीय बात यह है कि क्या यह वृद्धि जीवन की आवश्यक वस्तुओं के द्रुत गति से बढ़ते हुए मूल्यों के अनुपात में पर्याप्त होगी? अनेकों वस्तुओं के मूल्यों में १८ प्रतिशत से कहीं अधिक वृद्धि हो चुकी है। गत कुछ वर्षों का अनुभव बताता है कि मध्य तथा निम्न वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति पूर्व की अपेक्षा अधिक शोचनीय हो गई है। क्या इस परिस्थिति के फलस्वरूप सामान्य जनता की आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति की आशा की जा सकती है? यदि नहीं, तो प्राथमिक शिक्षा में इस कारण जो ६० प्रतिशत व्यय हो रहा है उसके समाप्त होने को आशा करना केवल काल्पनिक तथा निराधार है। आर्थिक संकटों के दुर्मेघ घेरे को केवल सरकार की सशक्त भुजाएँ ही भेद सकती हैं और इस दिशा में प्रथम पग होना निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों पर अंकुश लगाना। यदि सरकार यह नहीं करती है तो राष्ट्रीय उन्नति तथा अर्थ-विकास की योजनाओं के वावजूद भी जनसाधारण की आर्थिक समस्या का हल न हो सकेगा और शिक्षा में होने वाला अपभ्यय अपने अघातक रूप में विराजमान रहेगा।

## ६. सामाजिक समस्याओं का समाधान

जिस प्रकार आर्थिक कठिनाइयों ने अपभ्यय के सम्मूहन में अतिरोध

1. *Education in India*, 1955-56, p. 286.

2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ ४८२

3. वही, पृष्ठ ७०

प्राथमिक कर रहा है, जहाँ प्रसार हमारे समाज की दुर्बलता देश की दुर्बलता बन कर शिक्षा-प्रसार के मार्ग को घबराने लगे हुए है। "देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना जिसमें बालक मजदूरी बरतने में योगदान करने वाला एक कारक है।" इस संरचना में केवल बालक की मजदूरी बरतने में रोक कर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिवासिता पर आधारित हमारे समाज में गृह-शिक्षा की निरोधी प्रवृत्ति, बाल-शिक्षा तथा मानविक संशोधन की जड़ें इसकी मजदूरी पट्टी पर ही हैं कि उनको मजबूत करके शिक्षा में होने वाले घाव-भय को रोकना निश्चित अर्थ में सम्भव नहीं जान पड़ता है। समाज में व्याप्त शिक्षा निरोधी इन समस्याओं के निराकरण के लिये दो ही मार्ग हो सकते हैं। या तो समाज में जाति करके उसे पूर्ण रूप से हटा दिया जाय या समाज के इन दोषों का धीरे-धीरे संशुद्धिकरण किया जाय। द्वितीय मार्ग ही अधिक व्यावहारिक प्रतीत होता है पर इसका प्राथमिक देश के युवक-युवतियों पर है। यदि वे कमर बंध कर इन समस्याओं से सोंहा लें, तो वे जनता में नवीन चेतना धीरे-धीरे नवीन युग का सूत्रपात कर सकते हैं। उनके इसी कार्य पर उपर्युक्त सामाजिक दुर्गुणों के फलस्वरूप होने वाले घाव-भय की इतिथी हो सकती है।

हमें ध्याना है कि उपरोक्त सुझावों का कार्यान्वित करने से घाव-भय की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जायगी।

## अवरोधन

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही प्रतिक्रिया करने वाली अवरोधन नामक संज्ञात्मक व्याप्ति के प्रति भारतीय सरकार का ध्यान आकषिप्त करने का प्रयत्न हर्षा-समिति को प्राप्त है। प्राथमिक शिक्षा की तत्कालीन परिस्थिति का सूक्ष्म परीक्षण करने के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि प्राथमिक शिक्षा-क्षेत्र में कक्षा १ के परीक्षा प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में ग्लान्ति होती जाती जाती है और कक्षा ५ में पहुँचते-पहुँचते छात्र-संख्या सब से अधिक कम हो जाती है। इस सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है : "छात्र संख्या में यह ह्रास मुख्यतः दो कारणों के फलस्वरूप होता है, जिनमें हम 'घाव-भय' तथा 'अवरोधन की संज्ञा देंगे। उपलब्ध आँकड़ों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक कक्षा से दूसरी में छात्र-संख्या में

1. "The socio-economic structure in the country in which child labour had a place was another contributory factor." *Education in India, 1955-56, p. 64.*

होने वाला यह भविष्य ह्रास कितना 'अपव्यय' के कारण होता है और कितना 'अवरोधन' के कारण, पर हमारे भव्यपणों से व्यक्त होता है कि 'अपव्यय' की अपेक्षा 'अवरोधन' कम शक्तिशाली कारण है।<sup>१</sup> इस स्थान पर 'अवरोधन' के अर्थ एवं परिभाषा और प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन पर सूक्ष्म दृष्टिपात कर लेना युक्तिमुक्त प्रतीत होता है।

## अवरोधन का अर्थ एवं परिभाषा

अवरोधन का अर्थ स्पष्ट करते हुए हार्टग समिति ने लिखा है : "अवरोधन से हमारा अभिप्राय है एक बच्चे का एक निम्न कक्षा में एक वर्ष से अधिक रोका जाना।"<sup>२</sup> इस रोके जाने का प्रमुख कारण परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना है। यदि एक बालक एक या अधिक कक्षाओं में एक या एक से अधिक बार परीक्षा में असफल होता है, तो वह पाँच वर्ष में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समाप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार जो छात्र चार प्रथम पाँच वर्ष की निर्दिष्ट अवधि में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उन पर भी किसी बंध तक समय, धन और शक्ति का अपव्यय होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि 'अवरोधन' में आंशिक अपव्यय सदैव निहित रहता है।

## प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन

हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा में 'अवरोधन' की समस्या का उतना ही विकराल रूप है, जितना कि 'अपव्यय' की समस्या का। हम अपने इस कथन की पुष्टि १९२७-२८ से १९४४-४५ तक के परीक्षा फलों के आंकड़े देकर कर रहे हैं :—

1. "The diminution is mainly due to two causes, which we shall term, 'wastage' and 'stagnation'. The figures taken by themselves do not indicate how far the excessive diminution in numbers from class to class is due to 'wastage' and how far is due to 'stagnation', but our enquiries show that by far the more important factor is 'wastage'. *Report of the Hartog Committee, p. 47.*
2. "By stagnation we mean the retention in a lower class of a child for a period of more than one year." *Ibid.*

## प्रचरोधन के कारण

जिन बारणों के फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा में प्रचरोधन की समस्या स्थित हो रही है, उन्हें हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं :—

### १. बाल-विवाह

भारतीय समाज में आज भी बाल-विवाह का पर्याप्त प्रचलन परिणामतः जिन बालकों का दस-बारह वर्ष की आयु में विवाह हो जात अपने पाठों की प्रेरणा अपनी नवीन जीवन-संगिनी की ओर अधिक हो होने लगते हैं। वे अपने परिवार में अपने से बड़े विवाहित व्यक्तियों का स्पर्शिक व्यवहार तथा सम्बन्ध देखते हैं और मानव-स्वभाव के अनुसार अनुकरण करने लगते हैं। फलतः शिक्षा में उनका रुचि दिन प्रतिदिन न्यून होती है और वे एक वर्ष में एक कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं।

### २. द्रुषित वातावरण

साधारणतः छात्रों को विद्यालयों और उनसे बाहर द्रुषित वाता अपना समय व्यतीत करना पड़ता है। किसी भी कक्षा में ऐसे बाल प्रभाव नहीं होता है, जिनकी घावों, व्यवहार, बात-चीत का ढङ्ग भी रुचियाँ निम्ननीय न हों। इस प्रकार के विद्यार्थी प्रति वर्ष कक्षा में होने का कभी विचार ही नहीं करते हैं और अन्य छात्र भी उनके साथ घाबरकर विद्याभ्ययन से जो पुराने लगते हैं। फलस्वरूप वे भी एक कक्षा वर्ष से अधिक लगाने लगते हैं।

विद्यालयों से बाहर का वातावरण—विशेष रूप से नगरों में—प्रति हो गया है। अनिश्चरक यन्त्रों पर मुनाये जाने वाले प्रसूत गीत, फल उत्तंजक विज्ञापन, चित्राकर्षक पत्र, खेल-तमाषे तथा सिनेमापर विद्यार्थी के अध्ययन में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस विद्यावरण के फलस्वरूप बालापीठों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है स्थिति में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों में प्रचरोधन की समस्या का में और अधिक विकराल रूप धारण कर लेना कोई आश्चर्य न होगी।

कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के भी होते हैं जिनमें विद्या-देवी के

नहीं हो पाता है। यदि वे किसी निर्धन ग्रामीण परिवार के सदस्य हैं, पारिवारिक व्यय की पूर्ति करने में योग्य प्रदान करने के लिये प्रायः संकाय कोई कार्य करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में उनको अपने घर करने का अवसर नहीं मिल पाता है, और उन्हें एक कक्षा में एक अधिक व्यतीत करना पड़ता है।

### बच्चों की शारीरिक दुर्बलता

तथ्य प्रकाशित है कि गलत कुछ वर्षों से छात्रों की शारीरिक दुर्बलता है। विद्युत् संचयन-पदार्थों के विलोप, पोष्टिक भोजन के अभाव और प्रकोप ने भारतीयों और उनके बच्चों की जान निचोड़ ली है। "भारत संघों की निरन्तर अस्वस्थता के कारण देश की शक्ति क्षीण हो रही है। तक बच्चों का सम्बन्ध है उनमें से एक चौथाई एक वर्ष की आयु में से पूर्व और प्रति दस बच्चों में से चार बच्चे पाँच वर्ष के होने से के दास में पहुँच जाते हैं। जन्म लेने वाले बच्चों में से आधे कभी वर्ष की आयु को नहीं प्राप्त कर पाते हैं।" ऐसी दशा में हमारे शारीरिक दुर्बलता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। अस्वस्थ रहने के कारण वे अनवरत रूप से अध्ययन नहीं कर पाते। अतः प्रायः एक वर्ष का पाठ्यक्रम दो या अधिक वर्षों में समाप्त

### विषयों की अधिकता एवं अरोचकता

मेक विद्यालयों के छात्रों को पाँच और वैज्ञानिक विद्यालयों के छात्रों को अधिक विषयों का अध्ययन करना पड़ता है। इनमें से कुछ हैं, जिनमें विद्यार्थी सामान्यतः रुचि नहीं लेते हैं, उदाहरणार्थ—  
पि, विज्ञान, भूगोल तथा इतिहास। पाठ्य-विषयों की अधिकता का परिणाम यह होता है कि अधिकांश विद्यार्थी कुछ विषयों रह जाने के कारण ऊँची कक्षा में नहीं पहुँच पाते हैं।

lia's strength is sapped by the constant ill-health of people..... One quarter of all babies die before are one year old, and four out of every ten die before are five. Half the babies born never reach the age n."—James Hemming : *Mankind against the Killers*.

## ५. प्रभावहीन शिक्षण-पद्धति

अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण-पद्धति प्राचीन तथा मनोबैज्ञानिक होने के कारण छात्रों पर इच्छित प्रभाव नहीं डाल पाती है। शिक्षण-पद्धति की त्रुटि के लिये अयोग्य एवं अप्रशिक्षित अध्यापक, उचित शिक्षण-सामग्री का अभाव, स्थान की कमी, कक्षाओं में छात्रों की अधिकता, जिसके फलस्वरूप पिछड़े हुए छात्रों की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की असम्भावना और विशेष शिक्षा योग्य छात्रों की शिक्षा के प्रबन्ध की अविद्यमानता उत्तरदायी हैं। शिक्षण-पद्धति में समाविष्ट इन त्रुटियों के कारण उसका प्रभावहीन होना अनिवार्य है और फलस्वरूप छात्रों का उचित शिक्षा-स्तर तक पहुँचना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कुछ छात्रों का अपनी कक्षा में स्थिर हो जाना स्वाभाविक है।

अनेकों प्राथमिक विद्यालयों में एक ही शिक्षक है और सभी विद्यार्थियों को सभी विषयों की शिक्षा उसी के द्वारा दी जाती है। ऐसी दशा में शिक्षण उचित प्रकार से नहीं हो पाता है और शिक्षा का स्तर भी निम्न हो जाता है। यह कारण भी अवरोधन में योग्य प्रदान करता है।

## ६. विद्यालय-प्रवेश की अनियमिता

बालकों के विद्यालय प्रवेश के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है। वे किसी भी आयु में किसी भी कक्षा में वर्ष में किसी भी समय विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। ऐसी दशा में वे बालक जो एक कक्षा में देर में प्रविष्ट होते हैं अपना पाठ्य-क्रम पूर्ण नहीं कर पाते हैं और फलतः वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार वे छात्र जो अल्प आयु में उच्च कक्षा में प्रवेश ले लेते हैं, निर्धारित विषयों को समझने में असमर्थ रहते हैं और उन्हें आगामी वर्ष भी उसी कक्षा में अग्रणी करना पड़ता है।

## ७. दोष-पूर्ण परीक्षा-प्रणाली

अवरोधन का एक प्रमुख कारण दोष-पूर्ण परीक्षा-प्रणाली है। जो माँकड़े हमने ऊपर दिये हैं उनसे सिद्ध हो जाता है कि लगभग ५० प्रतिशत छात्र परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहते हैं। इसके लिये दोषारोपण परीक्षा-प्रणाली पर किया जाता है, न कि विद्यार्थियों पर। विद्यार्थी एक वर्ष तक कक्षा में जो कार्य करते हैं उस पर किसी प्रकार का भी विचार उनको उन्नति देने के समय नहीं किया जाता है, अपितु वार्षिक परीक्षा के आधार पर, जो मुख्य रूप से छात्रों की स्मरण शक्ति उनकी रटने की शक्ति की कसौटी होती है, उनकी कक्षा-उन्नति का निर्णय किया जाता है।





### ३. छात्रों की स्वास्थ्य-उन्नति

छात्रों के स्वास्थ्य की उन्नति की ओर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना है। आज के बालक भविष्य के नागरिक हैं। आज जब कि संसार तृतीय विश्व-युद्ध के काले बादलों से घाँट्टादित हो रहा है, देश की सुरक्षा के लिये बलिष्ठ संनिकों की आवश्यकता है। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब बालकों के स्वास्थ्य के प्रति उनके बाल्यकाल से ही ध्यान दिया जाय। अतः सरकार पर यह दायित्व है कि वह उनके लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था करे। आज के सभी प्रगतिशील देशों ने छात्रों के लिये किसी न किसी रूप में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था कर दी है। यदि भारत की निर्धन जनता के बच्चों के लिये कोई ऐसी योजना क्रियान्वित कर दी जाय, तो उनके स्वास्थ्य की अवश्य उन्नति होगी और इस कारक के फलस्वरूप होने वाला अवरोधन क्षुप्त हो जायगा।

### ४. पाठ्य-क्रम में परिवर्तन

पाठ्य-क्रम में विषयों को कम करना आवश्यक है। साथ ही उनमें ऐसे विषयों को स्थान दिया जाना चाहिये जो रोचक हों। यदि गणित, कृषि, विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा प्रदान ही करनी है, तो उनके शिक्षण के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे वे छात्रों को आकर्षित कर सकें। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को समस्त विषयों का समुचित ज्ञान प्राप्त हो जायगा, और सम्भवतः उन्हें एक कक्षा में एक वर्ष से अधिक समय नहीं व्यतीत करना पड़ेगा।

### ५. नवीन एवं मनोवैज्ञानिक शिक्षण-पद्धति

अवरोधन को समाप्त करने के लिये प्राथमिक विद्यालयों में नवीन एवं मनो-वैज्ञानिक शिक्षण-पद्धति का प्रचलन अनिवार्य है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों, इच्छित शिक्षा-उपकरणों, उत्तम विद्यालय-भवनों आदि की उपस्थिति आवश्यक है। इतने विद्यालय देश में अल्प समय में इन सब की व्यवस्था कर देना सम्भव नहीं प्रतीत होता है। परन्तु यदि सरकार और देश के उदार-हृदय धनी व्यक्ति शिक्षा के कार्य में पूर्ण हृदय से योग दें, तो कुछ ही वर्षों में इस कार्य की सफलता पूर्वक सम्पादित किया जा सकता है।

### ६. विद्यालय-प्रवेश पर प्रतिबन्ध

विद्यालय-प्रवेश की धनियमिता को शिक्षा-प्रदातकों तथा विद्यालय-निरीक्षकों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यदि शिक्षा-विभागाध्यक्ष विद्यालय-प्रवेश सम्बन्धी कुछ उपयुक्त नियम बना दें और प्रदातक तथा निरीक्षक कठोरता पूर्वक उनको क्रियान्वित करें, तो विद्यालय-प्रवेश की धनियमिता के कारण उत्पन्न होने वाले अवरोधन पर अंकुश लगाया जा सकता है।



अपभ्रम निवारण के उपाय—अपभ्रम-निवारण के लिये इन उपायों को अपनाया जा सकता है:—(१) शिक्षा-प्रशासन में सुधार, (२) शिक्षा-व्यवस्था में सुधार, (३) पाठ्य-क्रम में सुधार, (४) अभिभावकों की शिक्षा, (५) धार्मिक कठिनाइयों का निवारण, और (६) सामाजिक समस्याओं का समाधान।

अबरोधन की परिभाषा—अबरोधन से हमारा अभिप्राय है एक बच्चे का एक निम्न कक्षा में एक वर्ष से अधिक रोका जाना।

प्राथमिक शिक्षा में अबरोधन—प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से लगभग ४० प्रतिशत छात्रों को परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं। कक्षा १ में लगभग धाये विद्यार्थी ही परीक्षा में सफल हो पाते हैं।

अबरोधन के कारण—अबरोधन के कारण ये हैं:—(१) बाल-विवाह, (२) दूषित वातावरण, (३) छात्रों की शारीरिक दुर्बलता, (४) पाठ्य-विषयों की अधिकता एवं अरोचकता, (५) प्रभावहीन शिक्षण-पद्धति, (६) विद्यालय-प्रवेश की अनियमितता और (७) दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली।

अबरोधन-निवारण के उपाय—अबरोधन निवारण के उपाय अग्र-उल्लिखित हैं:—(१) बाल-विवाह-नियेष अधिनियम का पालन, (२) वातावरण में परिवर्तन, (३) छात्रों की स्वास्थ्य-उन्नति, (४) पाठ्य-क्रम में परिवर्तन, (५) नवीन एवं मनोवैज्ञानिक शिक्षण-पद्धति, (६) विद्यालय-प्रवेश पर प्रतिबन्ध और (७) परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन।

## सहायक पुस्तकों की सूची

1. *Report of the Hartog Committee.*
2. *Education in India, 1955-56.*
3. *Report on Wastage and Stagnation in Primary Schools, Bombay.*
4. K. G. Salyidain : *Compulsory Education in India.*
5. James Hemming : *Mankind against the Killers.*
6. *Literacy in India.*
7. द्वितीय पंचवर्षीय योजना
8. भारत (वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ), १९६०



अपक्षय निवारण के उपाय—अपक्षय-निवारण के लिये इन उपायों को अपनाया जा सकता है:—(१) शिक्षा-प्रदायन में सुधार, (२) शिक्षा-व्यवस्था में सुधार, (३) पाठ्य-क्रम में सुधार, (४) अभिभावकों की शिक्षा, (५) आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, और (६) सामाजिक समस्याओं का समाधान।

अवरोधन की परिभाषा—अवरोधन से हमारा अभिप्राय है एक बच्चे का एक निम्न कक्षा में एक वर्ष से अधिक रोका जाना।

प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन—प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से लगभग ४० प्रतिशत छात्रों को परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण एक कक्षा में एक से अधिक वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं। कक्षा १ में लगभग धाँपे विद्यार्थी ही परीक्षा में सफल हो पाते हैं।

अवरोधन के कारण—अवरोधन के कारण ये हैं:—(१) बाल-विवाह, (२) दूषित वातावरण, (३) छात्रों की शारीरिक दुर्बलता, (४) पाठ्य-विषयों की अधिकता एवं अरोचकता, (५) प्रभावहीन शिक्षण-पद्धति, (६) विद्यालय-प्रवेश की अनियमिता और (७) दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली।

अवरोधन-निवारण के उपाय—अवरोधन निवारण के उपाय अल्प-उत्ति-  
ष्ठित हैं:—(१) बाल-विवाह-निषेध अधिनियम का पालन, (२) वातावरण में परिवर्तन, (३) छात्रों की स्वास्थ्य-उन्नति, (४) पाठ्य-क्रम में परिवर्तन, (५) नवीन एवं मनोवैज्ञानिक शिक्षण-पद्धति, (६) विद्यालय-प्रवेश पर प्रतिबन्ध और (७) परीक्षा-प्रणाली में परिवर्तन।

## सहायक पुस्तकों की सूची

1. *Report of the Hartog Committee.*
2. *Education in India, 1955-56.*
3. *Report on Wastage and Stagnation in Primary Schools, Bombay.*
4. K. G. Saiyidain : *Compulsory Education in India.*
5. James Hemming : *Mankind against the Killers.*
6. *Literacy in India.*
7. द्वितीय पंचवर्षीय योजना



## अध्याय ३ ५

### स्त्री-शिक्षा

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” कहकर मनुस्मृति के रचयिता मनु ने नारी की श्रद्धार्पणा की है। मनु की इस उक्ति से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय विचारधारा नारी को कितना सम्माननीय एवं महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। परन्तु क्या नारी को वस्तुतः समाज द्वारा इतनी ही पूज्य और इतनी ही सम्मान्य समझ कर प्रारम्भ से लेकर आज तक शिक्षित करने का प्रयास किया गया है? इसका उत्तर खोजने के लिये जब हम प्राचीन काल से लेकर आज तक के समाज में नारी-शिक्षा का व्यवलोकन करते हैं, तब हमारा मस्तक सज्जा से झुक जाता है।

### हिन्दू-युग में स्त्री-शिक्षा

प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा का कितना प्रसार था और उसका संगठन किस प्रकार का था, इन बातों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। निस्संदेह इस युग में मैत्रेयी, गार्गी, विश्ववरा एवं लीलावती के समान उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ थीं, परन्तु इनकी शिक्षा का विचार करके यह कथन तर्क रहित होगा कि उस समय स्त्री-शिक्षा का पर्याप्त प्रचलन था अथवा स्त्री-शिक्षा अपने संगठित रूप में विद्यमान थी। “क्योंकि ये सब महिलाएँ या तो स्वयं शिक्षित विद्वानों की पत्नियाँ अथवा पुत्रियाँ थीं, अतः सम्भवतः उनको अपने शिक्षित पतियों अथवा पितामहों द्वारा शिक्षा दी गई थी और यह सम्भव है कि इस युग में स्त्रियों के लिए शिक्षा की कोई संगठित





उपलब्ध नहीं हैं। तथापि इस युग की हिन्दू महिलाओं में मेवाड़ की मीराबाई, शिवाजी की माता बोजीबाई, इन्दौर की शासिका महिल्याबाई एवं भोली की रानी लक्ष्मीबाई के नाम स्त्री-शिक्षा के जगत में आज भी स्मरणीय हैं।

## आधुनिक युग में स्त्री-शिक्षा

संघर्षों के भागमन के उपरान्त पारचात्य शिक्षा एवं संस्कृति के प्रसार के साथ-साथ नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने प्रारम्भ हुए। जो बन्धन अभी तक कठोर थे, वे शून्यः शून्यः ढीले होने लगे, जो स्वतन्त्रता उससे छीन ली गई थी, वह उसे प्राप्त होने लगी। नारी के सम्बन्ध में लोगों का दृष्टिकोण भी बदला, लोगों की मान्यताएँ भी बदलीं और भोग्या नारी पूज्या बनने लगी। सारांश में, आधुनिक युग में पारचात्य प्रभाववश सभ्यता के नये प्रकाश में नारी जाति ने एक करवट ली, जागरूक पुरुषों ने नारी के वास्तविक महत्व को पहिचाना, नारी भी अपनी गिरी दशा के प्रति सचेष्ट हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक युग नारी जागरण का युग बन गया। के० नटराजन (K. Natrajan) ने लिखा है: "यदि एक व्यक्ति जिसको सौ वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है, आज पुनर्जीवित हो आय, तो सर्व प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो वह देखेगा, स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा।"<sup>1</sup> परन्तु इस क्रान्ति के बावजूद भी धर्माचारी पुरुष वर्ग नारी की महत्ता को नहीं स्वीकार करता है। वह विषदा विवाह पर रोक लगाकर गर्व का अनुभव करता है, भले ही समाज में अभिचार फैले; वह नारी की शिक्षा का विरोध कर घटहास करता है, भले ही उसकी सन्तान निरक्षर हो। उसी के विरोध के फलस्वरूप स्त्री-जगत में जागरण होते हुए भी स्त्री-शिक्षा का प्रति धल्प प्रसार हुआ है। १९५९ में एक सीमित सर्वेक्षण के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता २८.८ प्रतिशत थी।<sup>2</sup> इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि स्त्री-शिक्षा की प्रगति प्रति मन्द रही है, जिसका स्पष्टीकरण स्त्री-शिक्षा के विकास से हो जाता है।

1. "If a person who died a hundred years ago came to life to-day, the first and the most important change that would strike him is the revolution in the position of women."  
*Indian Social Reformer*, September 25, 1937.
2. *Hindustan Year Book*, 1960, p. 385.

## स्त्री-शिक्षा का विकास

कम्पनी के शासन-काल में

ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में स्त्री-शिक्षा के प्रति अधिकारियों का रव मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। इसका प्रमुख कारण यह था कि कम्पनी को अपने राजकीय तथा व्यावसायिक कार्यालयों में कार्य करने के लिये शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी। मुनरो (Munro) के यात्रा के प्रालयों तथा एडम (Adam) के बंगाल के शिक्षालयों के वर्णन से ज्ञात होता कि इन प्रान्तों में जो प्राथमिक विद्यालय थे उनमें केवल बालक ही शिक्षा लेते थे। "शिक्षा की समस्त स्थापित संस्थाएँ केवल पुरुषों के लाभ के लिये ही हैं, और सम्पूर्ण स्त्री-जगत को विधिपूर्वक भ्रष्टानता के मार्ग पर ले जाया है।"<sup>१</sup>

कम्पनी के शासन-काल में स्त्री-शिक्षा का आन्दोलन प्रारम्भ करने का श्रेय मिशनरियों को है। १८५१ में प्रोटेस्टेण्ट मिशनरियों द्वारा ३७१ बालिका-विद्यालय खोलाये जा रहे थे, जिनमें ११,२६३ बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण कर रही थीं।<sup>२</sup> इसी प्रकार कुछ बालिका-विद्यालयों का संचालन, रोमन कैथोलिक मिशनरियों के द्वारा भी किया जा रहा था। इन मिशनरियों के प्रतिरित बम्बई में डेक्कन शिक्षा-समिति (Deccan Education Society) स्त्री-शिक्षा-प्रसार कार्य में संलग्न थी। कुछ सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों ने भी शिक्षित शिक्षा-संस्थाओं का विन्यास करके बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इन प्रकार की संस्थाओं में १८४६ में बंगाल की 'शिक्षा-परिषद्' (Council of Education) के प्रधान, जे० ई० डी० थ्यून (J. E. D. Thune) द्वारा स्थापित किया गया बालिका-विद्यालय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन विद्यालय का समस्त व्यवहार उन्होंने स्वयं बहुत किया।

विदेशियों द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने पर भी, भारतीय उसका घोर विरोध करते रहे। १८६७ में बम्बई में, बम्बई तथा पुणे में विश्वविद्यालयों का विन्यास किया जा चुका था, परन्तु प्रारम्भ में विश्वविद्यालयों ने स्त्रियों को परीक्षाओं में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं दी।

"All the established native institutions of education exist for the benefit of the male sex only, and the whole of the female sex is systematically consigned to ignorance."

Adam's Reports, p. 452.

M. A. Sherring: *The History of Protestant Missions*, pp. 411-47.

दी। १८५७ में बम्बई में एक पारसी बालिका को और १८५८ में कलकत्ता में एक ईसाई बालिका को एन्ट्रेन्स परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया।<sup>१</sup>

१८५८ से १८८२ तक

सत्ता हस्तान्तरण के उपरान्त ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन-सूत्र सम्हाला। १८५४ के पोपुलर-एज के आदेशानुसार सरकार ने स्त्रियों की शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। नवनिर्मित शिक्षा-विभागों ने स्त्री-शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और उपयुक्त स्थानों पर बालिका-विद्यालयों का निर्माण किया। फलस्वरूप स्त्री-शिक्षा की प्रगति प्रारम्भ हो गई। १८८२ तक स्त्रियों के लिये प्राथमिक, माध्यमिक, एवं उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधायें प्रदान कर दी गईं। उस वर्ष समस्त प्रकार के विद्यालयों की संख्या २,६१७ थी, जिनमें १,२७,०६६ छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर रही थीं।

१८८२ से १९०२ तक

१८८२ में भारतीय शिक्षा-आयोग (Indian Education Commission) ने तत्कालीन स्त्री-शिक्षा की दयनीय दशा पर अपने हृदयोद्गारों को व्यक्त करते हुए लिखा : "यह बात स्पष्ट है कि स्त्री-शिक्षा अभी तक अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है। घतः इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक सम्भव विधि से इसका पोषण किया जाय।"<sup>२</sup> आयोग ने स्त्री-शिक्षा के प्रायः सभी अंगों के सम्बन्ध में सुझाव दिये, परन्तु इनको महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। आयोग ने न तो बालिकाओं की घनिष्ठायें शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहा और न यह कहा कि उसे सरकार का सरक्षण प्रदान किया जाय। फलस्वरूप १८८२ से १९०२ तक स्त्री-शिक्षा की प्रगति मन्दर गति से हुई। १९०२ में बालिकाओं के लिये १२ कॉलेज, ४६७ माध्यमिक विद्यालय तथा ५,६२८ प्राथमिक विद्यालय थे, जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्रायें की संख्या ४४७, ४७० थी।

१९०२ से १९२१ तक

विद्या-प्रेमी लार्ड कर्जन (Curzon) ने स्त्री-शिक्षा की भूत-नुत्प दशा से

1. L. Mukherjee : *op. cit.*, p. 261.

2. "It will have been seen that female education is still in an extremely backward condition, and that it needs to be fostered in every legitimate way". *Indian Education Commission Report.*

वैत होकर, उसमें जीवन का संचार करने का संकल्प दिया, परन्तु भार-  
यों की रुढ़िवादिता, पर्दा-प्रथा तथा बाल-विवाह-प्रथा ने उसके प्रयासों पर  
एक कुठाराघात किया। पर उस कर्मठ राजनीतिज्ञ ने पराजय स्वीकार न  
धौर भादसं विद्यालयों की स्थापना करके स्त्री-शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त  
ने का कार्य सम्पन्न किया। १९१३ के 'शिक्षा-निति सम्बन्धी सरकार प्रस्ताव'  
Government Resolution on Educational Policy) के मुद्दामों के  
स्वरूप स्त्री-शिक्षा की प्रत्येक स्तर पर प्रगति हुई। १९२१ में १,२९९  
कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति  
उन्नति हुई, परन्तु उससे भी अधिक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुई।

इस काल में कतिपय विशिष्ट महिला-विद्यालयों की स्थापना हुई। इनमें प्रथम १९०४ में श्रीमती ऐनी बेसेन्ट (Annie Besant) द्वारा बनारस में स्थापित किया गया 'सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल' था। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू धर्म के अनुरूप एक आधुनिक विद्यालय में बालिकाओं को पाश्चात्य विद्या की शिक्षा प्रदान करना था। द्वितीय शिक्षा-संस्था १९१६ में पुना में स्थापित की गई 'एम्. एन. डी. टी. इंडियन बीसेन्ट यूनिवर्सिटी' थी। तृतीय शिक्षा-संस्था के मुख्य भारत के मुस्लिम समाज-सेवक महमूद अली जिन्नाह काई को प्राप्त हुआ। इस विद्यालय का उद्देश्य स्त्रियों को 'मुमताज' तथा 'मुमुक्षुणी' बनने की शिक्षा प्रदान करना था। चतुर्थ शिक्षा-संस्था में स्त्रियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education) की व्यवस्था की गई। यह १९१६ में स्थापित किया गया 'नेडी हाइविज कॉलेज' था।

१ से १६१७ तक

इस धरणि में मारी-जवन के प्रत्येक लीच में एक विमलान्ता काँति  
मिलि हुई । देव के कर्चक नेपायो, निम्नार्थ मयाज-नेवकों घोर लव  
ने घननी मायावक तथा रावनी।क विचित्र की मुपार करने के निवे  
दाक किउ के भारगोड हाहाल में देखोइ हैं । विचनों ने १९२६ में  
ए भारगोड लको लक' का निर्माण किया और १९३३ में 'सन्धि  
इ लको-दला मयवन' घोषित किया, किन्तु उ-ह'ने मुपारी  
कउ हाहाल प्रचार को प्रचार को आचकारिणी होने को लीच का लाल  
किया ।

हनुमान चालीसा का अर्थ है कि यह कवि ने इस विधा को अपनाया है।  
हनुमान चालीसा का अर्थ है कि यह कवि ने इस विधा को अपनाया है।  
हनुमान चालीसा का अर्थ है कि यह कवि ने इस विधा को अपनाया है।  
हनुमान चालीसा का अर्थ है कि यह कवि ने इस विधा को अपनाया है।

जिनमें २,६६७;५६८ बालिकायें अध्ययन कर रही थीं। इन भाँकड़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि इस काल में स्त्री-शिक्षा की प्रगति हुई। परन्तु इसके बावजूद भी सम्पूर्ण जनसंख्या में से केवल २-३८ प्रतिशत लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं और स्त्रियों की साक्षरता केवल ३ प्रतिशत थी।

### १९३७ से १९४७ तक

इस काल में स्त्री-शिक्षा की, विशेष रूप से उच्च शिक्षा की, प्रति तीव्र प्रगति हुई। विश्व-युद्ध के दौरान में भारत के विभिन्न सरकारी विभागों एवं व्यावसायिक कार्यालयों में शिक्षित व्यक्तियों की माँग बढ़ी। फल-स्वरूप अनेकों स्त्रियाँ उनमें कार्य करने लगीं। नौकरी करने से स्त्रियों ने जिस आर्थिक स्वतंत्रता के आनन्द का उपभोग किया, उससे उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की अधिक लालसा हुई। युद्ध-काल में मंहगाई अधिक हो जाने के कारण मध्य वर्ग के व्यक्ति आर्थिक संकट में थे। अतः उनमें से जो उदार विचार के थे, उन्होंने अपनी स्त्रियों को घर से बाहर जाकर नौकरी करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की। इस परिवर्तित दृष्टिकोण ने स्त्री-शिक्षा के अध्ययन में अतिशय योग दिया। १९४७ में स्त्रियों के लिये सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा के लिये १९,६५१ संस्थाएँ थीं, जिनमें ३,५५०,५०३ लड़कियाँ शिक्षा से लाभ उठा रही थीं।<sup>१</sup>

### १९४७ से १९६० तक

१९४७ के उपरान्त स्त्री-शिक्षा का एलापनीय विकास हुआ है। १९५५-५६ में स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की संख्या २४,८७६ थी और उनमें अध्ययन करने वाली बालिकाओं की ९,१८८,७०७।<sup>२</sup>

उपर्युक्त भाँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्र भारत में स्त्री-शिक्षा का विस्तार अति द्रुत गति से हो रहा है, परन्तु वास्तविकता यह है कि बालिकाओं की शिक्षा अत्यधिक पिछड़ी हुई अवस्था में है। बालिकाओं तथा बालकों का अनुपात प्राथमिक स्तर पर १ : ४, उच्च सामान्य शिक्षा के स्तर पर १ : ७ है।

हम निस्संकोच रूप से कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज किसी प्रकार की

भी शिक्षा-संस्था में बालिकाओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १५ के अनुसार "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" इस सिद्धान्त के अनुसार भारतीय स्त्रियों को पुरुषों के समान शैक्षिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त हो गये हैं। सरकार छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करके स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। स्त्री-शिक्षा के प्रति व्यक्तियों का पुरातन रुढ़िवादी दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहा है। राष्ट्रीय जीवन में स्त्री-शिक्षा के महत्व को प्रायः प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। आज जो भी भारतीय नागरिक राष्ट्र के भविष्य के सम्बन्ध में चिन्तित है, वह स्त्री-शिक्षा के तीव्र प्रसार का समर्थक है। इन सब बातों के बावजूद भी दुःख का विषय यह है कि स्त्री-शिक्षा अनाद्य गति से अपने पथ पर अग्रसर नहीं हो रही है। इसके क्या कारण हैं, हम इन पर नीचे विचार करेंगे।

## स्त्री-शिक्षा की समस्याएँ

आज स्त्री-शिक्षा के मार्ग को जिन कठिनाइयों अथवा समस्याओं ने घेरकर रखा है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

### १. रुढ़िवादिता

प्रगति एवं मानसिक विकास के इस युग में भी अनेक स्थानों पर भारतीय रुढ़िवादिता के शिकजे में जकड़े हुए हैं। वे अनेक भी प्राचीन विचारों तथा परम्पराओं के पोषक एवं समर्थक हैं। उनका विचार है कि स्त्रियों को विवाह करने के उपरान्त गृह में निवास करना ही उचित है। अतः उनको किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी विचार है कि बालिकाएँ शिक्षित होकर परित्रहीन तथा स्वतंत्र हो जाती हैं। यह धारणा भी स्त्री-शिक्षा के प्रसार में बाधक सिद्ध हो रही है।

### २. अशिक्षा

१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत की ८१.४ प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित थी। १९५६ में भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये एक सीमित सर्वेक्षण

1. "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."—Article 15 of the Constitution of Free India.

से ज्ञात हुआ है कि शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में स्थापनीय वृद्धि है। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ५६.३ प्रतिशत व्यक्ति ही अशिक्षित रह गये हैं।<sup>१</sup> यदि इन आँकड़ों को समस्त भारत के लिये सत्य स्वीकार कर लिया जाय, तो यह कहना अविश्वयोक्ति न होगी कि हमारा देश आज भी अशिक्षा के गर्त में डूबा हुआ है। जिस देश के लगभग आधे व्यक्तियों का मार्ग शिक्षा के प्रकाश से अश्लोभित नहीं है, वहाँ शिक्षा के महत्व का हृदयंगम किया जाना असम्भव है। यही कारण है कि भारतीय जनता शिक्षा के सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्व को समझने में पूर्णतया असमर्थ है। इन अशिक्षित व्यक्तियों को यह समझाना एक अति दुष्कर कार्य है कि शिक्षा से मस्तिष्क का विकास होता है, दृष्टिकोण विस्तृत होता है और व्यक्ति देश का उत्तम नागरिक बनता है। ऐसी स्थिति में जो नग्न सत्य अवलोकित होता है, वह यह है कि अधिकांश भारतीय, बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा को निरर्थक तथा समय का अप-व्यय समझते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में स्त्री शिक्षा के प्रसार की प्राप्ति करना गहन-तारिकाओं को स्वयं करने की इच्छा के समान है।

### ३. धार्मिक कट्टरता

शिक्षा के अभाव के कारण हमारा समाज धार्मिक कट्टरता तथा धार्मिक अन्धविश्वासों पर आधारित है। अशिक्षित हिन्दू एवं मुसलमानों को अपनी धार्मिक परम्पराओं में आज भी इसनी भास्था है कि किसी प्रकार के तर्क प्रस्तुत करके भी उनका परित्याग करने के लिये उनको उद्यत नहीं किया जा सकता है। प्रायः प्रत्येक अशिक्षित कट्टर हिन्दू का स्मृतिकारों के इस कथन में पूर्ण विश्वास है : "दशवें वर्ष में कन्या के पहुँचने पर जो पिता उसका विवाह नहीं कर देता है, वह मानो प्रतिभास उसका राज पीता है।"<sup>२</sup> इसी प्रकार धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करने वाले मुसलमान रजोदण्डन से पूर्व ही बालिकाओं का विवाह करने के लिये उत्कण्ठित रहते हैं क्योंकि उनके विचारानुसार प्रति मास का रजोदण्डन 'गुनाह' है।<sup>३</sup> दूसरे, भारतीय अल्पसंख्यक अधिनियम (Indian Majority Act) मुसलमानों पर विवाह इत्यादि के मामले में लागू नहीं होता है।<sup>४</sup> ऐसे हिन्दू तथा मुस्लिम समाज में अगणित

1. *Hindustan Year Book*, 1960, p. 385.

2. "प्राप्ते तु दशमे वर्षे यस्तु कन्या न यच्छति।

3. "मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति क्षीणितम् ॥

4. "Every month of menstruation is considered a period of *Gunnah* by the Muslims".

4. रामबिहारीसिंह सोमर : भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पृष्ठ २६१

बालिकाओं का विवाह अल्प आयु में ही सम्पन्न कर दिया जाता है। परिणामतः उनकी शिक्षा का स्वयं स्वभाविक है।

## ७. शिक्षा की अनुचित धारणा

ऐसे भारतीयों का प्रभाव नहीं है जिनमें स्त्री-शिक्षा की अनुचित धारणा है। उनके मतानुसार शिक्षा की प्राप्ति केवल व्यावसायिक तथा राजनीतिक लाभ के लिये की जाती है। शिक्षा ग्रहण करने का प्रमुख ध्येय उत्तम राजपद प्राप्त करना है। इस उद्देश्य से केवल बालकों को शिक्षित करना उचित है। हाँ तक बालिकाओं का प्रश्न है उनको केवल उत्तम वर प्राप्त करने के लिये तैयार से शिक्षित किया जाना चाहिये। फलस्वरूप जैसे ही एक बालिका शिक्षा-योग्यता से भाकपित होकर एक नवयुवक उसके सुकुमार कर्तों द्वारा प्रेम से प्रसक्त होने के लिये उद्यत हो जाता है, उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जिन अभिभावकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है वे अपनी बालिकाओं की शिक्षा के क्रम को प्रभाव रूप से चलते रहने में कोई हित नहीं देखते हैं। अशिक्षित समाज का यह दृष्टिकोण स्त्री-शिक्षा पर भीषण प्रहार कर रहा है।

## विवाह की अनुचित धारणा

जिस प्रकार अनेकों व्यक्तियों की बालिका-शिक्षा की अनुचित धारणा है, उसी प्रकार स्त्री-विवाह की भी है। प्रत्येक माता-पिता अपना यह पुनर्जन्म कर्त्तव्य समझते हैं कि वे अपनी बालिकाओं का विवाह यथासमय सम्पन्न कर दें। उनकी परिस्थितियाँ भी उनको इस दिशा में प्रवृत्त होने के लिये संकेत करती हैं। यदि वे अपनी बालिकाओं का विवाह उस समय नहीं कर देते हैं, जब कि जीवन-वस्था में पदापेक्ष करती है, तो उन्हें समाज की टीका-टिप्पणी सुननी पड़ेगी और विविध प्रकार के उचित-अनुचित लक्षणों का सामना करना पड़ेगा। अतः वे बालिकाओं की शिक्षा की प्रेरणा उनके विवाह पर अधिक देते हैं और साधारणतः जीवन के उपान्यास ही न उनका शिक्षा-संस्कारों का अन्ध विच्छेद कर देते हैं। अभिभावकों का यह विचार-विन्दु स्त्री-शिक्षा के लिये घातक सिद्ध हो रहा है।

## बाल-विवाह एवं वरदा-प्रथा

हिन्दू एवं मुस्लिम समाजों में बाल-विवाह तथा वरदा-प्रथा जितनी ही रूप में विद्यमान है। कितने ही माता-पिता अल्प आयु में ही अपनी बालिकाओं के विवाह-संस्कार से मुक्त हो जाते हैं। कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जो



पढ़ाई-पढ़ा का अनुसरण करने के कारण अपनी बालिकाओं को उन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिये नहीं भेजते हैं, जहाँ पढ़े की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार के विद्यालयों की संख्या प्रति नगण्य है। फलतः अनेकों बालिकाओं को अपनी शिक्षा आकांक्षा का दमन कर देना पड़ता है।

### ७. ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकसित दशा

भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अधिकसित दशा में हैं। उनमें जीवन की समस्त आवश्यकताओं की प्राप्ति दुर्लभ है। जहाँ तक विद्यालयों का प्रश्न है, ऐसे ग्राम दो-तिहाई हैं, जिनमें प्राथमिक विद्यालय भी नहीं हैं। फिर ध्यान देने की बात यह है कि भारत ग्राम-प्रधान देश है। यदि एक ग्राम-प्रधान देश के दो-तिहाई ग्रामों में शिक्षा की किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो बालकों तथा बालिकाओं को शिक्षित करने का विचार ही उपहासजनक है। सम्भव है कि मातृशिक्षा कुछ दूने-गिने व्यक्ति अपनी संतान को शिक्षित करने के लिये किसी प्रकार की व्यक्तिगत व्यवस्था कर लेते हों, पर इस विधि को अपना कर शिक्षा-प्रसार की कल्पना करने में कोई सार नहीं है। इन ग्रामों की जनता साधारणतः निर्बल है। अतः उनके समस्त अपने बालकों अथवा बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न कभी भी उपस्थित नहीं होता है। वस्तुतः हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकसित दशा बालिकाओं की ही नहीं, अपितु बालकों को भी शिक्षा से वंचित रखने के लिये उत्तरदायी है।

### ८. सरकार की उदासीनता

यह स्वीकार करते हुए भी कि हमारा देश निर्बल है और सरकार के पास विकास-कार्यों में व्यय किये जाने के लिये धन का अभाव है, हम निस्संकोच रूप से कह सकते हैं कि स्त्री-शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता इसके प्रसार में पर्याप्त मात्रा में बाधक रही है और अब भी है। विदेशी सरकार ने स्त्री-शिक्षा की स्पष्ट रूप से अवहेलना की और १९३५-३६ में भारत के अनेकों प्रांतों में स्त्रियों की शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले धन को कम कर दिया।<sup>१</sup> दुख की बात यह है कि स्वतन्त्र भारत की सरकार भी विदेशियों के पद-चिह्नों पर चल रही है। एक ओर तो अपनी उदारता का परिचय देते हुए सरकार ने स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति की घोषणा की है, परन्तु दूसरी ओर बालिकाओं की शिक्षा पर बालकों की शिक्षा की अपेक्षा कम धन व्यय किया है। १९५५-५६ में राज्य सरकारों ने बालिका-विद्यालयों पर १९,३४-

रहता है। ऐसी स्थिति में एक स्थान पर बालिका-विद्यालय होते हुए भी उस ग्राम्याधिकार्यों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं हो पाती है। फलतः बालिका उस विद्यालय से लाभ नहीं उठा पाती हैं।

### १३. दोषपूर्ण शिक्षा-प्रशासन

भारत में स्त्री-शिक्षा का प्रशासन अत्यधिक दोषपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बंगाल, हैदराबाद और दिल्ली के अतिरिक्त समस्त राज्यों में स्त्री-शिक्षा के प्रशासन का भार पुरुष अधिकारी वर्ग पर है। यह वर्ग न तो स्त्री-शिक्षा की समस्याओं से पूर्ण रूप से अवगत ही होता है और न उन पर्याप्त रुचि ही लेता है। फलस्वरूप न तो उनके द्वारा स्त्री-शिक्षा में होने वाला अपव्यय रोका जा सकता है और न वे स्त्री-शिक्षा के समुचित विकास में योग ही दे सकते हैं।

### १४. अनुपयुक्त पाठ्य-क्रम

स्त्री-शिक्षा की सर्व-प्रधान समस्या पाठ्य-क्रम की अनुपयुक्तता है। शिक्षा के समस्त स्तरों पर लड़कों तथा लड़कियों का पाठ्य-क्रम समान है। इतना अवश्य है कि लड़कियों को गृह-विज्ञान, संगीत आदि बंकल्पिक विषयों के अध्ययन की सुविधा प्राप्त है, परन्तु इससे उनका कोई विशेष हित नहीं होता है। कारण यह है कि माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर लड़कों तथा लड़कियों के लिये समान पाठ्य-क्रम की व्यवस्था है, क्योंकि दोनों के लिये परीक्षाएँ एक ही हैं। पाठ्य-पुस्तकें भी समान हैं। भारतीय जनता लड़कियों के लिये इस प्रकार की शिक्षा की विरोधी है। उसका कहना है कि बालिकाओं को जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह सामाजिक तथा पारिवारिक दृष्टि से उनके लिये हितकर नहीं है। जिन विषयों का विद्यालयों में शिक्षण किया जाता है वे गृहस्थ जीवन के लिये उपयोगी नहीं हैं। विद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा महिलाओं को भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता से विमुख करके पाश्चात्य संस्कृति तथा सभ्यता की अनुयायिनी बना देती है, जिससे देश का महान् धनर्ष हो रहा है। यह शिक्षा ज्ञान-प्रधान, पुस्तक-प्रधान एवं अभ्यावहारिक होने के कारण लड़कियों में सामाजिक भावनात्मकताओं के अनुकूल सामर्थ्य का विकास नहीं करती है। प्रचलित शिक्षा प्राप्त करके महिलाओं के अतिरिक्त पर जो पाश्चात्य मुनम्मा चढ़ जाता है, उसके अन्तर्गत भारतीय परिवार का प्रति स्वरित गति से विघटन हो रहा है।

### समस्याओं का समाधान

हमने स्त्री-शिक्षा की जिन समस्याओं की धोर ऊपर चर्चा किया है,

उनके समाधान में तीन तत्व सहायक हो सकते हैं। ये तत्व हैं—सरकार, जनता और स्थियाँ। यदि ये तीनों अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो क्षीमाविशीम इन समस्त समस्याओं का समाधान सम्भव हो सकता है। इनके क्या कर्तव्य हैं, इसका हम विस्तृत रूप से नीचे अध्ययन करेंगे।

## सरकार के कर्तव्य

स्त्री-शिक्षा की अधिकांश समस्याओं का समाधान केवल सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। जब तक देश की सरकार दक्षिण होकर जातिधर्मों के विचार-प्रसार की दिशा में सक्रिय पग नहीं उठायेगी, तब तक देश की जनता अपना किन्हीं भी सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा हिमालय पर्वत से कुमायी पन्तरीप तक फैली हुई तथा अधिशा के नोड में प्रति दीर्घकाल से घबरा करने वाली स्त्री-जाति का शैक्षिक उद्धार नहीं हो सकेगा। अतः यह बाध्यता ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है कि सरकार स्त्री-शिक्षा के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो और अपने सतत प्रयास के द्वारा उसका विस्तार, विकास तथा प्रचार करे। जब सरकार ने संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान समस्त अधिकार प्रदान कर दिये हैं, तब यह और भी आवश्यक है कि सरकार उनको अधिशा की चिर निद्रा से जागृत करके अपने अधिकारों का उपयोग करने को सामर्थ्य प्रदान करे। इन उद्देश्यों को अपने समक्ष रख कर सरकार जिन बहुमुखी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकती है, वे निम्नांकित हैं:

### १. ग्रामीण जनता का उत्थान

भारत ग्राम-प्रधान देश है और यहाँ की ८२.७ प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है।<sup>१</sup> इन ग्रामों की अधिकांश जनता कितने आर्थिक संकट में है, यह सर्वविदित है। अपनी आर्थिक असमर्थता के कारण ही अभिभावक अपनी लड़कियों के लिये शिक्षा के साधन को उठाने की बात का कभी विचार ही नहीं करते हैं। यह हर्ष का विषय है कि सरकार ग्रामीणों के विकास, कृषि की उन्नति, परिवहन की व्यवस्था एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों द्वारा ग्रामीणों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने की चेष्टा कर रही है। समाज-शिक्षा द्वारा उनके दृष्टिकोण का विस्तृत कर रही है एवं अन्य विविध विधियाँ द्वारा उनके उत्थान की योजनाएँ बना रही है। परन्तु जिस बात का अभाव सतक रहा है, वह यह है कि सरकार की विकास योजनाओं ने भारत के समस्त ग्रामों को, विशेष रूप से उनको जो नागरिक क्षेत्रों से अत्यधिक दूर हैं, अभी

तक स्पर्श नहीं किया है। साथ ही सरकार द्वारा कोई इस प्रकार का संघीय मान्दोलन नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्राम निवासियों की स्त्रुिवादि धार्मिक कट्टरता एवं स्त्री-शिक्षा, बाल-विवाह तथा विवाह की अनुचित प्रथाओं में आमूल-मूल परिवर्तन हो जाय। जब तक सरकार इस दिशा में नहीं उठायेगी, तब तक विकास-योजनाओं द्वारा ग्रामीणों का धार्मिक स्तर उन्नत करके भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उचित कार्य-क्रमों का निर्माण करके ग्राम-निवासियों की धार्मिक उन्नति के साथ-साथ उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक प्रगति की ओर भी विशेष ध्यान दे। ग्रामीणों की सर्वतोमुखी उन्नति करके ही स्त्री-शिक्षा के प्रति उनके संकुचित दृष्टिकोण को परिवर्तित किया सकता है।

## २. बालिका-विद्यालयों की व्यवस्था

हम ऊपर संकेत कर चुके हैं कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन है और बालको की शिक्षा की अपेक्षा उनकी शिक्षा पर कम धन व्यय कर रही है। इससे बालिकाओं की शिक्षा पर प्रबल ब्य-प्रहार हुआ है। धन-भाव के कारण उनकी शिक्षा के लिये समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जिसके फलस्वरूप मान्यता प्राप्त बालिका-विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में केवल ८.५ प्रतिशत वृद्धि हुई है<sup>१</sup> परन्तु प्रमान्यता-प्राप्त विद्यालयों तथा उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं की संख्या में ह्रास हो गया है। १९५४-५५ में इन विद्यालयों की संख्या २,३८,६८५ थी। परन्तु १९५५-५६ में यह संख्या घटकर २,२४,५८३ हो गई और इनमें शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या में ५.९ प्रतिशत का ह्रास हो गया।<sup>२</sup> यदि सरकार प्रमान्यता प्राप्त विद्यालयों की मान्यता प्रदान करके और उनको धार्मिक सहायता प्रदान करके अपनी उदारता का परिचय देती, तो निश्चय है कि बालिका-विद्यालयों और बालिकाओं की संख्या में ह्रास नहीं होता। धन-भाव के कारण इन विद्यालयों की अपना धार्मिक कार्य स्पष्ट करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप कितनी ही लड़कियाँ उनसे लाभ प्राप्त न कर सकीं।

बालिका-विद्यालयों के प्रभाव का एक स्पष्ट परिणाम यह है कि बालिकाओं को सह-शिक्षा ग्रहण करने के लिये बाध्य होना पड़ता है और यदि उनके अभिभावक संशोधन विचारों के हैं, तो उनको शिक्षा में अपना सम्बन्ध विच्छेद करना पड़ता है। शिक्षाविदों ने सह-शिक्षा की प्रशंसा नहीं की है।

1. *Education in India, (1955-56)*, p. 26.

2. *Ibid*, p. 27.

सह-शिक्षा के विद्यालयों में बालकों तथा बालिकाओं का सामीप्य उनकी काम-वासनाओं को उत्तेजित करता है ।' यौवनावस्था का सुमार उन्हें भला-बुरा सोचने का प्रबन्ध नहीं देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वे वय-भ्रष्ट हो जाते हैं और मर्यादा का अतिक्रमण कर वासना-पूर्ति में लिप्त हो जाते हैं । प्राथमिक स्तर पर तो नहीं, परन्तु माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर सह-शिक्षा का यह दोष विशेष रूप से परिलक्षित होता है । फिर बालिकाओं की अभिरूचियाँ तथा भावश्यकताएँ बालकों से भिन्न होती हैं । इसलिए भी सह-शिक्षा से बालिकाओं के लाभ की आशा नहीं की जा सकती है ।

सह-शिक्षा के विरुद्ध इन तथा इनके प्रतिरिक्त भ्रोर जिन धन्य धनेकों कारणों को प्रस्तुत किया जाता है, उनके आधार पर यह निदान्त आवश्यक है कि बालिकाओं के लिए माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर पृथक् विद्यालयों की स्थापना की जाय। हम अपने इस विचार की पुष्टि में माध्यमिक शिक्षा आयोग के इन शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं : “हमारा मत है कि जहाँ सम्भव हो वहाँ बालिकाओं के लिए पृथक् विद्यालय स्थापित किए जाय”, क्योंकि ऐसे विद्यालय सह-शिक्षा के विद्यालयों की अपेक्षा शारीरिक, सामाजिक तथा मानसिक विकास के लिए सम्भवतः अधिक उत्तम अवसर प्रदान करते हैं और समस्त राज्यों को इस प्रकार के विद्यालय पर्याप्त संख्या में स्थापित करने चाहिए।”<sup>१</sup>

खेद का विषय है कि राज्य-सरकारों ने माध्यमिक शिक्षा-भाषाओं की इस सिकारिण की ओर इतना लम्बा समय व्यतीत हो जाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। इस बात की परम आवश्यकता है कि बालिकाओं के लिये कम से कम माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पृथक् विद्यालयों का निर्माण किया जाय। ये विद्यालय केवल स्त्रियों ही नहीं, अपितु ग्रामों में भी हों। निस्सन्देह इस धन व्यय करना पड़ेगा, परन्तु शिक्षा का उत्तर-पुर यह इस लक्ष्य से उन्मुक्त नहीं हो सकती।

## ॥ हितोपदेश

It is possible separate  
ed as they are likely  
nna to deve-  
and all

है। इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे प्रगतिशील देशों में इस प्रकार के घोर यदि वे देश इन कार्य को सम्भव कर गये हैं, तो भारत क

हमें प्रसन्नता है कि भारत-सरकार ने धो-दिशा के मूल को  
 दिया है और उसके प्रसार के सम्बन्ध में सबको योजनाओं को प्रोत्साहित  
 का निश्चय किया है। "सहकियों की शिक्षा की समस्या सब से अधिक  
 है। सहकियों की शिक्षा के सम्बन्ध में देश के अनेक भाग में अन्वेषण  
 जा बाधित नहीं है। माता-पिताओं को शिक्षाने और शिक्षा को बढ़ावा  
 प्रदान करने के लिए और अधिक सम्बन्ध करने का विशेष प्रयत्न करने की  
 योजना है। हर क्षेत्र की परिस्थिति का ध्यान धन्य धन्य करना प्रारम्भ  
 होगा। जहाँ सह-शिक्षा शोकार करने में बाधाएँ हैं, वहाँ के लिए दूसरे  
 को योजना होगा। कुछ क्षेत्रों में दूर दूर स्थानों को देखते रहते और कुछ में  
 दिन बगल के रूप में पाठ्य पद्धति को प्रदान करना सम्भव होगा। एक पाठ्य  
 पद्धति की और दूसरी पाठ्य में सहकियों को प्रोत्साहित होगी।" बाविकाओं के  
 शिक्षा-प्रकार की ये योजनाएँ बलवत् सुन्दर हैं। यदि इनकी कार्य रूप में परि-  
 नत कर दिया गया तो बाविकाओं की शिक्षा-समस्या के समाधान की निश्चय  
 बलवत् में प्रगति की जा सकती है।

मन्त्रालयों को पूर्ण

[illegible]

हमारी सरकार द्वारा मनन किये गये ये विचार अभिनन्दनीय हैं, परन्तु इनके प्रतिरिक्त कतिपय अन्य विधियों की भी क्रियान्वित किया जा सकता है, जो भ्रष्टाकर हैं। प्रथम, सरकार द्वारा अधिक वेतन देकर स्त्रियों को अध्यापन वृत्ति की ओर आकृष्ट किया जाय। द्वितीय, अध्यापकों की शिक्षित पत्नियों को अध्यापन-वृत्ति प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। उनको इस बात की सुविधा दी जाय कि वे उही स्थान के बालिका-विद्यालयों में कार्य करें, जहाँ उनके पति बालक-विद्यालयों में नियुक्त हैं। तृतीय, विद्यालय-भवन की सीमा के अन्तर्गत अथवा उसके अधिक से अधिक निकट अध्यापिकाओं के लिये निःशुल्क आवास की व्यवस्था की जाय। चतुर्थ, शिक्षा-विभाग द्वारा स्त्रियों की नियुक्ति की आयु का प्रतिबन्ध हटा दिया जाय। चासीस वर्ष की आयु तक की महिलाओं को शिक्षा-विभाग द्वारा नियुक्त किया जाय। पंचम, जब तक उपयुक्त शिक्षा-योग्यता वाली महिलाएँ उपलब्ध न हो जायें, तब तक नितान्त आवश्यक शिक्षा-योग्यता वाली स्त्रियों को नियुक्त किया जाय, और उन्हें अपनी शिक्षा-योग्यता में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय तथा उन्हें इस कार्य के लिये सभी प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जायें। षष्ठम्, जो बालिकाएँ अध्यापन-वृत्ति को अङ्गीकार करना चाहती हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिये आर्थिक सहायता दी जाय। सप्तम्, महिलाओं के लिये पशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाय, जिनमें उन्हें निःशुल्क शिक्षा के साथ शिक्षा-वृत्ति भी प्रदान की जाय। अन्तिम, महिलाओं के लिये अल्प-सामयिक प्रशिक्षण पाठ्य-क्रमों एवं अभिनवन पाठ्य-क्रमों (Short-term training courses and refresher courses) की व्यवस्था की जाय।

उपयुक्त समस्त विधियों द्वारा बालिका-विद्यालयों में अध्यापिकाओं की वांछित संख्या की पूर्ति की जा सकती है।

#### ४. पाठ्यक्रम में परिवर्तन

स्त्री-शिक्षा का प्रसार केवल अध्यापिकाओं की पूर्ति से नहीं हो जायगा, अपितु बालिकाओं के शिक्षा पाठ्य-क्रम में भी परिवर्तन करना होगा। इस समय यद्यपि बालिकाओं को कतिपय वैकल्पिक विषयों का निर्वाचन करने की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु उनके लिये बही पाठ्य-क्रम है, जो बालकों के लिये है। दूसरे शब्दों में, बालिकाओं के लिये ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, जिससे वे बालकों के पाठ्य-क्रम से विभिन्न पाठ्य-क्रम से लाभान्वित हो सकें। परिणामस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा में भी वही दोष प्रकट होने लगे हैं, जो बालकों की शिक्षा में हैं। इनमें से एक प्रमुख दोष बेरोजगारी के रूप में व्यक्त

हो रहा है। जब बेरोजगारी पुरुषों के लिये इतनी हानिकारक है, तो वह स्त्रियों के लिये कितनी हो सकती है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।<sup>१</sup> अतः यह आवश्यक है कि सरकार बालिकाओं के पाठ्य-क्रम पर अपने ध्यान को केन्द्रित करे और उनके लिये एक पृथक् पाठ्य-क्रम निर्धारित करे।

इन पाठ्य-क्रम को देश की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राथमिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिये। यदि स्त्री-शिक्षा इन परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होगी, तो उसका उद्देश्य-विहीन हो जाय। स्त्री-शिक्षा का उद्देश्य रोजगार प्राप्ति नहीं है। इसके विपरीत स्त्री-शिक्षा का प्रयुक्त उद्देश्य हमारे देश में नहीं घपियु समस्त देशों में स्त्री को माता के रूप में पुष्टि के परिणाम को निर्माण करने की शिक्षा प्रदान करना है। महान् नेता-नायक नेपोलियन (Napoleon) का कथन है : "बालक का भावो धर्म संबंध उसकी माता के द्वारा निमित्त किया जाता है।"<sup>२</sup> राष्ट्रपति लिन्कन (Lincoln) ने स्वीकार किया है : "मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की विचार हमारे राष्ट्रपति डॉ॰ राबेन्सप्लास ने कच्चा महाविद्यालय, जन्म-दिन पर ने मानव-जाति को स्थिर बनाए रखने का भार स्त्री पर रखा है और आज का सुख पुष्ट नहीं, परियु स्त्रियाँ ही कर सकती हैं। इस दौर-वर्तुषी विविष्ट शासन को स्त्रियों और समाज को समझ लेना चाहिये और यदि भी विद्या-वर्द्धि हो उसने इसकी यत्नि या अनिवार्यता को ध्यान में रखा है। वह वास्तविक नहीं है कि स्त्री और पुष्ट होने सभी काम करें।"

Practically, there is no special provision for teaching the girls anything outside the boy's curriculum. The result is that none of the objectionable features of boys' education are slowly developing in the education of girls. Unemployment among men is bad enough; but among women will be terrible."—S. N. Chatterjee, *Education in India, Today and Tomorrow*, 1922.

"The future decay of the child is always the work of the mother. I am and have to be, I owe to my mother."



प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था नहीं की। इसलिये उन्हें अपने सबसे बड़े उत्तरदायित्व 'मानवमात्र के सृजन' को सबसे पहिले सभालना चाहिये। यह सृजन का काम सन्तानोत्पत्ति के साथ समाप्त नहीं होता। यह तो जब तक स्त्री जीती-जागती रहती है, मनुष्य को उन्नत बनाने में चलता ही रहता है। हमको महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का पालन करने के लिये विद्यालयों में लड़कियों को सुशिक्षित करके अपने देश के सर्वाङ्गीण विकास में उचित रीति से सहायक सिद्ध होना चाहिये।<sup>१</sup>

उपरिलिखित समस्त विचारों से यह सिद्ध हो जाता है कि बालिकाओं के लिये बालकों से वृषक् पाठ्य-क्रम होना अति आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही बालिकाओं के लिये वही पाठ्य-क्रम हो सकता है, जो बालकों के लिये है, परन्तु माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तरों पर उसमें आवश्यक रूप से परिवर्तन कर देना चाहिये। माध्यमिक स्तर पर भोजन शास्त्र, घुलाई, सिलाई-कटाई, गृह-विज्ञान, शिशु-संरक्षण आदि विषयों की विशेष रूप से शिक्षा दी जानी चाहिये और उच्च शिक्षा के स्तर पर कला का इतिहास, चित्रकारी, संगीत, गृह-अर्थशास्त्र, मातृत्व-कला (Mother Craft), गृह-प्रबन्ध (Household Management) और गृह परिचर्या (Home Nursing) आदि विषयों का समावेश किया जाना चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने गृह-विज्ञान की शिक्षा पर बल देते हुए और उसकी उपादेयता का वर्णन करते हुए लिखा है : "यदि गृह-विज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जाय, और प्रतिदिन की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर विशेष बल दिया जाय, तो इससे विद्यालय तथा गृह के जीवन और समाज में जो अन्तर है उसकी समाप्त करने में सहायता प्राप्त होगी, और इससे विद्यालय के उपरान्त के बालिका-जीवन के लिये अधिक उत्तम तैयारी की जा सकेगी, जिसमें गृह-प्रबन्ध का विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान होगा। एक शिक्षित बालिका जो अपने साधनों के अन्तर्गत अपने गृह का सुचारु रूप से तथा कुशलता पूर्वक प्रबन्ध नहीं कर सकती है, वह अपने परिवार के सुख तथा समृद्धि में अथवा अपने देश के सामाजिक स्तरणों को ऊँचा उठाने में उद्युक्त योग नहीं प्रदान कर सकती है।"<sup>२</sup>

१. राजेन्द्रप्रसाद : संकलित "भारतीय-शिक्षा" पृष्ठ ६०-६१

२. "If greater attention is given to Home Science, with special emphasis on practical work of every day needs and problems, it will help to bridge the gulf between the school and the life of the home, and the community, and be a

यदि हमारी सरकार उपरोक्त विचार विन्दुओं को ध्यान में रखकर श्री-शिक्षा के पाठ्य-क्रम का संगठन करे, तो इससे सम्बन्धित समस्या का समाधान निश्चय रूप से सम्भव हो सकता है।

## ५. शिक्षा-प्रशासन में सुधार

हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि श्री-शिक्षा का प्रशासन ज़िम्मे द्वारा न किये जाने के कारण दोष-पूर्ण है और इसके फलस्वरूप श्री-शिक्षा में होने वाला अप्रव्यय रोकना सम्भव नहीं प्रतीत होता है। भ्रतः यह आवश्यक है कि श्री-शिक्षा के प्रशासन का मूल पुष्टियों को न दिया जाकर ज़िम्मे को दिया जाय। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यह भविष्य में हो जाता है कि सरकार प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा-उपसंचालिका तथा उसकी अधीनता में विद्यालय-निरीक्षिकाओं की नियुक्ति करे। इन्दी महिलाओं के द्वारा बालिका-विद्यालयों का निरीक्षण किया जाय और बालिकाओं की शिक्षा-नीति का निर्धारण किया जाय। ज़िम्मे होने के नाते वे ज़िम्मे की समस्याओं को सरलतापूर्वक समझ सकेंगी और उनके समाधान के उपायों को भी सहज ही खोज सकेंगी। भ्रतः श्री-शिक्षा द्रुत गति से अपने उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकेगी।

## ६. वयस्क-शिक्षा की व्यवस्था

वयस्क शिक्षा के जिन कार्य-क्रमों का सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है, उनमें वयस्क ज़िम्मे की शिक्षा को प्रमुख स्थान प्रदान किया जाना चाहिये। इस समय केवल २८% प्रतिशत भारतीय ज़िम्मे शिक्षित हैं।<sup>१</sup> इनमें शिक्षित अत्यधिक ग़ुन है। भ्रतः सरकार को ग्रामीण ज़िम्मे की शिक्षा पर ज़रूर ध्यान एकाग्र करके उनको शीघ्रातिशीघ्र शिक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिये। जब वयस्क स्त्रियाँ स्वयं शिक्षित हो जायेंगी तभी वे शिक्षा के

better preparation for a girl's life after school, in which home-making will necessarily play an important part. An educated girl who cannot run her home smoothly and efficiently, within her resources can make no worthwhile contribution to the happiness and the well-being of her family or to raising the social standards in her country." *Report of the Secondary Education Commission*, p. 58. *Indian Year Book*, 1960, p. 385.

सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व को हृदयंगम कर सकेंगी और तभी वे अपनी कन्याओं को शिक्षित करने की दिशा में प्रयत्नशील हो सकेंगी।

### ७. पथ प्रदर्शन की व्यवस्था

बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का पथ-प्रदर्शन उपलब्ध नहीं है। वे यह नहीं जानती हैं कि उनके लिये किस प्रकार की शिक्षा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः वे अपनी तथा अपने माता पिता की इच्छानुसार किसी भी पाठ्य-क्रम का अनुसरण करती रहती हैं। जब उन्हें पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त हो जाता है, तब उन्हें आभास होता है कि उनके द्वारा चयन किया गया पाठ्य-क्रम सर्वथा त्रुटिपूर्ण है, परन्तु उस समय उन्हें इतना विलम्ब हो जाता है कि वे न तो पीछे हट सकती हैं और न शिक्षा के किसी अन्य पाठ्य-क्रम का अनुसरण कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पायः निराशा का ही भागिदार करना पड़ता है। बालिकाओं को इस संकटपूर्ण स्थिति से मुक्त करने का एक-मात्र उपाय यही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक बालिका-विद्यालय अथवा बालिका-विद्यालयों के एक समूह में शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय, जिनके ऊपर बालिकाओं का उचित पथ-प्रदर्शन करने का भार रखा जाय।

### ८. आर्थिक सहायता

सरकार का अन्तिम तथा प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह अपने विकास के कार्य-क्रमों में स्त्री-शिक्षा को प्रमुख स्थान प्रदान करे और स्त्री-शिक्षा के प्रसार के लिये अधिक से अधिक धन व्यय करने का दृढ़ संकल्प करे। ऐसी स्थिति में ही अशिक्षित स्त्रियों तथा बालिकाओं का कल्याण हो सकेगा और वे शिक्षा ग्रहण करके देश की सामाजिक संरचना में अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण कर सकेंगी। स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति (National Committee of Women's Education) ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार द्वारा स्त्री-शिक्षा पर अधिक धन व्यय किया जाना चाहिये। अतः समिति ने सिफारिश की है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में स्त्री-शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धन-राशि १०० करोड़ रुपए से कदापि कम न हो।<sup>२</sup>

1. "The Committee recommended that a sum of not less than Rs. 100 crores should be allocated for that purpose during the period 1961-66"—*Times of India*, July 12, 1959.



है। उसने स्त्री को उसके अर्थस्य पद से ध्युन करके और उसको अपमानजनक स्थान प्रदान करने में ही अपने कर्तव्यों की दृष्टि समझी है।

यदि पुरुष-वर्ग अपने राष्ट्र की प्रगति चाहता है, उसका उन्नयन करना चाहता है, तो उसे नारी को उसका सम्मानजनक स्थान पुनः प्रदान करना पड़ेगा और उसकी शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था करनी होगी। इस समय जब कि विश्व के सभी देश प्रगति के पथ पर अग्रणी बनने की प्राण-प्रण से चेष्टा कर रहे हैं, तब हमारे देश की जनता को स्त्री-शिक्षा का विरोध करके समय नष्ट नहीं करना चाहिये। जनता का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि वह इसी क्षण से स्त्री-शिक्षा के आन्दोलन में जुट जाय और उसमें स्फूर्ति का संचार कर दे। परन्तु जनता इस कार्य को सकलता पूर्वक तभी सम्पन्न कर सकेगी, जब वह पुरानी परिपाटियों का ढाल मूँद कर अनुसरण करना समाप्त कर दे। उसे स्त्री-शिक्षा के प्रति बिर-काल से विरासत में प्राप्त होने वाले अपने संकुचित दृष्टिकोण को पूर्णतया परिवर्तित कर देना चाहिये। उसे अपनी रुढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता तथा बालिकाओं की शिक्षा एवं विवाह की अनुचित धारणा को समूल उखाड़ फेंकना चाहिये। उसे यह समझ लेना चाहिये कि बालिकाओं की शिक्षा का भार उसी के कंधों पर है। उसे अपने मानस-पटल पर यह बात स्पष्ट चन्दों में प्रकट कर लेनी चाहिये कि प्रजातन्त्र की माँग और उसकी चुनौती को स्वीकार करने के लिये स्त्रियों को कम से कम सम्भव समय में शिक्षित कर देना चाहिये।

स्वतंत्र भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। मात्र राष्ट्र को सकल बनाने के लिये उनके ऊपर उतना ही दायित्व है जितना कि पुरुषों पर। इस बात की ध्यान में रख कर जनता को स्त्री-शिक्षा के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण विकसित करना चाहिये जिससे कि सरकार द्वारा स्त्री-शिक्षा के विस्तार के लिये किये जाने वाले प्रयासों पर कुठाराघात न हो। उसे स्त्री-शिक्षा के प्रति अपनी उदासीनता एवं बिरक्तता को परिवर्तित कर देना चाहिये। उसे अपनी रुढ़िवादिता, धार्मिक संकीर्णता एवं कट्टरता से उन्मुक्त होकर शिक्षा के द्वारा नारी का परिपालन करने का बीड़ा उठा लेना चाहिये। उसे यह बात याँठ बाँध लेनी चाहिये कि यह युग जब नारी को घरों की दीवारों

examples in the past, I think it would be true to say that the position and status of women in India for hundreds of years has not been a good one."—Jawahar Lal Nehru's Foreword in *Women of India*, edited by Tara Ali Baig, p. vii.



गृह का परित्याग करने के लिये और गृह की रक्षा करने के लिये, बन्दूक का प्रयोग करने के लिये कहा। अपना प्रलोभित किया जाय। यह पुनः बर्बरता को प्राप्त करना और सभ्यता के अन्त का प्रथम चिह्न होगा। उस अश्व पर धाव्य होने का प्रयास करके जिस पर पुरुष आरोहण करता है, वह स्वयं अपना और उसका भी पतन करेगी।”

राष्ट्रपिता के इन शब्दों में अनन्त सत्य की झलक मिलती है। पुरुषों को तो इन शब्दों का मनन करना ही चाहिये, परन्तु स्त्रियों को उनसे भी अधिक करना चाहिये क्योंकि स्त्रियों की जिस शिक्षा की ओर महात्मा गांधी ने संकेत किया है, उसी के अनुसार स्त्री-शिक्षा की रूप-रेखा का निर्माण करके स्त्रियों और उनके साथ पुरुषों के परित्राण की प्राप्ति को साध सकती है। पुरुषों द्वारा प्रदर्शित शिक्षा के पथ पर अग्रसर न होकर स्वयं स्त्रियों को अपने लिये उचित एवं वाञ्छित शिक्षा की व्यवस्था की मांग करना चाहिये। अतः यह आवश्यक है कि उन्हें पाश्चात्य शिक्षा की कट्टर उपासिका न बनकर भारतीय भावों एवं संस्कृति पर आधारित शिक्षा ग्रहण करने चाहिये। उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभावशाली आधुनिक शिक्षित नारी वर्ग उच्छृंखल हो गई है। उन्हें यह समझने में भूल नहीं करनी चाहिये कि आज की शिक्षित नारी पाश्चात्य स्त्री-जाति का अनुकरण कर अपने आदर्शों को सर्वथा विस्मृत कर चुकी है। पुरुष के साथ प्रतिस्पर्धा करने में उसने अपने जीवन की सबसे पवित्र बात ‘नारीत्व’ तक को तिलाञ्जलि दे दी है। आज कृत्रिम साधनों से अपने को सब प्रकार से सजाये-सँवारे कामिनी या मोहिनी बनकर पुरुष को रिझाने की, और उसके लिये रंग-बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से भूषोभित होने की दुर्बलता उसे पुनः के समान खा रही है। यदि स्त्रियों ने पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता तथा संस्कृति के आवरण को दूर फेंककर अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं किया, तो उन्हें पुरुषों के विरुद्ध क्रान्ति करके

1. "Whilst both are fundamentally one, it is also equally true that in the form there is a vital difference between the two. Hence the vocations of the two must also be different. In my opinion it is degrading both for man and woman that woman should be called upon or induced to forsake the hearth and shoulder the rifle for the protection of that hearth. It is a reversion to barbarity and the beginning of the end. In trying to ride the horse that man rides, she brings herself and him down."-*Harijan* of 25th February, 1940.

नापाये मत है कि भारतीय विषयों को शिक्षा के प्रति माने दृष्टिकोण को पूर्णतया परिवर्तित करना चाहिये। उन्हें एक स्वतंत्र मार्ग की ओर मुड़ना चाहिये और वास्तविक शिक्षा का प्राधान्य प्रदान करने नहीं बनाना चाहिये। मूरियन वासी (Muriel Wasi) के इन शब्दों में पूर्ण गहराई है : "स्त्रियों के शिक्षण, बुद्धि, गहराई एक कार्य-मुक्तता पर ही भारत में उनकी शिक्षा का वास्तविक निर्भर है।"

सारांश

हिन्दू-युग में स्त्री-शिक्षा— इस बात का स्फूर्त ज्ञान प्राप्त करने के विषय उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं है कि प्राचीन भारत में स्त्री-शिक्षा का कितना प्रसार था। उस युग की जिन लिखित महिलाओं के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें सम्भवतः अपने पतियों धनवान् पितामहों द्वारा शिक्षा दी गई थी।

मुस्लिम-युग में स्त्री-शिक्षा— मुस्लिम युग में स्त्री-शिक्षा—

मुस्लिम-युग में स्त्री-शिक्षा—मुस्लिम-युग में पर्दा एवं बात-विवाह की प्रथाओं के कारण जन-साधारण की बालिकाओं में शिक्षा का प्रचार न हो सका। मुस्लिम राजकुमारियों को भवशय व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी।

धार्मिक युग में स्त्री-शिक्षा—इस युग में स्त्री-शिक्षा प्रायः धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत ही दी जाती थी।

प्राथमिक युग में स्त्री-शिक्षा—कम्पनी के अधिकारियों ने स्त्री-शिक्षा के प्रति रचमान भी ध्यान नहीं दिया। इस युग में स्त्री-शिक्षा का पान्दोलन प्रारम्भ करने का श्रेय मिशनरियों को प्राप्त है। कम्पनी के शासन-काल में उन्होंने ३७१ बालिका-विद्यालय स्थापित किये। १८५८ से १८८२ तक ब्रिटिश सरकार ने स्त्रियों के लिये प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधायें प्रदान की। १८८२ से १९०२ तक स्त्री-शिक्षा की प्रगति तो धन्य है, परन्तु उसकी गति मन्द थी। १९०२ से १९२१ तक स्त्री-शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रगति हुई। इस काल में कतिपय विशिष्ट महिला-विद्यालयों की स्थापना हुई। १९२१ से १९३७ तक राष्ट्रीय पान्दोलन के

1. "Upon their determination efficiency..."

1. "Upon their determination, compactness, good sense and efficiency rests the future of education of women in India."—Tara Ali Baig, ed. *Women of India*, p. 160.



फलस्वरूप स्त्री-शिक्षा का बहुमुखी विकास हुआ। इस युग में सह-शिक्षा के प्रति किसी प्रकार का विरोध न रहा। १९३७ में १९४७ तक उच्च शिक्षा की विशेष रूप से प्रगति हुई। १९४७ से १९६० तक स्त्री-शिक्षा का दत्तावनीय विकास हुआ है। परन्तु बालकों की संख्या के अनुपात में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है।

स्त्री-शिक्षा की समस्याएँ—स्त्री-शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ प्रस्तुत हैं :—(१) रुढ़िवादिता, (२) अशिक्षा, (३) धार्मिक कट्टरता, (४) शिक्षा की अनुचित धारणा, (५) विवाह की अनुचित धारणा, (६) बाल-विवाह एवं पर्दा-प्रथा, (७) ग्रामीण क्षेत्रों की अविकसित दशा, (८) सरकार की उदासीनता, (९) जनता की निर्धनता, (१०) बालिका विद्यालयों का अभाव, (११) शिक्षा में अप्रवृत्ति, (१२) अध्यापिकाओं का अभाव, (१३) दोष-पूर्ण शिक्षा-प्रशासन, एवं (१४) अनुपयुक्त पाठ्यक्रम।

समस्याओं का समाधान—समस्याओं के समाधान में तीन तत्व सहायक हो सकते हैं—सरकार, जनता तथा स्त्रियाँ।

सरकार के कर्तव्य—सरकार के कर्तव्य प्रस्तुत हैं :—(१) ग्रामीण जनता का उत्थान, (२) बालिका-विद्यालयों की व्यवस्था, (३) अध्यापिकाओं की पूर्ति, (४) पाठ्य-क्रम में परिवर्तन, (५) शिक्षा-प्रशासन में सुधार, (६) व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था, (७) पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था, एवं (८) धार्मिक सह्यता।

जनता के कर्तव्य—जनता के कर्तव्य प्रस्तुत हैं :—स्त्री-शिक्षा के सरकारी कार्य-क्रमों में योग देना; स्त्री-शिक्षा का विरोध न करना; पुरानों परिपाटियों का अनुसरण न करना; संकुचित दृष्टिकोण को परिवर्तित करना; रुढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता तथा बाल-विवाह का अन्त करना; एवं धन द्वारा सहायता करना।

स्त्रियों के कर्तव्य—स्त्रियों के कर्तव्य इस प्रकार हैं :—शिक्षा के प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करना, पाठ्यक्रम शिक्षा का अनुसरण न करना तथा भारतीय संस्कृति एवं भावधर्मों के अनुकूल शिक्षा की माँग करना।

### सहायक पुस्तकों की सूची

1. L. Mukherjee : *Problems of Administration of Education in India*,
2. M. A. Sherring : *The History of Protestant Missions*,
3. S. N. Mukerjee : *Education in India, Today and Tomorrow*,

4. Tara Ali Beg, ed *Women of India*.
5. *Indian Education Commission Report*.
6. *Report of the Secondary Education Commission*.
7. *Seven Years of Freedom*.
8. *Education in India, 1935-36*.
9. *Education in India, 1955-56*.
10. *Constitution of Free India*.
11. *Hindustan Year Book, 1960*.
12. *Adam's Report*.
१३. राजेन्द्र प्रसाद : संकलित "भारतीय-शिक्षा"
१४. रामबिहारीसिंह सोमर : "भारतीय सामाजिक संस्थाएँ"
१५. द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१६. भारत, १९६०

### TEST QUESTIONS

1. Give a bird's eye-view of women's education during the Hindu and Muslim periods.
2. Trace in brief the development of women's education during the twentieth century.
3. Enumerate the causes of the backwardness of women's education in India. What measures should the Government and the people take to remove these causes?
4. What are the major problems of women's education in India? Give your suggestions for solving them?
5. Mention the difficulties that have been experienced in the expansion of women's education. What measures, in your opinion, should be adopted to overcome them?

## अध्याय ४

# समाज-शिक्षा ✓

### राष्ट्रीय जीवन में समाज-शिक्षा का स्थान

के० जी० संयदेन ने लिखा है : "हम राष्ट्रीय जीवन के एक ऐसे नवीन युग में प्रवेष्ट कर रहे हैं जो सम्भवतः भागामी अनेकों शताब्दियों के लिये हमारे देश की भावी व्यवस्था की रूप-रेखा निर्धारित कर देगा। हमारे राष्ट्रीय जीवन को विघात करने वाले पारस्परिक संगीन झगड़ों की घनघोर घटायें भी विनाश की बदली के समान छुट जायेंगी और हम फिर न्याय तथा स्वतन्त्रता और समझदारी के प्रकाशमय आलावरण में पहुँच जायेंगे। यदि आप मुझे एक स्वतः स्पष्ट सत्य को दोहराने की अनुमति दें तो मैं कहूँगा कि केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता किसी भी समाज या राष्ट्र के लिये 'उत्तम जीवन' ( Good Life ) का आश्वासन नहीं दे सकती है। हम भली प्रकार जानते हैं कि अनेकों राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होते हुए भी अल्प श्रेष्ठताओं से आवद्ध हैं, जो उन्हें 'उत्तम जीवन' की ओर अप्रसर नहीं होने देती हैं, क्योंकि इस प्रकार का जीवन कठिन परिश्रम तथा समाजोपयोगी कार्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में जब तक अनन्त निरन्तर सतर्कता ( Eternal Vigilance ) के रूप में अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता का भ्रूक्ष चुकाने के लिये तैयार न हो, तब तक वह इस स्वतन्त्रता को भी सुरक्षित नहीं रख सकती है और इस सतर्कता के लिये उचित नागरिक तथा सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता है। यदि हमारा लक्ष्य ऊँचा है और हम अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता के सहारे सामाजिक स्वतन्त्रता तथा प्राथमिक लोकतन्त्र के सदैव तक पहुँचना चाहते हैं, तो

हाष्टतः हमें जनसाधारण के लिये कहीं अधिक उच्च-स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होगी। नहीं तो सर्वत्र इस बात का मय रहेगा कि बहुत परन्तु बेईमान इस प्रथम व्यक्ति अपने निरुद्ध उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथाकथित "स्वतन्त्रता" का प्रनुचित लाभ उठावेंगे। इसी बात को मैं तत्काल तथा बड़े पैमाने पर प्रौढ़-शिक्षा (Adult Education) का प्रान्दोलन प्रारम्भ करने के राजनीतिक द्योचित्य का आधार कहूँगा।"१

इन शब्दों में शिक्षा-महारषी संयर्दन ने राष्ट्रीय जीवन में समाज-शिक्षा के स्थान तथा महत्त्व की प्रकृति किया है। उन्होंने राजनीतिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिये 'निरन्तर सतकंता' की ओर सामाजिक तथा धार्मिक लोकतन्त्र के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये जनसाधारण की उच्च शिक्षा को आवश्यक शर्त बताया है एवं इन बातों को पूर्ण करने के लिये प्रौढ़-शिक्षा के प्रान्दोलन पर बल दिया है। भारत में प्रौढ़-शिक्षा का यह प्रान्दोलन किस प्रकार किया जा रहा है, इस प्रान्दोलन की सफलता की कितनी प्राशा है, इन सफलताओं के मार्ग में कौन-सी कठिनाई है, इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है—इन्हीं तथा इनसे सम्बन्धित बातों पर विचार करना ही प्रस्तुत पाठ की विषय-सामग्री है। परन्तु इस सामग्री के प्रस्तुतिकरण से पूर्व 'प्रौढ़-शिक्षा' तथा 'समाज-शिक्षा' शब्दों के अर्थ का स्पष्टीकरण करना अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

### प्रौढ़-शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा

'प्रौढ़-शिक्षा' के अर्थ की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। जैसा कि 'प्रौढ़-शिक्षा' शब्द से व्यक्त होता है, इसका अर्थ है निरक्षर प्रौढ़ों को पढ़ना सिखाना अर्थात् कुछ लिखित चिह्नों को उनकी ध्वनि तथा अर्थ के रूप में पहचानना सिखाना। परन्तु वास्तविकता में 'प्रौढ़-शिक्षा' का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। इसको स्पष्ट करते हुए एच० एन० मुकर्जी ने लिखा है: "प्रौढ़-शिक्षा में मोटे तौर पर वह सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित है जो प्रौढ़ों को दी जाती है। भारत में प्रौढ़-शिक्षा के दो पदार्थ हैं: (१) प्रौढ़ साक्षरता, अर्थात् उन प्रौढ़ों की शिक्षा जिनको विद्यालयों में कभी भी किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, और (२) साक्षर प्रौढ़ों की अनवरत

विद्या ।”<sup>१</sup> संघर्ष के मतानुसार : “प्रौढ़-विद्या में राजनीतिक और नागरिक तथा नैतिक विद्याएँ भी सम्मिलित हैं ।”<sup>२</sup>

## प्रौढ़-शिक्षा की नवीन धारणा

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बहुत समय पूर्व ही भारत में प्रौढ़-विद्या का आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था । परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त होने के उपरान्त देश के नेताओं ने राष्ट्रीय जीवन में प्रौढ़-विद्या के महत्त्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया । उन्हें यह पूर्ण रूप से सामास्य हो गया कि यदि इस महान् तथा प्राचीन देश को जीवित रहना है, तो इस देश के निरक्षर वयस्कों को केवल साक्षर ही नहीं बनाना है, अपितु उनका बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक उत्थान भी करना है । इसी विचारधारा से अनुप्राणित होकर देश के राजनीतिक कर्णधारों ने प्रौढ़-विद्या को एक नवीन रूप प्रदान करके उसको अधिक व्यापक बनाया और उसको समाज-विद्या का नया नामांकन दिया । जनवरी, १९४६ में इसा-हाबाद में होने वाले ‘केन्द्रीय विद्या सलाहकार बोर्ड’ (Central Advisory Board of Education) के पन्द्रहवें अधिवेशन में भाग लेते हुए मौलाना अबुल कलाम आझाद ने प्रौढ़-विद्या के प्रति भारत-सरकार के नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया । उन्होंने कहा कि प्रौढ़ विद्या का उद्देश्य केवल वयस्कों को साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये, अपितु इसके अन्तर्गत उस विद्या को भी समाविष्ट कर देना चाहिये जो भारत के प्रत्येक नागरिक को भौतिक, धार्मिक, व्यवस्था का, विवेकपूर्ण सदस्य बना दे । उसी समय से प्रौढ़-विद्या की धारणा में परिवर्तन हुआ और उसे ‘समाज-विद्या’ में नाम से पुकारा जाने लगा ।

- 1 “Adult education may be defined very broadly so as to include all instruction, formal or informal, imparted to adults. In India, adult education has two aspects : (1) Adult literacy, i. e. education of those adults who never had any schooling, and (2) continuation education of the literate.”—S. N. Mukerji: *Education in India Today and Tomorrow*, pp. 344-45.
- 2 “Adult education .....includes political and civic as well as moral education,”—K. G. Saiyidain : *op. cit.*, p. 243.

## श्रीकृष्ण-शिक्षा तथा समाज-शिक्षा में अन्तर

श्रीकृष्ण-शिक्षा तथा समाज-शिक्षा के अन्तर को इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है : "श्रीकृष्ण-शिक्षा को सद्गुणों में मात्र बहुत उच्च परिवर्तन हो सकता है। साक्षरता के अपने छोटे दायरे में निरुद्ध कर यह सामाजिक शिक्षा व्यापक रूप ग्रहण कर चुकी है। वहिने उतका वायोवन केन घोषचारिक श और व्यक्ति को साक्षर बनाकर और उनके विषे घोष-बहुत पढ़ने-लिखने प्रवृत्त कर वह अपने कर्तव्य की दक्षिणी समझ लेती थी। अब उसका तत्त्व श्रीकृष्ण को इस प्रकार की शिक्षा देना हो गया है जिसने वे 'यक्ति के रूप में और समाज के एक घटक के रूप में अपनी धन्यता प्रस्तुत देना ने ऊपर उठकर वहिने से अधिक सम्पन्न और प्रसन्न जीवन व्यतीत कर गये।"

## समाज-शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा

समाज-शास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए भीमाना प्रमुख कृत्याम धावाह ने इसकी परिभाषा इन शब्दों में की है : "समाज-शिक्षा से हमारा तात्पर्य है पूर्ण मानव की शिक्षा। यह उसको साक्षरता प्रदान करेगी जिससे कि विश्व का ज्ञान उसे उपलब्ध हो सके। यह उसको बतायेगी कि वह अपने भाषका पर्यावरण से अनुकूलन किस प्रकार करे और जिन प्राकृतिक दशाओं में वह निवास करता है, उनका सर्वोत्तम प्रयोग किस प्रकार करे। इसका अभिप्राय उसे उत्तम कला-कौशल तथा उत्पादन की विधियों की शिक्षा देना है, जिससे कि वह अधिक उत्तम धार्मिक स्थिति को प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य उसे व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्वास्थ्य विज्ञान के प्राथमिक सिद्धान्तों की शिक्षा देना भी है, जिससे कि हमारा गृहस्थ जीवन स्वस्थ तथा समृद्ध हो सके। इस शिक्षा को उसे नागरिकता का पाठ पढ़ाना चाहिये जिससे कि उसे सवार की बातों का कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाय और वह अपनी सरकार को उन विधियों के

१. बंगीयर धीमास्तव, प्रपादाचार्य, राजकीय जूनियर बेंसिक इंजिन कॉलेज, इलाहाबाद, नवसाक्षरोपयोगी साहित्य निर्माण गोष्ठी की प्रस्ताव, १९५६  
शिक्षा-विभाग, उत्तरप्रदेश, पृष्ठ ५४-५५

निर्माण में सहायता दे सके जो व्यक्ति तथा प्रगति में योग्य प्रदान करें।<sup>1</sup>

समाज-विद्या की परिभाषा करते हुए हुमायूँ कबीर ने लिखा है : 'समाज विद्या को अध्ययन के एक प्रकार के पाठ्य-क्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों में नागरिकता की चेतना का उदय और उनमें सामाजिक समस्य की उपस्थिति करता है। समाज-विद्या निरक्षर व्यक्तियों में साक्षरता का प्रसार करके संतुष्ट नहीं होती है, बल्कि जनसाधारण में शिक्षित व्यक्ति के निर्माण को अपना सङ्कट बनाती है। स्वाभाविक उद्देश्य के रूप में समाज-विद्या व्यक्तियों में व्यक्तिगत तथा समाज के सदस्यों के रूप में नागरिकता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीव्र भावना का समावेश करने का प्रयास करती है।'<sup>2</sup>

1. "By Social Education we mean an education for the complete man. It will give him literacy so that knowledge of the world may become accessible to him. It will teach him how to harmonise himself with his environment and make the best use of the physical condition in which he subsists. It is intended to teach him improved crafts and modes of production so that he can achieve economic betterment. It also aims at teaching him the rudiments of hygiene both for the individual and the community so that our domestic life may be healthy and prosperous. The last, but not the least, this education should give him training in citizenship so that he obtains some insight into the affairs of the world and can help his Government to take decisions which will make for peace and progress."—Abul Kalam Azad's Inaugural Address to the UNESCO Seminar on Rural Adult Education held in December, 1949 in Mysore.
2. 'Social education may be defined as a course of study directed towards the production of consciousness of citizenship among the people and the promotion of social solidarity among them. It is not content with the introduction of literacy among the grown-up illiterates but aims at the production of an educated mind among the masses. As a natural corollary, it seeks to inculcate in them a lively sense of rights and duties of citizenship both as individuals and members of the community.'  
—Humayun Kabir : *Education in New India*, p. 82.

उपनिविष्ट विभागाधी के आधार पर हम समाज-शिक्षा के वर्गीकृत कर में इस प्रकार भ्रष्ट कर सकते हैं। समाज-शिक्षा एक निराला अनुभव है जो व्यक्तियों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने की क्षमता प्रदान करता है। समाज शिक्षा नागरिकता का उचित मूल्यांकन करने की योजना को मान्य करती है, व्यक्तियों के कर्तव्यों तथा अधिकारों का स्पष्टीकरण करती है और यह शिक्षा दती है कि वे अपने योगित साधनों पर धननिष्ठ होते हुए भी किम विधि का अनुसरण करके अपनी प्राय में रुचि कर सकते हैं।

### समाज-शिक्षा का कार्यक्रम

भारत-सरकार द्वारा समाज-शिक्षा की नवीन पारलाना के अन्तर्गत न केवल साक्षरता के महत्त्व को स्वीकार किया गया है, अपितु यह भी स्वीकार किया गया है कि बरस्क की विभिन्न अभिवृत्तियों को विकसित करने का प्रयास किया जाय। अतः सरकार ने समाज-शिक्षा के निम्नांकित 'पंचमुखी कार्यक्रम' (Five Point Programme) का निर्माण किया है :-

१. साक्षरता का प्रसार।
२. स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों की शिक्षा।
३. बरसकों की प्राथिक उपरति के लिये उद्योग-पन्थों की शिक्षा।
४. बरसकों में अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति पर्याप्त जागरूकता के साधन-साध नागरिकता की भावना का विकास।
५. व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल मनोरंजन के स्वस्थ साधनों की व्यवस्था।

समाज-शिक्षा का यह पंचमुखी कार्यक्रम अति विस्तृत तथा व्यापक है। इसके अन्तर्गत न केवल बरसकों को साक्षर बनाया जायगा, अपितु उनका शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा प्राथिक विकास भी किया जायगा, और इस प्रकार उनके जीवन का सर्वांगीण विकास किया जायगा जिससे भारतीय मानवता विकसित होकर अपनी सम्पूर्णता पर पहुँच जाय।

### समाज-शिक्षा के उद्देश्य

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही यह अनुभव किया जाने लगा कि भारत

2 India, 1958, p. 110.

1 Aims of Social Education.



में लोकतंत्र की स्थापना तथा स्थिरता के लिये जनता को शिक्षित किया जाना अति आवश्यक है। अतः स्वतंत्र भारत के नवनिर्मित तथा प्रथम शिक्षा-मंत्रालय ने बयस्कों की शिक्षा को अपने कार्य-क्रम में प्रमुख स्थान दिया। अतः १९४६ में श्री मोहन लाल सक्सेना की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया और उसे बयस्क-शिक्षा के प्रसार पर परामर्श देने का आदेश दिया गया। समिति ने बयस्क-शिक्षा के उद्देश्यों को अति संकुचित पाकर सरकार को यह परामर्श दिया कि इस शिक्षा को समाज-शिक्षा की संज्ञा दे दी जाय। सरकार द्वारा समिति का यह परामर्श स्वीकार कर लिया गया। इस समिति ने समाज शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये :-

१. नागरिकों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और उनमें समाज-सेवा की भावना का विकास करना।
२. उनमें जनतंत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना तथा उन्हें जनतंत्रीय सरकार की शासन-विधि की शिक्षा देना।
३. उनको देश तथा विश्व के समक्ष उपस्थित समस्याओं से अवगत कराना।
४. उनमें इतिहास, भूगोल तथा सांस्कृतिक शिक्षा के द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना।
५. उनको गायन, नृत्य, कविता तथा नाटक के द्वारा सांस्कृतिक परिषय तथा आनन्द के अवसर प्रदान करना।
६. उनको सामूहिक वाद-विवाद तथा पठन-पाठन के माध्यम से विशिष्ट नैतिक मूल्यों से अवगत कराना।
७. उनको लिखने-पढ़ने तथा साधारण गणित का उपयुक्त ज्ञान प्रदान करना एवं ज्ञान के प्रसार के प्रति प्रोत्साहन देना।
८. उनको दस्तकारी का आवश्यक प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने अवकाश का अपनी आर्थिक प्रगति के लिये उपयोग करने की शिक्षा देना।
९. उनमें पुस्तकालयों, विवाद-गोष्ठियों, शिक्षा-समितियों तथा जनता महाविद्यालयों द्वारा शिक्षा के क्रम को बनाये रखना।
१०. उनमें सहयोग की भावना का विकास करना।

### समाज-शिक्षा के लक्ष्य

समाज-शिक्षा के लक्ष्यों का सरकार द्वारा दो स्पष्ट वर्गों में विभाजन किया

27/11/77 14:00

व्यक्तिगत जीवन

व्यवस्थापक का जीवन ईद की मायाओं के साथ बँट रहा है। यह वह समय था जब वैज्ञानिक धारणाएँ तथा धर्मशास्त्रों के कारण जीवन की दृष्टिगतता में अंतर्दृष्टि होने लगी थी। इन दृष्टिगतता ने निरंतर वृद्धि के समय, विषय के अंतर्गत जो नवीन विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे, एक ऐसे जीवन की स्थापना कर रहे थे जिसका सामना करने के लिए उन्होंने अपने को समर्थ बनाया। ऐसे धर्मशास्त्र पर सरकार ने व्यवस्थापक को जीवन का कार्य-क्रम निर्धारित करके उनको सहायता में उपस्थित करने के लिए एक नई दिशा में सक्रिय बन उठाया। समय की गति के साथ व्यवस्थापक की धारणा अधिक हो अधिक व्यापक होती चली गई और धारणा समाज-विज्ञान के रूप में बहुत बलपूर्वक के मानसिक विकास तथा धार्मिक धर्मशास्त्र में दृष्टि करके एवं उनको उत्तम सांस्कृतिक जीवन अंगीकृत करने की सुविधा प्रदान करके उनके अस्तित्व का सर्वोत्तम विकास करने की चेष्टा करती है। अतः व्यक्ति के दृष्टिकोण समाज-विज्ञान अधोनिष्ठित सत्त्वों की प्राप्ति का प्रयास करती है :

१. व्यक्तियों का मानसिक विकास

जो समाज

१. वयस्कों का मानसिक विकास जो वयस्क होते

2. बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना।

2. व्यक्तियों की व्यावसायिक शिक्षा करना।  
व्यक्तियों की व्यावसायिक क्षमता का विकास करने के लिए व्यावसायिक तथा टेक्निकल शिक्षा देनी चाहिए।

वयस्कों की व्यावसायिक (Professional) क्षमता का विकास  
में व्यावसायिक तथा टेक्निकल शिक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कुटीर  
उद्योग-पन्थों की व्यवस्था करना ।

१. वयस्कों का शारीरिक विकास

बच्चों का शारीरिक विकास करने के लिये स्वास्थ्य के आधारभूत सिद्धान्तों, बाल स्वास्थ्य, अस्वस्थता से बचने के उपायों, विशिष्ट क्षेत्रों में फैलने वाले प्रमुख रोगों को रोकने और पोषक आहार की समस्याओं को हल करने के लिये प्रशिक्षण का समुचित प्रबन्ध करना ।

1. Teachers' 15

#### ४. वयस्कों की सामाजिक कुशलता (Social skill) का विकास

वयस्कों की सामाजिक कुशलता का विकास करने के लिये उन्हें अपने सानियों के मध्य निवास करने, जीवन में प्रगति करने, पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने और प्राधुनिक प्रचलित संसार में अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की शिक्षा प्रदान करना ।

#### ५. वयस्कों का सांस्कृतिक विकास

वयस्कों का सांस्कृतिक विकास करने के लिये तथा उन्हें अपने देश के प्राचीन तथा प्रचलित सांस्कृतिक कार्यों से अवगत कराने के लिये मनोरंजन, नृत्य तथा लोक-नृत्य, गीत तथा लोक-गीत, व्याख्यान भाषाओं आदि की उपयुक्त व्यवस्था करना ।

#### ६. वयस्कों का आत्म-विकास (Self-development)

वयस्कों का आत्म-विकास करने के लिये उनकी परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल किसी विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति, जीवन सिद्धान्तों के निर्माण अथवा किसी कला के अनुसरण के लिये सुविधा प्रदान करना ।

### समाजगत लक्ष्य

हम उम्मीद कर चुके हैं कि वयस्क-शिक्षा की प्राचीन धारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है और उसको समाज-शिक्षा की संज्ञा दे दी गई है । यद्यपि समाज-शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति करना है, परन्तु इसके साथ ही उसे समाज का बुद्धिमान तथा लाभप्रद सदस्य भी बनाना है जिससे कि न केवल उसका अपितु उसके सहयोग से समाज का भी उत्थान हो सके । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये समाज-शिक्षा "व्यक्तियों के समस्त विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को प्रस्तुत करती है । यह उनको विचार करने की विधियों तथा समूहों में सामान्य समस्याओं के समाधान की शिक्षा देती है । यह उनको इस बात को समझने की शिक्षा देती है कि वे समूह महान् परिवार अर्थात् भारत और उससे भी महान् परिवार अर्थात् विश्व का निर्माण करने के लिये किस प्रकार परस्पर भाव्य हैं और उनके समस्त भारत के भाग्य-निर्माण तथा विश्व-सेवा के लिये अनवरत प्रयास एवं कार्य करने का आदर्श उपस्थित करती है ।"

1. "It places before the people the needs and problems of various groups. It teaches them the way of thinking and solving the common problems in groups. It teaches them to see how these groups are knit together to form

समाज-विद्या की इस धारणा के आधार पर समाज-विद्या के  
 स्वरूप है :—

## १. सामाजिक एकता का विकास

सांस्कृतिक समाज की एक प्रमुख विशेषता है व्यक्तिगत के हितों का वारसपरि  
 संबंध। समाज को इस संबंध में गुरुत्व देने के निम्न सामान्य रूपों के  
 निर्माण की आवश्यकता होती है। यह न केवल वर्गों के वारसपरि हितों को  
 पूर करने के निम्न, अपितु व्यक्तियों तथा व्यक्तियों और समूहों तथा समूहों के  
 मध्य निरन्तर बढ़ती हुई पृथक्ता का, जो हमारे नागरिक तथा हमारे ग्रामीण  
 समाज का भी एक विशेष लक्षण है, घटाने के निम्न भी आवश्यक है।  
 किसी विशाल ने इस पृथक्ता को 'एकात्मता' कहकर परिभाषित किया है। इस  
 प्रकार की 'एकात्मता' (Solitude) विभिन्न भाषा-भाषी समूहों, धार्मिक समूहों,  
 ग्रामीण तथा नगरीय समूहों, निश्चित तथा अनिश्चित, स्थिर तथा परिवर्तमान  
 व्यक्तियों, पुरुषों तथा स्त्रियों, भूमि, देशवासियों तथा विदेशियों, युवकों तथा  
 वृद्धों, धनी तथा निर्धन व्यक्तियों के मध्य विद्यमान है। "समाज-विद्या का  
 लक्ष्य है इस एकात्मता को यथासम्भव कम करना और एक सामान्य संस्कृति  
 का निर्माण करना जिसमें देश के समस्त राष्ट्रीय तत्व भाग ले सकें।" १

## २. राष्ट्रीय साधनों की सुरक्षा तथा उत्पत्ति

समाज-विद्या व्यक्तियों को यह बात सिखाती है कि वे भारत को प्रकृति  
 द्वारा दिये गए उपहारों तथा यहाँ के निवासियों को ऐसे साधन समर्थन जिनकी  
 सहायता से इस देश के समस्त प्राणियों के लिए जीवन के एक उचित स्तर का  
 निर्माण करना सम्भव है। वे साधन दो प्रकार के हैं—भौतिक तथा  
 मानवीय।

विद्यमान हुए राष्ट्रों के मध्य एक कठिनतम कार्य है, अपने प्राकृतिक साधनों

the great family, that is, India and the greater family,  
 that is, world, and holds before them the ideal of sus-  
 tained effort and work as their offering to the destiny  
 of India and the service of the world." *Teachers' Hand-  
 book of Social Education*, p. 21-22.

1. Promoting Social Cohesion.
2. "It is the purpose of Social Education to reduce these  
 solitudes as far as possible and to create a common cul-  
 ture in which all national elements can participate."  
*Teachers' Handbook of Social Education*, p. 22.
3. Conservation and Improvement of National Resources.

की सुरक्षा तथा उन्नति । उदाहरणार्थ, भारत में हमारे समक्ष हमारी भूमि तथा वनों के क्षय की समस्याएँ हैं । यह आवश्यक है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इन समस्याओं से अवगत हो और वह न केवल उनकी सुरक्षा अपितु उनकी उन्नति में भी अपना योग्य प्रदान करे ।

प्राकृतिक साधनों से अधिक महत्वपूर्ण मानवीय साधन है । हमारे विद्यालयों तथा शिक्षा की उच्च संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे इन मानवीय साधनों की उन्नति करें । हमारे देश की अधिकांश जनता को विद्यालयों में शिक्षा प्रदत्त करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है और इसलिए वे साहित्यिक तथा अन्य आवश्यक योग्यताओं का विकास नहीं कर सके हैं । यही कारण है कि समाज-शिक्षा ने हमारे देश के निवासियों का साक्षरता तथा उत्पादक योग्यताओं के समान आधारभूत कुशलताओं की शिक्षा प्रदान करने का भार अपने ऊपर लिया है ।

लेनिन (Lenin) का मत था कि निरक्षर जनता के आधार पर समाजवाद (Socialism) का निर्माण केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक निरक्षर मनुष्य राजनीति के क्षेत्र से बाहर होता है । यही बात किसी भी वास्तविक जनतांत्रिक समाज के सम्बन्ध में कही जा सकती है । एक प्रशिक्षित व्यक्ति में दृष्टिकोण तथा भविष्य की वह विशालता नहीं होती है, जो स्वस्थ राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है ।

अन्त में, हमारी एक प्रमुख आवश्यकता है व्यक्तियों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, और इस कार्य को तब तक सम्पन्न नहीं किया जा सकता है, जब तक जनता प्रशिक्षित है । साक्षरता तथा शिक्षा के अभाव में उत्पादन में एक निश्चित सीमा तक ही वृद्धि की जा सकती है, उसके आगे नहीं ।

### ३. सहकारी समुदायों तथा संस्थाओं का संगठन

विभिन्न समूहों की 'एकान्तरता' को कम करना और राष्ट्रीय साधनों की सुरक्षा तथा उन्नति प्रारम्भिक कार्य है । "समाज-शिक्षा को मनुष्यों को ऐसी कुशलताओं की शिक्षा देनी है जो ऐसे समूहों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जो इन साधनों का सभी के हित के लिये प्रयोग करने के लिये योग्य तथा इच्छुक हों ।" इन कुशलताओं के अन्तर्गत तीन बातों का समावेश है :

1. Building Co-operative Groups and Institutions.
2. "Social education has to lead on to teach men the skills which are necessary for building up groups qualified and willing to use these resources for the good of all." *Teachers' Handbook of Social Education*, p. 23.

समूहों के समक्ष उपस्थित समस्याओं का सामूहिक अध्ययन, उनका स  
करने के लिये सामूहिक तथा सहकारी कार्य, और इन कार्यों के परिणामों  
सामूहिक भूत्यागन। अतः समाज-शिक्षा का लक्ष्य है—उन विधियों  
निर्माण करना जिनसे उपरिर्लिखित समूहों का निर्माण इस प्रकार किया  
कि व्यक्ति अपने स्वतन्त्रता तथा सम्मान से वंचित न हो सके, जिससे ने  
लोग बिना बल का प्रयोग किए समूहों का नेतृत्व कर सकें, जिससे अधिकत  
व्यक्तिगत सुख का सामाजिक प्रगति से सामंजस्य स्थापित किया जा सके,  
जिससे उन आधारभूत संस्थाओं की स्थापना की जा सके जो व्यक्त के कल्याण  
का सबसे बड़ा कल्याण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं और  
जिससे प्रत्येक व्यक्ति इन संस्थाओं के विकास तथा स्थायित्व में योग दे सके।

#### ४. सामाजिक भावार्थ का समावेश

‘समाज-शिक्षा का एक प्रधान कर्तव्य है—लोगों को अपने व्यक्तिगत  
कल्याण को अपने समूह, अपने समाज और अपने देश के कल्याण के लिए समर्पित  
करने के लिए और इस कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उत्तम करना।’<sup>१</sup>  
इस दृष्टिकोण को एक मजबूत लेखक के प्रसिद्ध शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया  
जा सकता है : ‘याद रखलें कि जीवित है तो अन्त कितना है, यदि इंग्लैंड का  
अन्त होता है, तो जीवित कौन है।’<sup>२</sup> समाज के जीवन में महानतम व्यक्ति  
का योग भी सीमित होता है। फिर भी उसके जीवन का महत्व इस बात से  
घटता जाता है कि उसने मानवजाति की प्रगति में क्या योगदान दिया है।  
समाज-शिक्षा का लक्ष्य है निम्नतम भारतीय में इस भावना का समावेश कर  
देना कि वह मानव-जाति की प्रगति में योगदान करने के कार्य को अपना  
भावार्थ समझे।

#### समाज-शिक्षा की आवश्यकता

समाज-शिक्षा के उपरिर्लिखित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किसी  
प्राकल्पिक घटना के परिणामस्वरूप न होकर, व्यक्ति, समाज तथा देश की

1. Inculcating Social Ideology.
2. ‘One of the most important functions of Social Education is to prepare the people to subordinate their private welfare to the welfare of their group community and their country and to do this joyfully.’ *Teachers' Handbook of Social Education*, p. 23.
3. “Who dies if England lives, who lives if England dies”

कतिपय आवश्यकताओं पर गम्भीर विचार करने के उपरान्त किया गया है। इन्हीं आवश्यकताओं के फलस्वरूप समाज-शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया गया। हम इनका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

### १. अशिक्षित वयस्कों की आवश्यकता

हमारे देश में अभी तक अनिवार्य-शिक्षा का पूर्णरूप से प्रसार नहीं हो पाया है। फलस्वरूप अनेकों बच्चे शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वयस्क होने पर भी उन्हें लिखने, पढ़ने तथा सामान्य गणित का कोई ज्ञान नहीं होता है, जिससे उनका मानसिक विकास सदैव के लिये घबड़ता हो जाता है। उनका स्थान समाज में निम्नतर होता है और शिक्षित व्यक्तियों द्वारा उनका अनेक प्रकार से शोषण किया जाता है। भारतीय संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समानता तथा स्वतन्त्रता के समान अधिकार प्रदान किये हैं, परन्तु अशिक्षित वयस्क उनका उपभोग नहीं कर पाते हैं। अशिक्षित वयस्कों की इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समाज-शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाना है।

### २. अर्द्ध-शिक्षित वयस्कों की आवश्यकता

भारत में अनेकों वयस्क ऐसे भी हैं, जिन्हें बाल्यकाल में प्राथमिक कठिनाई तथा अन्य किसी कारणवश अपनी शिक्षा को स्थगित करना पड़ा था। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इन अर्द्ध-शिक्षित वयस्कों को शिक्षित करके उनके मानसिक दृष्टिकोण को विस्तृत किया जाय जिससे कि वे देश के उन्नत नागरिक बन सकें और साथ ही अपने व्यवसाय में अधिक सफल हो सकें।

### ३. पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता

विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा-संस्थाओं में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह व्यक्तियों को जीवन के समस्त क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य करने की योग्यता नहीं प्रदान करती है। हमारे विद्यालयों की शिक्षा के प्रमुख दोष ये हैं कि वह स्वास्थ्य, परिवारिक जीवन तथा अवकाश के सदुपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं देती है। जीवन में प्रवेश करने पर व्यक्ति अनुभव करता है कि उसे इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। समाज-शिक्षा व्यक्तियों को इस आवश्यकता को पूर्ण करती है।

### ४. मनोरंजन की आवश्यकता

प्राधुनिक युग में अन्य देशवासियों के समान भारतीयों की आवश्यकताओं

मे भी वृद्धि हो गई है। वे इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये से लेकर सायंकाल तक किसी न किसी विधि से धन का ध्वनन करते रहते हैं। दिन भर के कठिन परिश्रम के उपरान्त व्यक्तियों में किसी मनोरंजन द्वारा स्वयं को आनन्दित करने की इच्छा का उदय होना स्वाभाविक है। जहाँ तक नगरों का प्रश्न है, वहाँ मनोरंजन के साधनों का अभाव है। परन्तु ग्रामों में उनका सर्वथा अभाव है। समाज-शिक्षा ने वास्तविकता के लिये विविध प्रकार के मनोरंजनों की व्यवस्था करने का भार धारण कर लिया है।

## ५. राजनीतिक आवश्यकता

“आज का समय हमारे देश के लिये पुनर्निर्माण एवं पुनर्निर्माण का, उत्थान एवं विकास का समय है। हमने अपने देश में धर्म निरपेक्ष कल्याणकारी लोकतन्त्र की स्थापना की है। हमें उसे सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाना है, किन्तु यह सब सब तक सम्भव नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी आधारशिला ही मुड़ एवं शक्तिशाली न हो। और यह आधार-शिला है इस देश की बहुसंख्य जनता जिसके ऊपर कि आज राज्य-सरकारों का सुयोग्य निर्वाचन निर्भर है तथा समूचे राष्ट्र के मंगलमय स्वरूप का निर्धारण अवलम्बित है। इस उद्देश्य के लिये आवश्यक है उस शिक्षा की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस उपयुक्त शिक्षा एवं उपयुक्त साहित्य। यद्यपि जिस प्रकार हम अपने सामाजिक-आर्थिक तथा नैतिक-व्यवस्थाओं की शिक्षा-दीक्षा, उनके निमित्त साहित्य को आवश्यक एवं साहित्य के व्यवस्थित निर्माण पर धन देने हैं, उगी प्रकार हमें ध्यान प्रोत्साहित करने की शिक्षा-दीक्षा एवं उनके लिये उपयुक्त एवं व्यापक विधि से साहित्य के सुवन को चिन्ता भी करना होगा।”<sup>१</sup> वास्तव में चिन्ता का भार समाज-शिक्षा ने पूर्ण रूप से धारण कर लिया है।

## ६. सामाजिक आवश्यकता

“समाज सुव्यवस्था के लिये सब से अधिक ज़रूरी है, जो कि सामान्य स्वार्थ, सामान्य भुलाव सामान्य प्रकार का रहन-सहन और सामान्य नैतिक मूल्यों का अभाव की भावना रखता है।”<sup>२</sup> समाज की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, “समाज-शिक्षा की आवश्यकता है।”<sup>३</sup>

1. "Society is the largest relatively permanent group who share common interests, common territory, a common code of law and a common system of language and behaviour." — J. G. Giddens: The Sociology of Man, p. 160.



परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि समाज का एक आवश्यक तत्व सहयोग है। समाज का सम्पूर्ण ढाँचा सहयोग की नींव पर ही खड़ा है। इस सहयोग से ही समाज की रक्षा हो सकती है और उनका निर्माण हो सकता है। समाज में जितनी भी संस्थाएँ, समितियाँ और संगठन होते हैं, उन सभी का अस्तित्व सहयोग पर निर्भर है। सहयोग प्राप्त करके ही वे समाज की प्रगतिशील बनाने में सफल हो सकते हैं। भारतीय समाज में सहयोग की भावना पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। विभिन्न समूहों, संस्थाओं और वर्गों में महान् संघर्ष है; जातीय तथा धार्मिक द्वेष है। फलस्वरूप हमारा समाज जड़ तक हिस गया है। ऐसे समाज को एकता के सूत्र में धाबड़ करने की आवश्यकता का अनुभव करके ही समाज-शिक्षा के कार्य-क्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है।

### ७. धार्मिक आवश्यकता

भारत की अधिवास जनता निर्धन है। नगर-निवासियों की अपेक्षा ग्राम-वासियों की दशा अधिक दयनीय है। उन्हें तन ढकने के लिये पर्याप्त वस्त्र और पेट भरने के लिये पर्याप्त भोजन भी नहीं मसीब होता है। हमारे देश के मस्तक पर निर्धनता की जो कलंक बालिमा लगी हुई है, उसको बिना घोंघ हम प्रगतिशील कहवाने के अधिकारी नहीं हैं। इसी विचार से उत्प्रेरित होकर भारत-सरकार ने करोड़ों निर्धन देशवासियों की धार्मिक उन्नति की ओर ध्यान दिया है और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर समाज-शिक्षा द्वारा उनको विविध प्रकार के कार्यों में प्रशिक्षित करके उनके धार्मिक स्तर को ऊँचा उठाने का निश्चय किया है।

### ८. देश की आवश्यकता

यदि एक देश के व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं, तो उस देश की क्रियात्मक शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है। शक्ति-संचय तथा शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिये शिक्षा की महान् आवश्यकता है। एक शिक्षित व्यक्ति को इस बात का ध्यान नहीं होता है कि उसमें कौन सी शक्तियाँ निहित हैं, और वह उनका उपयोग किस प्रकार कर सकता है। भारत के सम्बन्ध में यह बात अक्षरशः सत्य है। इस विद्याल देश की जन-शक्ति का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर समाज शिक्षा का आयोजन किया गया है।

समाज-शिक्षा द्वारा हमारे देशवासियों तथा देश का जो कल्याण होगा उसको हमारे कबोर के इन शब्दों में अंकित किया जा सकता है : "शिक्षित धर्मिक अधिक उत्साह में योग देंगे और इस प्रकार उद्योग तथा व्यवसाय

दोनों की अधिक उपजति होगी। यह उपजति केवल व्यवसाय तक ही नहीं रहेगी। अधिक शिक्षा के फलस्वरूप राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि होगी। आवश्यक समाज सेवाओं का विस्तार होगा। केवल शिक्षा ही हमारे देशवासी के जीवन के स्तर में उपजति करने के लिये वास्तविक माध्यम का निर्माण कर सकती है। शिक्षा ही मस्तिक तथा चरित्र के प्रशिक्षण की, जिससे व्यक्ति अपने व्यवसाय का निर्माणकारी प्रयोग कर सके, आवश्यक शक्ति है। इस प्रकार केवल समाज-शिक्षा ही वह माध्यम है, जिस पर स्वतंत्र भारत कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर सकता है, जो वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक सुरक्षा की माँगों को स्वीकार करेगा।”

### समाज-शिक्षा की समस्याएँ

समाज-शिक्षा की समस्याएँ शिक्षा के अन्य अवयवों की समस्याओं से अधिक जटिल और अधिक तरल भी हैं। वे अधिक जटिल इसीलिये हैं क्योंकि समाज-शिक्षा का उद्देश्य उन वयस्क पुरुषों तथा स्त्रियों को शिक्षित करना है जो शिक्षा प्राप्त करने की आयु को पार कर चुके हैं। वे अधिक तरल इसलिये हैं क्योंकि हमें इनको बालकों की प्रवृत्ता कम शिक्षा देनी है।

भारत में समाज-शिक्षा की समस्याएँ प्रगतिशील देशों की समस्याओं से भिन्न हैं। अन्य देशों में उन वयस्कों के लिए शिक्षा की योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं, जो अपने बाल्यकाल में अनिवार्य शिक्षा से लाभ उठा कर कुछ शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। भारत में मुख्य रूप से उन वयस्कों को शिक्षित किया जाना है जो किसी प्रकार की भी शिक्षा प्राप्त न करने के कारण पूर्ण रूप से निर-

1. “Educated workers would make for increased production and thus make for increased prosperity for both industry and trade. The benefits would not, however, be confined to business alone. Increased education would lead to an addition in the national wealth and create the basis for an expansion of necessary, social services. Education alone can create the material basis for an improvement in the standard of life of our people. It is also the necessary condition for the training of mind and character which will permit the people to make a creative use of their leisure. Social education is thus the foundation on which alone free India can build up a Welfare State which will recognize the claims of both individual freedom and social security.”—Humayun Kabir : *op. cit.*, p. 96.



की सम्पूर्ण संख्या के साथ से अधिक भारत में निवास करते हैं। ७ के अल्प प्रकाश में भी ताने का कार्य प्रति विद्यालय है।"

## २. पाठ्य-क्रम की समस्या

समाज-शिक्षा की दूसरी समस्या है—पाठ्य-क्रम की। बच्चों के उपयुक्त पाठ्य-क्रम न होने के कारण समाज-शिक्षा के कार्य में भारी पर पड़ रही है। अभी तक इस बात पर मर्तब्यता नहीं हो सकी है कि बच्चों के लिये किस प्रकार का पाठ्य-क्रम सबसे अधिक उपयोगी होगा। जिस पाठ्य-क्रम को बालकों की शिक्षा के लिये प्रयोग किया जाता है, उसे प्रौढ़ों के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको अधिक-विचार, भावदमकताओं और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण नितान्त भिन्न हैं। फिर समस्या प्रौढ़ों के लिये भी समाज पाठ्य-क्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनमें कुछ बिस्मय निराश है, जिनके लिये पहिले प्रसार-ज्ञान की व्यवस्था आवश्यक है; कुछ घट्ट-शिक्षित वयस्क हैं, जिनके लिये कुछ विशिष्ट विषयों के सिद्धान्त की आवश्यकता है और कुछ नवसाधार (Neo-literate) प्रौढ़ हैं, जो बोझ-शिक्षा-तत्त्वज्ञान प्राप्तते हैं तथा जिनमें नागरिकता की भावना का विकास करने के लिये "सम्यक्ता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, नागरिक शासन आदि विषयों का ज्ञान आवश्यक हो जाता है।"

इन कठिनायियों के प्रतिरिक्त पाठ्य-क्रम के निर्धारण में एक कठिनाई—यों है कि बच्चों के प्राथमिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये पाठ्य-क्रम में उद्देश्य केवल प्रौढ़ों को बौद्धिक ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होना चाहिये, बल्कि उनमें किसी कला या कौशल का भी प्रसारण देना चाहिये, जिससे कि वे समाज का सदस्य बन सकें और घन का भी उपयोग कर सकें। पाठ्य-क्रम के निर्माण में घनिष्ठ कठिनाई यह है कि बच्चों में सभी पाठ्य के कुछ और अर्थ हैं। हमारे देश में उन बच्चों तथा प्रौढ़ों को भी प्रौढ़ों को घण्टों में रखा गया है। जिनकी मातृ (२) से १८ वर्ष की है। मोटे तौर पर हम के अनुसार प्रौढ़ों का इस क्रम से रखा गया है—(१) १२ वर्ष से १८ वर्ष तक के प्रौढ़, (२) १८ वर्ष से २२ वर्ष तक के प्रौढ़, और (३) २२ वर्ष से अधिक आयु के प्रौढ़। स्पष्ट है कि इन तीनों वर्ग-वर्ग के प्रौढ़ों में,

1. "More than half the total number of adult illiterates in the world live in India. The work of bringing more light to them is one of tremendous magnitude."

२. श्रीमती राजवर्मा : प्रौढ़ शिक्षा विभाग, कुछ है

मानसिक प्रवृत्तियों, बौद्धिक-स्तरों, अभिरुचियों एवं रुझानों में घन्तर होगा। अतः सभी के लिये समान पाठ्य-क्रम निर्धारित किया जाना उचित न होगा।

इन सब कठिनाइयों ने बयस्कों के लिये पाठ्य-क्रम के संगठन-कार्य को एक जटिल समस्या का रूप दे दिया है।

### १. शिक्षण-पद्धति की समस्या

बयस्कों के लिये उपयुक्त शिक्षण-पद्धति का निर्धारण भी कुछ कम जटिल समस्या नहीं है। इसका कारण यह है कि जीवन तथा संसार के प्रति बयस्कों का दृष्टिकोण समान नहीं होता है। इस बात में वे बच्चों से भिन्न होते हैं। प्रत्येक आयु में दृष्टिकोण का विकास अधिक न होने के कारण प्रायः सभी उम्रों के लिये समान शिक्षण-पद्धति का अनुसरण किया जा सकता है। बयस्कों के लिये ऐसा करना न तो सम्भव ही है और न उचित ही। बयस्कों में 'ग्रहम्' की भावना पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती है। वे अधिक सामाजिक स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैं। उनके अपने कुछ सिद्धान्त होते हैं, उनको अपनी भावों होती हैं, जिनके विरुद्ध वे कार्य नहीं करना चाहते हैं। इन सभी बातों के कारण प्रौढ़ों के लिये उपयोगी शिक्षण-पद्धति का सरलता पूर्वक निश्चय करना सम्भव नहीं है। यदि शिक्षण-पद्धति में कोई भी ऐसा तत्व है, जो उनको अवचिकर प्रतीत होता है अथवा जो उनकी 'ग्रहम्' की भावना, स्वतन्त्रता, सिद्धान्तों तथा भावों से टकराता है, तो शिक्षण-पद्धति का प्रसफल होना अवश्यम्भावी है। यही कारण है कि अभी तक किसी एक पद्धति को बयस्कों के लिये निश्चय नहीं किया जा सका है।

### ४. अध्यापकों की समस्या

प्रौढ़-शिक्षा के अध्यापकों की समस्या समाज-शिक्षा के विस्तार में घड़ंगा बाले हुए है। प्रौढ़-विद्यालयों के लिये उपयुक्त शिक्षकों का अभाव है। जिन अध्यापकों को बयस्क-विद्यालयों में नियुक्त किया जाता है, वे साधारणतया प्राथमिक-विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। उनमें प्रौढ़ों की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है। वे प्रौढ़ों के मनोविज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। वे प्रौढ़ों के लिये उपयुक्त शिक्षण-पद्धतियों में परिचित होते हैं। वे समाज-शिक्षा के उद्देश्यों, तरीकों, आवश्यक साहित्य तथा शिक्षा के उपयोगी साधनों से अवगत नहीं होते हैं। अतः जब उनको प्रौढ़-शिक्षा का भार सौंप दिया जाता है, तब वे उसका दक्षता-पूर्वक संचालन करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। फलस्वरूप बयस्क-शिक्षा का प्रवाह निर्बाध गति से नहीं हो पाता है।

वयस्क-विद्यालयों के लिये उपयुक्त शिक्षकों के अभाव की समस्या पर इससे भी गुरुतर समस्या यह है कि अध्यापकों की वांछित संख्या उत्पन्न है। निरक्षर वयस्कों की अधिकांश संख्या भारतीय ग्रामों में निवास कर शिक्षकों को ग्रामों में जीवन की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि, आवास, रंजन के साधनों आदि की कठिनाइयों का सर्व्व सामना करना पड़ता है। वे ग्रामों में स्थित प्रौढ़-विद्यालयों में 'अध्यापन कार्य' करने के लिये उत्पन्न होते हैं। इन विद्यालयों में अध्यापिकाओं का और भी अधिक अभाव है क्योंकि वे अपने निवास-स्थानों से दूर अपरिचित स्त्रियों के मध्य में, जिन्हें वे स्व शिक्षित होने के कारण असम्यक् और गंवार समझती हैं, अपने जीवन तथा समय को नष्ट नहीं करना चाहती हैं।

#### ५. साहित्य की समस्या

समाज-शिक्षा का उत्तरदायित्व केवल वयस्कों को साक्षर बनाकर समाप्त नहीं हो जाता है। प्रौढ़ों को केवल लिखना, पढ़ना तथा साधारण गणित की शिक्षा दे देना पर्याप्त नहीं है। यदि इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त, वे शिक्षा ग्रहण करने का कार्य समाप्त कर दें, तो वे कुछ समय के पश्चात् फिर निरक्षर हो जायेंगे। अतः यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक ज्ञान उपलब्ध करने के बाद भी नवसाक्षरों के लिये साहित्य हो। "यदि हमारी समस्त जनता पढ़ना-लिखना और जोड़-बाकी तथा गुणा-भाग के सवाल सही-सही लगागा सीख भी लें, तो उससे उसे क्या फायदा होगा ?" "यदि हमारी में तथा सार्वजनिक मंच पर लपफ्राजी करने वालों को उन्हें बेवकूफ बनाने का उतना ही जयादा मसाला और मिल जायगा। इससे न तो उनके मानदण्ड ऊँचे होंगे, न उनकी रुचियों में सुधार होगा और न उनका जीवन ही समृद्ध बनेगा, उनकी सहानुभूति या समझ या सामाजिक चेतना में कोई गहराई नहीं पैदा होगी।" इसलिये नवसाक्षरों के लिये एक ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो उनमें चीजों को परखने की क्षमता, आलोचनात्मक शक्ति तथा सामाजिक भावना का विकास करने में योग्य दे, जिससे कि "वे कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट तथा निकृष्ट के बीच, ज्ञान के क्षेत्र में सच और झूठ के बीच और आचरण के क्षेत्र में भले और बुरे के बीच अन्तर ला सकें।" इस प्रकार के साहित्य का निर्माण एक समस्या है।

१. के० जी० संवरन : शिक्षा की पुनर्रचना, पृ० २११
२. वही

## ६. शिक्षा-साधनों की समस्या

“समाज-शिक्षा के साधनों से तात्पर्य है वे समूह अथवा संस्थाएँ जो समाज-शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क रखती हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं तथा उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं।”<sup>१</sup> प्रौढ़-शिक्षा के इन साधनों के चयन में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ये साधन व्यक्तियों को ज्ञान के प्रति आकृष्ट करने में असफल रहते हैं, तो वे पूर्णतया निरर्थक हो जाते हैं। इन साधनों का विवेकपूर्ण चयन सरल कार्य नहीं है। यही कारण है कि प्रौढ़-मानवविज्ञान में दश व्यक्ति साधनों की समस्याओं को सुलभ करने में व्यस्त हैं।

## ७. धन की समस्या

१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में १२ वर्ष से अधिक आयु के प्रौढ़ों की संख्या लगभग १८.५ करोड़ है। इतने प्रौढ़ों को साक्षर बनाने में कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिये कि एक अध्यापक ३० प्रौढ़ों की ६ मास में साक्षर बना सकता है। इस प्रकार यह ९० प्रौढ़ों को १ वर्ष में पढ़ना-लिखना सिखा सकता है। इस हिसाब से १८.५ करोड़ व्यक्तियों को १ वर्ष में साक्षर बनाने के लिये ३० लाख से अधिक अध्यापकों तथा प्रौढ़-विद्यालयों की आवश्यकता होगी। यदि एक प्रौढ़-विद्यालय का कम से कम व्यय २५० रुपये वार्षिक मान लिया जाय, तो ३० लाख प्रौढ़-विद्यालयों के लिये ७.५ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। सन् १९५६-५७ में भारत की राष्ट्रीय आय ११.३१० करोड़ रुपये प्रांकी गई थी।<sup>२</sup> अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिये धन की एक महान् समस्या है।

## ८. उत्तरदायित्व की समस्या

समाज-शिक्षा की अन्तिम समस्या यह है कि समाज-शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर होना चाहिये—केन्द्रीय सरकार पर, राज्य-सरकारों पर, शिक्षा-विभागों पर, शिक्षा परिषदों पर अथवा सार्वजनिक शिक्षा-संस्थाओं पर। केन्द्रीय सरकार ने इस उत्तरदायित्व को राज्य-सरकारों पर रखा है और इस प्रकार

1. “By agencies of social education is meant the bodies or institutions which ‘deliver the goods’ which contact the ‘consumers’ of social education and satisfy their needs.” *Teachers’ Handbook of Social Education*, p. 66.
2. भारत १९६०, पृ० १३१

घरने को समाज-शिक्षा के भार से मुक्त रखने का प्रयास किया है। पर इन्हीं समाज-शिक्षा की महान् समस्या का समाधान होना सम्भव नहीं प्रतीत होता है।

## समस्याओं का समाधान

समाज-शिक्षा की जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया है, उनके समाधान के लिये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दाव नीचे दिये जा रहे हैं :

### १. निरक्षरता का उन्मूलन

यद्यपि ८३.४ प्रतिशत बयस्कों की निरक्षरता का उन्मूलन कोई सरल कार्य नहीं है, फिर भी कुछ उपायों का सहारा लेकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। हम इस समस्या पर विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कि हम उनको संस्कृति तथा मानवता के उच्च शिखर पर आसीन करने के स्वर्णिम स्वप्नों को देखना बन्द कर दें और इस बात के लिये कटिबद्ध हो जायें कि हमें अल्प अवधि में उनको साक्षर बनाना है। साथ ही हमें केवल उनके अक्षर ज्ञान पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, न कि उनके मिथ्या तथा साधारण गणित की शोषणा पर। "लिखने-पढ़ने और साधारण गणित के साधारण तथ्यों में भी पढ़ने का स्थान सर्वोपरि है।" बयस्कों में पढ़ने का ज्ञान उत्पन्न करने के लिये हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी ऐसी विधि का प्रयोग करें जो वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण हो, परन्तु हमें ऐसी विधि को अपनाया चाहिये जिससे सीधे ही उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकें।

इस प्रकार की एक विधि की खोज अमेरिका के एक विद्यार्थी, फ्रैंक डॉक लाबैक (Dr. Frank Laubach) ने डिजिटल डीर मनुष्य के घोर अंधापन (Moros) के लोगों को शिक्षित करने के लिये अपनाई की। उन्होंने पढ़िये उन पत्रों का एक छोटा सा पुस्तक जो कि निरक्षर प्रसारित की जा रही है। और उन्होंने कुछ अन्य और लिये और उनको सहायता में राज्य का निवास किया। इस प्रकार उन्होंने आठों की सहायता में अनेक बच्चों को एक दिन में १० अक्षरों का ज्ञान करा दिया। अनेक बच्चों को दिवस-पढ़ना योग्य बनाया, कई बच्चों को पढ़ाया कि बच्चों को पढ़ाने की ११३ बच्चों का।

लेकर अपने परिवार के बच्चों तथा पड़ोसियों को पढ़ाने की ११३ बच्चों का।

पत्रों में बताया (Laubach) १९२० के १२०,००० बच्चों के ३०,०००

1. "Reading is the first requirement even among the  
Lancashire R's" - Quoted from Dr. Frank Laubach  
Speech at the British Educational Conference held at London  
on 21 & 22 October, 1920.



को न केवल पढ़ने भविष्य लिखने का भी ज्ञान करा दिया गया।<sup>१</sup>

डा० लॉबक ने १९३५, १९३७ तथा १९३८ में भारत प्यार कर मराठी, तेलगू, बंगला, हिन्दी, तामिल और गुजराती भाषाओं की अपनी विधि के द्वारा शिक्षा देने के मायों का प्रदर्शन किया। पंजाब में मोवा के मिशनरियों ने इस विधि को ग्रहण कर पर्याप्त सफलता प्राप्त की। दुख है कि इस विधि का परोक्ष रूप भारत के अन्य भागों में नहीं किया गया। हमें विश्वास है कि यदि भारत-सरकार डा० लॉबक द्वारा निर्मित विधि का अनुसरण करे, तो अल्प समय में ही भारत के जन-जन को साक्षर बनाया जा सकता है।

अभी तक सरकार ने बयस्को की विद्या के प्रसार की विद्या में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सैयदैन (Saiyidain) ने उचित ही लिखा है : "जो कुछ हम अभी तक नहीं कर पाये हैं, उसमें सबसे पहिले तो यह स्पष्ट सत्य हमारे सामने है कि भाषा की दृष्टि से अभी तक जो कुछ किया गया है, वह बहुत ही थोड़ा है। हमारे लगभग ५५% देशवासी न तो छोटी हुई पुस्तक का एक भी पृष्ठ पढ़ सकते हैं, न वे मतदान की पर्ची पर समझदायी के साथ निशान लगा सकते हैं और न ही रोजमर्रा के छोटे-छोटे हिसाब लगा सकते हैं। अगर संसार का एक ऐसा मानचित्र बनाया जाय, जिसमें साक्षरता की स्थिति दिखाई जाय और पृथ्वी के निरक्षर इलाकों को काला रंग जाय, तो भारत उस मानचित्र में एक अन्धकार पूर्ण महाद्वीप जैसा दिखाई देगा और यह हमारे लिये बड़ी लज्जा की बात है।"<sup>२</sup> स्पष्ट रूप से निरक्षरता का उन्मूलन करने का दायित्व सरकार पर है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार या तो डा० लॉबक की सफल विधि को अपना किसी अन्य उपाय को अपनाकर देश की जनता को निरक्षरता के गर्त के निकाले।

## २. उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण

उपयुक्त पाठ्य-क्रम का निर्धारण, निरक्षर, अर्द्ध-साक्षर तथा नवसाक्षरों और विभिन्न वय-वर्ग के बयस्कों की आवश्यकताओं का सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरान्त ही किया जा सकता है, क्योंकि समाज-शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता का प्रसार करना ही नहीं है, भविष्य बयस्कों का सर्वांगीण विकास भी करना है। अतः पाठ्य-क्रम में उन समस्त विषयों को स्थान देना होगा, जिनसे कि उनका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास भी हो सके। विषयों को निर्धारित करते समय बयस्कों की अभिरक्षियों

1. T. N. Siqueria : *Modern Indian Education*, p. 162.

२. के० जी० सैयदैन : शिक्षा की पुनर्रचना, पृष्ठ १८५

मानसिक प्रवृत्तियों, बौद्धिक स्तरों तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं के अनुसार एक नहीं अपितु अनेक पाठ्य-क्रमों का संगठन करना पड़ेगा, जिससे कि सभी वर्गों के बच्चों के जीवन का पूर्ण विकास किया जा सके। यद्यपि पाठ्य-क्रम विभिन्न होंगे, पर उनके विषय साधारणतः समान होंगे और बच्चों के बौद्धिक विकास के आधार पर उनका अल्प, गहन अथवा विस्तृत अध्ययन आवश्यक होगा।

उपरिर्कथित तत्त्वों को ध्यान में रखकर किस प्रकार पाठ्य-क्रम का निर्माण किया जाय और उसमें किन विषयों को स्थान दिया जाय, यही हम बात पर विचार कर लेना मुक्तिसंगत होगा।

उचित तो यह होगा कि पाठ्य-क्रम के निर्माणकर्ता किसी ऐसे देश के पाठ्य-क्रम को अपना आदर्श मान लें, जिसमें निवान करने वाले बच्चे प्रायः उसी परिस्थितियों में हों, जिनमें भारतीय हैं। हम दृष्टि से दो देशों के पाठ्य-क्रमों को आदर्श रूप में स्वीकार किया जा सकता है—डेन्मार्क और चीन।

डेन्मार्क के 'पीपुल्स हाई स्कूल' (People's High School in Denmark) का पाठ्य-क्रम भारत के लिये उपयुक्त होगा, क्योंकि हमारा देश डेन्मार्क से समान एक निर्धन तथा इति-प्रधान देश है। वहाँ पुरुषों को छोट नालों में मासों में और स्त्रियों को प्रौढ नालों में शिक्षा दी जाती है। उन्हें अध्ययन समाप्त करने पर किसी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना पड़ता है। प्रत्येक बच्चा में अध्ययन का कार्य किसी परम्परागत चीज से प्रारम्भ होता है। इस चीज का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को राष्ट्रीय भावना से परिचित करना होता है। प्रथम चरण में इतिहास का शिक्षण व्यावहारिक रूप में, कि वह देश-निक होंगे दिया जाता है। इस विषय का शिक्षण करते समय बच्चों को आवश्यकताओं तथा देश की परम्पराओं का उल्लेख किया जाता है। दूसरे चरण में ध्यान को आकर्षित होती है। तीसरे चरण में विज्ञानों शिक्षण में प्रथम चरण में ही और वह उनके ऊपर होता है। मध्यम चरण में भौतिक विज्ञान तथा रसायन-विज्ञान का शिक्षण दिया जाता है। चौथे चरण में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का शिक्षण दिया जाता है।

दूसरे चरण में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का शिक्षण दिया जाता है। तीसरे चरण में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का शिक्षण दिया जाता है। चौथे चरण में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का शिक्षण दिया जाता है।

T. N. S. 102 : 102 : 102 : 102 : 102

ज्ञान, पढ़ना लिखना, नागरिक शास्त्र, गणित, संगीत, चित्रकला, इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि, इंजिनियरिंग, वाणिज्य तथा राष्ट्रीयता, प्रजा-तन्त्र और सामाजिक न्याय। इनके अतिरिक्त प्रौढ़-विद्यालयों में स्व-शासन, वृक्षारोपण, सड़क-निर्माण, बाँध निर्माण, सहकारी समितियों की स्थापना तथा व्यायाम की भी शिक्षा प्रदान की जाती है। "इस प्रकार चीन में प्रौढ़-शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध तथा उसको पूर्ण करने वाली हो नहीं हो गई है, अपितु सामाजिक तथा राष्ट्रीय पुनर्रचना का साधन भी हो गई है।" प्रौढ़-शिक्षा का ऐसा पाठ्य-क्रम भारत के लिये भी हितकर सिद्ध हो सकता है।

यदि किन्हीं कारणों वश हमारे देश के नेता तथा शिक्षा-विद्वद् बेमार्क एवं चीन के पाठ्य-क्रमों को आदर्श मान कर भारतीय बयस्कों के लिये पाठ्य-क्रम का संगठन करने के लिये उद्यत नहीं है, तो एक अन्य उपयुक्त पाठ्य-क्रम का सुझाव प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु यही पक्ष बता देना आवश्यक है कि केवल साक्षरता को पाठ्य-क्रम का ध्येय निर्धारित न किया। "साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त है, और न प्रारम्भ; यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्यों तथा स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है।" १

बयस्क-शिक्षा के पाठ्य-क्रम में सर्व प्रथम स्थान पढ़ने और लिखने को दिया जाय। जब बयस्क इनका पर्याप्त ज्ञान उपलब्ध कर लें, तब उनके लिए मानु-माया, गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ग्राम-शास्त्र, भूगोल, कृषि, पशु-पालन सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, साहित्य, प्रारम्भिक बिक्रिस्ता तथा व्यायाम की शिक्षा की व्यवस्था की जाय। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इन विषयों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाय। बयस्कों के लाभार्थ सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रौढ़-विद्यालयों में बयस्कों के व्यवसायों तथा उनके लिये लाभप्रद विषयों पर व्याख्यानो की आयोजना की जाय। प्रत्येक बयस्क को किसी कला-कौशल में अवश्य प्रशिक्षित कर दिया जिससे कि वह उसको अपनी आय-वृद्धि का साधन बना सके।

1. "Adult education in China has thus become not only a continuation and completion of elementary education but also a means of social and national regeneration," T. N. Siqueria : *op. cit*, p. 166.
2. "Literacy is not the end of education, nor even the beginning. It is only one of the means whereby men and women can be educated." Mahatma Ghandhi's Article in *Harijan*, 31 July, 1937.

### ३. उपयुक्त शिक्षण-पद्धति का निर्धारण

बच्चों के लिये उपयुक्त शिक्षण-पद्धति का निर्धारण करने के लिये उनके मनोविज्ञान का गूढ़म अध्ययन किया जाना आवश्यक है। शिक्षण-पद्धति ऐसी हो जो उन्हें रुचिकर प्रतीत हो तथा उनको शिक्षा-ग्रहण करने के लिये प्रार्थित कर सके। हमारे देश के शिक्षा-विचारद्वन्द्व इन दिशा में यथेष्ट रूप से सक्रिय हैं और उन्होंने कुछ उपयुक्त शिक्षण-पद्धतियों को खोज भी निकाला है। इनका तथा कुछ अन्य पद्धतियों का विवरण निम्नांकित पंक्तियों में दे रहे हैं।

(१) **बर्ण-परिचय पद्धति**—इस पद्धति में सबसे पहिले धर्मों का ज्ञा कराया जाता है। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में इसी पद्धति का प्रचलन है।

(२) **वाक्य-पद्धति**—इस पद्धति में पहिले दो शब्दों का ज्ञान एक साथ कराया जाता है और फिर उनको संयुक्त करके विभिन्न वाक्यों का रूप दिया जाता है; उदाहरण के लिये 'मा' और 'मा' शब्दों को ले लीजिये। इनसे बनने वाले वाक्य इस प्रकार हो सकते हैं—“मा मा, मा मा, मा मा मा, मा मा मा”

(३) **लांबर्क (Laubach) की पद्धति**—लांबर्क नामक एक धर्मप्रेमी मिस-नरी ने विश्व के समस्त एक नवीन वाक्य-पद्धति प्रस्तुत की है। इसमें साधारण बोल-चाल के कुछ शब्दों को लेकर चार्टों की सहायता से सम्पूर्ण वाक्यों की शिक्षा दी जाती है। (देखिये 'निरक्षरता का उन्मूलन')।

(४) **कहानी-पद्धति**—इस पद्धति को निकालने का श्रेय श्री संगमलाल धर्मवाल को है। इसमें धर्मो की बनावट पर कुछ कहानियाँ लिखकर धर्म-ज्ञान कराया जाता है।

(५) **सरस शब्द-पद्धति**—यह पद्धति श्री 'परिक' की है। इसमें गीतों की प्रधानता दी गई है। पहिले उनको गाया जाता है और फिर चार्ट में देखकर उनको पहिचाना और याद किया जाता है। उदाहरणार्थ, “कलम से पढ़ेंगे, कलम से लिखेंगे, कलम से जियेंगे, कलम से बढ़ेंगे।”

सभी इन पद्धतियों के समर्थक हैं और सभी इन पद्धतियों को प्रौढ़ों के लिये उपयुक्त बताते हैं। परन्तु इनमें से किसी भी पद्धति को अपनाते समय यह आवश्यक है कि भारतीय भाषाओं के धर्मो को कुछ सरल बना दिया जाय जिससे कि बच्चों को उन्हें पहिचानने, समझने और लिखने में सुविधा हो। एक अन्य सुझाव यह भी है कि सभी भारतीय भाषाओं के लिये रोमन लिपि का प्रयोग किया जाय। इससे हमारे देश के निवासी अपनी भाषाओं के प्रयोग योरोपीय भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और भाषाओं की भ्रष्टता के कारण देश की एकता में जो बाधा उपस्थित हो रही है, उसका भी

घन्त हो जायगा। कमाल अतातुर्क (Kemal Ataturk) ने टर्की में रोमन अक्षरों का प्रयोग करके अपने देशवासियों की अज्ञानता का निवारण किया था तथा उनको एकता के सूत्र में बाँध दिया था।

#### ४. अध्यापकों की पूर्ति

आवश्यक योग्यताओं-युक्त अध्यापकों की वाञ्छित संख्या प्राप्त करने की समस्या वस्तुतः कठिन है, पर निरन्तर तथा दृढ़ प्रयास द्वारा इस समस्या पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस दिशा में सर्वप्रथम कार्य यह है कि प्रौढ़-विद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों को प्रौढ़-शिक्षा की विधियों और प्रौढ़ों के मनोविज्ञान में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाय। इसके प्रति-रिक्त ग्रामों के प्रौढ़-विद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों को कृषि, पशु-पालन, कुटीर उद्योगों, प्रारम्भिक चिकित्सा, स्वास्थ्य-विज्ञान, कढ़ाई और बुनाई का समुचित ज्ञान करा दिया जाय ताकि ग्रामीण वयस्क उस ज्ञान से लाभान्वित किये जा सकें।

प्रौढ़-विद्यालयों के लिये उपयुक्त शिक्षकों की पूर्ति करने में समय लगेगा। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जब तक उपयुक्त शिक्षकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध न हो जाय, तब तक समाज-शिक्षा के कार्य को स्थगित कर दिया जाय। ऐसा करना वयस्कों और देश के लिये हितकर न होगा। अतः इस अन्तः-कात्सीन समय में स्वयं सेवकों को प्रौढ़-विद्यालयों में अध्यापन-कार्य करने के लिये आमंत्रित किया जाय। महात्मा गांधी के पथ-प्रदर्शन में अध्यापन दिने के ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देने का कार्य स्वयं सेवकों द्वारा सुचारु रूप से सम्पन्न किया गया था।<sup>१</sup> उस आदर्श को प्रौढ़ों को शिक्षा देने के लिये भी अपनाया जा सकता है। यदि शिक्षा-संस्थानों के अध्यापक तथा विद्यार्थी, कार्यलयों के कर्मचारी, एन० सी० सी० तथा ए० सी० सी० के सदस्य, बालक तथा बाल-चारिकार्य और अन्य निस्वार्थ समाज-सेवी राष्ट्रपिता और उनके स्वयं सेवकों के उदाहरण से अनुप्राणित होकर "हर एक पढ़ाये एक" (Each one, Teach one) को अपना सिद्धान्त बना लें, तो प्रौढ़-विद्यालयों के लिये अन्तरिम काल में शिक्षक भी उपलब्ध हो जायेंगे, और अज्ञानान्धकार की जो धारा वयस्कों के मध्य से होकर प्रवाहित हो रही है, उसका रूप भी सरलता पूर्वक परिवर्तित किया जा सकेगा।

१. महात्मा गांधी : 'सत्य के प्रयोग और आत्मकथा', अनुवादक हरिभाऊ उपाध्याय, पृष्ठ ५२५-५२६



सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की "नवसाक्षरो-पयोगी साहित्य निर्माण-गोष्ठी" ने जो सुझाव दिये हैं, वे अप्रकट हैं—(१) वर्णन-प्रधान गद्य, (२) काव्य, लोकगीत एवं पहेलियाँ, (३) नाटक, प्रहसन तथा संवाद, (४) कथा-कहानी, (५) पत्र तथा दैनिकी, (६) विनोद वार्ता, (७) वचन।

उपरिलिखित शिक्षा-साधनों की उपादेयता पर शंका नहीं की जा सकती है, परन्तु हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इन साधनों का प्रमुख उद्देश्य केवल बयस्कों का बौद्धिक विकास करना है। यदि समाज-शिक्षा का कार्य यही तक सीमित रहेगा, तो बयस्कों के जीवन का सर्वाङ्गीण विकास करना सम्भव नहीं होगा और सर्वाङ्गीण विकास करना ही समाज-शिक्षा का प्रधान लक्ष्य है। अतः बयस्कों को शिक्षा देने के लिये अन्य साधनों को भी प्रयोग करना होगा। इनमें से जो पर्याप्त रूप से प्रभावोत्पादक सिद्ध हो सकते हैं, वे अप्रलक्षित हैं—श्रव्य-दृश्य साधन (Audio-Visual Aids), रेडियो, सिनेमा, ग्रामोफोन, नाटक, सामूहिक गीत तथा नृत्य, साहित्यिक तथा वाद-विवाद गोष्ठियाँ, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि। केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय ने श्रव्य-दृश्य साधनों के प्रयोग को विशेष रूप से अपनाया है।

### ७. धनभाव केवल एक बहाना

प्रायः यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि हमारे निर्धन देश के पास निरक्षर बयस्कों की १८-५ करोड़ की विद्याल संख्या को साक्षर बनाने के लिये धन नहीं उपलब्ध हो सकता है। के० जी० सैयद ने इस तर्क को तिरस्कृत करते हुए लिखते हैं : "वास्तव में केवल एक ही प्रकार की दरिद्रता होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है और वह होती है 'उत्साह की दरिद्रता', यदि हम गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न करें तो अन्य सभी प्रकार की दरिद्रताएँ दूर की जा सकती हैं। यह एक बहुत पिली-पिटो बात है, फिर भी मैं उसे दोहराना चाहूँगा कि इसी 'निर्धन' देश ने एक ऐसे युद्ध के लिये जिसे छेड़ने में उसका कोई हाथ नहीं था, करोड़ों रुपये खर्च कर दिये थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए इस बात का क्या कारण हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, जो दान्ति और मानवीय गुणों का मूल आधार है, इतना ही बड़ा प्रयास न किया जा सके? मेरा विश्वास है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बड़ी-बड़ी समस्याओं को सङ्कुचित वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये। मेरी राय में समस्या पर विचार करने का सही तरीका यह नहीं है कि हम एक अच्छी शिक्षा-व्यवस्था का या एक अच्छी स्वास्थ्य नीति चलाने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते बल्कि हमें इस तरह सोचना चाहिये कि इन 'थीवों' के बिना क्या हमारा काम चल सकता है।'

## ५. उपयुक्त साहित्य का निर्माण

उपयुक्त साहित्य के अभाव के कारण समाज-शिक्षा का कार्य साक्षरता के स्तर पर और घटन व्यापक धर्म में प्रति मन्द गति से चल रहा है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि ऐसी पुस्तको, चाटों, समाचार-पत्रों, मासिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं, चित्रों आदि की व्यवस्था की जाय, जो बच्चों को रुचि के अनुकूल हो। इस कार्य की विद्वान् लेखकों की सहायता से पूर्ण किया जा सकता है। इस हेतु उन्हें बचस्को के लिये उपयुक्त पुस्तको तथा पुस्तिकाओं की रचना करने के लिये प्रत्येक सम्भव विधि से प्रोत्साहित किया जान। विश-पूर्ण समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ प्रकाशित की जायँ। एक ऐसी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाय, जिसमें धर्म, स्वास्थ्य, कृषि तथा विविध से सम्बन्धित समाचार हों, क्योंकि नवमासरो के लिये इस प्रकार की पत्रिका की आवश्यकता है। हमारे देश की भाषा सभी राज्य सरकारें इस दिशा में क्रियाशील हैं।

श्री ३ तथा नवमासरो के लिये साहित्य के निर्माण के सम्बन्ध में उत्तर-प्रदेश की "नवमासरोयोगी साहित्य निर्माण गोष्ठी की घोषणा" में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं। उसमें उल्लेख किया गया है कि इस साहित्य का निर्माण करान समय पर चारों का ध्यान रखा जान—(१) समाज-शिक्षा के उद्देश्य, (२) धानु-भेद, (३) निच-भेद, (४) क्षेत्र-भेद, और (५) भाषा तथा आवश्यकता।

## ६. शिक्षा के उपयुक्त साधन

श्री ३ को लान प्रदान करने के निच विविध प्रकार के उपयुक्त साधनो के

1. "The work of Social Education is greatly handicapped—both at its Literacy stage and in its wider sense—by the paucity of suitable reading materials, graded to appeal to the adults. There is urgent need for producing large number of booklets, folders, charts, journals, newspapers, wall papers and other illustrated materials which will capture the adults' interest"—K. Q. Sreenivasan, *Report of the Joint Meeting of the Central Advisory Board of Education in India, Appendix C (d)*
2. *Four Years' Indian Education, p. 14*
3. *Report of the Literacy Workshop in the Production of Literature for Nandapuram, 1946*



सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की "नवसाक्षरो-पयोगी साहित्य निर्माण-गोष्ठी" ने जो सुझाव दिये हैं, वे अप्राकृतिक हैं—(१) वर्णन-प्रधान पद्य, (२) काव्य, लोकगीत एवं पहेलियाँ, (३) नाटक, प्रहसन तथा संवाद, (४) कथा-कहानी, (५) पत्र तथा दैनिकी, (६) विनोद वार्ता, (७) वचन।

उपरिलिखित शिक्षा-साधनों की उपादेयता पर संका नहीं की जा सकती है, परन्तु हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इन साधनों का प्रमुख उद्देश्य केवल बयस्कों का बौद्धिक विकास करना है। यदि समाज-शिक्षा का कार्य यही तक सीमित रहेगा, तो बयस्कों के जीवन का सर्वाङ्गीण विकास करना सम्भव नहीं होगा और सर्वाङ्गीण विकास करना ही समाज-शिक्षा का प्रधान लक्ष्य है। अतः बयस्कों को शिक्षा देने के लिये अन्य साधनों को भी प्रयोग करना होगा। इनमें से जो पर्याप्त रूप से प्रभावोत्पादक सिद्ध हो सकते हैं, वे अप्रलिखित हैं—श्रव्य-दृश्य साधन (Audio-Visual Aids), रेडियो, सिनेमा, फामोफोन, नाटक, सामूहिक गीत तथा नृत्य, साहित्यिक तथा वाद-विवाद मोष्ठियाँ, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि। केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय ने श्रव्य-दृश्य साधनों के प्रयोग को विशेष रूप से धननाया है।

### ७. धनाभाव केवल एक बहाना

प्रायः यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि हमारे निर्धन देश के पास निरक्षर बयस्कों की १८-२ करोड़ की विशाल संख्या को साक्षर बनाने के लिये धन नहीं उपलब्ध हो सकता है। के० जी० सैयदैन इस तर्क को तिरस्कृत करते हुए लिखते हैं: "वास्तव में केवल एक ही प्रकार की दरिद्रता होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है और वह होती है 'उत्साह की दरिद्रता', यदि हम गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न करें तो धन्य सभी प्रकार की दरिद्रतायें दूर का जा सकती हैं। यह एक बहुत पिली-पिली बात है, फिर भी मैं उसे दोहराना चाहूँगा कि इसी 'निर्धन' देश ने एक ऐसे युद्ध के लिये जिसे छेड़ने में उसका कोई हान नहीं था, करोड़ों रुपये खर्च कर दिये थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए इस बात का क्या कारण हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, जो शान्ति और मान-वीर्य गुणों का मूल आधार है, इतना ही बड़ा प्रयास न किया जा सके? मेरा विश्वास है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बड़ी-बड़ी समस्याओं को संकुचित वित्तीय दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये। मेरी राय में समस्या पर विचार करने का ठही तरीका यह नहीं है कि हम एक अच्छी शिक्षा-व्यवस्था का या एक अच्छी स्वास्थ्य नीति चलाने का खर्च बर्बाद नहीं कर सकते बल्कि हमें इस तरह सोचना चाहिये कि इन 'बीजों' के बिना क्या हमारा काम चल सकता है।"

यदि इस बात को स्वीकार किया जाता है कि कोई भी देश बहुत बड़ी हद तक प्रस्वस्थ और जाहिल और सांस्कृतिक दृष्टि से दरिद्र नहीं रह सकता है, तो इसके लिये धन जुटाना सरकार, वित्त-विभाग और राष्ट्रीय धर्मतंत्र की योजना बनाने वालों की जिम्मेदारी है।”

#### ८. समुक्त उत्तरदायित्व

समाज-शिक्षा की महात्न समस्या का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारों अथवा किसी अन्य सस्था पर नहीं रखा जा सकता है। इसका उत्तरदायित्व तो राज्य, विभिन्न सस्थाओं तथा इस देश के निवासियों को समुक्त रूप से अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा। “प्रत्यक्ष रूप से यह एक ऐसा उत्तरदायित्व है, जिसे न तो शिक्षा-विभाग ही पूर्ण कर सकता है और न सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था ही। इसके लिये सरकारी एवं गैरसरकारी सभी सस्थाओं तथा सद्भावना और सामाजिक चेतन रखने वाले उन सभी व्यक्तियों के मध्य, जो भारत का कल्याण चाहते हैं, प्रतिष्ठतम एवं हादिक सहयोग आवश्यक है। सभी हमारे समक्ष इतना और इतने विविध प्रकार का कार्य करने को पड़ा है कि जो भी इस सेवा-दल में सम्मिलित होना चाहे, उसके लिये इसमें स्थान है—बाल, शिक्षक, धनी व्यक्ति, राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक, श्रमिक, शिल्पी, व्यवसायों में कार्य करने वाले मनुष्य, सभी के लिये।”

उपरिक्त विषय-वस्तु का पर्वक्षण करके हम निस्संकोच भाव से कह सकते हैं कि समाज शिक्षा की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज-शिक्षा के प्रसार के प्रति ठोस-ढाला या सकुचित दृष्टिकोण बाला रबैया न अपना कर उत्साह और धादश-वादिता की लहर के सहारे अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास करें।

१. के० जी० संपर्न : शिक्षा की पुनर्रचना, पृष्ठ १८६-१९०
२. It is obviously a responsibility which neither the Education Department nor the Government machinery as a whole can take on by itself; it needs the closer and most cordial co-operation of all agencies, official and non-official and of all individuals of goodwill and social sense who are interested in the welfare of India. There is so much work to be done and it is of such varied kinds that there is scope for everyone who cares to join the cavalcade of service—students, teachers, men of leisure, political leaders, writers, labourers, craftsmen, professional men, everybody.”—K. G. Saigaldan : *op. cit.*, p. 247.

## प्रौढ़ तथा समाज-शिक्षा का इतिहास

[ समाज-शिक्षा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पूर्व हमें यह स्मरण रखना आवश्यक है कि १९४६ से जिसे हम समाज-शिक्षा कहते हैं, उसे उस समय से पूर्व प्रौढ़-शिक्षा की संज्ञा दी जाती थी । ]

बीसवीं शताब्दी के उषा-काल में भारतीयों ने एक नवीन युग में प्रवेश किया था । राष्ट्रीय आन्दोलन ने जन-जन के अन्तर में स्वदेश-प्रेम की भावना को प्रस्फुटित कर दिया था । देश के कर्मठ नेताओं ने विदेशी सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा की माँग की थी । वे अपने शासकों को देश के प्रत्येक कोने में शिक्षा का प्रसार करने के लिये विवश कर रहे थे । उन्होंने न केवल बच्चों अपितु प्रौढ़ों को भी ज्ञान से आलोकित करने का निश्चय किया था । फलस्वरूप १९१० से ही यज्ञ-तन्त्र प्रौढ़-शिक्षा के लिये प्रयास प्रारम्भ हो गये थे । परन्तु १९२१ तक प्रौढ़-शिक्षा के प्रसार के लिये किसी निश्चित योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया था । इसी आधार पर हम प्रौढ़-शिक्षा के इतिहास का विहंगावलोकन करेंगे ।

### १९२१ से पूर्व प्रौढ़-शिक्षा

१९२१ से पूर्व प्रौढ़-शिक्षा के लिये किये गये प्रयास प्रायः नगण्य थे । निस्सन्देह कुछ राजि-विद्यालयों का देश के विभिन्न भागों में निर्माण किया गया था, परन्तु इनका उद्देश्य फ़ैक्ट्रियों आदि में कार्य करने वाले उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना था, जिन्हें दिन में अध्ययन करने के लिये समय नहीं मिलता था । कुछ ब्यस्क भी उनमें शिक्षा ग्रहण करते थे, परन्तु विद्यालयों का प्रमुख ध्येय उन्हें शिक्षा देना नहीं था ।

भारतीय शिक्षा-प्रयोग ( Indian Education Commission ) की रिपोर्ट के अनुसार बम्बई प्रान्त में १८८१-८२ में १३४ वर्नाक्यूलर राजि-विद्यालय थे, जिनमें ३,९१६ छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इनके अनिरिक्त दिवा-विद्यालयों (Day Schools) से सम्बद्ध २२३ राजि-विद्यालय थे, जिनमें ४,६६२ ब्यस्क उपस्थित थे । इन ब्यस्क-विद्यालयों में साधारण लिखना, पढ़ना और अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी । इन विद्यालयों की लोकप्रियता एवं माँग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी । इनकी सफलता देखकर प्रायोग ने विकारित की कि देश में सभी सम्भव स्थानों पर राजि-विद्यालयों का संचालन किया जाय । परन्तु दुर्भाग्यवश इस ओर रंज मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया और ब्यस्क-साक्षरता की प्रगति न हो सकी । यदि सरकार ने प्रायोग का

गुभाय स्वीकार करके प्रगल्भता रात्रि-विद्यालय स्थापित कर दिये होते, तो आज यह देश निरक्षरता की कालिमा से मुक्त होता।

१९०१-०२ में केवल मद्रास, बम्बई और बंगाल में रात्रि-विद्यालय संघालित थे, जिनमें प्रौढ़-शिक्षा का प्रबन्ध था। परन्तु सरकार की उपेक्षा के फलस्वरूप ये परिपक्वित्व न हो सके और १९१७ तक इनकी संख्या में निरन्तर ह्रास होता चला गया।

१९१९ ने 'भारत-सरकार-प्रधिनियम' (Government of India Act) द्वारा भारतीयों को प्रति विद्यालय जनसंख्या में मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया। अतः प्रौढ़-शिक्षा में जन-साधारण की रुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के अभाव में भारतीय अपने मताधिकार का उचित उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस परिवर्तित दृष्टिकोण ने परिणामस्वरूप देश में बयस्क-साक्षरता के लिये क्रियात्मक पथ उठाये गये। सरकार ने भी प्राथमिक सहायता देकर इन पुनीत कार्य में योग दिया। परिणामतः संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बम्बई, मध्य प्रान्त, बंगाल और मद्रास में रात्रि-विद्यालयों तथा रात्रि-कक्षाओं का आयोजन किया गया।

१९२१ से १९३७ तक

इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी प्रौढ़-शिक्षा की योजना को कार्यान्वित करना। इसका श्रेय भारतीय मंत्रियों को है, जिन्होंने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारम्भ किया। यद्यपि उनके प्रयास अनियमित एवं अपर्याप्त थे, फिर भी उन्होंने अपने देशवासियों और सरकार को ऐसे क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुप्राणित किया, जहाँ शिक्षा-प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता थी।

१९२१ में 'भारत-सरकार-प्रधिनियम' कार्यान्वित कर दिया गया और हस्तान्तरित विषयों को जन-प्रिय मंत्रालयों के हाथों में सौंप दिया गया। शिक्षा भी एक हस्तान्तरित विषय था। भारतीय मंत्रियों ने प्रौढ़-शिक्षा की समस्या में अत्यधिक रुचि व्यक्त की। फलस्वरूप १९२७ तक भारत के विभिन्न प्रांतों में बयस्क-साक्षरता को लोकप्रिय बनाने के लिये अनवरत परिश्रम किया गया। १९२७ तक सम्पूर्ण भारत में ११,११८ स्कूल और कक्षाएँ पुरुषों के लिये तथा ४७ छियों के लिये संचालित की जा चुकी थीं। इनमें पुरुषों एवं छियों की संख्या क्रमशः २८६,००१ और १,३५१ थी। परन्तु प्रौढ़-शिक्षा ने समतल घरातल पर अपना अभियान प्रारम्भ किया ही था कि १९२० के विश्वव्यापी प्राथमिक संकट ने उसके मार्ग को अवरोध कर दिया। यथानाव में

वयस्क-साक्षरता की ओर से सरकार और जनता दोनों ने मुँह मोड़ लिया। फलतः प्रौढ़-विद्यालयों की संख्या क्षीण होती चली गई। १९३७ में इस प्रकार के पुरुष-विद्यालयों की संख्या २,०१६ और स्त्री-विद्यालयों की ११ रह गई। उनमें क्रमशः ६२,६६१ पुरुषों तथा ६४६ स्त्रियों को साक्षर बनाया जा रहा था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि १९३७ तक प्रौढ़-शिक्षा के लिये जो चेष्टायें की गईं, उनका कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला। परन्तु यह बात सर्वमान्य है कि उन चेष्टाओं ने वयस्क-शिक्षा की नींव डाल दी और उसी नींव पर उपयुक्त परिस्थितियों के उत्तर में हो जाने पर प्रौढ़-शिक्षा के भवन का निर्माण किया गया, जिसकी छाया में असंख्य निरक्षर वयस्क साक्षर बन कर देश के बुद्धिमान नागरिक और समाज के सामप्रद सदस्य बन सके।

### १९३७ से १९४७ तक

१९३७ में काँग्रेसी मंत्रिमंडलों के हाथ में स्वायत्त शासन की बागडोर आ जाने से जन-शिक्षा के भाग्य ने पलटा साया। शिक्षा-प्रसार के अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत काँग्रेसी मंत्रिमंडलों में प्रौढ़-शिक्षा को वरासन पर प्रतिष्ठित किया। यह देख कर केन्द्रीय सरकार ने भी १९३६ में 'वयस्क-शिक्षा-समिति' की नियुक्ति करके प्रथम बार वयस्क-शिक्षा में अपना रुचि प्रकट की।

काँग्रेसी मंत्रिमंडलों ने विभिन्न प्रान्तों में प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिये जो प्रयास किये उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिये जा रहा है :

**आसाम :**—इस प्रान्त में वयस्कों को साक्षर बनाने का कार्य शिक्षा-विभाग को सौंपा गया। इस विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों के सहयोग से साक्षरता एवं साक्षरता के उपरान्त भी शिक्षा की व्यवस्था की। एक वर्ष की अवधि में ही १८४० प्रौढ़-शिक्षा-केन्द्र खोले गये और आगामी दो वर्षों में २,१६,७११ प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया।

**बंगाल :**—इस प्रान्त में सरकार ने ग्राम-सभाओं द्वारा संचालित प्रौढ़-पाठशालाओं को विकसित करके तथा आर्थिक सहायता देकर प्रौढ़-शिक्षा की व्यवस्था की। यहाँ १९३६ में प्रौढ़-शिक्षा के लिये १०,००० विद्यालय थे। १९४२ में यह संख्या बढ़कर २२,५७४ हो गई। इनमें क्रमशः १,५०,००० और ५,३०,१७८ प्रौढ़ साक्षर बनाये जा रहे थे।

**बिहार :**—इस प्रान्त में प्रौढ़-शिक्षा का सबसे अधिक विस्तार हुआ। यहाँ एक ही वर्ष में ४,५०,००० वयस्क साक्षरता की परीक्षा में सम्मिलित हुए।





जक

में प्रौढ़-शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है ।  
 ता (Adult Education) को समाज-शिक्षा (Social Edu-  
 देकर उसके रूप को अभिवर्द्धित तथा परिवर्तित किया गया ।  
 या कि निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के साथ-साथ  
 शिक्षा प्रदान की जाय । इस प्रकार समाज-शिक्षा के अन्त-  
 दृष्टिकोण को प्रति व्यापक एवं विस्तृत बना दिया गया ।  
 योजना—निरक्षर व्यक्तियों में नागरिकता के गुणों का विकास  
 तंत्रों तथा अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनमें  
 ने के लिये माननीय केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री ने ३१ मई १९४८  
 गये प्रेस-सम्मेलन के समक्ष अपनी 'द्वादश-सूत्रीय योजना'

-मन्त्रियों का सम्मेलन—फरवरी, १९४९ में दिल्ली में  
 यों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें द्वादश  
 प्रकार विनिर्भर किया गया । तदुपरान्त यह कार्य-क्रम बनाया  
 अर्थात् १२ से ५० वर्ष तक की अवस्था वाले निरक्षर  
 से कम ५० प्रतिशत को साक्षर बना दिया जाय । परन्तु  
 सरकारों की वार्षिक कठिनाइयों के कारण इस कार्य-क्रम  
 पूरा नहीं हो सका ।

-क्रम—समाज-शिक्षा के अन्तर्गत एक 'पंच-मुखी कार्य-क्रम'  
 सके उद्देश्य हैं—(१) साक्षरता-प्रसार, (२) स्वास्थ्य तथा सफाई  
 का प्रसार, (३) वयस्क व्यक्तियों के वार्षिक स्तर की उन्नति,  
 की भावना, अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जनता की  
 ५) समाज एवं व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप स्वस्थ मनो-

।  
 र्थीय योजना—इस योजना में समाज-शिक्षा के लिये ७-५  
 रीकृति दी गई । अनेकों राज्यों ने सामाजिक सेवा-कार्य की  
 कार्य के लिये वार्षिक आवधिक कार्यक्रम को विकसित किया है ।



प्रणालियों में प्रस्तावित गुणों को कार्यान्वित करने के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर समाज-शिक्षा की कक्षाओं का विस्तार किया जाएगा। राज्य-सरकारों ने गांधारता एवं समाज-शिक्षा केन्द्रों के उत्पादन, समाज-शिक्षा कार्यकर्ताओं एवं संघटन कक्षाओं के प्रशिक्षण, पुस्तकालय, साहित्य-प्रकाशन, दूर-दृश्य शिक्षा को व्यवस्था मोह बनता कर्मियों की स्थापना की योजना बनाई है। द्वितीय योजना में समाज शिक्षा के लिये ५ करोड़ रुपये की धरास्वा को गई है। इसके प्रतिष्ठित १० करोड़ रुपया राष्ट्रीय विस्तार एवं सामुदायिक विरास-योजनाओं द्वारा समाज-शिक्षा पर व्यय किया जाएगा।

नवीनतम कार्य—उच्च कर्मचारियों को समाज-शिक्षा का प्रशिक्षण देने तथा प्रमुखा समस्याओं पर उपयुक्त अनुसंधान करने के लिये दिल्ली में एक 'राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र' की स्थापना की गई है।

'केन्द्रीय चलचित्र संग्रहालय' में शिक्षा एवं संस्कृति मन्त्रियों विभिन्न विषयों पर ४,६७४ चलचित्र आदि हैं, जो संग्रहालय की सदस्य शिक्षा-संस्थानों को निःशुल्क दिये जाते हैं। २,०४५ शिक्षा-संस्थान एवं सामाजिक संघटन इस संग्रहालय के सदस्य हैं। 'धर्म-दृश्य शिक्षा' शीर्षक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है।

केन्द्रीय एवं राज्य-सरकारें धर्म-दृश्य कार्यक्रमों की प्रशिक्षण मोष्ठियों का भी आयोजन करती रहती हैं। एक 'केन्द्रीय धर्म-दृश्य संस्था' स्थापित की जा चुकी है। यह संस्था प्रशिक्षण, उत्पादन तथा अनुसंधान-केन्द्र के रूप में कार्य करने के साथ-साथ, धर्म-दृश्य शिक्षा सम्बन्धी जानकारी भी उपलब्ध करती है।

## सारांश

राष्ट्रीय जीवन में समाज-शिक्षा का स्थान—राष्ट्रीय जीवन में समाज-शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी समाज या राष्ट्र के लिये 'उत्तम जीवन' का प्रादवाशन नहीं दे सकती है। वास्तव में जब तक जनता 'निरन्तर सतर्कता' के रूप में अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का मूल्य चुकाने के लिये तैयार न हो, तब तक वह इस स्वतंत्रता को भी सुरक्षित नहीं रख सकती है और इस सतर्कता के लिये उचित समाज शिक्षा की आवश्यकता है।

प्रौढ़-शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा—'प्रौढ़-शिक्षा में मोटे तौर पर वह

सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा सम्मिलित है, जो प्रौढ़ों को दी जाती है।"

**समाज-शिक्षा का ध्येय एवं परिभाषा**—समाज-शिक्षा एक नियंत्रित अनुभव है जो व्यक्तियों की सामूहिक कार्यों में भाग लेने की क्षमता में वृद्धि करता है। समाज-शिक्षा नागरिकता का उचित मूल्यांकन करने की चेतना एवं भावना को जन्म देती है; व्यक्तियों के कर्तव्यों तथा अधिकारों का स्पष्टीकरण करता है।

**समाज-शिक्षा का कार्यक्रम**—समाज-शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम के उद्देश्य हैं—(१) साक्षरता का प्रसार, (२) स्वास्थ्य की शिक्षा, (३) वयस्कों की उन्नति, (४) वयस्कों में अधिकारों तथा कर्तव्यों की भावना का प्रसार और (५) मनोरंजन की व्यवस्था।

**समाज-शिक्षा के उद्देश्य**—समाज-शिक्षा के उद्देश्य हैं:—(१) अधिकारों और कर्तव्यों की भावना का विकास, (२) जनतंत्र के प्रति प्रेम, (३) देश तथा समाज की समस्याओं का ज्ञान, (४) संस्कृति के प्रति श्रद्धा, (५) भारतीय संस्कृति से परिचय, (६) नैतिक मूल्यों से परिचय, (७) ज्ञान का प्रसार, (८) आर्थिक उन्नति, (९) शिक्षा की निरन्तरता, और (१०) सहयोग की भावना।

**समाज-शिक्षा के लक्ष्य**—व्यक्तिगत लक्ष्य—(१) वयस्कों का मानसिक विकास, (२) वयस्कों की व्यावसायिक क्षमता का विकास, (३) वयस्कों का शारीरिक विकास, (४) वयस्कों की सामाजिक कुशलता का विकास, (५) वयस्कों का सांस्कृतिक विकास, और (६) वयस्कों का आत्म-विकास। समाज-शिक्षा के लक्ष्य हैं—(१) सामाजिक एकरा का विकास, (२) राष्ट्रीय साधनों की सुरक्षा तथा उन्नति, (३) सहकारी समुदायों तथा संस्थाओं का संगठन, और (४) सामाजिक आदर्श का समावेश।

**समाज-शिक्षा की आवश्यकता के कारण**—(१) वैयक्तिक आवश्यकता, (२) अर्द्ध-शिक्षित वयस्कों की आवश्यकता, (३) पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता, (४) मनोरंजन की आवश्यकता, (५) राजनैतिक आवश्यकता, (६) सामाजिक आवश्यकता, (७) आर्थिक आवश्यकता, और (८) देश की आवश्यकता।

**समाज-शिक्षा की समस्याएँ**—(१) निरक्षरता की समस्या, (२) पाठ्यक्रम की समस्या, (३) शिक्षण पद्धति की समस्या, (४) प्रध्यापकों की समस्या, (५) साहित्य की समस्या, (६) शिक्षा-साधनों की समस्या, (७) धन की समस्या, और (८) उत्तरदायित्व की समस्या।

**समस्याओं का समाधान**—समस्याओं का समाधान करने के उपाय:—(१) निरक्षरता का उन्मूलन, (२) उपयुक्त पाठ्य-क्रम का निर्धारण, (३) उप-

पुस्तक शिक्षण-पद्धति का निर्धारण, (४) पर्यावरणों की पूर्ति, (५) उच्च शिक्षण का निर्माण, (६) शिक्षा के उच्चतम मापन, (७) परामर्श केंद्र का स्थापना, और (८) गुरुत्व उत्प्रेरणादि।

श्री ३ तथा समाज-शिक्षा का इतिहास—१९२१ से पूर्व—१९१७ से पूर्व श्री ३ शिक्षा के लिए प्रायः कुछ भी नहीं किया गया था। १९०२ तक केंद्र मद्रास, बम्बई और बंगाल में राज-विज्ञान मंचावित थे।

१९२१ से १९२७ तक—१९२१ के पश्चात् श्री ३-शिक्षा की ओर विद्वानों दिया गया। इसके लिये भारतीय मंत्री प्रयोग के पात्र हैं।

१९२७ से १९४७ तक—१९२७ में प्रान्तों में कई मंत्री नियमित होने के उपरान्त विभिन्न प्रान्तों में श्री ३ शिक्षा के लिये धन के कार्य बंगाल में धाम-मन्त्रियों द्वारा श्री ३-पाठशालाओं का प्रवर्धन किया गया। बिहार में श्री ३ शिक्षा का सबसे अधिक विस्तार हुआ, हजारों धामों में पुस्तकालय तथा वाचनालय खोले गये। बम्बई में नगर के श्री ३ के छात्र बनाने के लिये विशेष रूप से प्रयास किया गया। उड़ीसा सरकार ने बरहू शिक्षा-कार्य के लिये ₹५,००० रुपये का अनुदान दिया। पंजाब में बिना मूल्य लिये श्री ३ को पुस्तकें बांटी गईं।

१९४७ से १९६० तक—इस मूल्य योजना और पंचमुखी कार्य-क्रम का निर्माण किया गया। प्रथम योजना में ७-५ करोड़ और द्वितीय योजना में ५ करोड़ धन निर्धारित किया गया। नवीनतम कार्यों में 'केंद्रीय बालविन संप्रदाय', 'राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केंद्र' एवं 'केंद्रीय श्रम-द्वय संस्था' प्रमुख हैं।

### सहायक पुस्तकों की सूची

1. K. G. Saiyidain : Problems of Educational Reconstruction.
2. S. N. Mukerji : Education in India, Today and Tomorrow.
3. Humayun Kabir : Education in New India.
4. J. Gillin : The Ways of Men.
5. N. A. Tothi : The Vaishnavas of Gujarat.
6. T. N. Siqueira : Modern Indian Education.
7. Proceedings of the 19th Meeting of the Central Advisory Board of Education in India.

8. *Teachers' Handbook of Social Education.*
9. *India*, 1958
१०. महात्मा गाँधी : सत्य के प्रयोग और आत्म कथा, धनुवादक हरिभाऊ उपाध्याय
११. सीताराम जायसवाल : प्रौढ़-शिक्षा प्रसार
१२. के० जी० सैयदैन : शिक्षा की पुनर्रचना
१३. नवासादरोपयोगी साहित्य निर्माण गोष्ठी की भाष्य, शिक्षा विभाग, उत्तर-प्रदेश, १९५८
१४. प्रथम पंचवर्षीय योजना
१५. द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१६. आजादी का बारहवाँ वर्ष
१७. भारत, १९६०.

### TEST QUESTIONS

1. Trace briefly the history of Social Education Movement in India and indicate the more important phases through which it has passed.
2. Discuss the need and importance of suitable literature for neo-literates in India.
- ✓3. What should be the main aims of Social Education in a secular democratic society ? Discuss with special reference to India.
- ✓4. Discuss the causes of the slow growth of Social Education in India and give suggestions to remove them.
5. Define 'Social Education'. What are the main causes that have hindered its progress ?
6. "Social Education is the panacea for all social ills." What curriculum would you prescribe for Social Education to fulfil this purpose ?
- ✓7. What do you understand by 'Adult Education' ? Discuss its need in India.
8. Discuss the need and importance of Social Education in the national life of India.
- ✓9. Give a brief account of the purposes and agencies of Social Education.
- ✓10. Why was the term "Adult Education" changed to "Social Education"? What is the significance of this change ?

## अध्याय ५

### पाठ्य-क्रम का विभिन्नीकरण' ✓

#### ब्रिटिश शासन-काल में माध्यमिक शिक्षा

ब्रिटिश शासन-काल में माध्यमिक शिक्षा का संगठन देश के शासकों की आवश्यकताओं की पूर्ण करने के लिये किया गया था। इन शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना था जो बंग्रजों के राजकीय तथा व्यापारिक कार्यालयों में निम्न थोड़े से लिपिकों का स्थान भुगतता पूर्णक ग्रहण कर सकें। परिमाणतः माध्यमिक शिक्षा के साहित्यिक पक्ष पर विशेष बल दिया गया। माध्यमिक विद्यालयों के केवल दो उद्देश्य थे। शासकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करना। ये विद्यालय छात्रों को केवल संस्कारी शिक्षा (Liberal Education) प्रदान करते थे और उनको प्राविधिक (Technical) तथा व्यावसायिक (Vocational) शिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं था। उनका अधिकांश ध्यान बंग्रजों की शिक्षा पर केन्द्रित रहता था और बंग्रजों ही शिक्षा का माध्यम थी। हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक छात्र को चार अनिवार्य विषय (बंग्रजों, गणित, इतिहास या भूगोल और एक प्राधुनिक भारतीय भाषा) तथा कम से कम दो, और अधिक से अधिक चार वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना पड़ता था। इन वैकल्पिक विषयों में संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, विज्ञान-कला, विज्ञान आदि थे, पर इनमें से एक भी विषय प्राविधिक पक्ष या व्यावसायिक नहीं था।

1. Diversification of Courses.

सारांश में माध्यमिक शिक्षा का संगठन केवल अंग्रेज शासकों की प्रशा-  
कीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये किया गया था। परन्तु समय  
की गति के साथ भारत में शिक्षा का जो प्रसार हुआ, उस अनुपात में पदों  
की वृद्धि नहीं हुई। मेट्रीकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से  
लगभग ५० अथवा ५५ प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये  
किसी कॉलेज में प्रवेश ले लेते थे। शेष विद्यार्थी नौकरियों की खोज में दफ्तरों  
के चक्कर लगाते थे। उनमें से जिन पर विघाता की कृपा हो जाती थी, उन्हें  
कोई छोटी नौकरी मिल जाती थी, परन्तु शेष को निराशा के दावानल में  
भस्म होना पड़ता था। परिणामतः शत्रुः शत्रुः देश में बेकारी का प्रकोप बढ़ता  
चला गया।

### स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा

द्वितीय विश्व युद्ध ने ससार की काया पलट दी। उसके दो वर्ष उपरान्त ही  
भारत को अपनी छताब्दियों की दासता से मुक्त होने का अवसर उपलब्ध हुआ।  
स्वतन्त्र भारत ने नवीन राष्ट्रीय आवश्यकताओं का अनुभव किया और उनको  
पूर्ण करने के लिये सक्रिय पग उठाया। परन्तु शिक्षा की व्यवस्था में किसी प्रकार  
का परिवर्तन नहीं किया गया। उसका संगठन प्रायः पूर्ववत् ही बना रहा। निस्संदेह  
यत्र-तत्र कतिपय परिवर्तन अवश्य किए गए, परन्तु आधारभूत रूप में शिक्षा का  
ढांचा वैसा ही रहा, जैसा कि वह ब्रिटिश शासन-काल में था। हाँ, इन परि-  
वर्तनों से इतना अवश्य हुआ कि शिक्षा के दोष उभर आए और उसके अवनृण  
स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगे। फलतः लोगों को आभास होने लगा कि शिक्षा  
का पाठ्य-क्रम अति संकुचित और असंतुलित था। पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत कुछ  
विषयों को अति न्यून महत्व दिया गया था और कुछ की विस्तृत ही उपेक्षा की  
गई थी। स्वल्प जीवन तथा नैतिक शिक्षा की पूर्णरूप से अवहेलना की गई थी।  
हस्तकला की ओर रूचि मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया था और छात्रों की  
अभिधाचियों तथा अभिनवियों (Interests and inclinations) को जानने  
का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

सारांश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा में किसी प्रकार  
की प्रगति नहीं हुई। उसने अपने को देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और  
भौतिक परिवर्तनों के अनुकूल नहीं बनाया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिपादित  
नवीन सिद्धान्तों से किसी प्रकार का लाभ नहीं उठाया। यह पुस्तकीय, प्राचीनता  
से विपकी हुई और एक-भाषीय बनी रही। इसने छात्रों की विभिन्न स्वाभा-  
विक अभियोग्यताओं तथा विभिन्न स्वाभाविक अभियोग्यताओं वाले छात्रों की

भावश्यकताओं को पूर्ण करने का कोई प्रयास नहीं किया। शिक्षा की एकमुखी (Unilateral) योजना, जिसका एक मात्र उद्देश्य छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की योग्यता प्रदान करना था, न तो छात्रों की अभिवृत्तियों का प्रयोग एवं विकास कर सकती थी और न अभ्यासकों के शिक्षण-कार्य को ही रोचक बना सकती थी। इसके अतिरिक्त पाठ्य-क्रम का विभिन्नीकरण न होने से अनेकों छात्रों को अपनी वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुकूल विषय और इसके फलस्वरूप अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य उपलब्ध न हो सका।

### पाठ्य-क्रम के विभिन्नीकरण के प्रयास

सोभाग्य से देश के नेताओं ने अनुभव किया कि माध्यमिक शिक्षा के सप-ठन में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा में वांछित परिवर्तन करने के लिए समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति की। यहीं से पाठ्य-क्रम के विभिन्नीकरण का श्री गणेश होता है। हम कुछ प्रमुख समितियों तथा आयोगों का वर्णन निम्नांकित पक्तियों में कर रहे हैं :

#### १. प्रथम आचार्य नरेन्द्र देव समिति, १९३६

यद्यपि इस समिति की नियुक्ति स्वतन्त्रता से पूर्व हुई थी, परन्तु क्योंकि इसने पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया था, अतः इसका विवरण यहाँ अनिवार्य हो जाता है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा को इस प्रकार संगठित किया जाय जिससे छात्रों को अपनी अभियोग्यताओं तथा अभिरुचियों के अनुसार विविध प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध हो सके। समिति ने यह भी सिफारिश की कि जिस प्रकार व्यवसाय-विवलेषण (Job Analysis) किया जाता है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम-विवलेषण (Course Analysis) भी किया जाय। उसने कहा कि पाठ्य-क्रम वास्तविक एवं व्यावहारिक हो और वह विद्यार्थियों द्वारा देय तथा काल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाय। उसने सिफारिश की कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को चार वर्गों में विभाजित किया जाय :—(१) साहित्यिक, (२) वैज्ञानिक, (३) रचनात्मक, एवं (४) व्यावहारिक। छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार किसी भी एक वर्ग का चयन करने का अधिकार दिया जाय। विभिन्न वर्गों के लिए

छात्रों की उपयुक्तता की जानकारी प्राप्त करने के लिए 'माध्यमन-योग्यता परीक्षाओं' (Scholastic Aptitude Tests) का प्रयोग किया जाय।

## २. ताराचंद समिति,<sup>१</sup> १९४८

इस समिति की घनेकों सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि माध्यमिक विद्यालय बहुमुखी (Multilateral) होने चाहिये, परन्तु स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एकमुखी (Unilateral) विद्यालयों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। समिति की एक सिफारिश यह भी थी कि माध्यमिक शिक्षा की जीव करने के लिये एक प्रायोग की नियुक्ति की जाय।

## ३. द्वितीय आचार्य नरेन्द्र देव समिति,<sup>२</sup> १९५२-५३

इस समिति ने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम को व्यावहारिक रूप दिया जाय और उसे बालकों की रुचियों तथा योग्यताओं के अनुसार बनाया जाय। समिति ने एक सुझाव यह भी दिया कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाय और उनमें विभिन्न उद्देश्यों, अभिरुचियों तथा अभियोग्यताओं वाले छात्रों के लिये विभिन्न पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था की जाय। समिति का एक सुझाव यह भी था कि सामान्य शिक्षा के साथ-साथ टेकनिकल शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाय और अधिक से अधिक टेकनिकल संस्थाओं का निर्माण किया जाय। समिति ने छात्रों के मार्ग-प्रदर्शन एवं उनकी मनोवैज्ञानिक जीव के सम्बन्ध में भी अत्यन्त उपयोगी सुझाव दिये।

## ४. माध्यमिक शिक्षा-प्रायोग,<sup>३</sup> १९५२-५३

'ताराचंद समिति' और 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड'<sup>४</sup> की सिफारिशों के फलस्वरूप भारत-सरकार ने 'माध्यमिक शिक्षा-प्रायोग' (मुदालियर कमीशन)<sup>५</sup> की नियुक्ति की। प्रायोग से भारत की तरकाशीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने और उसका पुनर्संज्ञकन तथा सुधार करने के लिये सुझाव देने को कहा गया। प्रायोग ने जो घनेकों महत्वपूर्ण सुझाव दिये उनमें पाठ्य-क्रम के विभिन्नोकरण और बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना को सर्व प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रायोग ने कहा कि छात्रों के विविध उद्देश्यों, योग्य-

1. Tarachand Committee.
2. Second Acharya Narendra Deo Committee.
3. Secondary Education Commission.
4. Central Advisory Board of Education.
5. Mudaliar Commission



ताम्र एवं धातुओं की वृत्ति करने के लिये इन विधातयों का पाठ्य-क्रम उनमें विभिन्न स्तरों के अनुकूल होना चाहिये।

### विभिन्न पाठ्य-क्रम की रूप-रेखा

माध्यमिक शिक्षा-भाषाओं के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिय स्पष्ट रूप से पाठ्य-क्रम का विभिन्नोकरण होगा। शिक्षा के इस स्तर पर कुछ मान्तरक विषय (Core Subjects) होंगे जिनका अध्ययन सभी छात्रों को करना होगा। इनके प्रतिरिक्त कुछ वैकल्पिक विषय होंगे जो छात्र समूहों में विभाजित किये गये हैं। यही पर पाठ्य-क्रम को विभिन्नता प्रदान की गई है। हम इस विभिन्न पाठ्य-क्रम की रूपरेखा नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

#### क-मान्तरक विषय

क-(१) मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा अथवा मातृ-भाषा तथा एक शास्त्रीय भाषा (Classical Language) का मिश्रित पाठ्य-क्रम।

(२) निम्नांकित में से चुनी जाने वाली एक अन्य भाषा :

(i) हिन्दी (उनके लिये जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है)।

(ii) प्रारम्भिक अंग्रेजी (उनके लिये जिन्होंने माध्यमिक स्तर (Middle Stage) पर इसका अध्ययन नहीं किया है)।

(iii) उच्च अंग्रेजी (उनके लिये जिन्होंने पहिले अंग्रेजी का अध्ययन किया है)।

(iv) हिन्दी के प्रतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा।

(v) अंग्रेजी के प्रतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा।

(vi) एक शास्त्रीय भाषा।

ख-(१) समाज विज्ञान का सामान्य पाठ्य-क्रम ( केवल प्रथम दो वर्षों के लिये)।

(२) गणित सहित सामान्य विज्ञान का सामान्य पाठ्य-क्रम ( केवल प्रथम दो वर्षों के लिये)।

स - निम्नांकित में से एक शिल्प (Craft):

(१) मेटाई एवं बुनाई, (२) काष्ठ कर्म (Wood-Work), (३) धातु-कर्म (Metal Work), (४) वागवानी, (५) सूचिक-कर्म (Tailoring), (६) मुद्रण कर्म (Typography), (७) कर्मशाला प्रयोग (Workshop Practice) (८) सिलाई, सूची शिल्प (Needle work) और निवीकरण (Embroidery), तथा (९) प्रतिरूपण (Modelling)।

## ख—वैकल्पिक विषय

८—निम्नलिखित समूहों में से किसी एक समूह से तीन विषय :

### समूह १—मानव विज्ञान (Humanities)

(१) एक शास्त्रीय भाषा अथवा "घ २" से न ली गई एक भाषा, (२) इतिहास, (३) भूगोल, (४) धर्मशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र के तत्व, (५) मनोविज्ञान तथा तर्कशास्त्र के तत्व, (६) गणित, (७) संगीत, और (८) गृह-विज्ञान ।

### समूह २—विज्ञान (Sciences)

(१) भौतिक शास्त्र, (२) रसायन शास्त्र, (३) जीव शास्त्र, (४) भूगोल, (५) गणित, और (६) शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान के तत्व (इनको जीव शास्त्र के साथ नहीं लिया जा सकता है) ।

### समूह ३—प्रावधिक (Technical)

(१) व्यावहारिक गणित ( Applied Mathematics ) और रेखिकीय भोर्द्रेखिकी ( Geometrical Drawing ), (२) व्यावहारिक विज्ञान, (३) यांत्रिक घामियान्त्रिकी के तत्व (Elements of Mechanical Engineering), और (४) वैद्युत (Electrical) घामियान्त्रिकी के तत्व ।

### समूह ४—वाणिज्यिक—(Commercial)

(१) वाणिज्यिक प्रयोग ( Commercial Practice ), ( २ ) बही-खाता (Book-Keeping), (३) वाणिज्य भूगोल अथवा धर्मशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र के तत्व, और (४) प्राशुलिपि तथा टंकन (Short-hand and Type-writing)

### समूह ५—कृषि (Agriculture)

(१) सामान्य कृषि, (२) पशु-पालन, ( ३ ) औद्यानिकी (Horticulture) तथा बागवानी, और (४) कृषि-रसायन ( Agriculture Chemistry ) तथा वनस्पति विज्ञान ।

### समूह ६—(Fine Arts)

(२) ड्राइंग तथा स्पायून (Designing), (३) संगीत, और (६) नृत्य ।

पाक-कला (Nutrition)  
और (४) गृह-प्रबन्ध तथा

## विभिन्न पाठ्य-क्रम की आवश्यकता

विभिन्न पाठ्य-क्रम की आवश्यकता के पक्ष में जो तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं, वे प्रचलित हैं :

### १. शिक्षा-सम्बन्धी परिवर्तित दृष्टिकोण

शिक्षा-मनोविज्ञान की प्रगति के कारण व्यक्तियों की शिक्षा-सम्बन्धी धारणाओं में निरन्तर परिवर्तन होता जा रहा है। प्राज्ञ के शिक्षा-विशेषज्ञों का दृष्टिकोण वह नहीं है, जो प्राचीन समय के शिक्षा-विशेषज्ञों का था। पूर्व समय में यह विश्वास किया जाता था कि "जो पढ़ाया जा रहा है सभी बालक उसके लिये उपयुक्त हैं, सभी को उसमें रुचि है, सभी उससे बराबर लाभ उठावेंगे।" शिक्षा-मनोविज्ञान की सोचों ने यह सिद्ध कर दिया है कि उपयुक्त धारणा में सत्य का लेखमान भी भ्रंत नहीं है। इसके विपरीत यह विश्वास किया जाने लगा है कि प्रत्येक बालक की अभियोग्यताये, अभिरुचियाँ, क्षमतायें तथा प्रजाएँ (Energies) एक-दूसरे से भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम की विभिन्नोक्ति होना आवश्यक है, जिससे कि ज्ञानार्जन करने वाले समस्त बालकों का समान रूप से हित हो सके।

### २. छात्रों की मानसिक तथा शारीरिक विभिन्नता

प्रकृति ने प्रत्येक मानव को दूसरे से भिन्न बनाया है। यदि सभी बालक एक ही सचि में बड़े हुए होते, तो उनके लिये समान पाठ्य-क्रम सम्भव हो सकता था। वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि सभी बालकों में कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य होती है। कोई बालक तीव्र-बुद्धि है, तो कोई मन्द बुद्धि। किसी बालक का मानसिक मुकाब साहिर्य के प्रति है, तो किसी का विज्ञान के प्रति। कोई बालक सकल है, तो कोई निर्बल। जब बालकों में इस प्रकार की विभिन्नताये विद्यमान हैं, तो उनके लिये विभिन्न पाठ्य-क्रम की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

### ३. समाज की माँगों की पूर्ति

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह कर ही वह अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह उनी दशा में सम्भव होगा कि यह समाज क समाज एक कार्य तथा व्यवसाय को न करके विभिन्न कार्यों एवं व्यवसायों को करे। यही कारण है कि हमें प्रत्येक समाज में विविध कार्यों में सकल व्यक्ति दिखाई देता है। यदि वे ऐसा न करे, तो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी और समाज प्रगति नहीं करेगा। अतः यह धर्म-

यह है कि विभिन्न पाठ्य-क्रम का प्रबंध करके समाज के भावी नागरिकों को विभिन्न कार्य करने में कुशलता प्रदान की जाय जिससे कि वे समाज की माँगों में पूर्ति कर सकें। "पाठ्य-क्रम में इस प्रकार विभिन्नता लानी चाहिये और तथा इस प्रकार विस्तार दिया जाना चाहिये कि उससे विभिन्न प्रकार के तालकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो सके, जिससे वे अपने भावी जीवन में समाज की विभिन्न माँगों की पूर्ति कर सकें।"<sup>१</sup>

#### ६. छात्रों की माँगों की पूर्ति

भारतीय संविधान में १४ वर्ष तक की आयु के बालकों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अतः इन बात की पूर्ण धारणा है कि पश्चिम में प्रचलित बालक माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश करेंगे। इन बालकों की अध्ययन प्रवृत्तियाँ, रुचियाँ, योग्यताएँ तथा अभिनतियाँ विभिन्न होंगी। अतएव इस बात की आवश्यकता है कि हमारे माध्यमिक विद्यालय "एक-मार्गीय" (Single Track) न हों, अपितु ऐसे विभिन्न पाठ्य-क्रम की व्यवस्था करें, जिससे कि उन छात्रों की विभिन्न माँगों को पूर्ण किया जा सके। इस माँग की पूर्ति करने के लिये पाठ्य-क्रम को अधिक व्यापक बनाना होगा और उसमें सामान्य तथा व्यावसायिक विषयों का समावेश करना होगा क्योंकि सभी बालकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विषयों को चयन करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।<sup>२</sup>

1. *Headmasters' Report on Secondary Education*, Ministry of Education, p. 6..
2. "In view of the fact that education up to the age of 14 has been made and free compulsory under the Constitution, students with a very wide variety of talents will be seeking education in future. This postulates that our secondary schools should no longer be "single track" institutions but should offer a diversity of educational programmes calculated to meet varying aptitudes, interests and talents which come into prominence towards the end of the period of compulsory education. They should provide more comprehensive courses which will include both general and vocational subjects and pupils should have an opportunity to choose from them according to their needs," *Report of the Secondary Education Commission*, p. 39.

## विभिन्न पाठ्य-क्रम की आवश्यकता

विभिन्न पाठ्य-क्रम की आवश्यकता के पक्ष में जो मकते हैं, वे सधोतितित हैं :

### १. शिक्षा-सम्बन्धी परिवर्तित दृष्टिकोण

शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति के कारण व्यक्तियों की । सामो में निरन्तर परिवर्तन होता जा रहा है । पात्र के मि कोण बहु नहीं है, जो प्राचीन समय के शिक्षा-विशेषज्ञों का यह बिस्वास किया जाता था कि "जो पढ़ाया जा रहा है । लिये उपयुक्त है, सभी को उसमें रचि है, सभी उसने बराबर शिक्षा-मनोविज्ञान की सोचो ने यह सिद्ध कर दिया है कि २ में सत्य का लेखमान भी भ्रम नहीं है । इसके विपरीत यह बिस् लगा है कि प्रत्येक बालक की अभियोग्यताये, अभिरचिया, घर्जाएँ ( Encrygia ) एक-दूसरे से भिन्न हैं । ऐसी स्थिति में विभिन्नोकरण होना आवश्यक है, जिससे कि ज्ञानार्जन करने बालको का समान रूप से हित हो सके ।

### २. छात्रों की मानसिक तथा शरीरिक विभिन्नता

प्रकृति ने प्रत्येक मानव को दूसरे से भिन्न बनाया है । यदि स एक ही साथे मे डले हुए होते, तो उनके लिये समान पाठ्य-क्रम १ सकता था । वास्तविक जीवन मे हम देखते हैं कि सभी बालको मे कुछ विभिन्नता भवद्य होती है । कोई बालक तीव्र-बुद्धि है, तो कोई मन्द किसी बालक का मानसिक मुकाव साहित्य के प्रति है, तो किसी का वि प्रति । कोई बालक सबल है, तो कोई निर्बल । जब बालकों मे इस प्रकार विभिन्नताये विद्यमान है, तो उनके लिये विभिन्न पाठ्य-क्रम की आवश्यकता भी आवश्यक है ।

### ३. समाज की माँगों की पूर्ति

मनुष्य एक सामाजिक ५ आवश्यकताओं की पूर्ति ५ समाज के सदस्य एक कार्य साधों को करे । यही संलग्न व्यक्ति दिखाई २० कताओं की पूर्ति नहीं

करती है। अतः पाठ्य-क्रम के विभिन्नोद्धारण की आवश्यकता है।<sup>१</sup>

उपरोक्त तथ्यों पर गम्भीर दृष्टिगत करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्य-क्रम का विभिन्नोद्धारण अतिवश्यक है।

## विभिन्न पाठ्य-क्रम का महत्त्व

विभिन्न पाठ्य-क्रम का छात्रों के लिये अत्यधिक महत्त्व है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने पाठ्य-क्रम का विभिन्नोद्धारण करने का निश्चय किया है। इन नव महत्त्वों का विवरण नीचे की पंक्तियों में दे रहे हैं :

### ७. जीविका-उपार्जन की सुगमता

हमारे देश में साधारणतः पञ्चीस या तीस प्रतिशत छात्र ऐसे होते हैं, जो हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त किसी उच्च शिक्षा-संस्था में प्रवेश लेते हैं। अतः हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर चुकने के पश्चात् अधिकांश छात्र जीविका-उपार्जन की चिन्ता में पड़ जाते हैं। जो शिक्षा वे ग्रहण कर चुकते हैं, वह उनके लिये निरर्थक सिद्ध होती है। विभिन्न पाठ्य-क्रम में उनको वह शिक्षा तो प्राप्त होगी ही, जो कि उनको आधुनिक माध्यमिक विद्यालयों में प्राप्त हो रही है, परन्तु इसके साथ ही साथ उन्हें किसी ऐसी व्यावसायिक शिक्षा का भी ज्ञान हो जायगा, जिससे कि उनके लिये जीविका उपार्जन का कार्य सुगम हो जायगा।

### २. उत्तम मानव तथा उत्तम नागरिक का निर्माण

विभिन्न पाठ्यक्रम छात्रों को प्राविधिक (Technical) प्रकार की शिक्षा देने के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा भी पर्याप्त मात्रा में देगा जिससे कि वे उत्तम मानव बन कर अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। साथ ही वे जीवन की कला में प्रशिक्षित होकर उत्तम नागरिक भी बन सकेंगे।<sup>२</sup> यदि एक छात्र 'कृषि समूह'

1. "In fact it is the special function of Secondary Education to provide the country with the second line of its leaders in all walks of national life—art, science, industry and commerce. The present unilateral system is not planned to provide leadership which is yet another argument for its diversification." *Report of the Secondary Education Commission*, p. 91.
2. "Besides, giving him some training of a technical kind, the course should also give him a reasonable amount of general education so that he may be fit to discharge his duties as a human being and a citizen trained in the greatest of all arts—the art of living." *Ibid*, p. 85.

## ५. छात्रों के व्यक्तित्व का विकास

माध्यमिक शिक्षा प्रायोग द्वारा विभिन्न पाठ्य-क्रम में जिन सामान्य (General) और व्यावसायिक (Vocational) विषयों का उल्लेख किया गया है, उनका अभिप्राय यह नहीं है कि कुछ बालकों को 'सामान्य' (General) और कुछ को 'व्यावहारिक' (Practical) शिक्षा प्रदान की जायगी। इसके विपरीत प्रायोग की धारणा यह है कि छात्रों का मानसिक तथा सांस्कृतिक विकास अपने-के विषयों के अध्ययन से ही हो सकता है और व्यक्तित्व का विकास केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रथवा परम्परागत विषयों के अध्ययन से ही नहीं, अपितु बुद्धिमत्तापूर्वक किये गये व्यावहारिक कर्म (Practical work) से भी हो सकता है। प्रायोग को विश्वास है कि उचित रूप से संगठित व्यावहारिक कर्म परम्परागत विषयों की प्रपेक्षा, जिनका सम्बन्ध केवल भस्तिष्क से है, बालकों को अन्तर्हित प्रज्वालों को अधिक सफलतापूर्वक व्यक्त कर सकता है और इस प्रकार उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अधिक सुगमता से हो सकता है।<sup>१</sup> इस दृष्टि कोण के अनुसार पाठ्य-क्रम का विभिन्नोकरण आवश्यक है।

## ६. कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति

यदि माध्यमिक शिक्षा को केवल साहित्यिक रहने दिया जाय और उसमें व्यावहारिक विषयों को स्थान देकर उसका विभिन्नोकरण न किया जाय, तो हमारे तकनिकल विद्यालयों तथा राष्ट्रीय योजनाओं के लिये योग्य व्यक्ति उत्पन्न न हो सकेंगे। वास्तव में माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र—कला, विज्ञान, उद्योग और वाणिज्य के लिये कुशल व्यक्तियों का निर्माण करना। प्राथमिक एकमार्गीय शिक्षा इस उद्देश्य को पूर्ण नहीं

1. 'The whole modern approach to this question is based on the insight that the intellectual and cultural development of different individuals takes place best through a variety of media, that the book or the study of traditional academic subjects is not the only door to the education of the personality and that, in the case of many-perhaps a majority—of the children, practical work intelligently organized can unlock their latent energies much more successfully than the traditional subjects which address themselves only to the mind or, worse still, the memory.' *Report of the Secondary Education Commission*, p. 39.

## १. उत्तम परीक्षा-फल

पाठ्य-क्रम का विभिन्नीकरण इसलिये महत्वपूर्ण समझा गया है क्योंकि यह हमारी शिक्षा-प्रणाली के एक प्रमुख दोष का निराकरण कर देगा। यदि हम सम्पूर्ण भारत के हार्दिक स्कूल परीक्षाओं के परीक्षा-फलों पर दृष्टि डालें, तो हमें यह सरलता पूर्वक ज्ञात हो जायगा कि छात्रों की क्षति का घनि महान् अवश्य होता है। 'अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा समिति'<sup>१</sup> द्वारा अभी हाल में दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण भारत में इन परीक्षाओं में लगभग ५० प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। एन० एन० मुकर्जी के अनुसार यह प्रतिशत और भी कम है।<sup>२</sup> इसका प्रमुख कारण यह है कि छात्रों को अपनी अभिरूचियों तथा अभियोग्यताओं के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' द्वारा प्रतिपादित विभिन्न पाठ्यक्रम इस दोष का उन्मूलन करके अति सराहनीय कार्य करेगा और असंख्यों छात्रों को निराशा के गर्त में गिरने से बचावेगा।

## ६. बेकारी की समस्या का समाधान

भारत में बेकारी की समस्या अतिशय गम्भीर रूप धारण कर रही है। १९५३ में भारतीय योजना आयोग ने अपनी सिफारिश में बेकारी की इस महान् समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था जिसका परिणाम यह हुआ कि मार्च १९५४ में सरकार ने इस समस्या के समाधान के हेतु १८० करोड़ रुपये अधिक स्वीकृत किये। इतना होने के बावजूद भी समस्या लोहे की दीवार की भाँति अटल होकर हमारी सारी भावी प्रगति एवं सुख-समृद्धि को प्रवरुद्ध किये हुए है। इस समस्या के अनेकों कारणों में से एक कारण यह भी है कि हमारी शिक्षा एक मार्गीय है। इसीलिये मुदालियर कमिशन द्वारा इस शिक्षा को विविध-मार्गीय (Multi-purpose) बनाने का सुझाव दिया गया है। इस सम्बन्ध में कमिशन ने जिस विभिन्न पाठ्य-क्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है, उससे महान् हित होने की आशा की जा रही है। बालक अपनी रुचियों के अनुसार टेक्निकल, व्यावसायिक, वाणिज्यारमक एवं अन्य क्रियारमक विषयों का अध्ययन कर सकेंगे और साथ ही किसी हस्तकला में कुशल हो जायेंगे। परिणाम यह होगा कि उन्हें नौकरी खोजने के लिये दर-दर नहीं भटकना

1. All India Council for Secondary Education.

2. S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 131.





विभिन्न पाठ्यक्रम की रूप-रेखा—इस पाठ्य-क्रम में दो प्रकार के विषय हैं—(१) धान्तरक, और (२) वैकल्पिक। धान्तरक विषयों का अध्ययन सभी छात्रों को करना है। वैकल्पिक विषय सात समूहों में विभाजित हैं—मानव विज्ञान, विज्ञान, प्रावैधिक, वाणिज्यिक, कृषि, सलित कलायें और कृषिविज्ञान। छात्र किसी भी समूह में से तीन विषय ले सकता है।

विभिन्न पाठ्यक्रम की आवश्यकता—विभिन्न पाठ्य-क्रम की आवश्यकता अवलिखित कारणों के फलस्वरूप है—(१) शिक्षा-सम्बन्धी परिवर्तित दृष्टिकोण, (२) छात्रों की मानसिक तथा शारीरिक विभिन्नता, (३) समाज की माँगों की पूर्ति, (४) छात्रों की माँगों की पूर्ति, (५) छात्रों के व्यक्तित्व का विकास, और (६) कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति।

विभिन्न पाठ्यक्रम का महत्त्व—विभिन्न पाठ्य-क्रम का महत्त्व अवलिखित कारणों से हैं—(१) जीविका उपार्जन की सुगमता, (२) उत्तम मानव तथा उत्तम नागरिक का निर्माण, (३) पूर्ण सांस्कृतिक विकास, (४) शारीरिक श्रम का सम्मान, (५) उत्तम परीक्षा-फल, और (६) बेकारी की समस्या का समाधान।

## सहायक पुस्तकों की सूची

1. *Tarachand Committee Report.*
2. *First Acharya Narendra Deo Committee Report.*
3. *Second Acharya Narendra Deo Committee Report.*
4. *Report of the Secondary Education Commission.*
5. *Headmasters' Report on Secondary Education.*
6. S. N. Mukerji : *Education in India—Today and Tomorrow.*

## TEST QUESTIONS

1. Discuss the circumstances which necessitated the introduction of diversified courses.
2. What, in your opinion, is the need for and importance of diversification of courses?
3. Give a brief criticism of the curriculum envisaged by the Secondary Education Commission.
4. What arguments can you advance in favour of multi-lateral courses and their utility.

पड़ेगा। वे स्वतन्त्र रूप से स्वयं कोई व्यवसाय करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकेंगे जिससे बेकारी की समस्या का बहुत-कुछ समाधान हो जायगा।

उपरोक्त के आधार पर हम निस्संकोच रूप से कह सकते हैं कि पाठ्य-क्रम का विभिन्नीकरण प्रति सारगर्भित तथा महत्वपूर्ण है। जब हमारे देश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम कार्यान्वित कर दिया जाय, तब माध्यमिक शिक्षा का कलेवर एक नवीन रूप धारण करेगा। उसमें छात्रों को अपने प्रति आकर्षित करने की क्षमता होगी और छात्रों को उत्साह प्रदान करके अपने व्यक्तित्व, योग्यताओं एवं शक्तियों को विकसित करके शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति करने का अवसर प्राप्त होगा और साथ ही अपने गरीब जीवन में उन्हें जीविका का एक उपयुक्त आधार प्राप्त हो जायगा।

### सारांश

ब्रिटिश शासन-काल में माध्यमिक शिक्षा—ब्रिटिश शासन-काल में माध्यमिक शिक्षा के दो उद्देश्य थे। शासकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करना। शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान और अंग्रेजी पर अधिक बल दिया जाता था। उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं था। शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य नौकरी करना था। अनेकों नवयुवकों को नौकरिस्तान विदेशों के कारण बेकार रहना पड़ता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा—स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा में कतिपय परिवर्तन अवश्य किये गये, परन्तु आधारभूत रूप में शिक्षा का ढांचा वही रहा जैसा कि ब्रिटिश शासन-काल में था। शिक्षा में कोई प्रगति नहीं हुई और वह देश की आवश्यकताओं के अनुकूल न बनी। शिक्षा की योजना एक-मुठी रही। उसमें पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया गया और वह प्राचीनता से चिपकी रही।

पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण के प्रयास—देश के नेताओं ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन में परिवर्तन करना आवश्यक समझ कर समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति की। प्रथम आचार्य नरेन्द्रदेव समिति (१९३६) ने पाठ्य-क्रम के विभिन्नीकरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। ताराचन्द समिति (१९४०) ने नए नए विद्यालयों की स्थापना की विचारणा की। द्वितीय आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने पाठ्य-क्रम को व्यावहारिक रूप देने और टेक्निकल शिक्षा-प्रणाली की स्थापना की विचारणा की। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विभिन्न पाठ्य-क्रम की स्वीकृति प्रस्तुत की और उनकी उगाढ़ता की ओर संकेत किया।

विषयों तथा योग्यताओं वाले छात्रों के लिये विभिन्न प्रकार के पाठ्य क्रमों का आयोजन करता है। यह प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा चयन किये गये अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रम में अपनी स्वाभाविक योग्यताओं तथा अभिनतियों का प्रयोग करने तथा उनको विकसित करने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है।<sup>१</sup>

### बहुउद्देशीय विद्यालय के उद्देश्य

माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने पाठ्यक्रम के विभिन्नोद्देशों पर बल दिया है और उसकी शिक्षा के लिये बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है : "हमारे माध्यमिक विद्यालय एक मार्गीय संस्थाएँ न होकर इस प्रकार की संस्थाएँ हों जिनमें विभिन्न वैश्विक कार्यक्रमों की व्यवस्था हो और जिनसे विभिन्न प्रकार की अभियोग्यताओं, अभिविविधियों तथा मानसिक क्षमताओं का विकास हो सके। विद्यालय इस प्रकार के व्यापक पाठ्यक्रमों की सुलभ बनाएँ जिनमें सामान्य तथा व्यावसायिक (Vocational) विषय सम्मिलित हों और जिनमें से छात्रों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चयन करने का अवसर प्राप्त हो। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों को सम्मिलित करने और इनकी प्रायोगिक (Practical) विषयों को स्थान देने का अभिप्राय यह नहीं है कि 'सामान्य' (General) अथवा 'सांस्कृतिक' (Cultural) शिक्षा छात्रों के एक समूह को प्रदान की जाय, जब कि अन्य समूहों को संकुचित 'प्रायोगिक अथवा व्यावसायिक' अथवा 'प्रविधिक' शिक्षा दी जाय।..... इस बात को ध्यान में रखते हुए कि समस्त छात्रों को उन आधारभूत विचारों, योग्यताओं तथा मूल्यों में प्रशिक्षित किया जाना है, जो जनतन्त्र के बुद्धिमान नागरिकों के कर्तव्यों का पालन करने के लिये अनिवार्य हैं। अतएव पाठ्य-क्रम में सामान्य महत्व तथा लाभ के कुछ ऐसे सामान्य आन्तरिक विषयों (Core Subjects) का होना आवश्यक है जिनका अध्ययन समस्त छात्र कर सकें।"<sup>२</sup>

1. "A multipurpose school seeks to provide varied types of courses for students with diverse aims, interests and abilities. It endeavours to provide for each individual pupil suitable opportunity to use and develop his natural aptitudes and inclinations in special course of studies chosen by him." *Report of the Secondary Education Commission*, p. 39.
2. *Ibid*, pp. 38-39.

## अध्याय ६

# ✓ बहुउद्देशीय विद्यालय ✓

## बहुउद्देशीय विद्यालय का अर्थ

माध्यमिक शिक्षा-भाषायोग ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पाठ्य क्रम में सात विभिन्न समूहों का उल्लेख किया है—(१) मानव विज्ञान, (२) विज्ञान, (३) प्राबंधिक, (४) वाणिज्यिक, (५) कृषि (६) ललित कलाएँ, और (७) गृह विज्ञान। अभी तक भारत के साधारण माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम दो प्रकार के समूहों के विषयों की शिक्षा दी जा रही है। कुछ विद्यालय वाणिज्य तथा कृषि की भी शिक्षा दे रहे हैं। कुछ विशिष्ट विद्यालयों में ललित कलाओं की शिक्षा दी जा रही है। कतिपय बालिका विद्यालय ऐसे हैं जिनमें गृह-विज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था है। कतिपय प्राबंधिक विद्यालयों में टेक्निकल विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध है। सारांश में इस समय हमारे देश में ऐसे विद्यालय नहीं हैं, जिनमें माध्यमिक शिक्षा-भाषायोग द्वारा प्रस्तावित समस्त विषयों के शिक्षण की व्यवस्था एक ही स्थान पर हो। इसके प्रतिरक्त अधिकांश माध्यमिक विद्यालय एक-मुखी (Unilateral) हैं।

मुद्रानिबन्धन ने त्रिभुज विभिन्न पाठ्य-क्रम की कवरेज प्रस्तुत की है, उसके शिक्षण की व्यवस्था बहुमुखी (Multilateral) अथवा बहुउद्देशीय (Multi-purpose) विद्यालयों में की गई है। बहुउद्देशीय विद्यालय का अर्थ स्पष्ट करते हुए कपीडन ने लिखा है : "बहुउद्देशीय एकल विभिन्न उद्देश्यों,

सदस्यों ने विचार-विनिमय के उपरान्त बहुउद्देशीय विद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए<sup>१</sup> :

१. बहुउद्देशीय विद्यालय को छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास करना चाहिए ।
२. विद्यालय को छात्रों की क्षमताओं को राष्ट्रीय चरित्र एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माण की दिशा में परिचालित करना चाहिए ।
३. विद्यालय को छात्रों में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और उनमें स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए ।
४. विद्यालय को छात्रों में एक कौशल भयवा शिल्प की इतनी दक्षता उत्पन्न कर देनी चाहिए कि वे उससे सम्बन्धित व्यवसाय को सरलता पूर्वक कर सकें ।
५. विद्यालय को छात्रों को किसी रचनात्मक, उत्पादक और समाज के लिये हितकर कार्य की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उन्हें सहकारी जीवन में थड़ा उत्पन्न हो तथा उनमें जीवन-यापन की इतनी क्षमता पा जाय कि वे स्वावलम्बी बन सकें ।

### बहुउद्देशीय विद्यालयों की प्रगति

भारत-सरकार ने घनदूबर १९५४ से बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की योजना को क्रियान्वित किया । इस योजना के अनुसार कुछ चुने हुए हार्ड स्कूलों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिणत किया जा रहा है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५०० बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की व्यवस्था की गई थी, परन्तु योजना के अन्त तक केवल २५० बहुउद्देशीय विद्यालय ही स्थापित किए जा सके ।<sup>२</sup> द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १,१५० बहुउद्देशीय विद्यालयों का शिलान्यास हो जायगा ।<sup>३</sup> इस प्रकार द्वितीय योजना के अन्त तक भारत में १,५०० बहुउद्देशीय विद्यालय हो जायेंगे । तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग १,००० बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किये जायेंगे । इस समय देश में लगभग १५०० बहुउद्देशीय विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं । इन विद्यालयों में प्रायः दो वैकल्पिक समूहों के विषयों का शिक्षण किया जा रहा है ।

१. शिक्षा-विचार बोर्डो नेमोताल को विवरण-पत्रिका, उत्तर प्रदेश, १९५८ ।
२. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ ४७६ ।
३. तीसरी पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक रूप-रेखा, पृष्ठ १०० ।

भायोग ने बहुउद्देशीय विद्यालय में हस्तकला प्रयत्न को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। भायोग ने लिखा है : "हमने सिफारिश की है कि हाई-स्कूल के प्रत्येक छात्र को एक शिल्प का अध्ययन करना चाहिये। इस यह आवश्यक समझते हैं कि इस स्तर पर प्रत्येक छात्र किना शिल्प प्रयत्न के काम में कुछ समय लगाएँ और उस विशिष्ट शिल्प में दक्षता का पर्याप्त उच्च स्तर प्राप्त करले, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वह उस शिल्प के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर सके।" १

भायोग ने पाठ्य-क्रम के विभिन्नोत्तर तथा बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किए, उनका अध्ययन करने के लिए फोर्ड फाउण्डेशन (Ford Foundation) की भारतीय शाखा ने घाठ विशेषज्ञों की एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति नियुक्त की। इस समिति ने भायोग की सिफारिशों पर अपने विचार व्यक्त किए और बहुउद्देशीय विद्यालयों के उद्देश्यों की ओर संकेत किया। हमारे विषय से सम्बन्धित समिति के विचार अधोलिखित हैं :

"माध्यमिक विद्यालयों में समूहों की विभिन्नता का उद्देश्य व्यापक सामान्य शिक्षा देना है, न कि ऐसी औद्योगिक दक्षता प्रदान करना है जिससे छात्र एक-दम उद्योग में लग जायें। भायोग की रिपोर्ट में माध्यमिक स्तर पर अधिक गहन प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा के लिए पूर्ण कालीन (Full-Time) एवं अल्पकालीन (Part-Time) समानान्तर प्राविधिक शिक्षा-प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

"अतः यह स्पष्ट है कि मुदालियर कमिशन ने जिस बहुउद्देशीय विद्यालय की रूप-रेखा प्रस्तुत की है उसका उद्देश्य उन साधनों, सामग्रियों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग की व्यापक शिक्षा प्रदान करना है, जो सम्यता के विकास-क्रम को भागे बढ़ने में योग देती है। विद्यालय का उद्देश्य कारीगरों का निर्माण करना नहीं है।"

जून १९५७ में नैनोताल में होने वाली शिक्षा-विचार गोष्ठी में उपस्थित

1. "We have recommended that every high school student should take one craft. We consider it necessary that at this stage, every student should devote some time to work with the hands and attain a reasonably high standard of proficiency in one particular craft, so that if necessary, he may support himself by pursuing it." *Report of the Secondary Education Commission*, p. 95.

अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अतः उनके प्रति विशेष सहानुभूति, सावधानी तथा सतर्कता से व्यवहार किया जाना चाहिये। अतः माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रारम्भिक धपका उच्च शिक्षा की विधियों को प्रयोग करना गम्भीर परिणामों से परिपूर्ण होगा।

क्योंकि छात्रों में किशोरावस्था में विभिन्न मानसिक प्रवृत्तियाँ तथा अभिरूचियाँ होती हैं, अतः यह आवश्यक है कि माध्यमिक विद्यालय उनको विभिन्न मार्गों की पूर्ति करें। प्राथमिक शिक्षा को प्रायः समान प्रणाली में कुछ औचित्य हो सकता है। बच्चों की समस्त आवश्यक माधारभूत योग्यताओं को विकसित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जीवन के इस प्रारम्भिक काल में उनकी योग्यताओं में साधारणतः कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। जब बच्चे बड़े होकर किशोर हो जाते हैं, तब स्थिति पूर्णतया परिवर्तित हो जाती है। मानसिक प्रवृत्तियों तथा अभिरूचियों में बढ़ते हुए अन्तर के कारण एक प्रकार की शिक्षा का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक किशोर को विद्यालय में ऐसे विषयों का अध्ययन सुगम होना चाहिये जिससे कि उसके अन्तर्हित गुणों (Latent Qualities) की अभिव्यक्ति हो। ऐसा करने का एक मान्य उपाय यह है कि अधिक विभिन्न पाठ्य क्रम की व्यवस्था की जाय जिससे कि यह निश्चय हो जाय कि विद्यालय में प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि के अनुसार कुछ विषय मिल सकें। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य इसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करना है।<sup>1</sup>

आधुनिक परिवर्तित दशाओं में माध्यमिक विद्यालयों का सुधार आवश्यक हो गया था। यह आवश्यकता इसलिये और भी अधिक हो गई है क्योंकि सम्पूर्ण भारत के लिये वैश्विक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। वैश्विक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र किसी न किसी हस्तकला मयवा कौशल का अध्ययन करेंगे। अतः पूर्णतया पुस्तकीय

1. "As children grow into adolescents, the situation is radically changed. With growing differences in taste and aptitude, the case for a uniform type of education is gone. Each adolescent must find in the school something which calls out for its latent qualities. The only way of doing so is to offer a more diversified course which will ensure that every pupil in the school can find something to suit his or her taste. The establishment of multi-purpose schools is intended to meet this special need."—Humayun Kabir : *op. cit.*, p. 55.



## बहुउद्देशीय विद्यालयों की आवश्यकता

बहुउद्देशीय विद्यालयों की आवश्यकता पर हुमायूँ कबीर (Humayun Kabir) ने धनि गुप्तर विचार व्यक्त किये हैं।<sup>1</sup> धनः उन्हें संतोष में यही उद्भूत करना सुविशेष प्रतीत होता है। उन्होंने निगा है कि मुस्लिम कबीरान ने माध्यमिक शिक्षा के पुनः गन्त के सम्बन्ध में भी सुझाव दिये हैं, उनमें संबंधी स्थान देन में धनेकों बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की प्राप्ति है। जब तक हमारे देश में ऐसे विद्यालय नहीं होंगे जिनमें छात्र विभिन्न पाठ्य-क्रमों की शिक्षा से लाभ उठा सकें, तब तक माध्यमिक शिक्षा अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असमर्थ रहेगी। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली का एक प्रमुख दोष यह है कि वह एक-मार्गीय है। माध्यमिक विद्यालयों के समस्त छात्रों को प्रायः समान शिक्षा ही ग्रहण करनी पड़ती है। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास अवरोध हो जाता है क्योंकि एक ही प्रकार की शिक्षा सब के लिये उपयुक्त नहीं हो सकती है। मोटे तौर पर छात्रों को चार समूहों में विभक्त किया जा सकता है—(१) वे छात्र जिनको प्रायोगिक विषयों में रुचि है, (२) वे छात्र जिनकी मानसिक प्रवृत्ति गणित तथा विज्ञान में है, (३) वे छात्र जिनको सलिल कलाओं से प्रेम है, और (४) वे छात्र जो मानव-विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं। भारत में माध्यमिक शिक्षा की समस्या यह है कि वह छात्रों के लिये विभिन्न विषयों का अध्ययन सुलभ बनाये और साथ ही सबको कुछ समान मात्रात्मक विषयों की शिक्षा दे।

माध्यमिक शिक्षा वे बालक तथा बालिकाएँ ग्रहण करते हैं जो बाल्यावस्था से यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं। इस प्रकार बालकों की समस्त किशोरा-वस्था माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने में व्यतीत होती है। साधारणतः बाल्या-वस्था की विशेषताएँ स्पष्ट तथा समान होती हैं। अतः बच्चों को शिक्षा देते समय अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। बच्चों को एक निश्चित मात्रा में ज्ञान प्रदान करना होता है और उनमें विचार तथा कार्य की निश्चित आदतों का निर्माण करना पड़ता है। इसी प्रकार युवकों को शिक्षा देने में हम एक निश्चित विधि का अनुसरण कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आदतों तथा योग्यताओं का स्पष्टीकरण ही जाता है। किशोर न तो बच्चे होते हैं, और न बयस्क। अधिक व्यथित करने वाली बात यह है कि वे प्रति-स्वरित गति से एक अवस्था से दूसरी में प्रवेश करते हैं। उनमें इस प्रकार के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक परिवर्तन होते हैं जो उनके तथा समाज के लिये

1. Humayun Kabir : *Education in New India*, pp. 53-55.

इ सामुदायिक जीवन की संरचना के अन्तर्गत बालकों की योग्य-  
वृत्ति को सम्भव बना सकता है।

### घोर के विचार

कबीर ने बहुउद्देशीय विद्यालयों के पक्ष में निम्नांकित तर्क प्रस्तुत  
के विद्यालय विभिन्न योग्यताओं तथा रुचियों वाले छात्रों के लिये  
पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था करेंगे।

ये राष्ट्र के कुषि, भौद्योगिक तथा प्राविधिक कार्यक्रमों के लिये प्रशि-  
ता कुशल व्यक्तियों का निर्माण करेंगे।

ये अपनी विभिन्न प्रकार की पाठ्य-क्रम सहगामी क्रियाओं (Co-  
ular Activites) द्वारा छात्रों की व्यस्त रखेंगे, उन्हें आत्म-प्रतिभक्ति  
तुर प्रदान करेंगे और साथ ही विद्यालय-सेवाओं की उत्पत्ति करेंगे।

ये हस्तकला की शिक्षा द्वारा शारीरिक धम के प्रति सम्मान उत्पन्न  
हस्तकला से छात्रों के आत्म-विश्वास में भी वृद्धि होगी क्योंकि प्राव-  
ता पढ़ने पर वे उस हस्तकला द्वारा, जिसका उन्होंने अध्ययन किया है,  
जीवन-यापन कर सकेंगे।

उपरिलिखित विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय  
शाला से छात्र, समाज तथा राष्ट्र का महान् हित होगा। परन्तु इसके  
अबूझ भी बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना अति मन्द गति से हो रही  
इन विद्यालयों की योजना को कार्यान्वित किये हुए छः वर्ष व्यतीत हो चुके  
परन्तु अभी तक इस विशाल देश में केवल १,४०० बहुउद्देशीय विद्यालयों का  
निर्माण किया जा सका है। इसके क्या कारण हैं, वे कौन सी सम-  
यों घयवा कठिनाइयाँ हैं जो बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना में बाधायें  
गठित कर रही हैं, इन्हीं पर अब हम विचार करेंगे।

### बहुउद्देशीय विद्यालयों की समस्याएँ और उनका समाधान

बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना में जिन विभिन्न समस्याओं का अनुभव  
होया जा रहा है, वे निम्नांकित हैं:

1. "It can make possible the development of the abilities of children within a framework of community life." S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 149.
2. Humayun Kabir : *op. cit.*, pp. 56-57,

उनके लिए उपयुक्त नहीं होगी। उन्हें यह प्रस्ताव करने का जिस हस्तकला प्रयत्न कौशल का उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में किया है, उन्हें उसका अधिक अध्ययन करने का प्रवर्तन माध्यमिक विद्यालयों में प्रसारित यदि एक हस्तकला प्रयत्न कौशल के दो जाय, तो इससे छात्रों का और भी अधिक हित हो सकता है। विन्दु को ध्यान न रखकर बहुउद्देशीय विद्यालयों की आवश्यकता किया गया है।

अन्तिम कारण और है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि विभिन्न देशों के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए कि एक ही प्रकार के बहुउद्देशीय विद्यालय में उनके शिक्षण की जाय, जैसा कि भारत में किया जा रहा है। पाश्चात्य देशों में प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण किया गया, पर इस योजना की सफलता नहीं प्राप्त हुई। अमेरिका (संयुक्त राज्य) ऐसे प्रगतिशील देश में प्राविधिक (Technical) प्रयत्न प्रत्यक्ष सम्मान किया जाता है, उन विद्यालयों को प्रदान की जाती है, पुस्तकीय शिक्षा देने वाले विद्यालयों की प्रेरणा को शारीरिक श्रम की प्रेरणा नहीं अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, प्रत्यक्ष विषयों के लिये विभिन्न विद्यालयों की स्थापना ने शारीरिक श्रम के सामाजिक घुला की पुष्टि करती होती। एक ही विद्यालय में और उन्हीं विषयों में जिनमें कि पूर्णतया पुस्तकीय विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है, अधिक, कुवि प्रयत्न अन्य व्यावसायिक पाठ्य-क्रमों की शिक्षा की व्यवस्था न सब शिक्षाओं में समानता उत्पन्न करेगी और शारीरिक श्रम को हटाने सम्भव जायगा। परिणामतः बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना को प्रवर्तक सम्भव गया है।

1. "In a country like India, where tradition exalts intellectual at the cost of manual labour, provision of different courses in different schools would have confirmed the social aversion to manual work. The provision of technical, agricultural or other professional courses in the same school and under the same conditions as purely academic courses will be a visible symbol of the equal worth of all." —Humayun Kabir : *op. cit.* p. 55.

५. यह सामुदायिक जीवन की संरचना के अन्तर्गत बालकों की योग्यताओं की उन्नति को सम्भव बना सकता है।<sup>१</sup>

## हुमायूँ कबीर के विचार

हुमायूँ कबीर ने बहुउद्देशीय विद्यालयों के पक्ष में निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किये हैं<sup>२</sup> :

१. ये विद्यालय विभिन्न योग्यताओं तथा रुचियों वाले छात्रों के लिये विभिन्न पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था करेंगे।

२. ये राष्ट्र के कृषि, औद्योगिक तथा प्राविधिक कार्यक्रमों के लिये प्रशिक्षित तथा कुशल व्यक्तियों का निर्माण करेंगे।

३. ये अपनी विभिन्न प्रकार की पाठ्य-क्रम सहायमी क्रियाओं (Co-curricular Activities) द्वारा छात्रों को व्यस्त रखेंगे, उन्हें आत्म-प्रतिबद्धि के अवसर प्रदान करेंगे और साथ ही विद्यालय-सेवाओं की उन्नति करेंगे।

४. ये हस्तकला की शिक्षा द्वारा शारीरिक धर्म के प्रति सम्मान उत्पन्न करेंगे। हस्तकला से छात्रों के आत्म-विश्वास में भी वृद्धि होगी क्योंकि भाव-स्थिरता पढ़ने पर वे उस हस्तकला द्वारा, जिसका उन्होंने अध्ययन किया है, अपना जीवन-यापन कर सकेंगे।

उपरिलिखित विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय विद्यालयों से छात्र, समाज तथा राष्ट्र का महान् हित होगा। परन्तु इसके बावजूद भी बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना प्रति मन्दर गति से हो रही है। इन विद्यालयों की योजना को कार्यान्वित किये हुए छः वर्ष भ्रष्ट हो चुके हैं, परन्तु अभी तक इस विशाल देश में केवल १,४०० बहुउद्देशीय विद्यालयों का ही निर्माण किया जा सका है। इसके क्या कारण हैं, वे कौन सी समस्याएँ घबरा कठिनाइयाँ हैं जो बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना में बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं, इन्हीं पर अब हम विचार करेंगे।

## बहुउद्देशीय विद्यालयों की समस्याएँ और उनका समाधान

बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना में जिन विभिन्न समस्याओं का अनुभव किया जा रहा है, वे निम्नांकित हैं:

1. "It can make possible the development of the abilities of children within a framework of community life." S. N. Mukerji : *op. cit.*, p. 149.
2. Humayun Kabir : *op. cit.*, pp. 56-57,

० -  
 १. उही विद्यालय के किसी अन्य समूह में स्थानांतरित करना ज़रूर होगा है।

## ० एन० मुकर्जी के विचार

एन० एन० मुकर्जी न माध्यमिक विद्यालय के वर्गानुवर्गित चार मानते हैं।

१. यह छात्रों में जोर तुरन्त जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों तथा स्त्रियों में सामुदायिक एकता की कृति, घनिष्ठ सामुदायिक भावना की उत्पत्ति, अभिन्नता की स्मृति तथा 'समानता' के विस्तार में योग देता है।

२. यह छात्रों को उनके निम्ने उपयुक्त समूहों में प्रविष्ट करने के निम्ने एक विशिष्ट प्रकार का प्रवरण गृह है, क्योंकि बालका की योग्यताओं का अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उनकी एक प्रकार के पाठ्य-क्रम से दूसरे में स्थानांतरित कर देना अधिक सरल है।

३. यह उन विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा बालका की उच्च विद्यालय को उसमें अध्ययन करने वाले उन छात्रों में पूर्ण करने की सहाय्य प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है, जो उन विद्यालयों को प्रवेश देता है, जिनके निम्ने अन्य विद्यालयों के द्वार बन्द रहते हैं।

1. "It helps to solve the problem of the wrongly classified pupil, because transfer within the same school is easier to arrange than transfer from one school to another." *Ibid.*
2. "It contributes to the furtherance of social unity, the development of a closely knit community feeling, the reduction in class distinctions and the development of a 'parity of esteem' among students and later men and women in various walks of life." S. N. Mukerji : *Education in India, Today and Tomorrow*, p. 149.
3. "It is a suitable type of sorting house for directing pupils to their appropriate groups, since the transfer of children from one type of course to another in the light of fuller knowledge of their aptitudes is easier."—*Ibid.*
4. "It can overcome the inevitable tendency of teachers, parents and children to look down upon the school (and pupils who attend it) which admits those who are denied admission in other schools." *Ibid.*

है—मानव-विज्ञान विज्ञान, प्रागैहिक, वाणिज्यिक, कृषि, सलितकलायें और गृह-विज्ञान । इन समूहों के विषय निश्चित कर दिये गये हैं । 'प्रखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्' और कुछ राज्यों ने निश्चित कर दिया है कि छात्रों को विभिन्न कलाओं में इन विषयों का कितना अध्ययन करना है । परन्तु इसमें दो स्पष्ट दोष हैं । प्रथम, सब राज्यों में शिक्षा का समान स्तर नहीं है । द्वितीय, इन विषयों की पाठ्य-सामग्री को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त बहुउद्देशीय विद्यालयों को किन्हीं भी दो समूहों में शिक्षण प्रदान करने की आज्ञा दे दी गई है । इसका बहुउद्देशीय विद्यालयों के प्रबन्धकों ने अति अनुचित लाभ उठाया है, क्योंकि उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार किन्हीं भी दो समूहों का चयन कर लिया है । उन्होंने विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की आवश्यकताओं की ओर अल्प मात्रा में ध्यान नहीं दिया है । परिणामतः विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों की संज्ञा तो प्राप्त हो गई है, परन्तु उनके कनेवर में वांछित परिवर्तन नहीं हुआ है ।

इस समस्या का समाधान करने के लिये तीन बातों की आवश्यकता है । प्रथम, 'केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय' अथवा 'प्रखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्' समस्त भारत के बहुउद्देशीय विद्यालयों के विषयों की पाठ्य-सामग्री को शिक्षा-विशेषज्ञों के परामर्श से निर्धारित करे । परन्तु ऐसा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षा-विशेषज्ञ विभिन्न राज्यों का भ्रमण करके वहाँ के विभिन्न मार्गों की स्थानीय आवश्यकताओं का अध्ययन करें और उसके उपरान्त ही अपने सुझाव दें । द्वितीय, बहुउद्देशीय विद्यालयों को केवल उन्हीं समूहों में शिक्षा प्रदान करने की आज्ञा दी जाय जो उनमें अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये हितकर विद्य हो सकें । तृतीय, बहुउद्देशीय विद्यालयों में केवल उन्ही शिल्प का शिक्षण किया जाय, जो स्थानीय आवश्यकता के लिये उपयुक्त हो । इससे दो लाभ होंगे । छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रम किया जा सकेगा और उससे प्राप्त धन को विद्यालय के हितार्थ उपयोग किया जा सकेगा । दूसरा लाभ यह होगा कि उस शिल्प का अध्ययन करके छात्र स्थानीय उद्योगों में कार्य करके अथवा स्वतंत्र रूप से उस वस्तु का उत्पादन करके अपने जीवन का निर्वाह कर सकेंगे ।

एक अन्य सुझाव यह भी है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों में कम से कम तीन समूहों की शिक्षा दी जाय, दो की नहीं । यदि तीन समूह होंगे, तो कक्षा ६,

## १. विद्यालयों को परिणत तथा स्थापित करने की समस्या<sup>१</sup>

सरकारी निर्णय के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत में बहुउद्देशीय विद्यालयों की संख्या १,४०० हो जायगी। इनमें से कुछ वे होंगे जो हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों से बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिणत किये जायेंगे और कुछ का नवीन निर्माण होगा। परन्तु ऐसा कोई भी राजकीय लेख-प्रमाण नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि कौन से माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिणत किया जायगा और क्यों? वस्तुतः बिना किसी विचार-पूर्ण पूर्व योजना के यह कार्य सम्पादित किया जा रहा है। बहुउद्देशीय विद्यालयों के नवनिर्माण के सम्बन्ध में भी यही बात सत्य है। ऐसे अनेकों बहुउद्देशीय विद्यालय देश में स्थापित कर दिये गये हैं, जहाँ उनकी उपादेयता के पक्ष में कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

आवश्यकता इस बात की है कि बहुउद्देशीय विद्यालय सर्व प्रथम उन्हीं स्थानों में स्थापित किये जायें, जहाँ उनकी वास्तव में माँग हो और जहाँ वे स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ हों। इस कार्य में सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब कि सम्पूर्ण देश का सर्वेक्षण किया जाय और तब आवश्यकतानुसार बहुउद्देशीय विद्यालयों का वितरित किया जाय। इसके प्रतिरिक्त केवल उन्हीं माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिणत किया जाय, जो इस योग्य हों। एक स्कूल को बहुउद्देशीय विद्यालय में परिणत करते समय प्रयत्नित बातों को ध्यान में रखा जाय—(१) स्थानीय आवश्यकता, (२) उत्तम स्थान पर उत्तम भवन जिससे कि उसका विकास किया जा सके, (३) आवागमन की सुविधा, (४) संतोषजनक आर्थिक अवस्था, तथा (५) पर्याप्त शिक्षण सामग्री। यदि कोई स्कूल इन बातों को पूर्ण नहीं करता है, तो उसको बहुउद्देशीय विद्यालय में परिणत न किया जाय। प्रायः इन्हीं बातों का ध्यान नवीन बहुउद्देशीय विद्यालयों को निर्मित करते समय रखा जाय। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बलपूर्वक कहा जा सकता है कि सरकार की बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना पर ओपण कुठाराघात होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

## २. पाठ्य-क्रम के विभिन्नोत्प्रेरण की समस्या<sup>२</sup>

बहुउद्देशीय विद्यालयों के पाठ्य-क्रम में सात समूहों को स्थान दिया गया

1. Problem of selection of schools for conversion<sup>their</sup> establishment.
2. Problem of diversification of Cou

अपने कोई उचित परामर्श नहीं देते हैं। इसके विपरीत, वे हमें से माँग करते हैं कि बहुउद्देशीय विद्यालयों में पूर्णतया प्रयोगशालाएँ (Laboratories), विशाल कर्मशालाएँ (Work-shops), विस्तृत भूभाग आदि हों। शिक्षा-विभाग के अधिकारियों के इस बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना को कार्यान्वित करने में सफलता मिली है।

इसका समाधान अत्यन्त सरलता पूर्वक किया जा सकता है। इन विद्यालयों का अधिकांश प्रायोगिक (Practical) तथा कर्मशाला-युक्त निकटवर्ती औद्योगिक भवन या व्यावसायिक कर्मों में किया जा सकने का उदाहरण हमारे समक्ष है। विद्यालय जाने वाले प्रत्येक बच्चे को किसी निकट की फ़ैक्ट्री में कुछ घण्टे व्यतीत करने पड़ते हैं। यदि हम इस योजना को अपना लिया जाय, तो बहुउद्देशीय विद्यालयों में अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही अधिक उत्तम तथा व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

### कौनों की समस्या<sup>३</sup>

देशीय विद्यालयों के लिये उचित दीक्षाणुक्त प्रवृत्तियों (Educational Tendencies) वाले शिक्षकों की सेवाओं को प्राप्त करना एक ऐसी जटिल समस्या समाधान सरलता पूर्वक नहीं किया जा सकता है। जिन विज्ञान तथा प्रायोगिक विषयों में उच्च दीक्षाणुक्त प्रवृत्तियाँ हैं, वे प्रति आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि इसमें शिक्षकों को प्रति प्रति मिलता है। बात बहुत स्वाभाविक ही है कि जब विज्ञान तथा विषयों के स्नातकों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक कर्मों में उच्च विरक्त अन्य सुविधायें ही उपलब्ध हो सकती हैं, तब वे न्यून वेतन देने पर मुरझाए रहने का आश्वासन भी न पाकर अध्यापन के

udies in the class room are linked with practical  
ies, not only through excursions to museums and the  
of films and models and practical science, but through  
ing a certain number of hours with machines in a  
rby factory, and learning about the factory and how  
orks, what it makes and what its products are used  
"—Maurice Dobb: *U. S. S. R. Her Life and Her Peo-*  
p. 106.

problem of the Staff.



१० और ११ में ३०० से ५०० तक छात्र हो जायेंगे। यदि विद्यालयों में छात्रों की इतनी संख्या नहीं होगी, तो उनको सफलता मितव्ययता से संवाहित नहीं किया जा सकेगा।

### ३. पाठ्य-पुस्तकों तथा समय-सारणियों की समस्या<sup>१</sup>

बहुउद्देशीय विद्यालयों की एक समस्या पाठ्य-पुस्तकों तथा सारणियों की है। जो भी प्रधानाध्यापक बहुउद्देशीय विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं, उन्हें इन दोनों कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों का अभाव है। अध्यापकों को इस प्रकार के विद्यालयों की समय-सारणियाँ बनाने का अवसर नहीं है। वे इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि किस विषय के लिये किस विषय दिया जाना चाहिये। फलतः वे प्राविधिक विषयों तथा हस्तकलाओं में सामान्य शिक्षा के विषयों को अधिक प्रधानता प्रदान करते हैं। बहुउद्देशीय विद्यालयों के उद्देश्यों की पूर्ति होना सम्भव नहीं है।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक जान पड़ता है कि भारत सरकारें अथवा शिक्षा-विभाग अपनी देख-रेख में शीघ्रातिशीघ्र पुस्तकें तैयार करावें और जो शिक्षक तथा लेखक इस प्रकार की पुस्तकें लिखना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहन एवं प्राधिक सहायता दें। इस प्रकार सरकार प्रादर्श-समय सारणियाँ भी तैयार करावे जिससे कि प्रधानाध्यापकों का पथ-प्रदर्शन हो सके।

### ४. व्यावसायिक पाठ्य-क्रमों की समस्या<sup>२</sup>

व्यावसायिक विषयों के शिक्षण की व्यवस्था करने में पर्याप्त आवश्यकता होने के कारण बहुउद्देशीय विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा कुछ समस्या का अनुभव किया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों की संख्या न केवल उनके पास धन का अभाव नहीं है। साधारणतः प्रबन्ध समितियाँ विद्यालयों-स्थलों करके चला पाती हैं। अतः अजिकाल बहुउद्देशीय विद्यालयों को इतना धन नहीं है कि वे व्यावसायिक विषयों के शिक्षण का समुचित कर सकें। धनभाव के कारण ही अनेकों प्रबन्ध समितियाँ न तो हाई स्कूलों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिणत कर सकती हैं और न नवोन बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना कर सकती हैं। उनकी कठिनाई इसलिए अधिक हो जाती है क्योंकि शिक्षा-विभाग उन्हें अपनी कठिनाइयों पर

1. Problem of Text-Books and Time Tables.

2. Problem of Vocational Courses.

प्राप्त करने के लिये कोई उचित परामर्श नहीं देते हैं। इसके विपरीत, वे प्रबन्ध समितियों से माँग करते हैं कि बहुउद्देशीय विद्यालयों में पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशालायें (Laboratories), विद्यालय कर्मशालायें (Work-shops), कृषि के लिये विस्तृत भूभाग आदि हों। शिक्षा-विभाग के अधिकारियों के इस दृष्टिकोण से बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना को कार्यान्वित करने में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है।

इस समस्या का समाधान अत्यन्त सरलता पूर्वक किया जा सकता है। इन बहुउद्देशीय विद्यालयों का अधिकांश प्रायोगिक (Practical) तथा कर्मशाला-सम्बन्धी कार्य निकटवर्ती भौगोलिक अथवा व्यावसायिक क्रमों में किया जा सकता है। इस का उदाहरण हमारे समक्ष है। विद्यालय जाने वाले प्रत्येक बालक को किसी निकट की फ़ैक्ट्री में कुछ घण्टे व्यतीत करने पड़ते हैं।<sup>१</sup> यदि हमारे देश में भी इस योजना को अपना लिया जाय, तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना में अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही छात्रों को अधिक उत्तम तथा व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

## ५. शिक्षकों की समस्या<sup>२</sup>

बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिये उचित शैक्षणिक षट्तांशों (Educational Qualifications) वाले शिक्षकों की सेवाओं को प्राप्त करना एक ऐसी जटिल समस्या है जिसका समाधान सरलता पूर्वक नहीं किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों की विज्ञान तथा प्रावधिक विषयों में उच्च शैक्षणिक षट्तांश हैं, वे शिक्षा-वृत्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि इसमें शिक्षकों को प्रति म्यून वेतन मिलता है। बात बहुत स्वभाविक ही है कि जब विज्ञान तथा प्रावधिक विषयों के स्नातकों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्रमों में उच्च वेतन के प्रतिरिक्त अन्य सुविधायें ही उपलब्ध हो सकती हैं, तब वे न्यून वेतन पर और अपने पद पर सुरक्षित रहने का आश्वासन भी न पाकर अध्यापन के

1. "Studies in the class room are linked with practical studies, not only through excursions to museums and the use of films and models and practical science, but through having a certain number of hours with machines in a nearby factory, and learning about the factory and how it works, what it makes and what its products are used for."—Maurice Dobb: *U. S. S. R. Her Life and Her People*, p. 106.

2. Problem of the Staff.

१० धीरे ११ से १०० से १०० तक पाठ हो जायेंगे। यदि बहुउद्देशीय विद्यालयों में पाठों की इतनी संख्या नहीं हो गी, तो उनको सञ्चयता पूर्वक तथा मितव्ययता से संवाहित नहीं किया जा सकेगा।

### ३. पाठ्य-पुस्तकों तथा समय-सारणियों की समस्या

बहुउद्देशीय विद्यालयों की एक समस्या पाठ्य-पुस्तकों तथा समय-सारणियों की है। जो भी प्रधानाध्यापक बहुउद्देशीय विद्यालयों का संवाहन कर रहे हैं, उन्हें इन दोनों कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों का अभाव है। प्राधान्याध्यापकों को इस प्रकार के विद्यालयों की समय-सारणियाँ बनाने का कोई अनुभव नहीं है। वे इन तथ्य से परगत नहीं हैं कि किस विषय के लिये कितना समय दिया जाना चाहिये। फलतः वे प्राथमिक विषयों तथा हस्तकलाओं की प्रेरणा सामान्य शिक्षा के विषयों की अधिक प्रपानता प्रदान करते हैं। इससे बहु-उद्देशीय विद्यालयों के उद्देश्यों की पूर्ति होना सम्भव नहीं है।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक जान पड़ता है कि भारत सरकार, राज्य सरकारें अथवा शिक्षा-विभाग अपनी देल-रेल में लोप्रातिशील पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराये और जो शिक्षक तथा लेखक इस प्रकार की पुस्तकें लिखना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता दें। इसी प्रकार सरकार आदर्श-समय सारणियाँ भी तैयार करावे जिससे कि प्रधानाध्यापकों का पथ-प्रदर्शन हो सके।

### ४. व्यावसायिक पाठ्य-क्रमों की समस्या

व्यावसायिक विषयों के शिक्षण की व्यवस्था करने में पर्याप्त धन की आवश्यकता होने के कारण बहुउद्देशीय विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा प्रति दुर्लभ समस्या का अनुभव किया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों की संख्या नगण्य है, जिनके पास धन का अभाव नहीं है। साधारणतः प्रबन्ध समितियाँ विद्यालयों को ज्यों-ज्यों करके चला पाती हैं। अतः अधिकांश बहुउद्देशीय विद्यालयों के पास इतना धन नहीं है कि वे व्यावसायिक विषयों के शिक्षण का समुचित प्रबन्ध कर सकें। धनाभाव के कारण ही अनेकों प्रबन्ध समितियाँ न तो हाई स्कूलों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिणत कर सकती हैं और न नवोन बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना कर सकती हैं। उनकी कठिनाई इसलिए और भी अधिक हो जाती है क्योंकि शिक्षा-विभाग उन्हें अपनी कठिनाइयों पर विजय

1. Problem of Text-Books and Time Tables.
2. Problem of Vocational Courses.

## ६. अभिभावकों के विरोध की समस्या

श्री नटराजन (Natrajan) ने एक अन्य समस्या का उल्लेख किया है, जो व्यावहारिक रूप में बहुउद्देशीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को व्यापित कर रही है। यह समस्या है, छात्रों के अभिभावकों की संतुष्टि की। छात्रों द्वारा विषयों के चुनाव किये जाने में अभिभावकों की इच्छाओं को सम्मानित किया जाना आवश्यक है। यदि एक छात्र को उसकी अभियोग्यताओं तथा अभिरुचियों को ध्यान में रखकर 'रूपि समूह' के विषयों का अध्ययन करने का परामर्श दिया जाता है और यदि अभिभावक चाहता है कि छात्र को 'प्राथमिक समूह' के विषय दिये जायें, तो बहुउद्देशीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समक्ष एक जटिल समस्या उपस्थित हो जाती है।

श्री नटराजन ने इस समस्या का समाधान भी बताया है। उनका कहना है कि यदि मार्ग-प्रदर्शन की विधि को पूर्णरूप से समुपेत कर दिया जाय, तो अभिभावक को यह विश्वास दिताना कठिन नहीं होगा कि छात्र को जिस समूह के विषयों को लेने का परामर्श दिया गया है, वे उसके लिये हितकर सिद्ध होंगे, क्योंकि वह अपनी अभियोग्यताओं एवं अभिनतियों (Inclinations) के कारण उनके लिये उपयुक्त है।<sup>१</sup>

बहुउद्देशीय विद्यालयों की जिन समस्याओं का वर्णन ऊपर किया गया है, वे वस्तुतः बाधक सिद्ध हो रही हैं। यदि यह वांछित है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की सख्या में प्रबाध गति से वृद्धि हो, तो यह नितांत आवश्यक है कि इन समस्याओं के समाधान के लिये उपर्युक्त सुझावों का सरकार, विद्यालयों के प्रबन्धकों तथा शिक्षा-विभागों द्वारा परीक्षण किया जाय। यदि ऐसा किया गया, तो हमें विश्वास है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का कार्य पर्याप्त सरल हो जायगा।

1. "A problem which Headmasters of Multipurpose Schools are faced with is satisfying the wishes of the parents. Parents' views in respect of the choice of courses certainly constitute an important factor and cannot be ignored, but if the technique of guidance is well developed, it should not be impossible to convince the parents that a particular child would do better, if put into a practical course rather than in a purely academic course."—Sri Natrajan's Article; *"Multipurpose School and Guidance" in Educational and Vocational Guidance in Multipurpose Schools*, p. 33.



## ६. अभिभावकों के विरोध की समस्या

श्री नटराजन (Natrajan) ने एक अन्य समस्या का उल्लेख किया है, जो व्यावहारिक रूप में बहुउद्देशीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को व्यथित कर रही है। यह समस्या है, छात्रों के अभिभावकों की संतुष्टि की। छात्रों द्वारा विषयों के चुनाव किये जाने में अभिभावकों की इच्छाओं को सम्मानित किया जाना आवश्यक है। यदि एक छात्र को उसकी अभियोग्यताओं तथा अभिरूचियों को ध्यान में रखकर 'कृषि समूह' के विषयों का अध्ययन करने का परामर्श दिया जाता है और यदि अभिभावक चाहता है कि छात्र को 'प्रादेशिक समूह' के विषय दिये जायें, तो बहुउद्देशीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समक्ष एक जटिल समस्या उपस्थित हो जाती है।

श्री नटराजन ने इस समस्या का समाधान भी बताया है। उनका कहना है कि यदि मार्ग-प्रदर्शन की विधि को पूर्णरूप से समुन्नत कर दिया जाय, तो अभिभावक को यह विश्वास दिलाना कठिन नहीं होगा कि छात्र को जिस समूह के विषयों को लेने का परामर्श दिया गया है, वे उसके लिये हितकर सिद्ध होंगे, क्योंकि यह अपनी अभियोग्यताओं एवं अभिनतियों (Inclinations) के कारण उनके लिये उपयुक्त हैं।<sup>१</sup>

बहुउद्देशीय विद्यालयों की जिन समस्याओं का वर्णन ऊपर किया गया है, वे वस्तुतः बाधक सिद्ध हो रही हैं। यदि यह वाञ्छित है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की संख्या में प्रगति गति से वृद्धि हो, तो यह नितांत आवश्यक है कि इन समस्याओं के समाधान के लिये उपरिवर्णित सुझावों का सरकार, विद्यालयों के प्रबन्धकों तथा शिक्षा-विभागों द्वारा परीक्षण किया जाय। यदि ऐसा किया गया, तो हमें विश्वास है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का कार्य पूर्णतः सरल हो जायगा।

1. "A problem which Headmasters of Multipurpose Schools are faced with is satisfying the wishes of the parents. Parents' views in respect of the choice of courses certainly constitute an important factor and cannot be ignored, but if the technique of guidance is well developed, it should not be impossible to convince the parents that a particular child would do better, if put into a practical course rather than in a purely academic course."—Sri Natrajan's Article; "Multipurpose School and Guidance" in *Educational and Vocational Guidance in Multipurpose Schools*, p. 33.

## सारांश

बहुउद्देशीय विद्यालय का ध्येय :—मुद्रालियर कमीशन के अनुसार "एक बहुउद्देशीय विद्यालय विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों तथा योग्यताओं वाले छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्य-क्रमों का आयोजन करता है। यह प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा चयन किये गए अध्ययन के विशिष्ट पाठ्य-क्रम में अपनी स्वाभाविक योग्यताओं तथा अभिनतियों का प्रयोग करने तथा उनको विकसित करने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है।"

बहुउद्देशीय विद्यालय के उद्देश्य—बहुउद्देशीय विद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—(१) उन साधनों, सामग्रियों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग की व्यापक शिक्षा प्रदान करना जो सम्प्रदाय के विकास-क्रम को आगे बढ़ाने में योग्य है, (२) छात्रों की समताओं को राष्ट्रीय चरित्र एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माण की दिशा में परिवर्तित करना, (४) छात्रों में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और उनमें स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की योग्यता उत्पन्न करना, (५) छात्रों में एक शिल्प की इतनी दक्षता उत्पन्न कर देना कि वे उससे सम्बन्धित व्यवसाय को सफलतापूर्वक कर सकें, और (६) छात्रों को किसी रचनात्मक, उत्पादक तथा समाज के लिए हितकर कार्य की शिक्षा देना।

बहुउद्देशीय विद्यालयों की प्रगति—बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना प्रारम्भ १९५४ से प्रारम्भ की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में २५० बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए गए। द्वितीय योजना के अन्त तक १,४०० बहुउद्देशीय विद्यालय हो जायेंगे।

बहुउद्देशीय विद्यालयों की आवश्यकताएँ—ये आवश्यकताएँ हुपायूँ के अनुसार अपरलिखित हैं :—(१) बहुउद्देशीय विद्यालय विभिन्न पाठ्य-की शिक्षा देगे, (२) माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय नहीं रहेगी, (३) अपनी के अनुसार विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करके छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होगा, (४) बहुउद्देशीय विद्यालयों का विभिन्न पाठ्य-क्रम किछोर की वापरीक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक मामों की पूर्ति करेगा, (५) के अन्तर्हित गुणों का विकास होगा, (६) छात्रों को वैज्ञानिक शक्तों में हुए शिल्प का बहुउद्देशीय विद्यालयों में अधिक अध्ययन करने का अवसर होगा, और (७) वापरीक धन के प्रति सामाजिक पूर्णा का अन्त होगा।

बहुउद्देशीय विद्यालयों के लाभ—माध्यमिक शिक्षा-आयोग के अनुसार (१) विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के कारण छात्रों में उत्पन्न हो

पुष्पास्पद भेद-भाव का अन्त, (२) शिक्षा-प्रणाली का प्रजातन्त्रीय आधार पर आयोजन, (३) छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषयों का चयन, और (४) छात्रों का भूल के कारण एक पाठ्य-क्रम से दूसरे को स्थानांतरण। मुकर्जी के अनुसार—(१) सामुदायिक एकता की वृद्धि, (२) सामुदायिक भावना की उन्नति, (३) वर्ग-भेदों की न्यूनता, (४) सम्मान की समानता में वृद्धि, (५) छात्रों का उपयुक्त समूहों में प्रवेश, (६) सामुदायिक जीवन की संरचना के अन्तर्गत बालकों की योग्यताओं में उन्नति। हुमायूँ कबीर के अनुसार—(१) विभिन्न योग्यताओं तथा रुचियों वाले छात्रों के लिये विभिन्न पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था, (२) कृषि, भौतिक तथा प्राविधिक कार्यों के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण, (३) पाठ्य-क्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा छात्रों को आत्म-अभिध्यात का अवसर और (४) हस्तकला की शिक्षा द्वारा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान।

बहुउद्देशीय विद्यालयों की समस्याएँ—ये समस्याएँ अश्राकित हैं—(१) विद्यालयों की परिणत तथा स्थापित करने की समस्या, (२) पाठ्य-क्रम के विभिन्नीकरण की समस्या, (३) पाठ्य-पुस्तकों तथा समय-सारणियों की समस्या, (४) व्यावसायिक पाठ्य-क्रमों की समस्या, (५) शिक्षकों की समस्या, और (६) अभिभावकों के विरोध की समस्या।

## सहायक पुस्तकों की सूची

1. *Report of the Secondary Education Commission.*
2. *Educational and Vocational Guidance in Multipurpose Schools.*
3. *Humayun Kabir : Education in New India.*
4. *S. N. Mukerji : Education in India, Today and Tomorrow.*
5. *Maurice Dobb : U. S. S. R. Her Life and Her people.*
6. शिक्षा-विचार गोष्ठी, नैनीताल की विवरण-पत्रिका।
7. द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
8. तीसरी पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक रूपरेखा।
9. मिगरेन और शर्मा : हमारे शिक्षा-प्रतिवेदन।



## सारांश

**बहुउद्देशीय विद्यालय का धर्म :—**मुद्रालियर कमीशन के अनुसार "एक बहुउद्देशीय विद्यालय विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों तथा योग्यताओं वाले छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्य-क्रमों का आयोजन करता है। यह प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा चयन किये गए अध्ययन के विशिष्ट पाठ्य-क्रम में अपनी स्वाभाविक योग्यताओं तथा अभिनतियों का प्रयोग करने तथा उनको विकसित करने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है।"

**बहुउद्देश्य विद्यालय के उद्देश्य—**बहुउद्देशीय विद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—(१) उन साधनों, सामग्रियों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग की व्यापक शिक्षा प्रदान करना जो सम्प्रदाय के विकास-क्रम को धीमे बढ़ाने में योग्य देती हैं, (२) छात्र के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास करना, (३) छात्रों की क्षमताओं को राष्ट्रीय चरित्र एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माण की दिशा में परिचालित करना, (४) छात्रों में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और उनमें स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की योग्यता उत्पन्न करना, (५) छात्रों में एक शिल्प की इतनी दक्षता उत्पन्न कर देना कि वे उससे सम्बन्धित व्यवसाय को सफलतापूर्वक कर सकें, और (६) छात्रों को किसी रचनात्मक, उत्पादक तथा समाज के लिए हितकर कार्य की शिक्षा देना।

बहुउद्देशीय विद्यालयों की प्रगति—बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना अक्टूबर १९५४ से प्रारम्भ की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में २५० बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए गए। द्वितीय योजना के अन्त तक १,४०० बहुउद्देशीय विद्यालय हो जायेंगे।

**बहुउद्देशीय विद्यालयों की आवश्यकताएँ—**ये आवश्यकताएँ हुमायूँ कबीर के अनुसार अम्लिखित हैं :—(१) बहुउद्देशीय विद्यालय विभिन्न पाठ्य-क्रमों की शिक्षा देगे, (२) माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय नहीं रहेगी, (३) अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करके छात्रों के व्यक्तित्व का विकास सम्भव होगा, (४) बहुउद्देशीय विद्यालयों का विभिन्न पाठ्य-क्रम किशोर छात्रों की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक माँगों की पूर्ति करेगा, (५) छात्रों के अन्तर्हित गुणों का विकास होगा, (६) छात्रों को बेहिक स्कूलों में सीखे हुए शिल्प का बहुउद्देशीय विद्यालयों में अधिक अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा, और (७) शारीरिक धर्म के प्रति सामाजिक दृष्टि का अन्त होगा।

बहुउद्देशीय विद्यालयों के लाभ—माध्यमिक शिक्षा-आयोग के अनुसार—(१) विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के कारण छात्रों में उत्पन्न होने वाले

दृष्टास्पद भेद-भाव का अन्त, (२) शिक्षा-प्रणाली का प्रजातन्त्रीय आधार पर आयोजन, (३) छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषयों का चयन, और (४) छात्रों का भूल के कारण एक पाठ्य-क्रम से दूसरे को स्थानांतरण। मुकर्जी के अनुसार—(१) सामुदायिक एकता की वृद्धि, (२) सामुदायिक भावना की उन्नति, (३) वर्ग-भेदों की न्यूनता, (४) सम्मान की समानता में वृद्धि, (५) छात्रों का उपयुक्त समूहों में प्रेषण, (६) सामुदायिक जीवन की संरचना के अन्तर्गत बालकों की योग्यताओं में उन्नति। हुमायूँ कबीर के अनुसार—(१) विभिन्न योग्यताओं तथा रुचियों वाले छात्रों के लिये विभिन्न पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था, (२) कृषि, औद्योगिक तथा प्राविधिक कार्यों के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण, (३) पाठ्य-क्रम सहभागी क्रियाओं द्वारा छात्रों को आत्म-प्रतिबद्धता का अवसर और (४) हस्तकला की शिक्षा द्वारा शारीरिक धर्म के प्रति सम्मान।

बहुउद्देशीय विद्यालयों की समस्याएँ—ये समस्याएँ प्रदाकित हैं—(१) विद्यालयों को परिणत तथा स्थापित करने की समस्या, (२) पाठ्य-क्रम के विभिन्नीकरण की समस्या, (३) पाठ्य-पुस्तकों तथा समय-सारणियों की समस्या, (४) व्यावसायिक पाठ्य-क्रमों की समस्या, (५) शिक्षकों की समस्या, और (६) अभिभावकों के विरोध की समस्या।

## सहायक पुस्तकों की सूची

1. *Report of the Secondary Education Commission.*
2. *Educational and Vocational Guidance in Multipurpose Schools.*
3. Humayun Kabir : *Education in New India.*
4. S. N. Mukerji : *Education in India, Today and Tomorrow.*
5. Maurice Dobb : *U. S. S. R. Her Life and Her people.*
६. शिक्षा-विचार गोष्ठी, नैनीताल की विवरण-पत्रिका।
७. द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
८. तीसरी पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक रूपरेखा।
९. फ्लारन और शर्मा : हमारे शिक्षा-प्रतिवेदन।

## सारांश

**बहुउद्देशीय विद्यालय का अर्थ :**—मुद्रालियर कमीशन के अनुसार "एक बहुउद्देशीय विद्यालय विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों तथा योग्यताओं वाले छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्य-क्रमों का आयोजन करता है। यह प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा चयन किये गए अध्ययन के विशिष्ट पाठ्य-क्रम में अपनी स्वाभाविक योग्यताओं तथा अभिनतियों का प्रयोग करने तथा उनको विकसित करने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है।"

**बहुउद्देश्य विद्यालय के उद्देश्य**—बहुउद्देशीय विद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—(१) उन साधनों, सामग्रियों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग की व्यापक शिक्षा प्रदान करना जो सम्पत्ता के विकास-क्रम को भागे बढ़ाने में योग्य होती है, (२) छात्र के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास करना, (३) छात्रों की क्षमताओं को राष्ट्रीय चरित्र एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माण की दिशा में परिचित करना, (४) छात्रों में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और उनमें स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की योग्यता उत्पन्न करना, (५) छात्रों में एक चित्त की इतनी दक्षता उत्पन्न कर देना कि वे उससे सम्बन्धित व्यवसाय को सफलतापूर्वक कर सकें, और (६) छात्रों को किसी रचनात्मक, उत्साहक तथा समाज के लिए हितकर कार्य की शिक्षा देना।

**बहुउद्देशीय विद्यालयों की प्रगति**—बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना सन् १९४४ से प्रारम्भ की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में २५० बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए गए। द्वितीय योजना के अन्त तक १,४०० बहुउद्देशीय विद्यालय हो जायेंगे।

**बहुउद्देशीय विद्यालयों की आवश्यकताएँ**—ये आवश्यकताएँ हमारे कबीर के अनुसार सप्रतिष्ठित हैं :—(१) बहुउद्देशीय विद्यालय विभिन्न पाठ्य-क्रमों की शिक्षा देगे, (२) माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय नहीं रहेगी, (३) अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करके छात्रों के व्यक्तित्व का विकास सम्भव होगा, (४) बहुउद्देशीय विद्यालयों का विभिन्न पाठ्य-क्रम किछोर छात्रों की पारोरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मानवतात्मक मानों की पूर्ति करेगा, (५) छात्रों के अन्तर्हित गुणों का विकास होगा, (६) छात्रों को वैज्ञानिक सूत्रों में सीधे हुए चित्त का बहुउद्देशीय विद्यालयों में अधिक अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा, और (७) पारोरिक अर्थ के प्रति सामाजिक पूर्णा का अन्त होगा।

**बहुउद्देशीय विद्यालयों के लाभ**—माध्यमिक शिक्षा-आयोग के अनुसार—(१) विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के कारण छात्रों में उत्पन्न होने वाले

धृष्टास्वयं भेद-भाव का अन्त, (२) शिक्षा-प्रणाली का प्रजातन्त्रीय आधार पर आयोजन, (३) छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषयों का चयन, और (४) छात्रों का भूल के कारण एक पाठ्य-क्रम से दूसरे को स्थानांतरण। मुकर्जी के अनुसार—(१) सामुदायिक एकता की वृद्धि, (२) सामुदायिक भावना की उन्नति, (३) वर्ग-भेदों की न्यूनता, (४) सम्मान की समानता में वृद्धि, (५) छात्रों का उपयुक्त समूहों में प्रेषण, (६) सामुदायिक जीवन की संरचना के अन्तर्गत बालकों की योग्यताओं में उन्नति। हुमायूँ कबीर के अनुसार—(१) विभिन्न योग्यताओं तथा रुचियों वाले छात्रों के लिये विभिन्न पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था, (२) कृषि, औद्योगिक तथा प्राविधिक कार्यों के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण, (३) पाठ्य-क्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा छात्रों को आत्म-प्रतिबोध का अवसर और (४) हस्तकला की शिक्षा द्वारा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान।

बहुउद्देशीय विद्यालयों की समस्याएँ—ये समस्याएँ अप्रकट हैं—(१) विद्यालयों को परिणत तथा स्थापित करने की समस्या, (२) पाठ्य-क्रम के विभिन्नीकरण की समस्या, (३) पाठ्य-पुस्तकों तथा समय-सारणियों की समस्या, (४) व्यावसायिक पाठ्य-क्रमों की समस्या, (५) शिक्षकों की समस्या, और (६) अभिभावकों के विरोध की समस्या।

## सहायक पुस्तकों की सूची

1. *Report of the Secondary Education Commission.*
2. *Educational and Vocational Guidance in Multipurpose Schools.*
3. Humayun Kabir : *Education in New India.*
4. S. N. Mukerji : *Education in India, Today and Tomorrow.*
5. Maurice Dobb : *U. S. S. R. Her Life and Her people.*
6. शिक्षा-विचार गोष्ठी, नैनीताल की विवरण-पत्रिका।
7. द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
8. तृतीय पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक रूपरेखा।
9. फ़िररन और शर्मा : हमारे शिक्षा-प्रतिवेदन।

## सारांश

**बहुउद्देशीय विद्यालय का अर्थ :**—मुदालियर कमिशन के अनुसार "एक बहुउद्देशीय विद्यालय विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों तथा योग्यताओं वाले छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्य-क्रमों का आयोजन करता है। यह प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा चयन किये गए अध्ययन के विशिष्ट पाठ्य-क्रम में अपनी स्वाभाविक योग्यताओं तथा अभिनतियों का प्रयोग करने तथा उनको विकसित करने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है।"

**बहुउद्देश्य विद्यालय के उद्देश्य**—बहुउद्देशीय विद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—(१) उन साधनों, सामग्रियों एवं प्रक्रियाओं के प्रयोग की व्यापक शिक्षा प्रदान करना जो सम्पत्ता के विकास-क्रम को आगे बढ़ाने में योग्य होती हैं, (२) छात्र के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास करना, (३) छात्रों की क्षमताओं को राष्ट्रीय चरित्र एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति के निर्माण की दिशा में परिचित करना, (४) छात्रों में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और उनमें स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की योग्यता उत्पन्न करना, (५) छात्रों में एक चित्त की इतनी दक्षता उत्पन्न कर देना कि वे उससे सम्बन्धित व्यवसाय को सफलतापूर्वक कर सकें, और (६) छात्रों को किसी रचनात्मक, उत्साहक तथा समाज के लिए हितकर कार्य की शिक्षा देना।

**बहुउद्देशीय विद्यालयों की प्रगति**—बहुउद्देशीय विद्यालयों की योजना अक्टूबर १९५४ से प्रारम्भ की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में २५० बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए गए। द्वितीय योजना के अन्त तक १,४०० बहुउद्देशीय विद्यालय हो जायेंगे।

**बहुउद्देशीय विद्यालयों की आवश्यकताएँ**—ये आवश्यकताएँ हुमायूँ कबीर के अनुसार अवलिखित हैं :—(१) बहुउद्देशीय विद्यालय विभिन्न पाठ्य-क्रमों की शिक्षा देंगे, (२) माध्यमिक शिक्षा एक मार्गीय नहीं रहेगी, (३) अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करके छात्रों के व्यक्तित्व का विकास सम्भव होगा, (४) बहुउद्देशीय विद्यालयों का विभिन्न पाठ्य-क्रम किशोर छात्रों की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक मार्गों की पूर्ति करेगा, (५) छात्रों के अन्तर्हित गुणों का विकास होगा, (६) छात्रों को बेसिक स्कूलों से सीखे हुए चित्त का बहुउद्देशीय विद्यालयों में अधिक अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा, और (७) शारीरिक खेल के प्रति सामाजिक धृष्टि का अन्त होगा।

**बहुउद्देशीय विद्यालयों के लाभ**—माध्यमिक शिक्षा-आयोग के अनुसार—  
(१) विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के कारण छात्रों में उत्पन्न होने वाले

पुष्पास्पद भेद-भाव का मन्त, (२) शिक्षा-प्रणाली का प्रजातन्त्रीय माध्यम पर आयोजन, (३) छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषयों का चयन, और (४) छात्रों का भूल के कारण एक पाठ्य-क्रम से दूसरे को स्थानांतरण। मुकर्जी के अनुसार—(१) सामुदायिक एकता की वृद्धि, (२) सामुदायिक भावना की उन्नति, (३) वर्ग-भेदों की न्यूनता, (४) सम्मान की समानता में वृद्धि, (५) छात्रों का उपयुक्त समूहों में प्रवेश, (६) सामुदायिक जीवन की संरचना के अन्तर्गत बालकों की योग्यताओं में उन्नति। हुमायूँ कबीर के अनुसार—(१) विभिन्न योग्यताओं तथा रुचियों वाले छात्रों के लिये विभिन्न पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था, (२) कृषि, औद्योगिक तथा प्राविधिक कार्यों के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण, (३) पाठ्य-क्रम सहजामो क्रियाओं द्वारा छात्रों को आत्म-अभिव्यक्त का अवसर और (४) हस्तकला की शिक्षा द्वारा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान।

बहुवर्षीय विद्यालयों की समस्याएँ—ये समस्याएँ अग्रलिखित हैं—(१) विद्यालयों को परिणत तथा स्थापित करने की समस्या, (२) पाठ्य-क्रम के विभिन्नीकरण की समस्या, (३) पाठ्य-पुस्तकों तथा समव-सारणियों की समस्या, (४) व्यावसायिक पाठ्य-क्रमों की समस्या, (५) शिक्षकों की समस्या, और (६) अभिभावकों के विरोध की समस्या।

## सहायक पुस्तकों की सूची

1. *Report of the Secondary Education Commission.*
2. *Educational and Vocational Guidance in Multipurpose Schools.*
3. Humayun Kabir : *Education in New India.*
4. S. N. Mukerji : *Education in India, Today and Tomorrow.*
5. Maurice Dobb : *U. S. S. R. Her Life and Her people.*
6. शिक्षा-विचार गोष्ठी, नैनीताल की विवरण-पत्रिका।
7. द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
8. तीसरी पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक रूपरेखा।
9. फ़िररन और शर्मा : हमारे शिक्षा-प्रतिवेदन।

## TEST QUESTIONS

1. What do you understand by a multipurpose school? Describe its aims and objects.
2. Briefly describe the need of multipurpose schools in India. How far has this need been fulfilled by the establishment of multipurpose schools in our country?
3. What arguments have you to offer in favour of the establishment of multipurpose schools in your country?
4. "The organisation of multipurpose school is presenting a number of problems." What are these problems and how can they be solved?

## अध्याय ७

### ✓ शिक्षा पर प्रौद्योगिकीय संचात' X

शिक्षा के अन्तर्गत प्रौद्योगिकीय विषयों का समावेश प्राधुनिक युग की देन है। प्राचीन तथा मध्यकालीन युगों में प्रौद्योगिकीय शिक्षा का सामान्य एवं संस्कारी (Liberal) शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं था। भौतिक विज्ञानों तथा प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में गत दो-सौ वर्षों में आवश्यकजनक आविष्कार होने के परिणामस्वरूप संसार का रूप परिवर्तित हो गया है।<sup>1</sup> "व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राधुनिक सभ्यता की प्रमुख विशेषतायें हैं और इनकी प्रगति ने मानव जीवन की दशाओं को परिवर्तित कर दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये मानव जीवन के स्वामी और भादा हो गये हैं। अतः इस परिवर्तन को देखते हुए स्वाभाविक निष्कर्ष यह निकलता है कि शिक्षा को भी परिवर्तित कर देना चाहिये"<sup>2</sup> और उसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय विषयों को महत्वपूर्ण

1. Technological Impact upon Education.
2. "The strides which discoveries in physical sciences and technology have taken within the last two hundred years have changed the face of the world."—Quoted from Dr. Rajendra Prasad's Speech at the Joint meeting of the Inter University Board of India and the Executive Council of the Association of the Universities of the British Commonwealth on December 21, 1951 at the Delhi University.
3. "Applied science and technology are the most characteristic features of modern civilization, and their development has transformed the conditions of human life, and appears to have become its mistress and hope. An obvious conclusion is that, in keeping with this transformation, education should be transformed."—Sir Richard Livingstone : *Some Tasks for Education*, p. 6.





के गर्त में डूब गई। परन्तु भारत में कच्चे माल और खनिज पदार्थों का अभाव नहीं है। हमारे देश की पृथ्वी के गर्भ में अन्न भी लोहे, मैंगनीज, तेल, सोमा-इट, तंबा, बाक्साइट, अभ्रक, इस्मेनाइट आदि के भंडार छिपे हुए हैं। इनके अतिरिक्त, विद्युत के अत्युत्तम साधन भी हैं। परन्तु इनका प्रयोग अभी किया जा सकता है, जब देश में प्रौद्योगिक विषयों तथा विज्ञानों का पूर्ण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हों। दुर्भाग्यवश हमारा देश अभी इस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाया है, यद्यपि हमारी राष्ट्रीय सरकार इस कार्य में संलग्न है। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में प्रौद्योगिक शिक्षा में स्थापनीय उन्नति हुई है और यदि इसी गति से प्रगति होती रहो, तो आगामी कुछ ही वर्षों में देश का आर्थिक विकास हो जायगा और निर्धनता का अन्त हो जायगा।

यद्यपि स्वतंत्र भारत के लिये प्रौद्योगिक शिक्षा नवीन प्रतीत होती है, परन्तु यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करें, तो हमको श्रांत होगा कि प्रौद्योगिक क्षेत्र में भारत उन्नति के प्रति उच्च शिखर पर था। इस क्षेत्र में अवनति के क्या कारण थे और किन कारणों वश आज फिर हमारा देश उस दिशा में अग्रसर हो रहा है— इनका उत्तर खोजने के लिये हमें प्रौद्योगिक शिक्षा के इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालनी पड़ेगी।

## प्राचीन काल में प्रौद्योगिक शिक्षा

प्राचीन काल में प्रौद्योगिक शिक्षा का भारत में अव्यधिक विस्तार था, परन्तु यह शिक्षा विद्यालयों में नहीं प्रदान की जाती थी। विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के लिये विभिन्न कार्य एवं व्यवसाय निश्चित थे। इनमें से कुछ व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शिल्पों का ज्ञान रखते थे और वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इन्हीं के द्वारा उन शिल्पों में अपने पुत्रों तथा शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार वैदिक युग में सूती और ऊनी वस्त्र, रंगसादी, कसीदाकारी, आदि का कार्य किया जाता था। इस युग में सुनार, धातुकार, चर्मकार और कुम्ह-कार का उल्लेख मिलता है। ये लोग विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, आभूषण, घनुष की प्रत्यक्षाएँ आदि वस्तुएँ बनाते थे।<sup>१</sup>

प्रौद्योगिक शिक्षा का उपरोक्त क्रम वैदिक काल से राजपूत काल तक यथावत् चलता रहा और भारत ने प्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रति उन्नति की। राजपूत युग तक विभिन्न शिल्पों के कारिगारों में आशादीप्त वृद्धि हुई।

१. बी० एन० लूनिपा : भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, पृष्ठ ११-५२



चौरी-चारों तरफ से घनेक रास्तों से घा-घाकर जमा होता है, और जिससे बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता नहीं मिलता है।" २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत की दशा का वर्णन विलियम डिग्बी (William Digby) ने इन शब्दों में किया है : "बीसवीं सदी के शुरू में करीब दस करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी पेट भर भोजन नहीं मिल सकता है.... इस भयःपतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी सम्य और उन्नति-शील देश में कही पर भी दिखाई नहीं दे सकती है।" इस भयःपतन का कारण या अग्रजों का "भयनी निर्धारित नीति के अनुसार भारत की प्राचीन ग्राम-व्यवस्था, शिक्षा-प्रणाली, हज़ारों और लाखों पाठशालाओं और हज़ारों साल के उन्नत उद्योग-धन्धों का नाश कर डालना।"<sup>१</sup>

इन उद्योग-धन्धों में सबसे पहिले बारी प्राई सूती व्यवसाय की और उसके उपरान्त अन्य प्राचीन उद्योगों की, यथा—जल-चोठ, धातु, काँच, कागज आदि। इस प्रकार भारत को भारतीय माल से रिक्त करके अग्रजों माल से भर दिया गया।<sup>२</sup> परिणाम यह हुआ कि भारत के घसंक्ष्यो शिल्पी बेकार हो गये और उनमें से भयङ्गित काल के माल में पहुँच गये। इसका वर्णन करते हुए भारत के अग्रज गवर्नर-जनरल, लार्ड बेंटिंक (Lord Bentinck) ने १८३४ में अपनी रिपोर्ट में लिखा : "व्यवसाय के इतिहास में ऐसे दुर्भाग्य का अन्य उदाहरण कठिनाई से मिलता है। जुलाहों की हठियों ने भारत के मीदानों को सफ़ेद कर कर दिया है।"<sup>३</sup> ऐसी दशा में भारत में जो प्रौद्योगिक शिक्षा पिता द्वारा पुत्र को घनेकों पीढ़ियों से प्रदान की जा रही थी, उसका सदैव के लिये अन्त हो जाना स्वाभाविक था। यह दशा प्रति दीर्घ काल तक चलती रही। उसके उप-रान्त स्थिति में घनैः घनैः कुछ परिवर्तन होना प्रारम्भ हुआ। इसका अध्ययन हम सुविधा के लिये निम्नलिखित कालों में करेंगे।

१८०० से १८८२ तक

यद्यपि इस काल में इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के फलस्वरूप प्राविधिक तथा प्रौद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा था, तथापि उस देश के शासकों ने अपने दास भारत में इस शिक्षा का प्रचार

१. सुन्दरलाल : भारत में अंगरेजी राज, प्रथम खण्ड, पृष्ठ २३
२. Jawahar Lal Nehru : *The Discovery of India* (1946 Edition), p. 351.
३. "The misery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of the cotton-weavers are bleaching the plains of India."

आवश्यक नहीं समझा। इसकी घोर सरकार का ध्यान सर्व प्रथम (१८७७-७८) के 'दुर्भिक्ष-आयोग' (Famine Commission) द्वारा आकर्षित किया गया। फिर भी सरकार ने इस शिक्षा की आवश्यकता की। हाँ, मिशनरियों ने कुछ कार्य प्रवर्धन किया। उन्होंने घोड़े से 'प्रौद्योगिक स्कूल' स्थापित किये, जिनमें भारतीय ईसाई बालकों को जीविकोपार्जन के लिये बड़ई घोर सुधार के कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु इन स्कूलों को प्रौद्योगिक 'स्कूल' न कहकर 'हस्तकारी के स्कूल' (Craft School) कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। १८८२ से १९०२ तक

भारत सरकार प्रारम्भ से ही प्राविधिक तथा प्रौद्योगिक शिक्षा की विरोधी थी। अंग्रेज शासकों का विचार था कि यदि भारत में इस शिक्षा की आवश्यकता कर दी गई, तो देश का प्रौद्योगिक विकास प्रारम्भ हो जायगा और इसके अंग्रेजों के उद्योगों को घावा पहुँचेगा। भारत के राष्ट्रीय नेतृत्वों का विश्वास था कि देश की निर्धनता को दूर करने के लिये प्राविधिक तथा प्रौद्योगिक शिक्षा अति आवश्यक है। कांग्रेस ने १८८७ में होने वाले अपने तीसरे अधिवेशन में सरकार से इस शिक्षा की माँग की और अन्य माँगों में इस माँग को दोहराती रही।<sup>१</sup> परन्तु निज स्वार्थ में लित भारत की प्रत्येकी सरकार इस माँग का निरन्तर दुकराती रही। १९०२ में सम्पूर्ण भारत में केवल ८० प्राविधिक तथा प्रौद्योगिक स्कूल थे। इनमें से कुछ ही प्रौद्योगिक शिक्षा-लय कहलाने के अधिकारी थे।

१९०२ से १९२१ तक

इस काल में भी भारत सरकार ने प्रौद्योगिक शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, इसका प्रवर्धन किया कि 'भारतीय शिक्षा-आयोग' (Indian Education Commission) की सिफारिशों को स्वीकार करके विभिन्न प्रान्तों में हाई स्कूल के पाठ्य क्रम के अन्तर्गत प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों को स्थान दे दिया गया।

१९२१ से १९३७ तक

इस ऊपर निम्न पुक्त है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार से निरन्तर प्राविधिक तथा प्रौद्योगिक शिक्षा का माँग कर रही थी, परन्तु सरकार ने इस माँग का स्वागत नहीं किया था। हाँ, इसका प्रवर्धन किया था कि प्रौद्योगिक

2. *Indian Education Commission in Report of the Indian Educational Commission, 1914-15, p. 20.*

शिक्षा प्राप्त करने लिये कुछ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने लगे थे। १९०५ से १९१७ तक ११३ छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं। सरकार के इस कार्य से जनता को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि प्रौद्योगिक शिक्षा के अभिलाषी सभी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ नहीं प्राप्त होती थीं। इसके प्रतिरक्त, वे बहुत कम थीं और उनमें व्यय भी अधिक होता था। १९१७ में 'मॉरिसन समिति' (Morrison Committee) ने सुझाव दिया कि ये छात्रवृत्तियाँ, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को दी जायें जो वस्त्र (Textile), खनिज (Mining), मृदमण्ड (Pottery), धर्म संस्कार (Tanning), दीपेयिका (Matches), काँच, चीनी, पेन्सिल और कागज के उद्योगों में कार्य करना चाहते हों<sup>१</sup>, परन्तु इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।

१९२१ में प्रान्तों में ईंधन शासन की स्थापना के उपरान्त जनता ने प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की माँग को प्रबल किया। यह कहा गया कि इस शिक्षा की व्यवस्था भारत में ही की जाय। सरकार ने इसका निर्णय करने का कार्य लॉर्ड लिटन (Lytton) की अध्यक्षता में एक विशिष्ट समिति<sup>२</sup> को सौंप दिया। इसने विदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की कठिनाइयों का अध्ययन किया और उनको दूर करने के लिये धनकों सुझाव दिये। समिति का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि भारत में प्रौद्योगिक, प्राविधिक तथा प्रौद्योगिक संस्थाओं का निर्माण किया जाय और उनमें उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाय। भारतीयों को अपने देश में ही यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये। अतः यह आवश्यक है कि इस शिक्षा के विभिन्न अंगों का धीमे धीमे विकास किया जाय।<sup>३</sup>

इस सिफारिश के फलस्वरूप भारत में जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया, वे इस प्रकार हैं :—(१) हारकोर्ट बटलर टेक्नॉलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर; (२) कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी, जादवपुर; और (३) गवर्नमेन्ट स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी, मद्रास। १९६७ में सम्पूर्ण भारत में १३५ प्रौद्योगिक, प्राविधिक तथा प्रौद्योगिक विद्यालय थे।

१९३७ से १९४७ तक

तक प्रौद्योगिक शिक्षा की भवदेलना की गई थी, परन्तु इस अवधि में

1. Bhagwan Dayal : *The Development of Modern Indian Education*, p. 432.
2. Committee on Indian Students in England, 1921-22.
3. *The Report of the Committee on Indian Students in England*, para 84.

इसका प्राथमिक प्रसार हुआ। इसके तीन प्रमुख कारण ये:—(१) विभिन्न देशों के कारण ऐसे शक्तिशाली की माँग में वृद्धि हो गई थी, जो प्रयोगिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हों। (२) पुनः-जागृति का उत्थापन करने के लिये भारत में नवीन उद्योगों की स्थापना हो गई थी और उनमें प्रयोगिक शिक्षा-प्राप्त मनुष्यों की आवश्यकता थी। (३) केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा बनाई गई प्रयोगिक शिक्षा विभागों की स्थापना करने के लिये प्रयोगिक शिक्षा का विस्तार होना स्वाभाविक था। परन्तु इन तीनों कारणों के अतिरिक्त इसका एक कारण है, क्योंकि १८८१-४२ में केवल २१७ स्नातक प्रयोगिक शिक्षा और २० स्नातक सामान्य शिक्षा प्रयोगिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

### स्वतन्त्र भारत में प्रयोगिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

जैसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, स्वतन्त्र भारत में लोगों का प्रयोगिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहा था और वे विदेशी सरकार से इस शिक्षा की निरन्तर माँग कर रहे थे। इसके पक्षरूप शिक्षा पर प्रयोगिकीय प्रभाव पड़ा था, परन्तु उसे प्रति धन्य हो कहा जा सकता है। स्वतन्त्र भारत में इन प्रभाव में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इसका सर्व-प्रधान कारण है प्रयोगिक शिक्षा के प्रति देश के नेताओं तथा निवासियों का परिवर्तित दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण क्यों परिवर्तित हो रहा है, इसकी ओर हम निम्नांकित पंक्तियों में संकेत कर रहे हैं।

विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समाज के साधनों का अधिकारिक सकलतापूर्वक उपयोग करना होता है। ये साधन कुछ प्रकृति के द्वारा दिये हुए होते हैं, परन्तु इनको नवीन वैज्ञानिक उपायों और ज्ञान के प्रयोग द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और कर लिया जाता है। इस दृष्टि से वैज्ञानिक उपायों और ज्ञान का मुख्य पूँजी निर्माण की प्रक्रिया भी अधिक है। किसी भी धन्य उत्पत्तिशील अर्थ-व्यवस्था में प्रकृति द्वारा दिये हुए साधनों का पूरा ज्ञान नहीं होता है और उनको उत्पन्न करने के लिये नवीन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। भारत में इन साधनों की खोज और इनका उपयोग, प्रारम्भिक अवस्था में है। आवश्यक वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान भी अल्प है। इस कारण ज्ञात साधनों का उपयोग करने के लिये भी उन पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना सरल नहीं है। रहन-

सहन के स्तर को निरन्तर और अधिक ऊँचा उठाने के लिये न केवल ज्ञात साधनों के अधिक सफल उपयोग को, अपितु ज्ञात वैज्ञानिक विधियों के भी अधिक उत्तम प्रयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिये नए-नए साधनों को निरन्तर खोज करते रहना और नवीन उत्पादक विधियों का विकास करते रहना आवश्यक होता है।

यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि देश का आर्थिक विकास अधिक सीधता से करने के लिये जिस एक वस्तु का महत्व और सबसे अधिक है, वह उत्पादन की प्रक्रियाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी की विधियों का प्रयोग करने के लिये समाज की इच्छा और तत्परता है। इस क्षेत्र में नवीन प्रगति प्रति शीघ्र हो रही है और उसका प्रयोग न केवल उत्पादन, परिवहन एवं अन्य कार्यों के संगठन के लिये, अपितु आर्थिक तथा सामाजिक संगठन से सम्बद्ध प्रश्नों का हल करने में भी महत्वपूर्ण है। विकास में पीछे रह जाने का कारण प्रौद्योगिक विधियों में पर्याप्त उप्रति न कर सकना होता है और इस अपर्याप्त उप्रति का कारण विविध राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ होती हैं। यदि इन परिस्थितियों में अभीष्ट परिवर्तन हो जाय, तो प्रौद्योगिक विधियों में उप्रति करने मात्र से विकास की गति तीव्र हो सकती है। जिन देशों में प्रौद्योगिक जीवन का आरम्भ विलम्ब से होता है, वे कुछ लाभ में भी रहते हैं, क्योंकि वे उन प्रौद्योगिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनको अन्य उन्नत देशों में परीक्षा हो चुकी है। परन्तु इसके लिये आवश्यक है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अन्यत्र जो प्रगति हो चुकी है, उसके साथ-साथ चलने का भी ध्यान रखा जाय। सरासरी यह है कि नए-नए साधनों की खोज, नवीन वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा प्रौद्योगिक विधियों का प्रयोग और उपलब्ध जनशक्ति की विकास-कार्यों के लिये आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार उपयोग, विकास की नींव का काम देता है।

### स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर प्रौद्योगिक संघात

स्वतंत्र भारत में प्रौद्योगिक शिक्षा के प्रति जिस परिवर्तित दृष्टिकोण का वर्णन हमने ऊपर किया है, उसके परिणामस्वरूप शिक्षा पर प्रौद्योगिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। हम इसका वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत कर रहे हैं :

#### १९४७ से १९९० तक

स्वातंत्र्योत्तर काल में देश के औद्योगीकरण के साथ-साथ प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की भी अभिनन्दनीय प्रगति हुई है। १९४७ में केवल



१.६०० छात्रों को औद्योगिक तथा वाणिज्य विभाग देने का उद्देश्य था। १९१०-११ में ११,००० छात्रों के निम्न दिये विभाग की व्यवस्था कर दी गई। १९१०-११ में औद्योगिक तथा वैज्ञानिकों के दिनों राज्य-कर्मों काय की कठिनाई तथा विज्ञानों काय कर्म के १९११ प्रतिशतों के विवरण दर्शाते हैं। १९१०-११ में ११,००० छात्रों को उद्योग की कठिनाई की १ नवीन विभाग प्रतिशतों के प्रतिशतों के १९१०-११ में ११,००० से ६००० एवं विज्ञानों काय-कर्म में ११,००० छात्रों का उद्देश्य हो गया था। १९१०-११ में विभिन्न औद्योगिक कार्मिक एवं औद्योगिक छात्रों के विभाग के निम्न १९१०-११ काय काय दिने जाने का अनुमान है एवं छात्रों वर्ष १९१०-११ काय काय की व्यवस्था की गई है।

द्वितीय एवं तृतीय योजना की प्रतिशतों के कार्मिक करने के निम्न छात्रों के कार्य-कर्मों के छात्रों का दूर करने के विचार से १९ छात्रों एवं ४१ प्रतिशतों के विभाग के निम्न पुनः बना है, निम्न कि १९१०-११ के तथा १,६०० छात्रों १९११ के प्रतिशत स्थान निम्न हैं। १९१०-११ में प्रतिशत प्रती दिने एवं छात्रों की संख्या दिने पाठ्य-क्रम में २,१०० एवं विज्ञानों पाठ्य-क्रम में १,६०० को, जब कि १९१०-११ में प्रतिशत प्रती दिने एवं छात्रों की संख्या एवं पाठ्य-क्रमों में क्रमशः २,०६६ एवं १,६६६ को। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रसारित ८ क्षेत्रीय इन्सॉनिटिव कलेजों एवं २० प्रतिशतों एवं दिनों में एक इन्सॉनिटिव कलेज की स्थापना की योजना में कुल २,०१६ दिने पाठ्य-क्रम एवं ४,०२४ विज्ञानों पाठ्य-क्रम के स्थापना की व्यवस्था की गई है। विभिन्न राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित ८ इन्सॉनिटिव कलेजों में से केवल छात्रों के जोरहट कलेज के प्रतिशत दोष सभी की स्थापना हो चुकी है। दिल्ली के कलेज का विभाग २० जनवरी १९१६ को दिने राजेंत हाइनेव स्पूक डॉक एक्टिवरा द्वारा किया गया था।

१९१६ के वित्तीय वर्ष से राज्यों की प्रयोगिक प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया है। जब केन्द्रीय सरकार पूर्व-स्नातक पाठ्य-क्रम की परिवर्तनाओं के ध्येय का १० प्रतिशत तथा स्नातकोत्तर एवं विधिष्ट या गवेषणात्मक पाठ्य-क्रमों के ध्येय का १०० प्रतिशत अतः देगी।

सरकार ने निजी संगठनों द्वारा संस्थापित प्रयोगिक तथा प्राविधिक संस्थाओं के प्रति उदार नीति अपनाई है। इस प्रोत्साहन के फलस्वरूप निजी

क्षेत्रों में जो सब प्रशिक्षित की है, उनसे देश की औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा के विकास में प्रगतिशील सहयोग प्राप्त हुआ है।

औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थाओं के सम्पादकों के प्रशिक्षण के लिये कई परिपोषणार्थ प्रारम्भ की गई हैं। योजना समायोज ने सिद्धान्त रूप में इन सम्पादकों की तैयारी तथा काम की शक्तों के गुणों की बात को इस चर्च के साथ स्वीकार कर लिया है कि केन्द्र इसके सम्बन्धित समस्त प्रतिरिक्त धन को केवल पाँच वर्ष तक उठाये और उसके उपरान्त तृतीय वित्तीय समायोज स्थिति का पुनरावलोकन करे।

### प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक शिक्षा

प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। यह निश्चय किया गया कि 'इंजियर इंस्टीट्यूट ऑफ़ इण्डिया', बंगलौर का विकास किया जाय, इंजीनियरिंग के १४ कॉलेज स्थापित किये जायें, विशेष व्यावसायिक विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की जाय, एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिये 'परामर्शदाता केन्द्रों' की स्थापना की जाय। इसके प्रतिरिक्त औद्योगिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना, छात्र स्कूलों का जूनियर टेक्निकल हाई स्कूलों में परिवर्तन, जूनियर बहुउद्योगीय स्कूलों का निर्माण, सामान्य माध्यमिक विद्यालयों का टेक्निकल हाई स्कूलों के रूप में विकास, औद्योगिक स्कूलों का विलान्वास, राज्य-स्तरों में कृषि शिक्षा का उपयुक्त स्थान, वाणिज्य, औद्योगिक एवं प्राविधिक स्कूलों का कनिष्ठों में रूपान्तर और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियों प्रदान करने की योजनाओं का निर्माण किया गया। कलाकारों एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने की भाषक सुविधाएँ तथा ग्रामों में भी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई।

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक शिक्षा

प्रथम पंचवर्षीय योजना में किये गये उपायों के प्रतिरिक्त, द्वितीय योजना में औद्योगिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की बढ़ती हुई माँग के कारण औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा के विस्तार को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। इसी उद्देश्य से द्वितीय योजना में औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा के लिये ४८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जब कि प्रथम योजना में यह धन-राशि कुल २३ करोड़ थी। द्वितीय योजना के लिये निर्धारित धन का कुछ भाग उन कार्य-क्रमों पर व्यय किया जायगा, जो प्रथम योजना में प्रारम्भ किये गये थे।

इनके अन्तर्गत 'इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नॉलॉजी,' लखनपुर की स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये पूर्णतया विकसित कर दिया जायगा। इस इन्स्टीट्यूट में योजना के अनुसार १,२०० छात्रों के लिये प्राक्-स्नातक, और ६०० छात्रों के लिये स्नातकोत्तर एवं शोध की व्यवस्था की जायगी। यहाँ विषयों की दृष्टि से बहुत व्यापक विषयों के प्रशिक्षण की सुविधायें हैं, जैसे जलपोत निर्माण, शिला और सामुद्रिक इंजीनियरी, ईंधन और ज्वलन इंजीनियरी, उत्पादन टेक्नॉलॉजी, पदार्थों का रासायनिक प्रणयन, द्रुपि इंजीनियरी, भू-भौतिकी, नगर व प्रादेशिक निर्माण योजना और निर्माण विद्या।

बंगलोर में 'इन्स्टीट्यूट ऑफ़ साइन्स' नामक संस्था का विनाश बाधु एवं जल सेना इंजीनियरी, शक्ति इंजीनियरी, धातु-रिक्त ज्वलन इंजीनियरी, धातु-विज्ञान और विद्युत इंजीनियरिंग विषयक शोध, शैक्षणिक तथा प्राविधिक शिक्षा के लिये किया गया है।

प्रथम योजना काल में स्थापित किये गये प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा के अन्व केन्द्रों में स्नातकोत्तरकालीन पाठ्य-क्रमों एवं इंजीनियरिंग और शैक्षणिकी के अनुसंधान की व्यवस्था की जायगी। वर्तमान संस्थाओं को द्वितीय और द्वितीय पाठ्य-क्रमों के लिये विकसित करने का जो कार्य-क्रम प्रथम योजना में प्रारम्भ किया गया था, उसे द्वितीययोजना में पूर्ण किया जायगा। शेष घन देश के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी प्रदेशों में उच्चतर प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थाओं की स्थापना में ध्यान दिया जायगा। इनमें से दो संस्थाओं का निर्माण बम्बई और कानपुर में किया जायगा। पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर प्रत्येक संस्था में १,२०० प्राक्-स्नातक और ६०० स्नातकोत्तर छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

द्वितीय योजना काल में 'दिल्ली पॉलीटेक्निक संस्था' में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया जायगा। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिये ६ संस्थाएँ द्वितीय स्तर की और २१ संस्थाएँ द्वितीय स्तर की स्थापित की जायेंगी। क्रोमैनों के प्रशिक्षण की योजना को उद्योग संस्थाओं के सहयोग से क्रियान्वित किया जायगा। छात्रवृत्तियों की संख्या को ६३३ से बढ़ाकर ८०० कर दिया जायगा। प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा-संस्थाओं में योग्य छात्रों के लिये कुछ निःशुल्क स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। १३,००० टेक्निकल छात्रों और ३,३०० जूनियर टेक्निकल स्त्रुलों के विद्यार्थियों के लिये अतिरिक्त छात्रा-

घासों का निर्माण किया जायगा। मुद्रण शिल्प विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिये एक संस्था का निर्माण किया जायगा। धनुवाद के 'इण्डियन स्कूल ऑफ साइन्स एण्ड टेक्नाइक ज्योलोजी' का विस्तार किया जायगा, जिससे खान की इंजीनियरिंग एवं उससे सम्बन्ध विषयों में प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी। श्रम, लोहा तथा इस्पात और रेलवे मंत्रालय भी टेक्निकल स्कूलों की स्थापना का कार्य-क्रम बना रहे हैं। इन समस्त प्रयासों के फलस्वरूप १९६०-६१ तक प्रतिवर्ष ५,७०० स्नातक तथा ६,८०० डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध हुआ करेंगे। यह संस्था प्रथम योजना के अन्त में प्राप्त होने वाले स्नातको तथा डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्तियों से क्रमशः दुगुनी और तिगुनी होगी।

## आधुनिकतम प्रौद्योगिक गतिविधियाँ

### विज्ञान मन्दिर

देश के विभिन्न भागों में ३८ विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जा चुके हैं। प्राप्त सूचनाओं से ज्ञात हुआ है कि ये विज्ञान मन्दिर, लोकप्रिय सिद्ध हो रहे हैं। ज्ञान मन्दिरों के साथ एक सांस्कृतिक ग्रंथ स्थापित किये जाने के सुझाव पर श्री बलवंतराय मेहता, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति विचार कर रही है। 'वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय' द्वारा स्थापित इस समिति की रिपोर्ट सीधे ही पेश की जाने वाली है।

### प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा

प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक क्षेत्र में इस वर्ष की उल्लेखनीय घटना मद्रास में 'इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी' की स्थापना है। इस प्रकार की उच्च प्रौद्योगिक शिक्षा की चार संस्थाएँ खोली जाने वाली हैं, जिनमें से यह तीसरी है। मद्रास की इस संस्था को कार्यकर्ताओं और राज-समाज दोनों की सहायता पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त हो रही है। इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में ४ नये इंजीनियरिंग कॉलेज और १० पोलिटेक्नीक खोले गये हैं। धारा है कि घोषा हायर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जुलाई १९६० से कानपुर में कार्य प्रारम्भ कर देगा।

### शिक्षण संस्थाएँ

१९५९-६० के वर्ष में ४० पोलिटेक्नीक और ९ इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना से सम्बन्धित योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया जिनमें से कुछ संस्थाओं ने इष्टी-कारण कर दिया है और शेष आगामी वर्ष प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा-संस्थाओं में

द्वितीय कोर्स के लिये ११,१६० छात्र और डिप्लोमा कोर्स के लिये २१,१०० छात्रों की व्यवस्था है।  
**छात्रवृत्तियाँ**

विभिन्न संस्थाओं में दी जाने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय ने इस वर्ष से "योग्यता और साधन छात्रवृत्ति" प्रारम्भ की है ताकि एक बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक छात्रों की सहायता प्राप्त हो सके।

### अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ

इस वर्ष अनुसंधान छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत ११६ छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं। इस प्रकार अब तक ८०० छात्रवृत्तियाँ दी जा चुकी हैं। इस वर्ष २३ राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं ने विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों में अपना कार्य जारी रखा।

### व्यय

इस वर्ष देश में प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा के विकास और प्रसार के लिये राज्य सरकारों, निजी संस्थाओं व अन्य संगठनों को ३.७० लाख रुपये के अनुदान और १.४५ लाख रुपये से अधिक ऋण दिये गये।

### प्रौद्योगिक शिक्षा की प्रगति (इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी)

पाठ्य-क्रम	१९४६-४७			१९४७-४८		
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश	प्रतिफल	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश	प्रतिफल
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व अनुसंधान सुविधाएँ	८	११६	६१	१८	२७०	१६१
द्वितीय या तृतीय पाठ्यक्रम	२३	४,१२०	२,२००	६०	१,०४०	१,७००
डिप्लोमा पाठ्यक्रम	८१	५,६००	२,४६०	१०८	८,७००	१,६००

१. छात्रावृत्तियों का वितरण वर्ष, पृष्ठ २११
२. वही पृष्ठ २१६
३. द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना, पृष्ठ ४००

## ✓ प्रौद्योगिक शिक्षा की समस्याएँ और उनका समाधान

भारतीय शासन-काल में भारतीय शिक्षा पर प्रौद्योगिक प्रभाव घटि घल्ल था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त से इस प्रभाव में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत प्रौद्योगिक विषयों का समावेश किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके प्रतिरिक्त डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रमों की शिक्षा प्रदान करने के लिये विविध प्रौद्योगिक संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। सरकार तथा व्यक्तिगत संस्थाएँ इस दिशा में पूर्णरूप से व्यस्त हैं, पर फिर भी भारत में प्रौद्योगिक शिक्षा की प्रगति मन्दर गति से हो रही है। इसका कारण यह है कि घनेकों बाधाओं तथा समस्याओं ने प्रौद्योगिक शिक्षा के प्रवाह को अवरोध कर रखा है। ये बाधाएँ, कठिनाइयाँ तथा समस्याएँ क्या हैं, इन्हीं पर हम यहाँ विचार करेंगे।

### १. प्रौद्योगिक शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोण

भारत में प्रति प्राचीन काल से मानसिक श्रम को बराबर पर प्रतिष्ठित किया गया है और शारीरिक श्रम को हीन दृष्टि से देखा गया है। कार्य अवकाश के आधार पर ही हमारे देश में जाति-व्यवस्था का निर्माण किया गया था। पठन-पाठन करने वाले ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया और व्यवसाय तथा हस्तकार्य करने वाले व्यक्तियों को उनसे निम्नतर स्थान दिया गया था। सहस्रो वर्ष प्राचीन जाति-व्यवस्था पर आधारित श्रम विभाजन की जड़ें हमारे समाज में इतनी गहरी पहुँच गई हैं कि उनकी हिलाना अत्यन्त कठिन है। यही कारण है कि आज के प्रगतिशील युग में भी हस्तकार्य करने वालों को आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। प्रौद्योगिक शिक्षा में हस्तकलाओं तथा कौशल्यों का प्रमुख स्थान है। अतः जैसा स्वाभाविक है, भारतीय इस शिक्षा को सम्मान नहीं देते हैं। इस अनुचित दृष्टिकोण का परिणाम यह है कि उच्च जातियों तथा परिवारों के नवयुवक प्रौद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के प्रति साधारणतः उदासीन रहते हैं। फलतः इस शिक्षा का उचित विस्तार नहीं हो रहा है।

इस समस्या का समाधान कठिन नहीं है। यदि सरकार और कर्मठ समाज सेवा यह आन्दोलन प्रारम्भ कर दें कि शारीरिक श्रम किसी दशा में भी मानसिक श्रम से हीन नहीं है, तो देश के नवयुवकों को प्रौद्योगिक शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। परन्तु केवल आन्दोलन से ही काम नहीं चलेगा। इसके जनता के दृष्टिकोण के परिवर्तन में प्रयास आवश्यक मिलेगा, परन्तु केवल यही पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को उन छात्रों को प्रोत्साहन की सुविधाएँ देनी

होगी, जो प्रौद्योगिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सरकार उनको छात्रवृत्तियाँ दे, अध्ययन ममाप्त करने के उपरान्त उनके लिये नौकरियाँ सुलभ बनावे और उन्हें अधिक वेतन तथा अन्य सुविधाओं का प्राप्तामान दे।

## २. प्रौद्योगिक विद्यालयों का अभाव

यद्यपि स्वतन्त्रोत्तर काल में अनेकों प्रौद्योगिक विद्यालयों की स्थापना की गई है, तथापि उनका संख्या को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। अतः जागरूक भारतीय जनता समझने लगी है कि प्रौद्योगिक शिक्षा-प्राप्त नवयुवकों का भविष्य उज्ज्वल है। परन्तु विद्यालयों की न्यूनता के कारण लगभग ६० प्रतिशत छात्रों को इस शिक्षा की सुविधा न प्राप्त होने के कारण महान् निराशा होती है। ऐसी स्थिति में प्रौद्योगिक शिक्षा के विकास की प्राप्ति करना व्यर्थ है।

इस कठिनाई पर विचार सभी प्राप्त की जा सकती है, जब देश में और अधिक प्रौद्योगिक विद्यालयों की आधार-सिला रखी जाय और उनमें सभी स्तरों की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय, जिससे कि विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं वाले छात्र उनमें प्रवेश लेकर प्रौद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने की अपनी इच्छा को संतुष्ट कर सकें। इस समय भारत में प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक विद्यालयों की संख्या २६४ है।<sup>१</sup> इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश के लिये विद्यालयों की यह संख्या अति न्यून है। अतः सरकार का कर्तव्य है कि त्वरित गति से नवीन प्रौद्योगिक विद्यालयों की स्थापना करे।

## ३. संकीर्ण पाठ्य-क्रम

हमारे प्रौद्योगिक विद्यालयों के पाठ्य-क्रम संकीर्ण हैं, क्योंकि उनमें प्रौद्योगिक विषयों को ही स्थान दिया गया है। उनमें सामान्य तथा सत्कारी शिक्षण (Liberal Education) का कोई स्थान नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रौद्योगिक शिक्षा प्राप्त करके भी नवयुवक उत्पादन कार्य के सामाजिक उद्देश्य तथा मानव-सम्बन्धों का ज्ञान प्राप्त करने में असफल रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संकीर्ण पाठ्य-क्रमों के कारण प्रौद्योगिक शिक्षा प्रायः निरर्थक हो जाती है।

पाठ्य-क्रमों के इस दोष का निवारण करने के लिये उनमें प्रौद्योगिक

१. तीसरी पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक रूपरेखा, पृष्ठ १०१

शिक्षा के साथ-साथ सामान्य तथा संस्कारी शिक्षण को भी उचित स्थान प्रदान करना चाहिये। हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार का ध्यान इस घोर भाकपित हुआ है और वह प्रौद्योगिक विद्यालयों के पाठ्य-क्रमों को विस्तृत करके उनमें सामान्य तथा सरकारी शिक्षण को स्थान दे रही है।

#### ४. शिक्षा का अनुपयुक्त माध्यम

आधुनिक भारत के सभी प्रौद्योगिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। राज्यों के शिक्षा-मन्त्रियों के सम्मेलन में २ सितम्बर, १९५६ को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रौद्योगिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा। पर क्यों? क्या अंग्रेजी के कारण छात्रों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है? उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में इन्टरमीडिएट कक्षाओं तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। अब यदि एक छात्र इन्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त किसी प्रौद्योगिक विद्यालय में प्रवेश करता है, तो उसे वही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी मिलता है। अब तक तो उसने हिन्दी में पढ़ा और समझा है, पर अब सहसा उसे अंग्रेजी में सुनना, पढ़ना और लिखना है। इस परिवर्तन के कारण कितने ही छात्र खो निराश होकर अपना अध्ययन समाप्त कर देते हैं और कितने ही वर्ष के भ्रम में परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण विद्यालय का त्याग करने के लिये बाध्य कर दिये जाते हैं। तनिक विचार कीजिये, इन छात्रों की निराशा पर, उनके परिस्थित के अध्ययन पर और उनके अभिभावकों के नष्ट धन पर।

यह स्पष्ट है कि इस समस्या का निराकरण करने के लिये भारत के प्रशासकों को अपनी दोहरी नीति का परित्याग करना पड़ेगा। हिन्दी या विभिन्न राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं को प्रौद्योगिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाना पड़ेगा। हमने माना कि इस कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि न तो अभी हमारे पास प्रौद्योगिक विषयों की भारतीय भाषाओं में पुस्तकें ही हैं और न उनकी उपयुक्त शब्दावली ही तैयार है। परन्तु हर्ष निश्चय इस कार्य में अवश्य सफलता प्रदान करेगा। अन्य देशों के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। चीन, जापान, रूस, जर्मनी और कितने ही अन्य देशों में शिक्षा का माध्यम वहाँ की भाषाएँ हैं, न कि अंग्रेजी। यदि उन देशों में यह कार्य सम्भव हो सकता है, तो अंग्रेजी की दासता से मुक्ति प्राप्त करके अंग्रेजी की दासता की बेड़ियाँ भारत को क्यों पहिनाई जायें?



## ५. प्रायोगिक शिक्षा का न्यून महत्व

हमारे प्रौद्योगिक विद्यालयों में सैद्धान्तिक शिक्षा (Theoretical Education) की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान की जा रहा है। परिणाम यह होता है कि प्रौद्योगिकीय विद्यालयों से निकले हुए स्नातक प्रायोगिक कार्य में दक्ष नहीं होते हैं। यथार्थ में उन्हें इसी कार्य से अधिक प्रयोजन रहता है। फलतः उन्हें अपने को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये उन्हें साधारणतः अपने अधीनस्थ और कम शिक्षित कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ता है। इससे उनके सम्मान की हानि होती है।

इस दोष का उन्मूलन करने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे प्रौद्योगिक विद्यालय प्रायोगिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करें। इस कार्य में उन्हें योक्ष तथा अमेरिका के प्रौद्योगिक विद्यालयों से पाठ सीखना चाहिए। वहाँ छात्रों को कर्मशालाओं, लैबोरेटरी आदि में भेजकर इतना प्रायोगिक ज्ञान करा दिया जाता है कि उन्हें कोई भी कार्य करने में असफल होने की संभावना नहीं रहती है। और न उन्हें अन्य व्यक्तियों का मुँह ताकना पड़ता है।

## ६. अध्ययन समाप्ति के उपरान्त शिक्षा का अभाव

प्रौद्योगिक विद्यालय शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त नवयुवक कितना उद्योग में प्रवेश करते हैं। कुछ समय तक तो उनके मस्तिष्क धातु ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं, परन्तु धीरे-धीरे उनमें रिक्तता घाने लगती है। वे अपने-अपने बाँटें विस्तृत कर देते हैं। फलतः उनकी दक्षता में न्यूनता आ जाती है। जितना अधिक प्रौद्योगिक ज्ञान एक मनुष्य में होगा, उतनी ही अधिक कुशलतापूर्वक वह प्रौद्योगिक कार्य को सम्पन्न कर सकेगा। परन्तु यदि ऐसा नहीं है, तो वह कुशलता के स्तर से नीचे गिर जायगा। साधारणतः देखा भी ऐसा ही जाता है। इसका प्रभाव कारण यह है कि प्रौद्योगिक शिक्षा प्रायः व्यक्तियों के लिए अध्ययन समाप्ति के उपरान्त शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।

प्रौद्योगिक शिक्षा की इस समस्या का निवारण अनेक विधियों द्वारा किया जा सकता है। प्रथम, अंतरात्मिक शिक्षा (Part-time instruction) की व्यवस्था की जाय। परन्तु यदि दिन में किसी समय इस शिक्षा की व्यवस्था की जाय, तो कर्मचारियों को उसे प्राप्त करने की सुविधा ही नहीं पार्दिए। इस शिक्षा में केवल सिद्धान्त (Theory) की ही स्थान दिया जाय, क्योंकि प्रायोगिक कार्य में तो कर्मचारी अपनी कर्मशालाओं में ही कार्य कर रहे हुए होते हैं। द्वितीय, कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त पाठ्यक्रम (Refresher Courses)

की व्यवस्था की जाय। यहाँ यह लिख देना बाँझनीय है कि प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिवर्ष या दो वर्ष के उपरान्त उपरोक्त दो में से किसी एक व्यवस्था से एक निश्चित अवधि में लाभ उठाने के लिये बाध्य किया जाय।

### ७. शिक्षकों का प्रभाव

प्रौद्योगिक शिक्षा की एक प्रमुख समस्या है उत्तम शिक्षकों का प्रभाव। प्रौद्योगिक विद्यालयों के लिये उपयुक्त बर्न्हाताओं वाले शिक्षकों को प्राप्त करना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है। कारण यह है कि उद्योगों में प्रौद्योगिक शिक्षा प्राप्त योग्य मनुष्यों को इतना अधिक वेतन और इतने प्रकार की सुविधायें मिलती हैं कि वे प्रौद्योगिक विद्यालयों में शिक्षकों का कार्य करने की बात कभी स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं। फिर शिक्षकों का समाज में कोई सम्मान नहीं है। इसके विपरीत किसी उद्योग तथा अवकाश में कार्य करने वाले अधिक ठाढ़-बाढ़ से रहने वाले व्यक्तियों का समाज में आदर होता है। फलतः प्रौद्योगिक विद्यालय उत्तम शिक्षकों की सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। फलतः इन विद्यालयों का शिक्षा-स्तर गिर गया है।

इस समस्या का समाधान केवल सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार इस घोर शीघ्र ही ध्यान दे और प्रौद्योगिक विद्यालयों के लिये योग्य शिक्षकों की सेवाओं को सुलभ बनाये। इस कार्य में सरकार की सफलता अभी प्राप्त हो सकती है, जब वह प्रौद्योगिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनों में वृद्धि करे और उनकी सेवाओं को शर्तों को उत्तम बनाये। यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया, तो प्रौद्योगिक शिक्षा का विस्तार नहीं हो सकेगा।

हम हर्ष है कि सरकार इस समस्या के समाधान में व्यस्त है। "तकनीकी शिक्षा के विस्तार की एक कठिन समस्या शिक्षकों की कमी है। हिसाब लगा कर देखा गया है कि आजकल यह कमी डिग्री कॉलेजों में लगभग ३३ प्रतिशत और डिप्लोमा-संस्थाओं में २५ प्रतिशत है। दूसरी योजना में कुछ योजनायें घुने हुए इन्वोनियरो कालिजों में शिष्यवृत्ति देकर शिक्षक तैयार करने की और स्नातक की इस शर्त पर विदेशी छात्रवृत्तियाँ देनी शुरू की गई थीं कि वे वहाँ से लौटकर भी शिक्षक का ही कार्य करेंगे। एहूँ तीसरी योजना में भी जारी रखा जायगा। 'ग्रहिल भारतीय तकनीकी शिक्षा-परिषद्' ने सिफारिश की है कि तकनीकी विषय पढ़ाने वालों की वेतन-दरें ऊँची कर दी जायें। आशा है कि इस सिफारिश के कारण भी कुछ अधिक लोग इस पेशे की ओर आकृष्ट होंगे।"

उपरिक्तित समस्यायें प्रौद्योगिक शिक्षा के मार्ग को घबका कर रही हैं। हमने उनके समाधान के लिये कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं। यदि इन सुझावों को स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया जाय, तो भारत को जा सकती है कि प्रौद्योगिक शिक्षा जीम ही बनने प्रसस्त मार्ग पर प्रगति होने लगेगी।

## सारांश

प्रौद्योगिक शिक्षा की आवश्यकता—किसी देश प्रगति राष्ट्र की सम्पन्नता का मापक विज्ञान तथा प्रौद्योगिक शिक्षा है। यदि देश में इस शिक्षा की प्रगति हो रही है, तो राष्ट्र की उन्नति प्रत्यक्ष होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, जर्मनी और जापान के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। भारत में कच्चे माल और खनिज पदार्थों का अभाव नहीं है। यदि हमारे देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विषयों का पूर्ण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हों, तो इनका उपयोग होने लगेगा और भारत का आर्थिक विकास हो जायगा।

प्राचीन काल में प्रौद्योगिक शिक्षा—प्राचीन काल में प्रौद्योगिक शिक्षा का भारत में अत्यधिक विस्तार था, परन्तु यह शिक्षा विद्यालयों में न दी जाकर पिता द्वारा पुत्र को परम्परागत रूप में दी जाती थी।

मुस्लिम काल में प्रौद्योगिक शिक्षा—मुस्लिम काल में प्रौद्योगिक शिक्षा का वही रूप रहा जो प्राचीन काल में था। इस काल में ललित कलाओं, मुक्त-ऐरान की वस्तुओं, सूती व्यवसाय, रेशमी वस्त्र आदि के उत्पादन की विशेष प्रोत्साहन मिला।

अंग्रेजी राज्य में प्रौद्योगिक शिक्षा—भारत में परम्परागत रूप में प्रौद्योगिक शिक्षा देने की जो प्रणाली चल रही थी, उसका गता स्वार्थी अंग्रेजों ने धोटा दिया। फलस्वरूप इस देश के सभी उद्योग धोटा हो गये। भारत को अंग्रेजी माल से भर दिया गया। उद्योगों के धोटा होने से अर्थव्यवस्था बंकाव हो गये और अग्रणी काल के माल में पहुँच गये। ऐसी दशा में भारत में जो प्रौद्योगिक शिक्षा पिता से पुत्र को देनेकी परम्परा से प्रदान की जा रही थी, उसका सर्व के लिये अर्थ हो जाना स्वाभाविक था।

१८०० से १८८२ तक—प्रौद्योगिक शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान सर्व प्रथम १८७७-७८ के 'दुग्ध-मायाम' द्वारा आकर्षित किया गया, पर फिर भी सरकार ने इस शिक्षा की व्यवस्था की।

१८८२ से १९०२ तक—कॉलेज ने १८८७ में होने वाले अपने तीसरे अधिवेशन में सरकार से प्रौद्योगिक शिक्षा की माँग की और अन्य अधिवेशनों

में इस माँग को दोहराती रही। परन्तु निज स्वार्थ में लिप्त भारत की मंत्रिजी सरकार इस माँग को निरन्तर ठुकराती रही।

१९०२ से १९२१ तक—सरकार ने 'भारतीय शिक्षा आयोग' की सिफारिश को स्वीकार करके विभिन्न प्रान्तों में हाई स्कूल के पाठ्य-क्रम में 'प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों' को स्थान दिया।

१९२१ से १९३७ तक—प्रौद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये कुछ विद्यालयों को छात्र-वृत्तियाँ दी गईं। 'मारिशन समिति' ने इन छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये, पर उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। लार्ड लिटन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति ने सुझाव दिया कि भारत में प्रौद्योगिक, प्राविधिक तथा प्रौद्योगिक संस्थाओं का निर्माण किया जाय। फलस्वरूप भारत में ३ प्रौद्योगिक विद्यालय स्थापित किये गये।

१९३७ से १९४७ तक—भारत में युद्ध सामग्री का उत्पादन करने के कारण इस काल में प्रौद्योगिक शिक्षा की विशेष प्रगति हुई परन्तु उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

स्वतन्त्र भारत में प्रौद्योगिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण—भारतीयों का प्रौद्योगिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो रहा है। उन्हें यह विश्वास हो गया है कि देश का आर्थिक विकास करने के लिये उत्पादन की प्रक्रियाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी की विधियों का प्रयोग करना है। फलतः प्रौद्योगिक शिक्षा का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है।

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा पर प्रौद्योगिक संघात—स्वातन्त्र्योत्तर काल में देश के प्रौद्योगिकीकरण के साथ-साथ प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की भी प्रगति हुई है। १९४७ में केवल ६,९०० छात्रों को प्रौद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा देने का प्रबन्ध था। १९५३ में १२,७०० छात्रों के लिये इस शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। १९५८-५९ में इंजीनियरिंग तथा टेक्नॉलोजी के द्वितीय पाठ्यक्रमों वाले ८३ कॉलेज तथा डिप्लोमा पाठ्य-क्रम के १४९ पॉलीटेक्नीक थे। १९५८-५९ में विभिन्न प्रौद्योगिक, प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग संस्थाओं के विकास के लिये १३६.२० लाख रुपये दिये जाने का अनुमान है एवं १९५९-६० में १४५-१९ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिक शिक्षा—'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स' का विकास; १४ इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना; विशेष व्यावसायिक विषयों का शिक्षण; प्रौद्योगिक, प्राविधिक एवं व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना; जूनियर बहुचौकीय स्कूलों का निर्माण तथा प्रौद्योगिक स्कूलों का शिलान्यास।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिक शिक्षा—प्रथम योजना में स्थापित

शिक्षा-संस्थाओं का विकास, स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रमों एवं इंजीनियरिंग टेकनॉलाजी के अनुसंधान की व्यवस्था, तीन उच्चतर टेकनिकल संस्थानों की स्थापना और द्वितीय स्तर की ६ संस्थाओं तथा डिप्लोमा स्तर की २१ संस्थाओं का निर्माण ।

प्रामुखिकतः प्रौद्योगिक गतिविधियाँ—३८ विज्ञान मन्दिरों की स्थापना महात्मा में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेकनॉलाजी' की स्थापना, १९११-१२ में ४० पोलिटेक्नीक और ६ इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना, बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिक तथा शैक्षणिक छात्रों की सहायता व १११ अनुसंधान छात्रवृत्तियाँ ।

प्रौद्योगिक शिक्षा की समस्याएँ—ये समस्याएँ प्रकटित हैं—(१) प्रौद्योगिक शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोण, (२) प्रौद्योगिक विद्यार्थी का अभाव, (३) संकीर्ण पाठ्य-क्रम, (४) शिक्षा का अनुपयुक्त माध्यम, (५) प्रायोगिक शिक्षा का न्यून महत्त्व, (६) अध्ययन समाप्ति के उपरान्त शिक्षा का अभाव, और (७) शिक्षकों का अभाव ।

### सहायक पुस्तकों की सूची

1. *The Leader*, Republic Day Supplement, 1959.
2. *Report of the Indian Industrial Commission*, 1916-18.
3. *Report of the Commission on Indian Students in England*.
4. *Oxford Pamphlets on Indian Affairs*, No. 15.
5. Sir Richard Livingstone : *Some Tasks for Education*.
6. Jawahar Lal Nehru : *The Discovery of India*.
7. Bagwan Dayal : *The Development of Modern Indian Education*.

८. बी० एन० सूनिया : भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास

९. मुन्दर लाल : भारत में अंगरेजी राज

१०. माज़ारी का लेखकों वर्ष

११. प्रथम पंचवर्षीय योजना

१२. द्वितीय पंचवर्षीय योजना

१३. तीसरी पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक

---

TEST QUESTIONS

1. What, in your opinion, is the importance of Technological Education ? How has this need been met in Free India ?
2. Briefly describe the technological impact on education during the British rule and since the achievement of independence.
- ✓3. Give an account of the technological activities from 1950 to 1960.
- ✓4. What problems are being faced in the expansion of technological education ? How can they be tackled ?

## शिक्षा पर सामाजिक-आर्थिक संघात'X

समान दुसरी शार्विक वार्षिक (Annals) का कहना है कि "धनुष एक सामाजिक प्राणी है।" वह समाज में रहकर अन्य व्यक्तियों के साथ घना जीवन व्यतीत करता है। समाज के सदस्य कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के निम्न एक-दूसरे से घटने सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। सामाजिक अंतर्क्रिया (Social Interaction) के कारण उनके सामाजिक सम्बन्धों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक सम्बन्धों के परिवर्तन के कारण समाज का परिवर्तन होता रहता है। यदि हम अपने समाज के इतिहास का घनोद्घन करें, तो हमें स्पष्ट रूप से धनुष हो जाना कि जब से हमारे समाज का प्रादुर्भाव हुआ है, सबसे उसमें समय-समय पर परिवर्तन होता आया है। बहुत दूर नहीं, धनुष मात्र से १०-१२ वर्ष पूर्व हमारे समाज का रूप वह नहीं था, जो आज है। सामाजिक परिवर्तन के घनेको कारण है। मार्क्स (Marx) के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण आर्थिक सम्बन्धों का संघर्ष होता है। यह संघर्ष समाज के पर्यावरण में परिवर्तन करता है और पर्यावरण समाज तथा विद्या-संस्थाओं में परिवर्तन करता है।

### सामाजिक परिवर्तनों का शिक्षा पर प्रभाव

यदि हम मार्क्स (Marx) की सामाजिक परिवर्तन की आर्थिक व्याख्या को स्वीकार कर लें, तो हम कह सकते हैं कि समाज की आर्थिक रचना की

1. Socio-Economic Impact upon Education.

नींव पर ही समाज की अधिरचना (Super Structure) खड़ी है। शिक्षा का कार्य इस अधिरचना को यथावत् बनाये रखना है। शिक्षा का रूप वही होता है, जिसकी भाँव समाज द्वारा की जाती है। अन्य चम्दों में शिक्षा समाज की भाव-स्थवताओं, मान्यताओं तथा उद्देश्यों के अनुकूल होती है। प्रत्येक समाज का अपना एक विशिष्ट संगठन है। उसके अपने मूल्य तथा प्रवृत्तियाँ होती हैं। उसकी अपनी निश्चित परम्पराएँ होती हैं। उसका अपना एक लक्ष्य होता है और उसी शिक्षा में वह प्रसर होना चाहता है। उदाहरणार्थ, जैन समाज तथा धार्मिक समाज दोनों के संगठन, मान्यताएँ एवं परम्पराएँ एक-दूसरे से भिन्न हैं। परन्तु इन दोनों तथा अन्य समाजों के संगठन की इकाई मानव है। मानव समाज के अन्य सदस्यों के सहयोग से उसके संगठन, सिद्धान्तों तथा नीतियों का निर्माण करता है। अतः समाज में परिवर्तन लाने के लिये उसके सदस्यों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। यह कार्य शिक्षा के द्वारा किया जाता है। जर्मनी के अधिनायक हिटलर (Hitler) ने सामाजिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा का रूपान्तर किया और शिक्षा के परिवर्तित रूप से अपने देश के समाज की रूप-रेखा को बदला। जर्मन बालकों तथा बालिकाओं को प्रारम्भ से ही यह शिक्षा दी जाती थी कि जर्मन जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति है, वह विश्व पर शासन करने के लिये उत्पन्न हुई है। यह अपना उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकती है, जब सब जर्मन व्यक्ति एक नेता का अनुसरण करें, और एक दल के रूप में संगठित होकर रहें। जर्मन प्रजाति की श्रेष्ठता तथा गृहियों की निम्नता का भाव उनमें कूट-कूट कर भर दिया जाता था। यही कारण था कि जर्मनी के निवासियों में यह विचार पूर्ण रूप से प्रविष्ट हो गया था कि उन्हें अपने देश की प्रगति के लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर देना है।

विश्व के जिन देशों में महान् क्रान्तियाँ हुई हैं, उन्होंने वहाँ की सामाजिक संरचना को परिवर्तित कर दिया। फलस्वरूप वहाँ की शिक्षा के रूप में परिवर्तन हुआ। १७८९ की फ्रांस की राज्यक्रान्ति (French Revolution) ने वहाँ के निवासियों में विद्रोह की भावना भर दी और वहाँ भारत का राज्य स्थापित हो गया। फलस्वरूप सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं में अन्तर आ गया। जनता राजसत्ता की विरोधी हो गई। १८०२ में नैपोलिन (Napoleon) फ्रांस का सम्राट् बना। उसने पुनः प्राचीन राजसत्ता का प्रारम्भ करके समाज के रूप को परिवर्तित किया। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये उसने शिक्षा का रूपान्तर किया। प्रत्येक नगर में शिक्षणालयों की स्थापना की गई। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा। पेरिस के विश्वविद्यालय का



पुनः संगठन किया गया। यह शिक्षणालयों में राजनीति की शिक्षा देने लिए विशेष रूप से बल दिया गया।

फ्रांस में जिस राज्य-क्रान्ति का मूत्रपात हुआ था, उसने न केवल यूरोप के अन्य यूरोप के अन्य घनेकों देशों के सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाला। फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति के तीन धातु हैं—समानता, स्वाधीनता और भ्रातृभाव (Equality, Liberty and Fraternity)। क्रान्ति के मूत्रपात के फलस्वरूप १७८९ से १८१४ तक यूरोप में जिस नवीन समाज के निर्माण का प्रयत्न किया गया, उसके ये ही आधार स्तम्भ थे। शिक्षा को नवीन समाज के अनुकूल बनाने के लिये घनेको देशों में उसका रूप परिवर्तित किया गया। रॉबिन्सन क्रिस्चो, लन्दन और न्यूयार्क के विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, या उनका पुनः संगठन किया गया। शिक्षा के रूपान्तर के कारण यूरोप में जिस नवीन जीवन का प्रारम्भ हुआ वह इस युग के लेखकों तथा कवियों की रचनाओं में भली-भाँति प्रतिबिम्बित होता है। फ्रांस के विक्टर ह्यूगो (Victor Hugo) और लामार्तीन (Lamartine) जैसे साहित्यिक क्रान्ति-युग की ही उपज थे। ब्रिटेन में बायरन (Byron) और शेली (Shelley) और जर्मेनी में हेइने (Heine) जैसे साहित्यिकों पर भी इस युग की भावनाओं का प्रभाव बहुत स्पष्ट है।

उपरिलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है और शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इतना ही नहीं, शिक्षा समाज को किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। वह उन्नति भी कर सकती है और भ्रष्टता भी। अतः सामाजिक शिक्षा, भावों तथा मूल्यों के परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा के रूप में भी परिवर्तन होता रहता है।

### आर्थिक परिवर्तनों का शिक्षा पर प्रभाव

समाज में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों का भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक प्रगति के साथ-साथ शिक्षा की प्रगति और उसका रूपान्तर होना अनिवार्य है। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution), जिसका काल १७५० से १८५० तक माना जाता है, के फलस्वरूप देश का अर्थ-स्थिति गति से औद्योगीकरण हुआ। घनेकों नवीन औद्योगिक नगरों का निर्माण हुआ और दैनिक वर्ग का जन्म हुआ। इस सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप १८६७ के 'सुधार अधिनियम' (Reform Act) के द्वारा घनेकों अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान किया गया।

परन्तु इस अतिधिकार का उचित प्रयोग करने के लिये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आवश्यक समझी गई। लो (Lowe) का कथन था : "हमें अपने स्वामियों (महशतानों) को शिक्षित करना चाहिये।" (We must educate our masters.) अतः प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकता मान कर १८७० में प्रथम शिक्षा अधिनियम (First Education Act) पारित किया गया।<sup>१</sup>

रूस में १९१७ में बोल्शेविकों ने क्रान्ति द्वारा राजसत्ति प्राप्त करके अपने देश के समाज में घामूल-मूल परिवर्तन कर दिया। वही की प्राथमिक व्यवस्था को पूर्णतः बदल डाला। कारखानों पर से पूँजीपतियों के स्वत्व का अन्त हो गया और उनका संचालन श्रमिकों की एक प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाने लगा। बड़े-बड़े कारखाने, रेलवे, खानें आदि राज्य की सम्पत्ति हो गईं। बोल्शेविक सोव भली-भाँति समझते थे कि उनके सिद्धान्त तभी सफल हो सकते हैं, जब कि साधारण कृषक-श्रमिक जनता की समृद्धि हो, उन्हें भर पेट भोजन और पहिने के वस्त्र मिलें, उनके घराम में वृद्धि हो और वे अपने को सुखी एवं संतुष्ट करें। साम्यवाद (Communism) का आदर्श तो यह है कि "सबको उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो।"

रूस में इस प्राथमिक व्यवस्था और उससे सम्बन्धित परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। अपने साम्यवादी आदर्श के अनुसार साम्यवादी सरकार ने रूस के सभी बालकों तथा बालिकाओं के लिये शिक्षा को मुलभ बनाने का अभि-नन्दनीय प्रयास किया है। पिछड़े हुए व्यक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिये कम्युनिस्टों ने विशेष चेष्टा की है। "रूस के विशाल साम्राज्य के अन्तर्गत अनेक ऐसी जातियों का भी निवास था, जो किसी भी वर्णमाला या लिपि से अपरिचित थीं। कम्युनिस्टों ने इनकी भाषा को लेखबद्ध करने के लिये उन्हें वर्णमाला और लिपि का ज्ञान प्रदान किया, जिसमें वे अपनी भाषा को लिखकर साहित्य का निर्माण करने में सफल हुईं। परिणाम यह हुआ कि उजबेक, काज़क आदि भाषाओं के साहित्य का विकास शुरू हुआ और धीरे-धीरे ये भाषाएँ इतनी अधिक विकसित हो गईं कि इनके माध्यमसे उच्च शिक्षा का प्राप्त कर सकना भी सम्भव हो गया। रूस में १९१९ विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन शुरू हुआ और विविध जातियों के लोगों को यह अवसर मिला कि वे अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि १९४१ में रूस में महिलाओं की संख्या केवल १० प्रतिशत रह गई। इस

1. J. A. R. Marriott : *England Since Waterloo*, p. 530.

प्रसंग में यह ध्यान रखना चाहिये कि वास्तविक क्रान्ति से पूर्व स्व की प्रतिष्ठित जनता सर्वथा अक्षित हो ।”

उपरोक्त के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि सामाजिक, धार्मिक एवं वैश्विक प्रक्रियाओं का पारस्परिक सम्बन्ध है। किसी भी देश की शिक्षा, उसके रूप, उसके उद्देश्यों एवं उसके संगठन पर, बड़ी होने वाले सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है और उल्टा स्थानंतर होता रहता है। भारत के सम्बन्ध में भी यह बात सत्य है।

ब्रिटिश शासन-काल में शिक्षा पर सामाजिक-धार्मिक संघर्ष

सन् १८४८ तक भारत का एकीकरण हो गया था। इसके दस वर्षों पश्चात् ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत-सरकार का दायित्व सोधे अपने हाथ में ले लिया। यह व्यवस्था लगभग एक सौ वर्षों तक जारी रही। इन वर्षों में भारत में क्रान्तिकारी, सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तन हुए और उनका भारतीय शिक्षा पर घनिष्ठ व्यापक प्रभाव पड़ा। इसका अध्ययन हम मुविषा की दृष्टि से निम्नांकित कालों में करते हैं :

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में

मुगल सम्राट् औरंगजेब की मृत्यु (१७०७) के उपरान्त देश में अस्थिरता तथा अराजकता फैल गई थी। ऐसी स्थिति में शिक्षा-संस्थाओं को घन का प्रभाव हो गया था। फलस्वरूप वे उत्तरोत्तर अवनति को प्राप्त हो रही थीं। १८वीं शताब्दी के अन्त तक भारत में होने वाली सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था के कारण भारतीय शिक्षा की काया पर्वान रूप से जीर्ण और नवीन हो गई थी। १८२३ तक भारत के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। १८३२ से १८३८ तक ऐडम (Adam) द्वारा भारत-सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि उस समय भारत में शिक्षा का उचित प्रबन्ध था और यह इस देश की प्राचीन परम्पराओं पर आधारित थी। यह शिक्षा किसी वर्ग-विभेद के बिना न होकर जन साधारण की शिक्षा की धर्म की पूर्ति करती थी। परन्तु शिक्षा-संस्थाओं के नाम धर्म का प्रचार होने के कारण उनकी निरन्तर अवनति हो रही थी। ब्रिटिश शासन-काल में होने के कारण उनकी निरन्तर अवनति हो रही थी। ब्रिटिश शासन-काल में होने के कारण उनकी निरन्तर अवनति हो रही थी। ब्रिटिश शासन-काल में होने के कारण उनकी निरन्तर अवनति हो रही थी।

प्रचार करके भारतीय जनता के सामाजिक दृष्टिकोण को पूर्णरूप से परिवर्तित करने का प्रयास किया। फलस्वरूप अनेकों भारतीयों ने अपने धर्म का परित्याग करके ईसाई धर्म को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, मिशनरियों ने शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करके भारतवासियों से सम्पर्क स्थापित किया और उनके द्वारा अपने धर्म का प्रचार भी किया। इन शिक्षा-संस्थाओं का रूप भारत की देशी शिक्षा-संस्थाओं से पूर्णतया भिन्न था।

इन नवीन शिक्षा-संस्थाओं के समक्ष देशी शिक्षा-संस्थाएँ न टिक सकीं। कारण यह था कि मिशनरियों द्वारा स्थापित शिक्षा-संस्थाओं के लिए धन का अभाव नहीं था। इसके विपरीत देशी शिक्षा-संस्थाओं में धन की न्यूनता में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी। एक तो उनके पास पहिले से ही धन का अभाव था, दूसरे अंग्रेजों की नीति के कारण भारत में ऐसे कान्तिकारी आर्थिक परिवर्तन हुए जिनका प्रभाव देशी शिक्षा-संस्थाओं पर भी पड़ा और धनः शून्य उनका अस्तित्व सदैव के लिये समाप्त हो गया।

भारत में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों ने जनता को निर्धनता के गहरे गर्त में डकेल दिया। अंग्रेजों के द्वारा यह किस प्रकार किया गया, इसका वर्णन करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेज उल्लेखता, हर्बर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) सन् १८४१ में लगभग सौ वर्ष के ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारतीय शासन का सिद्धान्तोक्त करते हुए लिखता है : "कल्पना कीजिये कि उनकी (अंग्रेजों की) करतूतें कितनी काली रही होंगी, जब कि कम्पनी के डाइरेक्टरों तक ने यह स्वीकार किया कि 'भारत के आन्तरिक व्यापार में जो बड़ी-बड़ी पूर्जियाँ कमाई गईं हैं, वे इतने महान् अन्धकारों तथा भ्रष्टाचारों द्वारा प्राप्त की गईं हैं, जिनसे बढ़कर अन्धकार तथा भ्रष्टाचार कभी किसी देश या किसी युग में भी उनसे भी नहीं पाये।' अनुमान कीजिये कि वन्सीटॉर्ट (Vansittart) ने समाज की जिस दशा का वर्णन किया है वह कितनी बीभत्स रही होगी जब कि वन्सीटॉर्ट हमें बताता है कि अंग्रेज भारतवासियों को विवश करके, जिस भाव चाहते थे उनसे भाल खींचते थे, और जिस भाव चाहते थे उनके हाथ बेचते थे, और जो कोई इन्कार करता था, उसे बँत या कारावास का दण्ड देते थे। विचार कीजिये कि उस समय देश की क्या दशा रही होगी, जबकि कम्पनी किसी यात्रा का वर्णन करते हुए बारेन हेस्टिंग्स लिखता है कि 'हमारे पहुँचते ही लोग अधिकतर छोटे-छोटे कस्बों और सरायों को छोड़-छोड़कर भाग जाते थे।' आज के दिन तक साहस लोग हाथियों पर बैठ कर निर्धन

किसानों की खड़ी फ़मतों में से जाते हैं और गाँव के लोगों से बिना मूल्य दिए रसद वसूल कर लेते हैं।<sup>१</sup>

मंत्रियों के इन हृदयहीन कृत्यों से जनता की प्राणिक दशा कैसी रही होगी और समाज में कितनी समस्या फैल गई होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी दशा में भारतीय शिक्षा का पतनना असम्भव था, और हुआ भी ऐसा ही। अपनी समस्या में भारत की निचन जनता ने अपनी प्राचीन शिक्षा को तिलाजलि देकर मंत्रों के अध्ययन में अपना प्रत्यक्ष हिस्सा देला। इसका मजत करके राजपद प्राप्त हो सकता था और जीविकोपार्जन की समस्या को भी हल किया जा सकता था। घट: मंत्रों शिक्षा की माँग बढ़ी। देशी शिक्षा ज्यों-ज्यों करके कुछ समय तक चली, परन्तु उसके उपरान्त वह प्रायः निष्प्राण हो गई।

### उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में

उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध धर्म एवं समाज के सुधारवादी कार्यों के महाद् प्रान्दोलनों के लिये प्रसिद्ध है।<sup>२</sup> वस्तुतः इस काल में भारत में युगान्तर प्रारम्भ होता है। यह प्राधुनिककरण का शी गणेश था। इसका

1. "Imagine how black must have been their deeds when even the Directors of the Company admitted that, 'the vast fortunes acquired in the inland trade have been obtained by a scene of the most tyrannical and oppressive conduct, that was ever known in any age or country.' Conceive the atrocious state of society described by Vansittart who tells us that the English compelled the natives to buy or sell at just what rates they pleased on pain of flogging or confinement. Judge to what a pass things must have come when, in describing a journey, Warren Hastings says, 'Most of the petty towns and serais are deserted at our approach'. Down to our own day, so called gentlemen will ride their elephants through the crops of impoverished peasants and will supply themselves with provisions from the native villages without paying for them."—Herbert Spencer : *Social Statics*.
2. "The second half of the nineteenth century was marked by a strong wave of reforming activities in religion and society."—Majumdar, Raychaudhari and Datta. : *An Advanced History of India*, p. 876.

सूत्रपात तब हुआ, जब भारतीयों ने पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता तथा संस्कृति से प्रभावित होकर ज्ञान एवं प्रकाश के लिये अपना मुख पश्चिम की ओर मोड़ा और देश का आधुनिककरण करके सर्वाङ्गीण सामाजिक सुधार की उद्योग को जन्मपाया ।

“उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक हमारे देश में धर्मान्धता, मन्धविश्वास, भ्रष्टृभ्रष्टा, सामाजिक ऊँटियाँ, कुप्रथाएँ आदि ऐसे दोष उत्पन्न हो गये थे कि हमारा सामाजिक और आर्थिक जीवन जीर्ण और जर्जरित हो गया था, उसकी जीवन शक्ति खोखली हो चुकी थी । अंग्रेजों की विशिष्ट व्यापारिक नीति के कारण भारत का आर्थिक जीवन भ्रष्ट-व्यस्त और असंतुलित हो गया था । दरिद्रता और भुखमरी का ताडक नृत्य होने लगा था और उद्योग-धन्धे विनिष्ट हो गये थे । फलतः आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया था और समृद्धि का प्रभाव शुष्क हो गया था । इस आर्थिक दुर्दशा ने भारत के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया । विभिन्न तलितकलाओं की प्रगति रुक गई, जीवन नीरस हो गया और भारत का प्राचीनतम आध्यात्मिक स्रोत सूख गया । पश्चिम के प्रभाव के अन्तर्गत धीरे-धीरे इन दोषों का निवारण किया गया और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की प्रगति के साथ-साथ आधुनिककरण भी किया गया ।”

सामाजिक परिवर्तन—जब १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई, तब यह अनुभव किया गया कि समाज की दशा में सुधार करना आवश्यक है । फल-स्वरूप १८८८ से कांग्रेस की प्रत्येक बैठक के साथ-साथ प्रतिवर्ष ‘राष्ट्रीय समाज-सुधार परिषद्’ के अधिवेशन भी होने लगे । इनमें प्रतिवर्ष स्त्री-शिक्षा के प्रचार बाल-विवाह एवं पदों के विरोध, विधवाओं और अछूतों की दशा सुधारने, अन्तर्जातीय सान-मान एवं विवाहों के प्रोत्साहन पर प्रस्ताव पास किये जाने लगे । १८९० में समाज-सुधार का प्रबल समर्थक ‘इंडियन सोशल रिफार्मर’ (Indian Social Reformer) नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित किया जाने लगा । १८९७ में बम्बई एवं मद्रास में समाज-सुधार के लिये प्रांतीय संगठन बनाये गये ।

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में सती-प्रथा, कन्या-वध, बाल-वध आदि दूषित प्रथाओं को कानून बनाकर अनियमित ठहरा दिया गया । प्रारम्भ में जनता ने इन कानूनों को धर्म के विरुद्ध समझकर इनका विरोध किया था,

१. श्री० एन० सुनिवा : भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का इतिहास, पृष्ठ ४९६

परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इनके महत्त्व को स्पष्टतया समझने लगी थी और इनकी पूर्ण रूपांतर विरोधी हो गई थी। वरिणामस्वरूप १६वीं शताब्दी के अन्त तक इन सब बातों का पूर्णतया अन्त हो जाने के कारण समाज में एक धारपर्यन्तक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा था। सामाजिक परिवर्तन में कुछ अन्य कारकों ने भी योग दिया। १८२६ में भारत-सरकार ने विधवा-विवाह का आयज ठहराने के लिये एक कानून बनाया। शिक्षित व्यक्तिओं ने जाति-भेद को समाप्त करना प्रारम्भ कर दिया। रेलों एवं होटलों ने भी पुमा-पूत को दूर करने में बड़ी सहायता की। धर्म-समाज ने जाति के बन्धनों को तोड़ने का पूर्ण प्रयास किया। शास्त्रानों की स्थापना होने से जाति के अनुसार वेदों का बन्धन समाप्त हो गया। हरिजनोद्धार के लिये धर्म-समाज, ब्रह्म-समाज एवं प्रार्थना-समाज ने कार्य किये। धार्मिक चतक गांधी जी ने इनके उद्धार के लिये अथक प्रयास किये। इन समस्त कारकों ने १९ वीं शताब्दी के अन्त तक भारतीय समाज की रूप-रेखा को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया।

**धार्मिक परिवर्तन**—उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत के धार्मिक पुनरुत्थान की कहानी भी देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई है। भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें ज्यों-ज्यों गहरी पड़चती गईं, त्यों-त्यों इस देश में दखिन्नारायण का प्रभावक्षेत्र बढ़ता गया। अंग्रेजों ने देश के उत्तम उद्योग-धन्ये एक-एक करके नष्ट कर दिये और वरिणामस्वरूप लाखों कारीगर बेकार हो गये। विवश होकर उन्होंने कृषि का सहारा लिया। हमारे विदेशी दासकों का स्वार्थ इसी में था कि भारतीय जनता की धार्मिकता का एकमात्र साधन कृषि हो जाय, जिससे कि उन्हें निर्यात के लिये कच्चा माल बहुत कम मूल्य पर मिलता रहे और इंग्लैण्ड का बना माल यहाँ अत्यन्त मूल्य पर बिक सके।<sup>१</sup> अंग्रेजों की इस धार्मिक नीति का परिणाम यह हुआ कि वह दिन आ पड़ूँगा जब भारत भर में पेट-पीठ मिले लोग दृष्टिगत होने लगे। अनेकों यूरोपीय प्रशासकों ने अपनी धार्मिक भरी भावों से देखा था कि भारतीयों की कंठी दुर्दसा हो गई थी। लार्ड विलियम बेंटिक (Lord William Bentinck) ने लिखा था : “भारत में व्यापारिक क्रांति का भीषण दुष्प्रभाव पड़ा है जिससे देश में सर्वत्र निर्धनता छा गई है, और उससे अनेकों बगों के कटों में वृद्धि हो गई है, जो हमारी भावों के सामने हैं और ऐसा उदाहरण व्यापारिक इतिहास में कहीं बूढ़ेने से भी नहीं मिलेगा।”

जब औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के कारण इंग्लैण्ड के निवासी प्राविधिक ज्ञान में दिन दूनी, रात चौगुनी उन्नति कर रहे थे, तब भारत पराधीनता के क्लोरोफार्म में बेसुध पड़ा था। आखिरकार एक लम्बी बेहोशी के बाद भारत जागा और उसका धार्मिक पुनरुत्थान प्रारम्भ हुआ, परन्तु धीमी गति से। 'अमेरिका में गृहयुद्ध (१८६१-६५) छिड़ने के कारण भारत के कपड़ा उद्योग को यूरोपीय डॉबा स्वीकार करने के लिये प्रोत्साहन मिला और भारत ने धीरे-धीरे सूती मिल बनाने प्रारम्भ कर दिये जिसके कारण आज वह कपड़ा के उत्पादन की वर्तमान सुदृढ़ स्थिति में आ गया है। इसके बाद में अन्य उद्योगों का सूत्रपात हुआ जिनमें इस्पात और लोहा, सीमेंट पीली आदि उद्योगों के क्रमशः नाम गिनाये जा सकते हैं। यद्यपि भारतीय पूँजी के मागे आने में हिचकिचाहट-सी नजर आती रही, किन्तु बाद में औद्योगिक कारखानों में यह पूँजी धड़ाधड़ लगने लगी। एशिया के अंग्रेजी उपनिवेशों, विशेषतः बर्मा और मलाया में तथा ममरीकी प्रदेशों में भारतीय पूँजी की सफल होने लगी और एक बार भारतीय व्यापारिक फर्म उन प्रदेशों में खुलने लगे जहाँ कुछ शताब्दियों पहिले हाथ फँसाकर भारतीय व्यापारियों के साहस और सद्भावना का स्वागत किया जाता था।”<sup>१</sup>

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उपरिखिण्त सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तनों का शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा, इसका उल्लेख हम नीचे कर रहे हैं।

**शिक्षा पर प्रभाव—**उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए उनके फलस्वरूप राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव हुआ। देश के नेताओं ने अनुभव किया कि वे राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य तभी सम्पन्न कर सकेंगे, जब देश के नवयुवकों को राष्ट्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय भावनाओं से प्रीत-प्रोत कर दिया जायगा। परिणामस्वरूप भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक शिक्षा का विस्तार करने के लिये स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण तीव्र गति से किया जाने लगा।

भारतीयों के इस कार्य का प्रभाव यहाँ के छात्रों पर भी पड़ा। उन्होंने सहायता-अनुदान (Grant-in-aid) सम्बन्धी नियम बनाये और गैर-सरकारी स्कूलों को धार्मिक सहायता देकर, धनाभाव की बिन्ना से मुक्त किया। फलतः वे एकाग्रचित्त होकर शिक्षा-कार्य में जुट गये।

सामाजिक-धार्मिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के सभी अवयवों की प्रगति





सारांश में, १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। उसके सभी घंग विकसित हुए और भारत की समस्त जनता के लिये शिक्षा सुलभ हो गई। शिक्षा का रूप प्रायः वही रहा, जो १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में था। पुस्तकीय ज्ञान पर यथावत् बल दिया गया, परन्तु माध्यमिक स्तर पर उसमें भौतिकीय विषयों को सम्मिलित किया गया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहा, जिससे भारतीय भाषाओं का विकास न हो सका। भारतवासियों को अंग्रेजी शिक्षा से अधिक लाभ होने के कारण अंग्रेजी विद्यालयों की ही स्थापना हुई। उनकी व्यवस्था पाश्चात्य ढंग पर की गई। यही यह बताना आवश्यक है कि शिक्षा का प्रसार नगरों में ही हुआ। ग्रामों तक वह प्रवेश न कर सकी, क्योंकि देश में होने वाले सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तन नगरों तक ही सीमित रहे और ग्रामों में उनका प्रवेश न हो सका। परिणामस्वरूप वही शिक्षा का रूपान्तर नहीं हुआ और ग्रामीण पाठशालाएँ ही शिक्षा का केन्द्र बनी रहीं, जिनमें शिक्षा प्राचीन ढंग से दी जाती थी।

### बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में

अन्तीसवीं शताब्दी में भारत में जिस सामाजिक तथा धार्मिक पुनरुत्थान का सूत्रपात हुआ था, उसमें बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में वितरण तीव्रता पा गई। परिणामस्वरूप किस प्रकार के सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तन हुए, उनका सक्षिप्त विवरण प्रचलित पत्रिकाओं में प्रकट किया जा रहा है :

सामाजिक परिवर्तन—ब्रह्म समाज, प्रार्यना समाज, दक्षिणी शिक्षा-समिति, पियोसोफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से सामाजिक उत्थान के कार्य में संलग्न थे। २० वीं शताब्दी में भी उन्होंने अपने कार्य-क्रमों को जारी रखा। इन कार्य-क्रमों के सन्तर्गत प्रसृत्यता-निवारण, हरिजनोद्धार, शिक्षा-प्रसार तथा सामाजिक क्रूरतियों के निवारण को स्थान दिया गया। १९०५ में मोखले ने 'सर्वोद्देश्य आज़ाद इंडिया सोसाइटी' (Servants of India Society) की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत-माता की सेवा करना था। १९११ में नारायण मस्हार जोशी ने बम्बई में 'सोशल सर्विस लीग' (Social Service League) का संगठन किया जिसका मुख्य लक्ष्य जनसाधारण के लिये जीवन तथा कार्य की उत्तम दशाएँ प्राप्त करना था। इस लीग ने १५ वर्षों में बयस्को के लिये १७ रात्रि-विशालय और ११ पुस्तकालय स्थापित किये।

१९१४ में हृदय नाथ कुंजर ने इलाहाबाद में 'सेवा समिति' (Seva Samiti) का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई में उन्नति करना था। उसी वर्ष श्रीराम बाबुपेई ने 'सेवा समिति ब्यांघ' स्थापित

हुई। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई और उसके स्वीकृत स्थानीय कर लगाये गये। १८८२ के 'भारतीय शिक्षा आयोग' (Education Commission) की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत स्थायी संस्थाओं को सौंप दिया गया।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। परन्तु समाज पर शिक्षा तथा संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण माध्यम के स्तर भाषाओं की उपेक्षा की गई और अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया गया। परिवर्तनों के कारण औद्योगिक विषयों की शिक्षा की मांग बढ़ी। सभी प्रान्तों में औद्योगिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

परिवर्तित सामाजिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं के कारण उच्च शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान गया और उसने १८५७ में कलकत्ता, बंगाल में विद्यालयों का शिलान्यास किया। १८८२ में पंजाब विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। समाज में राष्ट्रीय चेतना के उदय होने के अनेकों भारतीयों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से उच्च शिक्षा के लिये स्थापित किये। इनमें पूना का फर्ग्यूसन कॉलेज, लाहौर का दवान्त कॉलेज और बनारस का सेन्दुल हिन्दू कॉलेज था।

इस काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में विशेष परिवर्तन हुआ। स्त्री-शिक्षा के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदला। इसका श्रेय पं० ईश्वरदास विद्यासागर, भगवत्कृष्ण, महादेव गोविन्द रानाडे और बैराम जी माना जाता है। इन निस्स्वार्थ समाज-सेवकों ने कन्या विद्यालयों के निर्माण के लिये धन एकत्रित करने में अथक प्रयास किया और देश के विभिन्न भागों में स्त्री-शिक्षा-विद्यालयों का निर्माण किया। समाज-सुधारकों के कार्यों से प्राप्त करके स्वयं स्त्रियों ने शिक्षा के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की और वे व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में भी अग्रसर हुईं।

हम ऊपर संकेत कर चुके हैं कि इस अवधि में हरिजनोद्धार के विशेष प्रयत्न किये गये। मितों और फ़ैक्ट्रियों की स्थापना की गई, साथ साथ काम करने के कारण छुमा-छूत तथा जाति व्यवस्था के बन्धन हटते चले गये। फलतः निम्न जातियों की सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति परिवर्तन हुआ। इस दिशा में महारमा फूले, ब्रह्म-समाज, प्रार्थना-समाज आर्य-समाज ने अति दलावनीय कार्य किया। उनके आन्दोलनों का प्रभाव हुआ कि १९ वीं शताब्दी के अन्त तक भारतीयों के मस्तिष्क से छुमा-छूत का अन्धना बहुत कुछ निकल गई। परिणामतः अछूतों के बालक सार्वजनिक स्कूलों में प्रवेश करने लगे।

द्वार के कार्य में सबसे अधिक योग महात्मा गांधी ने दिया। परिणामतः हरिजन अपने राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों के प्रति जागृत हुए। कुछ समय से शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे इसके लाभ को पूर्णतः समझ गये। उनमें ज्ञान-पिपासा की वृद्धि हुई और वे शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार की माँग करने लगे। इस कार्य में उन्हें अपने नेताओं—डाक्टर बी० धार० अम्बेदेकर और एम० सी० राजा से विशेष सहायता प्राप्त हुई।

**आर्थिक परिवर्तन—**उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में आर्थिक अभ्युत्थान का युग प्रारम्भ हो गया था। बीसवीं सदी के प्रारम्भ से स्वदेशी आन्दोलन ने प्रबल रूप धारण किया, जिससे हमारे उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। देश में साबुन, दियासलाई, पैसिल आदि के अनेकों छोटे-बड़े कारखानों का निर्माण हुआ। परन्तु सरकार की अनुदार आर्थिक नीति के कारण हमारे उद्योग-धंधे पनप न सके। प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के काल में देश के उद्योग-धन्धों की कुछ उन्नति हुई क्योंकि हमारे लिये विदेशों से माल प्राप्त करना कठिन था। इसीसे, वस्त्र और पटसन के उद्योगों ने पर्याप्त उन्नति की। प्रथम और द्वितीय महायुद्धों के अन्तरिम काल (१९१९-२९) में चीनी, लोहा, वस्त्र, लोहा व इस्पात, दियासलाई, फागड़ आदि अनेकों उद्योगों को सरकारी सुरक्षण की सुविधा मिल जाने के कारण औद्योगिक विकास की गति निश्चिन्नेष्ट प्रपेक्षाकृत तेज थी। द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) में इंग्लैण्ड, अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि देशों के उद्योग युद्ध-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में फँसे रहने के कारण भारत को अपना माल न भेज सके। फलतः भारतीय उद्योगों का सराहनीय विकास हुआ।

२० वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में उद्योगों के क्रमिक विकास से जनता के जीवन में आर्थिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। विशाल औद्योगिक नगरों में विभिन्न जातियों के लाखों श्रमिक निवास करने तथा कल-कारखानों में कार्य करने लगे। पर्याप्त धन मिलने के कारण उनकी आर्थिक दशा में सुधार हुआ। साथ-साथ काम करने और विभिन्न मनोरंजनों में भाग लेने के कारण उनका भेद-भाव समाप्त होना प्रारम्भ हुआ और उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। उन्होंने सामान्य तथा औद्योगिक शिक्षा के मूल्य को समझा और वे अपने बच्चों के लिये उसे मुलभ बनाने के लिये क्रियाशील हुए।

**शिक्षा पर प्रभाव—**उपरोक्त सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का शिक्षा के सभी अंशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आन्दोलन ने इस कार्य में योग दिया। भारतीयों ने विदेशी सरकार से शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की बलपूर्वक माँग की। १९११ में मोसले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य

एसोसियेशन' (Seva Samiti Boy Scouts Association) का संघटन किया।

उपर्युक्त सभी संगठनों के प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में जागृति की लहर दौड़ गई, जिससे उनके विचारों, धारतों तथा रीति-रिवाजों में बहुत परिवर्तन हुआ। सबसे अधिक परिवर्तन स्त्रियों और बच्चों की स्थिति में हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्त्रियों तथा बच्चों के उत्थान में प्रतिष्ठित योग प्राप्त हुआ। उन्होंने ही महिला तथा बच्चों के उत्थान में नवीन स्फूर्ति प्रदान की।

१९१७ में भारत-मन्त्री मोण्टेग्यू (Montague) के भारत आने पर यहाँ की महिलाओं ने उनसे अपने राजनैतिक अधिकारों की माँग की। महिलाओं ने अपने आन्दोलनों को सुसंगठित रूप प्रदान करने के लिये अपने-अपने संस्थाओं का निर्माण किया। १९१७ में श्रीमती डोरोथी जिनराबदास ने 'महिला भारतीय संघ' (Women's Indian Association) की स्थापना की। १९२३ में 'भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय समिति' (National Council of Women in India) का निर्माण किया गया। १९२६ में 'संयुक्त भारतीय महिला सम्मेलन' (All India Women's Conference) का आयोजन किया गया। इन संस्थाओं ने अन्य माँगों के साथ-साथ शिक्षा-सम्बन्धी माँगें भी की जो इस प्रकार थीं:—(१) बालिकाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, (२) हाई स्कूल तक बालिकाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पदार्पण कर सकें, और (३) बालिकाओं को धार्मिक तथा निःशुल्क शिक्षा दी जाए।

महिला आन्दोलन से प्रभावित होकर सरकार ने उनकी प्रार्थना सभी बच्चों को दूर करने का प्रयास किया। १९२३ में बच्चों को प्रथम बार प्रांतीय धारा-सभाई एवं केन्द्रीय व्यवस्थापिका के लिए भेज देने का अधिकार प्राप्त हुआ। १९३० के 'शारदा ऐक्ट' (Sharda Act) के अनुसार दान रिवाज का निषेध कर दिया गया।

इस अवधि में सर्वत्र हिन्दुओं में जागृति प्रारम्भ हो गई थी और राष्ट्रीय भारतीय समाज पर नयी धाराधारा की कर्मक-कानिशा को जो खानने का एक मकल कर लिया था। धार्मिक-धर्म, ब्रह्म-धर्म और धर्मना समाज जीवन के ही प्राणी-आर के पुरातन कार्य में अपनी योग्यता को प्रकट कर चुका था। योपान ३५५ कोषने न धर्मधारा को समुक्त नष्ट करने के लिए १९०६ में 'भारत सरकार' की स्थापना की गई थी और वह धार्मिक कार्य कर रहा था। हरिजनो के उत्थान के लिए १९०६ में निर्धारण की गई थी और १९३० में 'भारत के उत्थान' (Depressed Class Movement) प्रारम्भ की। हरिजनो-

शिक्षा देना था। १९२१ के उपरान्त जनता ने अपनी सामाजिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा की माँग का नारा नुज्जद किया। फलस्वरूप १९३७ तक व्यावसायिक शिक्षा का प्रवाह निर्बाध गति से रहा। तत्पश्चात् द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण उसमें क्षिप्तता आ गई। कानून, चिकित्सा, पशु-चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वन विज्ञान, कला, वाणिज्य तथा कृषि की शिक्षा के लिये नवीन संस्थाओं का निर्माण हुआ और उनसे भारतीयों की परिवर्तित सामाजिक तथा धार्मिक आवश्यकतायें कुछ सीमा तक पूर्ण हो गईं। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों की वृद्धि भी स्थान दिया जा चुका था। द्वितीय महायुद्ध की अवधि में ऐसे व्यक्तियों की माँग बढ़ गई थी, जो प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हों। इस शिक्षा से अधिक धार्मिक लाभ देखकर भारतीयों ने प्राविधिक शिक्षा का आन्दोलन प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप १९४६ में 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा-समिति' (All India Council of Technical Education) का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य सरकार को प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देना और प्राविधिक शिक्षा-संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना था।

हम ऊपर लिख चुके हैं कि २० वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में त्वरित गति से परिवर्तन हो रहा था और वे मनुष्यों के समान शिक्षा की माँग कर रही थीं। उदार समाज सेवकों ने उन्हें सहयोग दिया और सरकार ने उनकी माँगों को पूर्ण करने का प्रयास किया। फलतः प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा-संस्थाओं की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। स्त्रियों को उनकी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा देने के लिये १९१६ में गुना में 'एस० एन० डी० टी० इंडियन वीमेन्स यूनीवर्सिटी' की स्थापना की गई। समाज-सुधारकों के प्रयासों के फलस्वरूप स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे थे, उन्होंने श्री-शिक्षा की गति को और भी द्रुत कर दिया। १९२१ से १९३७ तक श्री-शिक्षा की प्रगति का बहुमुखी रूप दिखाई देने लगा। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाने के कारण जनता सह-शिक्षा की विरोधी नहीं रही। अतः सभी प्रान्तों में सह-शिक्षा का प्रचलन हो गया। इसके प्रतिरिक्त शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक प्रकार की शिक्षा-शाला में लड़कियों की उपस्थिति एक सामान्य बात हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में शिक्षित व्यक्तियों की माँग में वृद्धि होने के कारण अनेकों स्त्रियाँ नौकरी करने लगीं। नौकरी करने से स्त्रियों ने अपनी धार्मिक स्थिति को परिवर्तित पाया क्योंकि वे धार्मिक स्वतन्त्रता का उपयोग करने लगीं थीं। अतः उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की अधिक प्रेरणा प्राप्त हुई।

ने के लिये केन्द्रीय धारा-मभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया, पर उन्हें ने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हुई। उनके उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त के विभिन्न प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किये। हार्टग समिति (Hartog Committee) ने प्राथमिक शिक्षा को लाभप्रद करने के लिए अपव्यय (Wastage) तथा प्रवरोधन (Stagnation) का कार्य-सी मंत्रिमंडल ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रचलित करने के प्रयत्न किये। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई वैयक्तिक शिक्षा की योजना को कार्यान्वित किया गया।

इस युग के सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि में वृद्धि हुई। फलस्वरूप शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट प्रगति दृष्टिगत होने लगी। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। इन विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के स्थान पर अंग्रेजी को ही प्रतिष्ठित रखा गया। कारण यह था कि अंग्रेजी की शिक्षा से सामाजिक सम्मान में वृद्धि होती थी। परन्तु राष्ट्रीयता की भावना के उदय के कारण अंग्रेजी के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदल रहा था। फलतः प्रान्तीय स्वशासन में प्रायः सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं हो गई। धार्मिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप प्रान्तीय सरकारों ने टेक्निकल और कृषि हाई स्कूल खोले। वाणिज्य की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया।

सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तनों ने उच्च शिक्षा के प्रसार में भी योगदान दिया। दो महायुद्धों तथा 'भारत छोड़ो' (Quit India) प्रस्ताव के कारण जन-साधारण में सर्वव्यापक जागृति का प्रविर्भाव हो गया था और वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये उत्कण्ठित हो गई थी। गुडकालीन समय में व्यवसायी वर्ग को व्यापार में अत्यधिक लाभ हुआ था और वह उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिये उदार धन-राशि देने को उत्तम था। परिणामतः २० वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में १६ विश्वविद्यालयों की माधार-शिला रखी गई और पुराने विश्वविद्यालयों का पुनः गठन किया गया।

सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तनों के कारण व्यावसायिक शिक्षा की मांग भी बढ़ी। भारतीय जनमत इस पक्ष में था कि राष्ट्रीय शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को उचित स्थान दिया जाय। ऐसा करने से ही देश का धार्मिक विकास हो सकेगा। परन्तु विदेशी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। १९२१ में सम्पूर्ण देश में केवल ४८ व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएँ थीं, जिनका प्रमुख उद्देश्य श्रमकीय विभागों के लिये भारतीयों की किसी उद्योग व व्यवसाय की

“सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न” होगा अर्थात् भारत पर किसी बाह्य शक्ति का अधिकार नहीं रहेगा। साथ ही भारत “गणराज्य” होगा अर्थात् भारत में किसी राजवंश का शासन नहीं होगा। फिर देश में ‘लोकतन्त्रात्मक’ राज्य होगा अर्थात् देश का शासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से चलाया जायगा। नागरिकों को “विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता” होगी और उन्हें “सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय” प्राप्त होगा। इनका अर्थ यह हुआ कि भारत एक धर्म निरपेक्ष (Secular State) राज्य होगा, जिसमें समस्त नागरिक धर्म अथवा जाति के भेदभाव बिना, सामाजिक, धार्मिक तथा राज-नितिक अधिकारों का उपयोग करेंगे। इन सब परिवर्तनों के फलस्वरूप समाज की एक नवीन रूप-रेखा होगी।

दिसम्बर, १९५४ में भारतीय संसद ने घोषणा की कि भारत की अर्थ-नीति का सामान्य उद्देश्य ‘समाजवादी ढाँचा के समाज’ (Socialistic Pattern of Society) की रचना है। इस समाज के कुछ अथवा मूल उद्देश्य क्या होंगे, उनका स्पष्टीकरण करते हुए योजना-आयोग ने लिखा है : “रहन-सहन का ऊँचा मान, या जिसको कभी-कभी भौतिक उन्नति कहा जाता है, अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। वस्तुतः यह भौतिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का एक साधन है। जिस समाज की अपनी अधिकतर जन-बल और समय जीवन के निर्वाह-मात्र की आवश्यकताएँ पूरी करने पर ही लगाना पड़ेगा, वह जीवन के उच्च लक्ष्यों की ओर उतना ही कम ध्यान दे सकेगा। धार्मिक विकास का उद्देश्य समाज की उत्पादक शक्ति को बढ़ा कर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है कि परस्पर विरोधी प्रतिभाओं और प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति और उपयोग अच्छे ढङ्ग से हो सकें। इसलिये विकास और धार्मिक उन्नति की गति आरम्भ से ही ऐसी होनी चाहिये कि वह समाज के बुनियादी उद्देश्यों के साथ मेल खाती रहे। किसी अविकसित देश के सामने अपने वर्तमान धार्मिक और सामाजिक ढाँचे से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेने का ही काम नहीं होता है, अपितु उन्हें इस प्रकार ढालने और पुनर्गठित करने का भी होता है कि वे अधिक उच्च और व्यापक सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक हों। इन गुणों या मूल उद्देश्यों को ‘समाज का समाजवादी ढाँचा’ (Socialistic Pattern of Society) शब्दों में बोधा गया है।”

‘समाज का समाजवादी ढाँचा’ का अभिप्राय यह है कि उन्नति के कार्यों की कसौटी जिन्नी लाम न होकर समाज का लाम होना चाहिये, और विकास



सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव हरिजनों पर भी पड़ा और वे शिक्षा-अधिकार की माँग करने लगे थे। फलतः २० वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हरिजनों की शिक्षा में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। १९२१ में प्रांतीय शिक्षा का संचालन-सूत्र भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ जाने के कारण हरिजन-शिक्षा की प्रगति में तेजी आ गई। १९३७ में विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का निर्माण हो जाने से हरिजनों की सभी शिक्षा-सम्बन्धी माँग पूर्ण हो गई।

इस अवधि की एक प्रमुख विशेषता थी प्रौढ़-शिक्षा। उद्योगों के विस्तार के कारण लाखों श्रमिक कल-कारखानों में कार्य करने लगे थे। उनमें शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही थी। अतः उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिये प्रौढ़-शिक्षा की व्यवस्था की गई। यह कार्य संगठित रूप में १९३७ से भारत के सभी प्रान्तों में प्रारम्भ किया गया।

### स्वतन्त्र भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन

१५ अगस्त १९४७ को देश के सपूतों ने अपने महाधारण बलिदानों के पुरस्कारस्वरूप भारत माता को परतन्त्रता की झेंड़ियों से मुक्त किया। शताब्दियों से पद-दलित भारतवासियों ने स्वतन्त्रता के वातावरण में एक नवीन युग में प्रवेश किया। उनकी वर्षों की साधना पूर्ण हुई और उन्होंने अपनी इच्छानुसार देश की शासन-व्यवस्था संचालित करने के लिये २६ जनवरी, १९५० को भारत में एक नवीन संविधान लागू किया। संविधान की प्रस्तावना में भारत की नवीन रूप-रेखा इन शब्दों में अंकित की गई : "हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली वन्धुता बढ़ाने के लिये एक संकल्प होकर.....इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और धार्यापित करते हैं।"

प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का सामाजिक-आर्थिक जीवन उससे पूर्वतया भिन्न होगा जो कि ब्रिटिश शासन-वा संविधान के उपरोक्त शब्दों की व्याख्या करने

शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वतन्त्र भारत में शिक्षा पर सामाजिक-धार्मिक संघात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है।

## स्वतंत्र-भारत में शिक्षा पर सामाजिक-धार्मिक संघात

स्वतन्त्र भारत में सामाजिक-धार्मिक संघात के फलस्वरूप शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

**प्राथमिक शिक्षा**—“किसी भी राष्ट्र का सामाजिक तथा धार्मिक विकास उसके निवासियों की शिक्षा पर निर्भर है।” इसी कथन को ध्यान में रखकर देश के नेताओं ने भारतीय संविधान में यह घोषित किया है कि १४ वर्ष तक की आयु के बालकों तथा बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क होगी।<sup>१</sup> आयु की इस अवधि में शिक्षा से लाभ उठाकर भारत के भावी नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकेंगे और परिवर्तित सामाजिक धार्मिक-व्यवस्था में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा का रूप बेसिक शिक्षा होगी जिसमें प्रत्येक छात्र को एक आधारभूत चित्त का प्रशिक्षण दिया जायगा। इससे यह लाभ होगा कि छात्र बड़ा होकर, यदि वह चाहेगा, तो उस चित्त में अधिक दक्षता प्राप्त करके अपना जीवन-यापन कर सकेगा। इससे समाज में बेकारी भी नहीं फैलेगी और छात्र एक नवयुवक के रूप में अपने को धार्मिक व्यवस्था के लिये उपयुक्त पायेगा।

**माध्यमिक शिक्षा**—माध्यमिक शिक्षा का रूपान्तर करके उसे देश की सामाजिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाये जाने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने ‘माध्यमिक शिक्षा-आयोग’ द्वारा पाठ्य-क्रम के विभिन्नोत्तरण (Diversification of Courses) और बहुउद्देशीय विद्यालयों, (Multipurpose Schools) की स्थापना के प्रस्तावों को स्वीकार करके कार्यान्वित कर दिया है। इन विद्यालयों में छात्रों को अपनी अभिरुचियों तथा अभिनतियों के अनुकूल विषयों के अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने हाथ, मस्तिष्क, हृदय तथा शरीर के उचित उपयोग की शिक्षा का अवसर सुलभ होगा। फलतः उनका सर्वांगीण विकास होगा, जिससे वे नवीन समाज के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे।

1. Article 45 of the Constitution Adopted by Free India on January 26, 1950.

के मादशों तथा सामाजिक और धार्मिक सम्बन्धों का गठन ऐसा होना चाहिये कि वे केवल राष्ट्रीय धाय और नियोजन में ही वृद्धि नहीं, अपितु धाय और धन की अधिकाधिक समानता लाने में भी सहायक हों। उत्पादन, वितरण, खपत और पूँजी-विनियोग सम्बन्धी मुख्य निर्णय और वस्तुतः सभी सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों के निर्णय—ऐसी संस्थाओं द्वारा किये जाने चाहिये जो सामाजिक उद्देश्यों की भावना से अनुप्रेरित हों। धार्मिक विकास के साथ समाज के उन वर्गों को अधिकाधिक पहुँचाने चाहिये जो कि अपेक्षाकृत कम सम्पन्न हैं और धाय, धन तथा धार्मिक सत्ता का केन्द्रीकरण क्रमशः कम होता जाय। सब मिलाकर समस्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देने की है कि उसमें वे व्यक्ति भी अपने जीवन का मान ऊँचा उठाने और देश की समृद्धि में अधिक भाग लेने में समर्थ हो जायें जो कि अब तक संगठित प्रयत्नों के द्वारा की हुई उन्नति में बहुत कम भागीदार बन सके हैं और बैठा करने की बल्कि तक नहीं कर सके हैं। इस प्रक्रिया में इस वर्ग के लोगों की धार्मिक और सामाजिक स्थिति ऊँची हो जायगी।

उपरोक्त धार्मिक तथा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यान्वित किया गया है। इनमें धार्मिक नियोजन (Economic Planning) को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। इन योजनाओं के सामाजिक उल्लेख (Social Implications) पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे भारतीय समाज में कान्तिकारी परिवर्तन कर देंगे। इन योजनाओं के अनुसार भारत के विधान में बताये गये राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्तों (Directive Principles of State Policy) का अनुसरण किया जायगा जिससे भारत में कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना होगी। इन राज्य में ऐसी सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था होगी जो स्वतन्त्रता और भौतिकान्त्रिक मुक्त्यो पर आधारित होगी, जिसमें जाति, वर्ग तथा मर्दासंगत भेदभाव नहीं होगा और छोटी-छोटी-छोटी एवं उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होगी तथा अधिक से अधिक सामाजिक न्याय (Social Justice) उपलब्ध होगा।

भारत में कारिर्वर्धित सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तन माने जाते हैं सरकार पूर्वकालीन संन्य है। परन्तु इन विधान कावों का यत्न करने के उत्तरदायित्व को सरकार तभी पूर्ण कर सकती, जब उसे जनता का हार्दिक सहयोग प्राप्त होता हो और वह सभी सम्भव होता जब विधा के द्वारा जन जन का दृष्टिकोण परिवर्तित कर दिया जायगा। इसी उद्देश्य के लक्ष्य भारत में विधा का पुनरुद्भव किया जा रहा है और यह सामाजिक तथा धार्मिक मुक्त्यो, उद्देश्यो, धारणाओं तथा परिवर्तनों का अनुद्भव बनाय जा रहा है। पुनरु

की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से विकिसा-शिक्षा की संस्थाओं की संख्या में वृद्धि की जा रही है। १९५६ में मेडिकल कॉलेजों की संख्या ३० थी, जो १९६१ में ५५ हो जायगी। इसके अतिरिक्त देशी विकिसा प्रणालियों में प्रशिक्षण देने का भी कार्यक्रम सरकार ने कार्यान्वित कर दिया है। इसके लिए द्वितीय योजना में ६ करोड़ रुपये रखे गये थे और तृतीय योजना में अस्थायी रूप से ८ करोड़ रखे गये हैं।

**ग्रामीण उच्च-शिक्षा**—भारत ग्रामों का देश है। १९५१ की जनगणना के अनुसार इस देश की ८३ प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है। ब्रिटिश शासन-काल में इस विशाल ग्रामीण जन-समुदाय की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। स्वतन्त्र भारत के नव-निर्माण के लिये ग्रामीणों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था को अनिवार्य माना गया है। यह स्वीकार किया गया है कि यदि ग्रामवासियों को उच्च शिक्षा का अवसर नहीं प्राप्त होगा, तो उनका सामाजिक तथा धार्मिक उत्थान नहीं हो सकेगा और वे समाज की नवीन व्यवस्था में अपना उचित स्थान ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसी विचार से प्रेरित होकर 'विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग' (University Education Commission) ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध स्नातक पूर्व कॉलेजों की स्थापना का सुझाव सरकार के समक्ष रखा। 'सरकार ने आयोग के सुझाव को मान्यता प्रदान की है और 'रूरल इंस्टीट्यूट्स' (Rural Institutes) की स्थापना कर रही है।

**स्त्री-शिक्षा**—भारतीय संविधान में लिंग के कारण व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया गया है। स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान सभी अधिकार प्रदान किये गये हैं। देश के सामाजिक तथा धार्मिक उत्थान में स्त्रियों के स्थान को महत्वपूर्ण माना गया है। अतः पतान्दियों से पददलित तथा शिक्षा से वंचित नारों के लिये सभी शिक्षा-संस्थाओं के द्वार खोल दिये गये हैं। इतना ही नहीं, उसको शिक्षा प्राप्त करने की विशेष सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। वस्तुतः इस कार्य में राष्ट्रीय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रदर्शित पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। गांधी जी का कथन था : "जहाँ तक स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न है, मैं इस बात में निश्चित नहीं हूँ कि क्या उनकी शिक्षा अनुष्यों की शिक्षा से भिन्न होना चाहिये और इसे कब प्रारम्भ होना चाहिये। परन्तु मेरा यह हृदय विचार है कि स्त्रियों को शिक्षा की वे ही सुविधायें प्राप्त होनी चाहिये, जो अनुष्यों को प्राप्त हैं और जहाँ

**विद्यालय शिक्षा**—विश्वविद्यालय शिक्षा को समाज के समाजवाद को अग्रगण्य बनाने की चेष्टा प्रारम्भ कर दी गई है। इस उद्देश्य के लिए 'सामान्य शिक्षा' (General Education) की दो योजनाएँ तैयार की गई हैं। मुख्य योजना में प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि के मूल विषयों के अध्ययन की 'सामान्य शिक्षा' सभी स्नातक-पूर्व (graduates), गैर व्यावसायिक (Non-Professional) स्तरों के विद्यार्थियों में 'सामान्य शिक्षा' के लिये सप्ताह में ६ घण्टों (Period) के अन्तर्गत की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह इसलिये किया जा रहा है जिससे कि भारत की नवीन धार्मिक व्यवस्था में, जिसमें उद्योगों का विकास होना है कि इस (तीसरी) योजना के अन्तर्गत विज्ञान के विद्यार्थियों का अनुपात लगभग ४० प्रतिशत हो जाय। विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षकों, इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं में विद्यार्थियों और उद्योगों के कार्यकर्ताओं आदि की बढ़ती हुई माँग पूरी करने के लिये ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है।<sup>१</sup>

**प्राविधिक शिक्षा**—भारत की पर्य-नीति के अन्तर्गत देश का औद्योगिककरण प्रति तीव्र गति से किया जा रहा है। नवीन उद्योगों के लिये प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों की निरन्तर अधिकाधिक संख्या में आवश्यकता होगी। अतः सरकार ने प्राविधिक शिक्षा के प्रति उदार नीति अपनाई है। फलस्वरूप द्वितीय योजना की अवधि में इंजीनियरों की संख्या ६५ से बढ़कर ९७ हो गई है। पोलिटैक्नीकों की संख्या ५,८८८ से बढ़कर १३,१९५ हो गई है। पोलिटैक्नीकों की संख्या ११४ से बढ़कर १९७ और प्रति वर्ष प्रविष्ट किये जा सकने वालों की संख्या १०,४८४ से बढ़कर २४,०२० हो गई है। उद्योगों के विकास के कारण तीसरी योजना के समय ४५,००० स्नातक और ८०,००० डिप्लोमाधारियों की आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है। यह सब पूरी हो जायेगी।<sup>२</sup>

**विकसित-शिक्षा**—'समाज के समाजवादी ढाँचे' में नागरिकों के स्वास्थ्य

१. तीसरी पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक रूप-रेखा, पृष्ठ १०१
२. Technical Education.
३. तीसरी पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक रूप-रेखा, पृष्ठ १०३

धर्मशास्त्रों को हल करने के लिये बंबई की माध्यमिक प्रारम्भ किया। १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कावेरि, चार्म-समाज, ब्रह्म-समाज एवं प्रार्थना-समाज ने सामाजिक सुधार किये। इस काल में भारत की धार्मिक दशा में सुधार हुआ। इन सामाजिक तथा धार्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप शिक्षा का तीव्र गति से प्रसार हुआ। सरकार ने गैर-सरकारी स्कूलों को धार्मिक सहायता दी। प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया गया। माध्यमिक विद्यालयों में औद्योगिक पाठ्य-क्रम प्रारम्भ किया गया। स्त्रियों तथा हरिजनों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के कारण उनकी शिक्षा की माँग में वृद्धि हुई। २० शताब्दी के पूर्वार्द्ध में 'सर्वेन्द्रस मांछ इडिया सोसाइटी', 'सोशल-सर्विस लीग' आदि की स्थापना के कारण सामाजिक सुधार में तीव्रता आ गई। महिला संगठनों ने शिक्षा की माँग की। सबल हिन्दुओं में जागृति हुई। इस काल में धार्मिक अभ्युत्थान भी हुआ। विश्व-युद्धों के कारण बाहर से माल आना बन्द हो गया। फलतः देश में धनकी उद्योग स्थापित हुए। उनमें कार्य करने वालों की धार्मिक दशा में सुधार हुआ। इन सामाजिक-धार्मिक परिवर्तनों के कारण भारतीयों ने शिक्षा-प्रविकार की माँग की। मोरले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का विधेयक केन्द्रीय धारा-सभा में प्रस्तुत किया। हर्टाग समिति ने प्राथमिक शिक्षा को अधिक लाभप्रद बनाने के लिये प्रवर्धन तथा प्रवर्धन को समाप्त करने के लिये सुझाव दिये। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। टेक्निकल और वृषि हाई स्कूल खोले गये। व्यावसायिक शिक्षा की माँग की गई। प्राथमिक शिक्षा का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। स्त्री-शिक्षा की विशेष प्रगति हुई। हरिजनों की शिक्षा-सम्बन्धी माँग पूर्ण हुई। प्रौढ़ शिक्षा का कार्य-क्रम प्रारम्भ किया गया।

स्वतन्त्र भारत में सामाजिक-धार्मिक परिवर्तन—स्वतन्त्र भारत की सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का रूप दिया गया है। देश एक धर्म-निरपेक्ष राज्य होगा। नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। भारत की धर्मनीति का सामान्य उद्देश्य 'समाजवादी आदर्श के समाज' की रचना है। धार्मिक विकास के साथ समाज के उन वर्गों के अधिकधिक पहुँचाये जायेंगे जो अपेक्षाकृत कम सम्पन्न हैं। देश के नव निर्माण के लिये पंचवर्षीय योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं। भारत की भावी सामाजिक तथा धार्मिक रचना अविध्य में पूर्णतः समाजवादी ढंग की हो जायगी। समाज के इसी रूप के अनुसार शिक्षा को निरन्तर परिवर्तित किया जा रहा है।

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा पर सामाजिक-धार्मिक संघात—देश ने सामाजिक

आवश्यक हो, वहाँ उनको शिक्षा को विशेष सुविधाएँ प्रदान की गईं।<sup>१</sup>

शिक्षा के अन्य कार्य-क्रम—नव-भारत की सामाजिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अन्य कार्य-क्रमों का भी ध्यान रखा गया है। इनके अन्तर्गत हैं :—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों तथा विद्यार्थियों की शिक्षा; विकलांगों की शिक्षा (Education of the Handicapped); संगीत, नृत्य, सज्जित कलाओं एवं प्रौद्योगिक शिक्षा।

## सारांश

सामाजिक परिवर्तनों का शिक्षा पर प्रभाव—समाज की धार्मिक एवं नीति पर समाज की अभिरचना पड़ी होती है। शिक्षा का कार्य अभिरचना को सफल बनाने रहता है। इस शिक्षा का रूप बहो होता जिसकी माँग समाज द्वारा की जाती है। हिटलर और बेनोनिपन ने सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल शिक्षा का रूपान्तर किया और शिक्षा की सहायता समाज के रूप को परिवर्तित किया।

धार्मिक परिवर्तनों का शिक्षा पर प्रभाव—समाज की धार्मिक धर्म मान-आचर शिक्षा की प्रगति और उमड़ा रूपान्तर होता है। ईसाई धर्म और धर्म के कारण जो धार्मिक परिवर्तन हुए, उनका प्रभाव शिक्षा पर पड़ा। कम की गति ने उन देशों की धार्मिक व्यवस्था को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। साम्प्रदायी सरकार ने कम के सभी कामकाज तथा धार्मिकान्ति में शिक्षा को सुलभ बनाने का अभिनन्दनीय प्रयास किया है।

ब्रिटिश शासन-काल में शिक्षा पर सामाजिक-धार्मिक लक्षण—१६ वीं शताब्दी के शुरू में भारत में सामाजिक-धार्मिक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ा। विद्वानों द्वारा समाज की गई शिक्षा व्यवस्था का देखा शिक्षा-व्यवस्था से निर्यात था। समाज के कारण देशी शिक्षा व्यवस्था का हानि होता बना रहा। जन-हीन बनाने से कोशिशों की गईं।

1. As for women's education I am not sure whether it should be different from men's and when it should begin. But I am strongly of opinion that women should have the same facilities as men and even more of them if necessary."—Dr. B. C. Chatterjee, p. 1.

3. "The first half of the twentieth century was marked by uncommon socio-economic changes." What effect did these changes produce on education ?
4. Discuss briefly the socio-economic impact upon the major aspects of education in free India.



तथा आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है, उसे बेसिक शिक्षा का रूप दिया है और उसमें प्रत्येक छात्र के लिये एक शिल्प की अध्ययन आवश्यक कर दिया गया है। माध्यमिक विद्यालयों के लिये पाठ्यक्रम का विभिन्नोकरण किया गया है और उसके अभ्यास की व्यवस्था बहुउद्देशीय विद्यालयों में की गई है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में 'सामान्य शिक्षा' की व्यवस्था की गई है और विज्ञान के शिक्षण के लिये विशेष आयोजन किया जा रहा है। उद्योगों में कार्यकर्ताओं की पूर्ति करने के लिये प्राविधिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ग्रामीणों के बौद्धिक विकास के लिये उच्च शिक्षा के 'रूरल इंस्टीट्यूट्स' स्थापित किये जा रहे हैं। बिना को शिक्षा को विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं।

## सहायक पुस्तकों की सूची

1. J. A. R. Marriott : *England Since Waterloo*.
2. Herbert Spencer : *Social Statics*.
3. Majumdar, Raychaudhri and Datta : *An Advanced History of India*.
4. M. K. Gandhi : *India of My Dreams*.
5. *Report of the University Education Commission*.
६. सत्यकेतु विद्यासंसार : यूरोप का प्रागुनिक इतिहास
७. बी० एन० मुनिया : भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का इतिहास
८. धर्मनाथ धरवाल : भारत की आर्थिक समस्याएँ
९. के० एम० पण्डितकर : भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण
१०. धर्मर नन्दी : भारत का संविधान
११. द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१२. तीसरी पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक कार्रवाई

## TEST QUESTIONS

1. How do socio-economic changes affect education ? Support your answer by giving concrete example from history.
2. Write a short essay on : "The socio-economic impact upon education during the Br..."

में राजनैतिक शिक्षा का हस्तक्षेप प्रारम्भ हुआ। सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जर्मनी के दो राज्यों—वरटम्बर्ग (Wurtemberg) और सेक्सनी (Saxony) ने शिक्षा को अपने राजनैतिक अधिकार के अन्तर्गत ले लिया और शिक्षा की व्यवस्था को रूपान्तरित करके उसको नया जामा पहिनाया। प्रठारहवीं शताब्दी में हैनोवर (Hanover) के शासक जार्ज द्वितीय (George II) और प्रुषा (Prussia) के शासक फ्रेडरिक महान् (Frederick the Great) ने वरटम्बर्ग तथा सेक्सनी का अनुकरण करके शिक्षा के रूप को परिवर्तित किया<sup>१</sup>। फ्रांस में राज्यक्रान्ति (Revolution) के समय तक प्राथमिक शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं था और उच्च-शिक्षा संस्थाओं पर अधिकार स्थापित करने के लिये चर्च और सरकार में संघर्ष चल रहा था। क्रान्तिकारियों ने प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का अन्त करके समाज का पुनः गठन किया और राजसत्ता की दाह-क्रिया करके 'गणतन्त्र' की स्थापना की।<sup>२</sup> इस राजनैतिक उथल-पुथल का शिक्षा पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उसको पूर्णतया राज्य के अधीन करके उसका काया-कल्प किया गया। नेपोलियन ने 'गणतन्त्र' को उखाड़ फेंका और फ्रांस में राजसत्ता की पुनः दृढ़ स्थापना करने के लिये शिक्षा-व्यवस्था पर अपना एक मात्र अधिकार स्थापित किया और घोषित किया कि सभी शिष्यालयों में राजभक्ति की शिक्षा प्रदान की जाय<sup>३</sup>। इतिहास में ऐसे उदारणों का अभाव नहीं है, जो यह प्रमाणित करते हैं कि शिक्षा पर राजनैतिक संपात होता है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, उसे भी अपवाद नहीं कहा जा सकता है। यही भी शिक्षा पर राजनैतिक संपात हुआ है और हो रहा है और समय-समय पर होने वाले राजनैतिक परिवर्तनों ने शिक्षा के रूप एवं उसकी व्यवस्था में अन्तर उदरन्न किया है। यह किस प्रकार हुआ है, इस पर हम नीचे विहंगम दृष्टि डाल रहे हैं।

### ब्रिटिश शासन-काल में शिक्षा पर राजनैतिक संपात

अंग्रेज किस प्रकार यहाँ तुला लेकर आये, उन्होंने किस प्रकार यहाँ कार-

1. T. Rayment : *The Principles of Education*, p. 44.
२. महाजन, गहराना और सेठी : *आधुनिक शासन विधान*, पृष्ठ ७१२
3. "All these schools were directed to take as the bases of their teaching of the ethical principles of Christianity, Royalty to the head of the state, and obedience to the statutes of university."—Carlton J. H. Hayes : *A Political and Cultural History of Modern Europe*, Vol. I, p. 655.

## अध्याय ६

# शिक्षा पर राजनैतिक संधात' X

शिक्षा तथा समाज दोनों अविच्छिन्न रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। शिक्षा समाज में ही फलती-फूलती है और समाज भी शिक्षा की छाया में अपने अधिक प्राणवान, सजग तथा सुसंस्कृत बनाता है। एक की प्रगति पर दूसरे की प्रगति निर्भर है और एक की प्रगति बहुत मंशों तक दूसरे के नाश का कारण बन जाती है।

शिक्षा का रूप समाज के रूप का परिवर्तन कर सकता है। शिक्षा अपनी व्यवस्था को रूपान्तरित करके एक ऐसी प्रापिक प्रयत्न राजनैतिक व्यवस्था का निर्माण कर सकती है, जो वर्तमान से पूर्णतः भिन्न हो। यदि कोई प्रभुत्व सम्पन्न राज्य किसी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है, तो उसे शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा द्वारा रूपान्तरित किये हुए समाज में स्थिरता होती है। यही कारण है कि सत्ताधारी राज्य अपनी राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करके शिक्षा के रूप को परिवर्तित करते हैं। अनेकों राज्यों और अनेकों राजनीतिक परिवर्तनों के समय ऐसा किया गया है। इस सम्बन्ध में इतिहास से कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं।

मध्य-युग में योरोप के देशों में शिक्षा की व्यवस्था चर्च द्वारा की जाती थी। चर्च ही शिक्षकों की नियुक्ति करता था, विद्यालयों का व्यय-भार वहन करता था, और शिक्षा के उद्देश्यों तथा मादशों को निश्चित करता था। जब योरोप में पुनः जागरण के कारण नवयुग का सूत्रपात हुआ, तो शिक्षा-व्यवस्था

में अपनी राजनैतिक नीति के अन्तर्गत अंगरेजों ने अन्तिम के उपरान्त जिस दमन पद्धति का सहारा लिया, उसने भारतीयों के देश-प्रेम तथा राष्ट्रीय चेतना को बलवती बनाया और फलस्वरूप शिक्षा का भारतीयकरण हुआ।

१८८२ से १९०५ तक

इस काल की प्रमुख घटना राष्ट्रीयता की भावना का प्रबल प्रवाह था। भारतीय अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति सजग होने लगे। वे शिक्षा के लाभों को समझ कर विदेशी सरकार से उसकी मांग करने लगे। राजनीति में पट्टे अंगरेजों ने उनको मुलावा देने के लिये 'भारतीय शिक्षा-आयोग' (Indian Education Commission) की नियुक्ति की, जिसने शिक्षा के सभी स्तरों की उन्नति करने के लिये विवेकपूर्ण सुझाव दिये। उनमें से भारत-सरकार ने उन्हीं को स्वीकृति प्रदान की जिनसे उनके राजनैतिक हित की पूर्ति होती थी। उदाहरणार्थ, आयोग का सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार का संरक्षण प्रदान किया जाय और उसे स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया जाय। सरकार ने केवल द्वितीय सुझाव को ही स्वीकार किया क्योंकि उसने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं को सौंप कर उससे अपना बोझा छुड़ाया। इस प्रकार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले धन की कटौत करके, उसे अपनी राजसत्ता को दृढ़ करने में व्यय किया। आयोग द्वारा 'सहायता-धनुवान' सम्बन्धी जो सुझाव दिये गये, उनको सरकार ने स्वीकार करके माध्यमिक विद्यालयों के लिये कार्यान्वित किया। ऐसा करते समय सरकार ने अपने राजनैतिक हित का ध्यान रखा। उसे अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करके ही उपलब्ध किया जा सकता था। परन्तु इसका एक परिणाम और निकला। गैर-सरकारी स्कूलों को आर्थिक सहायता मिलने से भारतीयों द्वारा व्यक्तिगत विद्यालयों का निर्माण किया गया और माध्यमिक शिक्षा तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी। सरकार द्वारा अपने राजनैतिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिये माध्यमिक शिक्षा का जो प्रसार किया गया, उसका प्रभाव उच्च शिक्षा पर भी पड़ा। उसका भी निरन्तर विस्तार होता गया। परन्तु अंग्रेजों ने माध्यमिक शिक्षा के समान उसको भी पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का आधार रखा। अंग्रेज तो केवल अपने राज्य-संचालन में उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयों को चाहते थे। उन्हें इस बात से क्या प्रयोजन था कि शिक्षा का रूप ऐसा हो, जिससे वह व्यक्तियों को समाज का लाभप्रद सदस्य बना सके।

इस समय तक अंग्रेजी सरकार को यह पूर्णतया विदित हो गया था कि भारत पर अपना शासन स्थापित रखने के लिये, उन्हें मुसलमानों से अधिक

## अध्याय ६

# शिक्षा पर राजनैतिक संघात

शिक्षा तथा समाज दोनों अविच्छिन्न रूप से परस्पर गुंथे समाज में ही फलती-फूलती है और समाज भी शिक्षा की छाया अधिक प्राणवान, सजग तथा सुसंस्कृत बनाता है। एक की प्रगति प्रगति निर्भर है और एक की भवति बहुत धंशों तक दूरी कारण बन जाती है।

शिक्षा का रूप समाज के रूप का परिवर्तन कर सकता है। व्यवस्था को रूपान्तरित करके एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था राजनीति का निर्माण कर सकती है, जो वर्तमान से पूर्णतः भिन्न हो। यदि सम्पूर्ण राज्य किसी विविष्ट सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे तो उसे शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा द्वारा रूपान्तरित समाज में स्थिरता होती है। यही कारण है कि सत्ताधारी राज्य नैतिक शक्ति का प्रयोग करके शिक्षा के रूप को परिवर्तित करते हैं। राज्यों और घनेको राजनीतिक परिवर्तनों के समय ऐसा किया गया है। सम्पूर्ण में इतिहास से कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं।

मध्य-युग में पोप के देशों में शिक्षा की व्यवस्था खर्च द्वारा थी। खर्च ही शिक्षकों की नियुक्ति करना था, विद्यालयों का भूय करना था, और शिक्षा के उद्देश्यों तथा धारणों को निश्चित करना पोप ने पुनः वास्तव के कारण नवयुग का मूलभूत हुवा, तो शिक्षा

में अपनी राजनैतिक नीति के अन्तर्गत अंगरेजों ने कान्ति के उपरान्त जिस दमन-चक्र का सहारा लिया, उसने भारतीयों के देश-प्रेम तथा राष्ट्रीय चेतना को बलवती बनाया और फलस्वरूप शिक्षा का भारतीयकरण हुआ।

१८८२ से १९०५ तक

इस काल की प्रमुख घटना राष्ट्रीयता की भावना का प्रबल प्रवाह था। भारतीय अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति सजग होने लगे। वे शिक्षा के साधनों को समझ कर विदेशी सरकार से उसकी माँग करने लगे। राजनीति में पटु अंग्रेजों ने उनको भुलावा देने के लिये 'भारतीय शिक्षा-आयोग' (Indian Education Commission) की नियुक्ति की, जिसने शिक्षा के सभी स्तरों को उन्नत करने के लिये विवेकपूर्ण सुझाव दिये। उनमें से भारत-सरकार ने उन्हीं को स्वीकृति प्रदान की जिससे उनके राजनैतिक हित की पूर्ति होती थी। उदाहरणार्थ, आयोग का सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार का संरक्षण प्रदान किया जाय और उसे स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया जाय। सरकार ने केवल द्वितीय सुझाव को ही स्वीकार किया क्योंकि उसने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं को सौंप कर उसके अपना बोझ छुड़ाया। इस प्रकार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले धन की कटौत करके, उसे अपनी राजसत्ता को हड़ करने में व्यय किया। आयोग द्वारा 'सहायता-अनुदान' सम्बन्धी जो सुझाव दिये गये, उनको सरकार ने स्वीकार करके माध्यमिक विद्यालयों के लिये कार्यान्वित किया। ऐसा करते समय सरकार ने अपने राजनैतिक हित का ध्यान रखा। उसे अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करके ही उपलब्ध किया जा सकता था। परन्तु इसका एक परिणाम और निकला। गैर-सरकारी स्कूलों को धार्मिक सहायता मिलने से भारतीयों द्वारा व्यक्तिगत विद्यालयों का निर्माण किया गया और माध्यमिक शिक्षा तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी। सरकार द्वारा अपने राजनैतिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिये माध्यमिक शिक्षा का जो प्रसार किया गया, उसका प्रभाव उच्च शिक्षा पर भी पड़ा। उसका भी निरन्तर विस्तार होता गया। परन्तु अंग्रेजों ने माध्यमिक शिक्षा के समान उसको भी पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का आधार रखा। अंग्रेजों को केवल अपने राज्य-संचालन में उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयों की चाहते थे। उन्हें इस बात से क्या प्रयोजन था कि शिक्षा का रूप ऐसा हो, जिससे वह व्यक्तियों को समाज का लाभप्रद सदस्य बना सके।

इस समय तक अंग्रेजी सरकार को यह पूर्णतया विदित हो गया था कि भारत पर अपना शासन स्थापित रखने के लिये, उन्हें मुसलमानों से अधिक

प्रति रचमात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा प्राप्त करके उच्च  
नेको व्यक्ति ब्रिटिश राज्य के स्तम्भ के रूप में अपने देशवासियों के  
तान्दोलन के प्रबल विरोधी हो गये।

सन् १८३५ के प्रस्ताव द्वारा सरकारी निर्णय प्रकाशित किया गया :  
सरकार का महान् उद्देश्य भारतवासियों में यूरोपीय साहित्य और  
का प्रसार करना होना चाहिये और शिक्षा के लिये जो निधि है, उनका  
उपयोग अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में ही होगा।" इस प्रकार अपनी  
तक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये कम्पनी के शासकों ने अंग्रेजी  
स्थापन देकर देशी शिक्षा का गला घोटने में कोई कसर न उठा रखी।  
उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये १८४४ में लार्ड हार्डिज (Hardinge) ने  
जाही कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राप्-  
ता दी जायगी। इसका प्रत्यक्ष फल यह हुआ कि अंग्रेजी की दिन दूनी,  
धौमुनी उभरती होने लगी और शिक्षा का चरम लक्ष्य नौकरी करना  
जाने लगा। अंग्रेजों का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करने के लिये अंग्रेजी  
शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। इसने भी प्राच्य शिक्षा के हाव में  
न दिया। अंग्रेजों का राजनैतिक हित इसी बात में था कि भारतीय अपनी  
प्राचीन शिक्षा से अनभिज्ञ रहकर अपनी संस्कृति को विस्मृत कर दें और अंग्रेजी  
माध्यम करके पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति के उपासक बन जायें।

१८५३ से १८८२ तक

१८५७ की क्रान्ति ने अंग्रेज शासकों की आँखें खोल दीं और वे इस  
निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत में अपनी राजनैतिक सत्ता बनाये रखने के लिये  
मिशनरियों के धर्म-प्रचार के कार्य पर संकुच लगाना आवश्यक है। उन्होंने  
किया भी ऐसा ही। परिणाम यह हुआ कि भारतीयों को व्यक्तिगत रूप से  
शिक्षा-प्रसार का कार्य करने के लिये विस्तृत क्षेत्र मिल गया। क्रान्ति के उप-  
रान्त अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर जो प्रत्याचार किये गये, उन्होंने यहाँ के  
निवासियों के हृदयों में विदेशी शासकों के प्रति घृणा की भावनाएँ भर दीं। देश-  
प्रेम की भावना जो पहिले ही आबिर्भूत हो चुकी थी, अब एक प्रबल सहर के  
रूप में सम्पूर्ण देश में फैल गई। राष्ट्रीय चेतना का निश्चय रूप से विकास  
होने लगा। फलस्वरूप समस्त देश में सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक  
क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के लिये भारतीय कटिबद्ध हो गये। इस  
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वे शिक्षा-प्रसार के कार्य में जुट गये। सरास

में धरती राजनैतिक नीति के घन्तरगत घंघरेजों ने क्रांति के उपरान्त जिस दमन चक्र का सहारा लिया, उसने भारतीयों के देश-प्रेम तथा राष्ट्रीय चेतना को बलवती बनाया और फलस्वरूप विद्या का भारतीयकरण हुआ ।

१८८२ से १९०५ तक

इस काल की प्रमुख घटना राष्ट्रीयता की भावना का प्रबल प्रवाह था । भारतीय अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति सजग होने लगे । वे विद्या के सारों को समझ कर विदेशी सरकार से उसकी माँग करने लगे । राजनीति में पटु घंघरेजों ने उनको मुलाका देने के लिये 'भारतीय शिक्षा-आयोग' ( Indian Education Commission ) की नियुक्ति की, जिसने विद्या के सभी स्तरों को उन्नत करने के लिये विवेकपूर्ण सुझाव दिये । उनमें से भारत-सरकार ने उन्हीं को स्वीकृति प्रदान की जिनसे उनके राजनैतिक हित की पूर्ति होती थी । उदाहरणार्थ, आयोग का सुझाव था कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार का संरक्षण प्रदान किया जाय और उसे स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया जाय । सरकार ने केवल द्वितीय सुझाव को ही स्वीकार किया क्योंकि उसने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाओं को सौंप कर उससे अपना बोझा छुड़ाया । इस प्रकार सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किये जाने वाले धन की बचत करके, उसे अपनी राजसत्ता को दृढ़ करने में व्यय किया । आयोग द्वारा 'सहायता-अनुदान' सम्बन्धी जो सुझाव दिये गये, उनको सरकार ने स्वीकार करके माध्यमिक विद्यालयों के लिये वार्षिक व्यय किया । ऐसा करते समय सरकार ने अपने राजनैतिक हित का ध्यान रखा । उसे घंघरेजी शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करके ही उपलब्ध किया जा सकता था । परन्तु इसका एक परिणाम और निकला । गैर-सरकारी स्कूलों को आर्थिक सहायता मिलने से भारतीयों द्वारा व्यक्तिगत विद्यालयों का निर्माण किया गया और माध्यमिक शिक्षा तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी । सरकार द्वारा अपने राजनैतिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिये माध्यमिक शिक्षा का जो प्रसार किया गया, उसका प्रभाव उच्च शिक्षा पर भी पड़ा । उसका भी निरन्तर विस्तार होता गया । परन्तु अंग्रेजों ने माध्यमिक शिक्षा के समान उसको भी पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का आधार रखा । अंग्रेज तो केवल अपने राज्य-संचालन में उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयों को चाहते थे । उन्हें इस बात से क्या प्रयोजन था कि शिक्षा का रूप ऐसा हो, जिससे वह व्यक्तियों को समाज का लाभप्रद सदस्य बना सके ।

इस समय तक अंग्रेजी सरकार को यह पूर्णतया विदित हो गया था कि भारत पर अपना शासन स्थापित रखने के लिये, उन्हें मुसलमानों से अधिक



सहयोग प्राप्त हो सकता है। धन: उन्होंने 'फूट बानो घोर राज करो' (Divide and rule) राजनीति का प्रतिपादन किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने मुसलमानों को शिक्षा की अपेक्षा उत्तम मुविषाये दी जिससे कि शिक्षित मुसलमान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हड़ स्तम्भ बन सकें। हिन्दुओं को धनहीन राजनैतिक मुक्ति से धनमित्र बनाने के लिये अंग्रेज शासकों ने घोषित किया कि मुसलमानों की शिक्षा को इसलिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि यह परवन्त विद्रोही हुई दत्ता में है। भारत के विदेशी शासकों की दृष्टि पूर्ण हुई। उन्होंने मुसलमानों की शिक्षा करके घोर इस प्रकार राजनीय पदों के लिये उन्हें हिन्दुओं का प्रतिद्वन्द्वी बनाकर अपने राजनैतिक उद्देश्य को प्राप्त की। शिक्षित मुसलमानों ने धनत समय तक विदेशी सरकार को हार्दिक सहयोग प्रदान किया घोर धनत में भारत को दो राष्ट्रों में विभक्त करवा दिया।

फूटनीति का अंग्रेज यह बात मली-माली जानते थे कि हरिजनों के प्रति सर्वान हिन्दू घृणास्पद व्यवहार करते हैं। धन: उनका यह विचार उचित हो या कि हरिजनों को शिक्षा की मुविषाये प्रदान करके उन्हें भी मुसलमानों के समान ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाया जा सकता है। इसी सद्य को अपने समक्ष रखकर अंग्रेजों ने हरिजनों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की। परन्तु यहाँ उनकी राजनैतिक चाल को सफलता नहीं प्राप्त हुई। महारत्ना गाँधी के प्रयासों के कारण हरिजन हिन्दू समाज से पृथक् न हो सके।

१८६६ में लार्ड कर्जन (Curzon) वाइसरॉय होकर भारत आया। वह एक पुरांचर विद्वान घोर कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने शिक्षा सम्बन्धी जिस राजनीति को अपनाया उससे भारतीय शिक्षा का परम कल्याण हुआ। उसने 'भारतीय विश्वविद्यालय आयोग' (Indian Universities Commission) को नियुक्ति करके उच्च शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाया, माध्यमिक विद्यालयों में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित किया, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करके जन-साधारण को शिक्षित करना सरकार का स्पष्ट कर्तव्य बताया तथा देश की आवश्यकताओं को समझ कर कृषि, कला घोर जियो की शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया। शिक्षा-सुधार के जिस आन्दोलन का उसने सूत्रपात किया, उसकी गति में आज तीव्रता दृष्टिगोचर हो रही है। उसी की प्रेरणा के फलस्वरूप स्वतन्त्र भारत की शिक्षा में मातृभाषाओं के साथ-साथ वाइचारण विज्ञानों को समाविष्ट करके शिक्षा को संतुष्टि करने की अनेकानेक चेष्टाओं की जा रही है।

१९०५ से १९२१ तक

१८८५ में 'भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस' की स्थापना हो चुकी थी। इस

प्रयासों के फलस्वरूप "भारत के राजनीतिक वातावरण में १८६६ में १९०४ तक निरुद्ध शान्ति रही। यह शान्ति घाने वाले भ्रमभावत की चोटक थी। सन् १९०५ के अन्तिम महीनों में यह भ्रमभावत फूट पड़ा और इसका प्रकोप सर्वत्र विशेष कर बंगाल में चार वर्ष तक रहा।"<sup>१</sup> इसका ब्रिटिश राजनीति पर गम्भीर प्रभाव पड़ा। शिक्षा भी उससे बर्धित न रही।

१९०५ में बंगाल का विभाजन किया गया। यह सुनकर सम्पूर्ण बंगाल एका साथ उठ खड़ा हुआ और कांग्रेस ने राष्ट्रीय आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया। इस आन्दोलन के चार मुख्य अंग थे—स्वराज्य की प्राप्ति, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं की माँग और राष्ट्रीय शिक्षा की माँग। यहाँ हमें केवल यह देखना है कि कांग्रेस के इस राजनीतिक आन्दोलन और उसके विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई प्रतिक्रियावादी राजनीति का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा।

कांग्रेस ने जो आन्दोलन प्रारम्भ किया वह बंगाल के स्कूलों और कनिजों के विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रिय हो गया। राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-ओत उन्होंने विभाजन-विरोधी सभाओं का आयोजन किया। इस पर सरकार का दमन शक्त बला। "ब्रिजा मेजिस्ट्रेटों ने शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्षों को यह आदेश दिया कि यदि किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने आन्दोलन में भाग लिया तो उस स्कूल को सरकारी सहायता नहीं दी जायगी; उसके विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति के लिये प्रतिद्वन्द्विता करने का अधिकार नहीं होगा और विश्वविद्यालय द्वारा उनको छात्रोत्तीकार नहीं किया जायगा।"<sup>२</sup> जब इस आदेश पर भी विद्यार्थी राजनीति से पृथक् नहीं हुए, तब उनको विद्यालयों से निकाल दिये जाने की धमकी दी गई। छात्रों ने इसका उत्तर स्वयं ही विद्यालयों का बहिष्कार करके दिया। इन नवयुवकों की शिक्षा का प्रबन्ध करना राष्ट्रीय कर्तव्य समझ गया। अतः बंगाल में गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय शिक्षा-समिति' (Society for the promotion of National Education in Bengal) का संगठन किया गया। इस समिति ने राष्ट्रीय हाई स्कूलों और कलकत्ता के 'नेशनल कॉलेज' की स्थापना की, राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन टंगोर के 'ब्रह्मचर्य आश्रम' (अब विश्वभारती) और 'गुरुकुल' के रूप में भी दृष्टिगोचर हुआ।

१९२० में कांग्रेस के नागपुर के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने जनता से विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय स्कूलों और कालेजों की स्थापित करने की अपील

१. गुरुमुख निहान्तसिंह : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास, पृष्ठ १७२

२. Nevinson : *The New Spirit in India*, p. 185.

की।<sup>१</sup> फलस्वरूप असीमद्वय विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने विश्वविद्यालय के राष्ट्रीयकरण की माँग की। त्रिन विचारियों ने इस आन्दोलन में भाग लेकर विश्वविद्यालय का बहिष्कार किया था, उनही शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये मोलाना मुहम्मद जहाँ ने असीमद्वय में 'जामिया मिलिया इस्लामिया' (जो अब दिल्ली में है) नामक विश्वविद्यालय स्थापित किया। इस कान में घोर जो राष्ट्रीय शिक्षालय स्थापित हुए, यथा—बिहार शिक्षापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ आदि।

राष्ट्रीय आन्दोलन ने अंग्रेजों की आँखें खोल दीं। उन्हें विश्वास हो गया कि सरकारी शिक्षा-प्रणाली घोर उमके उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक है। फलस्वरूप १९१३ में 'शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव' (Government Resolution on Educational Policy) प्रकाशित किया गया जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की उन्नति तथा विस्तार की योजनाएँ प्रस्तुत की गईं। १९१७ में 'कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' (Calcutta University Commission) की नियुक्ति की गई, जिसके परामर्श के फलस्वरूप १९१६ से १९२१ तक ७ नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलन से प्रभावित होकर प्राथमिक शिक्षा को अग्रिम बनाने की दिशा में पग उठाया गया। सर्व प्रथम १९०६ में बड़ोदा-नरेश ने एक अधिनियम बनाकर अपने राज्य के सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया।<sup>२</sup> इस उदाहरण से प्रेरित होकर मोखले ने १९११ में समस्त देश के लिये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये केन्द्रीय धारा-सभा में अपना विधेयक प्रस्तुत किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। मोखले की इस असफलता में सफलता निहित थी क्योंकि १९२० तक 'प्राथमिक शिक्षा अधिनियम' पारित करके पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बंगाल, बिहार व उड़ीसा, बम्बई, मध्यप्रान्त एवं मद्रास में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया।

१९२१ से १९३७ तक

१९१९ के 'भारत-सरकार अधिनियम' (Government of India Act) के अनुसार १९२१ में भारत में द्वैध शासन-प्रणाली (Dyarchy) की स्थापना

1. Dr. Pattabhi Sitaramayya : *History of the National Congress*, Vol. I, p. 203.
2. *The Gazetteer of the Baroda State*, p. 312.

की गई और शिक्षा को लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया। परन्तु यहाँ भी कूटनीति परायण अंग्रेज अपनी राजनैतिक नीति को काम में लाये। उन्होंने विस्तारित विभाग पर अंग्रेज मंत्रियों का अधिकार रखा। परिणाम यह हुआ कि भारतीय मंत्रियों को शिक्षा का प्रसार करने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कुछ प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिनियम पारित किये, औद्योगिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया, वयस्क शिक्षा की दिशा में रचनात्मक कदम उठाये एवं शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य भी किये।

देश में जिस राजनैतिक जागृति का प्रादुर्भाव हो चुका था उससे भारतीय यद्वा भली-भाँति समझ गये थे कि ब्रिटिश सरकार उनके देश में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार केवल इसलिये नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उससे इंग्लैण्ड के उद्योगों को क्षति पहुँचती। अतः भारतीयों ने सरकार की नीति के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया। कलतः १९२१ से १९३७ तक व्यावसायिक शिक्षा का प्रभाव निर्वाध रहा। कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा, वन-विज्ञान, कला, कृषि और वाणिज्य की शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार किया गया। बारांश में, इस काल में व्यावसायिक शिक्षा का प्रत्येक अवयव संशोधित तथा परिष्कृत होकर सुसंगठित बना।

१९३७ से १९४७ तक

१९३५ का 'भारत-मन्त्रालय अधिनियम' (Government of India Act) १९३७ ने कार्यान्वित किया गया जिससे प्रान्तीय प्रशासन के सम्पूर्ण क्षेत्र में उत्तरदायी शासन को स्थापना हुई। राजनैतिक सत्ता में इस परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा का भाग्य उदय हुआ। जिन ६ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का निर्माण हुआ, वहाँ की जनता को इस बात का पूर्ण आश्वासन हो गया कि शिक्षा के पुनर्गठन का कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न किया जायगा। परन्तु भारत के दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ होने पर अंग्रेजों की नीति से मतभेद होने के कारण कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने अपने पद त्याग दिये। अतः जनता की आशा पर असमय ही तुपारपात हो गया। १९४६ में भारत का सीमागम्य सूर्य फिर उदय हुआ और ८ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों का निर्माण हुआ। उसी वर्ष बनने वाली 'अस्थायी सरकार' (Interim Government) में जवाहरलाल नेहरू वाइसराय की कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। अतः केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-विभाग पर भारतीयों का अधिकार स्थापित हो गया।

उपरोक्त काल में तत्कालीन राजनैतिक स्थिति के कारण प्रशासन-कार्य में

भारतीयों का अधिकार अधिक हो गया। फलतः शिक्षा में नव-  
दृष्टि। नेहरू की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा की  
देना प्रारम्भ किया। केन्द्रीय शिक्षा-नीतियों में सामंजस्य स्था-  
केन्द्रीय सरकार को शिक्षा-मन्त्रियों विषयों पर परामर्श देने  
शिक्षा सलाहकार बोर्ड' (Central Advisory Board of E-  
पुनर्जीवित किया गया। केन्द्रीय सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त कर  
भक्तों का विकास हुआ। अल्पों, हरिजनों तथा प्रौढ़ों की शिक्षा  
रूप से ध्यान दिया गया।

राजनैतिक जागरण के इस काल में राष्ट्र-प्रेमी नेताओं  
शिक्षा के विकास की पुरातन विधियों में कोई आकर्षण नहीं  
अपनी नवीन योजनाओं का परीक्षण करने के लिये उत्कृष्ट  
योजनायें थीं :—विद्यामन्दिर योजना, वालंटरी स्कूलों की योजना  
शिक्षा की योजना। प्रथम योजना को प्रतिपादित करने का  
तत्कालीन शिक्षा-मंत्री पं० रविशंकर शुक्ल थे। द्वितीय योजना  
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने क्रियान्वित किया था। परन्तु इन दोनों  
अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। तीसरी योजना का प्रतिपाद  
द्वारा किया गया था। इस योजना को भारत के लिये इतना  
गया है कि स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा  
जा रहा है।

### एक समीक्षा

हमने गत पृष्ठों में ब्रिटिश शासन-काल में शिक्षा पर राज  
सजीव चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस संघर्ष  
भारतीय शिक्षा और उसकी प्रणाली में समय-समय परिवर्तन  
वर्तनों के फलस्वरूप कतिपय प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। पहिला  
कि भारत ने अपनी प्राचीन शिक्षा और उसकी प्रणाली का  
अंग्रेजी शिक्षा और उसकी पद्धति को अपनाया। कतिपय भार-  
को भूरि-भूरि प्रशंसा की है। वे निस्संकोच रूप से स्वीकार क-  
शिक्षा ने भारत में युग-परिवर्तन का कार्य किया। यदि भारत  
शिक्षा-व्यवस्था से निपटा रहता, तो सम्भवतः इस देश में नव-  
न प्रारम्भ हुआ होता और भारतीय सदैव पदाग्रस्त रहते।

दूसरा प्रभाव यह हुआ कि भारतीय अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा  
ले। परिणाम यह हुआ कि उनको अपने साहित्य तथा भाषा

ज्ञान न प्राप्त हो सका। साथ ही भारतीय भाषाओं तथा भारतीय मस्तिष्क का विकास भवरुद्ध हो गया।

तीसरा प्रभाव यह हुआ कि शिक्षा में धर्म को कोई स्थान नहीं दिया गया जिससे शिक्षा पूर्णतया लौकिक हो गई। धार्मिक शिक्षा के प्रभाव में छात्रों का नैतिक पतन प्रारम्भ हो गया और उनमें अनुशासनहीनता तथा भक्तिहीनता का समावेश हो गया।

चौथा प्रभाव यह हुआ कि जनसाधारण शिक्षा से वंचित रह गई, क्योंकि बंबेजों के निस्पन्दन सिद्धान्त से केवल उच्च वर्गों को ही लाभ हुआ।

अन्तिम प्रभाव यह हुआ कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की भाँति की गई। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, और प्राथमिक शिक्षा की नवीन योजनाओं का परीक्षण किया गया। इन योजनाओं में वैज्ञानिक शिक्षा योजना अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हुई और स्वतन्त्र भारत ने जनसाधारण के हितार्थ उसे प्राथमिक शिक्षा का रूप दिया।

उपरोक्त के आधार पर हम निःसंकोच रूप से कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में राजनैतिक कारणों से शिक्षा में जो परिवर्तन हुए उनके प्रभाव भारत के लिये हितकर भी हुए और अहितकर भी।

### स्वतन्त्र भारत में राजनैतिक परिवर्तन

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक शताब्दी के अविश्रांत संघर्ष के पश्चात् भारत नवीन विचारों एवं धारणों को आत्मसात् करके स्वतन्त्र संसार के भँव पर भवतीर्थ हुआ। १५ अगस्त १९४७ को उसने नवीन युग के प्रांगण में प्रवेश किया। उस समय से लेकर आज तक "अपने अविष्य के बारे में उसके सामने जो प्रश्न है वह यह है : भारत को पिछले पाँच हजार वर्षों से पीढ़ी पर पीढ़ी जिस जीवन सत्त्व की परम्परागत बनीठी उपलब्ध होती आ रही है क्या वह उसे, निरन्तर जागरूक रहकर, अपने प्रयोजनार्थक प्रयास द्वारा उत्पत्ति के उत्तरोत्तर उच्चतर शिखरों पर पहुँचाता रहेगा?"<sup>१</sup> भारत के आत्म-विविदानी एवं निस्स्वार्थी नेता जिन्होंने खून से होनी खेलकर अपने देश को विदेशियों के चंगुल से मुक्त किया है, इन सम्बन्ध में आशापूर्ण हैं। भावी भारत के उज्ज्वल चित्र को अपने मानस-चटल पर अंकित किये हुए एक के बाद एक राजनैतिक परिवर्तनों को उपस्थित करके वे भारत को उस दिशा में प्रसर कर रहे हैं। इन राजनैतिक परिवर्तनों को उपस्थित करने के लिये उन्होंने सर्व प्रथम एक नवीन संविधान का सहारा लिया। २६ जनवरी, १९५० को स्वतन्त्र भारत

संविधान कार्यान्वित किया गया, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करने से हमें हो जाता है कि अंग्रेजों के प्रस्थान के उपरान्त देश में किस प्रकार परिवर्तन उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। संविधान में घोषित गया है :

- भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त होगा।
- नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतन्त्रता होगी।
- नागरिकों में प्रतिष्ठा तथा भवसर की समता प्राप्त होगी।
- नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता की वृद्धि की जायगी।

इसके प्रतिरिक्त भारतीय संविधान में नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकारों (Fundamental Rights) का प्रतिपादन किया गया है। इन अधिकारों को एक शानदार सूची दी गई। "इस सूची में वर्णित अधिकारों के अनुसार सब लोग कानून की दृष्टि में एक समान समझे जायेंगे और सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में सब नागरिकों को एक-सा मौका दिया जायगा। भ्रष्टाचार का घंड कर दिया गया है और राज्य द्वारा उपाधि वितरण की प्रथा का भी अन्त कर दिया है। राज्य को और से केवल सैनिक और विद्वता सम्बन्धी उपाधियों का वितरण होगा। संविधान सब नागरिकों को भाषण सम्बन्धी स्वतन्त्रता, सार्वजनिक सभा करने की स्वतन्त्रता, धावागमन तथा निवास सम्बन्धी स्वतन्त्रता सम्पत्ति प्राप्त करने रखने तथा बेचने की स्वतन्त्रता, तथा मनचाहा व्यवसाय या पेशा करने का अधिकार देता है। संविधान ने बेगार और दास-प्रथा को एकदम बन्द कर दिया है। १४ वर्ष से कम अवस्था वाले बालक कारखानों, शानों घसना भाषा, निवि और संरक्षित की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। अन्य में यह कहा गया है कि इन अधिकारों के उपयोग के लिए नागरिकों को धार्मिक तथा विचार सम्बन्धी स्वतन्त्रता देता है। अल्पसंख्यक जातियों को उच्चतम न्यायालय की महायुक्त और सरलता मौल सकते हैं।"

१९४७ के राजनैतिक परिवर्तन और उसके अनन्तर १९५० में जारी-विद्यमान विवेक यद्यपि इन संविधान की व्याख्या हमने ऊपर की है, उसने स्पष्ट हो जाता है कि कानूनी परिचरिता द्वारा हमारे समाज को एक नवीन बन-रेखा देने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, 'समाजवादी धार्मिक क समाज' को स्था-

पना की ओर सक्रिय पग उठाया जा रहा है। जिस प्रकार के समाज की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिये धर्मियों द्वारा दी गई शिक्षा-व्यवस्था सर्वथा अनुपयुक्त रहेगी। कारण यह है कि कई दशान्धियों से "हमारी शिक्षा-मदति राष्ट्रीय सस्कृति की विस्तृत नींव पर आधारित नहीं रही है और वह अपनी प्रतीत की उपलब्धियों या वर्तमान के महत्त्वपूर्ण कामों या अपने भविष्य की आशाओं से प्रेरणा प्राप्त नहीं करती है।"<sup>१</sup> अतः 'समाजवादी आदर्श के समाज' की स्थापना के लिये जिसमें उन्मुक्त आदान-प्रदान की सुगमता हो और आर्थिक तथा सामाजिक पद पर आधारित पूर्वाग्रहों के लिये कोई स्थान न हो, तो शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया। इसीलिये हमारी शिक्षा-व्यवस्था में शूनः शूनः परन्तु निरन्तर परिवर्तन किया रहा है और यह कहना पुनश्चित न होगी कि यह परिवर्तन राजनैतिक संघात के कारण हो रहा है। हम निम्नांकित पंक्तियों में इस राजनैतिक संघात के फलस्वरूप शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

## स्वतन्त्र भारत में शिक्षा पर राजनैतिक संघात

राजनैतिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज में जो महान् क्रांति परितक्षित हो रही है, उसको सफल तथा पूर्ण बनाने के लिये वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। ६० से अधिक वर्षों के एक लम्बे राजनैतिक संघर्ष के उपरान्त हमें जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, उसने हमारे समक्ष महान् उत्तरदायित्व उपस्थित किये हैं। उनका भार सभालने के लिये हम नैतिक तथा बौद्धिक रूप से तैयार नहीं हैं। "हमने अपनी राजनैतिक सरणियों के जरिये बहुत कुछ राजनैतिक शिक्षा प्राप्त की, परन्तु वह बुनियादी तौर पर रणकौशल की शिक्षा थी—हालांकि यह रणकौशल मुख्यतः अहिंसात्मक लड़ाई का कौशल था। परन्तु सत्ता जनता के हाथ में आ जाने से और जो कुछ बुरा तथा प्रतिक्रियावादी तथा सामाजिक दृष्टि से अनुचित था उसकी केवल आलोचना करने के बजाय अन्धो तथा सामाजिक दृष्टि से बाधनीय चीजों का निर्माण करने की जो चुनौती हमें दी गई है, उसके कारण हमारे सामने नई आवश्यकताएँ तथा नई समस्याएँ उपस्थित हो गईं।

1. "Our present system of education is not based on the broad foundations of national culture and does not derive its inspiration from the achievements of its past or the pre-occupations of its present or the hopes of its future."  
—K. G. Saiyidain : *Problems of Educational Reconstruction*. p. 13.



हैं और हमारे लिए अपने अन्दर नये गुण तथा नई प्रकृतियाँ पैदा करना आवश्यक हो गया है। यदि इस महान् तथा प्राचीन देश को जो अभी हाल में एक स्वतन्त्र राज्य बना है, जीवित रहना है—और क्रूर काल किसी को सुख-सुविधा की प्रतीक्षा नहीं करता !—तो उचित बौद्धिक तथा आबनात्मक वातावरण पैदा करने के लिये और उचित सामाजिक तथा नैतिक रवैये पैदा करने के लिए हमें बहुत साहसपूर्ण, द्रुतगामी तथा आसूल परिवर्तन करने वाली नीतियाँ अपनानी होंगी। जन-साधारण के विचारों को नए सचि में ढालने के लिए शिक्षा निस्सन्देह एक शक्तिशाली उद्देश्य पूर्ण साधन है।<sup>१</sup> इसीलिये राज-नैतिक परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिये भारतीय शिक्षा को एक नए सचि में ढाला जा रहा है जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में निम्नांकित परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। :

## १. जन-साधारण की शिक्षा

भारत में 'धर्म निरपेक्ष कल्याणकारी लोकतन्त्र' की स्थापना की गई है। उसे तब तक सुरक्षित एवं शक्तिशाली बनाना सम्भव नहीं है, जब तक कि उसकी आधार-शिक्षा सुरक्षित एवं शक्तिशाली न हो। वह आधार-शिक्षा है इस देश की वह समस्त जनता जिसके ऊपर राज्य-सरकारों का विवेक-पूर्ण निर्वाचन निर्भर है तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के मंगलमय स्वरूप का निर्धारण शक्तम्बित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है, उस दिशा की ओर अग्रसर करने वाली जन-जन की उपयुक्त शिक्षा। इसीलिए भारत के संविधान की ४५ वीं धारा में स्पष्ट रूप से १० वर्ष के अन्दर १४ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने की घोषणा की गई है। जनसंख्या की विचालता और कुछ इलाकों के छाव तौर पर पिछड़ा के होने के कारण अभी तक इस कार्य में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है। प्राथमिक शिक्षा को वैश्विक शिक्षा का रूप प्रदान किया जा रहा है, जिससे बालक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर सके और अध्ययन की समाप्ति के उपरान्त उसमें बराबरी प्राप्त करके अपनी आजीविका की समस्या को हल करे तथा समाज में लाभ-प्रद सदस्य बन सके।

## २. पाठ्य-क्रम का विभिन्नोकरण

प्राथमिक विधानों के लिये विभिन्न पाठ्य-क्रम (Diversified Courses) का प्रावधान किया गया है, जिससे विभिन्न अभिरुचियाँ तथा अभियोग्यताओं वाले छात्र अपने मनोनुहून विषयों का अध्ययन करके अपने भविष्य के

सर्वांगीण विकास कर सकें और विद्याध्ययन के उपरान्त समाज की विभिन्न भागों की पूर्ति कर सकें तथा विश्वविद्यालयों की निरुद्देश्य भौड़ कम हो सके।

### ३. बहुउद्देशीय विद्यालय

हमारे माध्यमिक विद्यालय अभी तक एक-भागीय थे और वे विभिन्न अभिरूचियों, प्रवृत्तियों तथा भौतिक क्षमताओं वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते थे। फलतः उनके व्यक्तित्व का विकास अवलब्ध हो जाता था। स्वतंत्र भारत में इन शिक्षाशास्त्रात्मों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिणत किया जा रहा है। उनमें विभिन्न पाठ्यक्रम और शिल्पों का शिक्षण किया जा रहा है। इससे लाभ यह होगा कि छात्रों को अपनी अभिरूचियों के अनुसार विषयों को चयन करने का अवसर प्राप्त होगा, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा और वे किसी शिल्प में दक्षता प्राप्त करके किसी उद्योग में लग सकेंगे।

### ४. पाठ्य-वाह्य एवं पाठ्य-क्रम सहगामी क्रियायें<sup>१</sup>

पाठ्य-वाह्य एवं पाठ्य-क्रम सहगामी क्रियायें छात्रों की शारीरिक एवं मानसिक उन्नति में योग देती हैं, उनकी अभियोग्यताओं का विकास करती हैं और उनमें सफल सामुदायिक जीवन के लिये आवश्यक सामाजिक गुणों का समावेश करती हैं। यही कारण है कि भारतीय विद्यालयों में इन क्रियाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है।

### ५. शिक्षा का राष्ट्रीयकरण

एच० जी० वेल्स (H. G. Wells) ने किसी प्रसंग में कहा था : "यदि भाव इस बात का अनुभव करना चाहते हैं कि पीढ़ियों के बाद पीढ़ियाँ किस प्रकार पहाड़ी नदियों के समान — जी हाँ, पहाड़ी नदियों के समान विनाश की ओर बढ़ती जा रही हैं, तो किसी प्राइवेट स्कूल को ध्यान से देखिये।"<sup>२</sup> हमारे देश के अधिकांश प्राइवेट स्कूलों के विषय में यह बात सत्य उतरती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन स्कूलों के पास धन का अभाव है। अतः वे छात्रों के लिए उचित शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं। फलस्वरूप छात्रों की वैयक्तिक क्षमताओं के विकास में बाधा पड़ती है, उनके विशिष्ट गुणों तथा

1. Extra-curricular and Co-curricular activities.

2. "If you want to feel the generations rushing to waste like rapids—like rapids—you should put your heart and mind into a private school."—H. G. Wells. Quoted by K. G. Salyidain : *Problems of Educational Reconstruction*, p. 1.

उनकी निहित योग्यताओं की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है और उनकी सामाजिक प्रतिभायें पोषक तत्वों के अभाव के कारण मुरझा जाती हैं। ऐसे क्षम देश के नागरिक के रूप में न तो राष्ट्र की प्रगति में योग दे सकते हैं और न अपने उत्तरदायित्व के भार को वहन कर सकते हैं। अतः सरकार शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की योजना बना रही है, जिससे विद्यालयों का उद्धार उत्तम भावी नागरिकों का निर्माण हो सके। कुछ राज्यों में यह योजना का न्वित भी हो रहा है।

#### ६. स्कूल : एक सक्रिय वातावरण के रूप में

हमारे विद्यालयों का दृष्टिकोण प्रति संकुचित है। उनमें पुस्तकीय ज्ञान को अत्यधिक बल दिया जाता है, प्रत्येक वस्तु को जिसे ज्ञान माना जाता है बहुत महत्त्व दिया जाता है और आत्म-प्रभिव्यक्ति, मौलिकता एवं स्वनामकता को बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि बालक को मान्यतायें आरम्भ से ही गलत दिशा में मुड़ जाती हैं। वस्तुतः विज्ञान बना है, इस बात को स्पष्ट करते हुए नान्टन (Nunn) ने लिखा है : "स्कूल की वस्तुना मुख्यतः जानोपाजन के एक ऐसे स्थान के रूप में नहीं की जानी चाहिये, जहाँ ज्ञान की कुछ बातें सिखाई जानी हैं अपितु उसकी वस्तुना एक ऐसे स्थान के रूप में की जानी चाहिये, जहाँ बच्चों को कुछ प्रकार की व्यापक जगत् में सबसे अधिक एवं सबन स्थानी महत्त्व रखा है।" इसी में एक सक्रिय वातावरण है। The School is an active environment। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के स्कूल की वस्तुना की गई है और विद्यार्थियों को प्रेरित होकर भारतीय शिक्षा-विद् इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि "The school must be thought of primarily not as a place for learning where certain knowledge is learnt but as a place where the young are disciplined in certain forms of behaviour—namely, those that are of the greatest and greatest significance in the wider world." Education is a social and moral discipline.

समय छात्रों के समस्त वास्तविक जीवन की स्थितियाँ एवं समस्याएँ उपस्थित होंगी। इनके विषय में उन्हें विचार करना पड़ेगा एवं इन्हें हल करने के लिये उन्हें विभिन्न प्रकार के ज्ञान तथा अपने माता-पिता, अध्यापकों, मित्रों आदि की आवश्यकता होगी। केवल इस बात के परिणामस्वरूप कि छात्र स्वयं कुछ गणित प्रश्नवाचक भूगोल प्रश्नवाचक भौतिकी का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुभव करेंगे, इस प्रकार के कार्य के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलेगा। वे आनन्द पूर्वक उस कार्य को तन-मन से करेंगे और 'अपने कार्य करने' (Self-activity) के पाठ को सीखेंगे। इस प्रकार वे उचित भावना के साथ अपना साहस पूर्ण जीवन प्रारम्भ करेंगे। भारत की परिवर्तित राजनैतिक दशाओं में ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है।

### ७. स्कूल : एक सृजनात्मक वातावरण के रूप में

स्कूलों के वर्तमान वातावरण को इस प्रकार से प्रायोजित नहीं किया गया है कि वह बच्चों की अभिरूचियों को समझ सके और उन्हें अपनी अभिरूचियों का उपयोग करने के लिये उचित माध्यम प्रदान कर सके। कारण यह है कि स्कूल आवश्यकता से अधिक औपचारिक तथा पुस्तकीय रहे हैं और भय भी हैं। उनके अन्तर्गत ज्ञानोपाजन के प्रतीक एवं साधनों के महत्व को पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जाता है और क्रियाशीलता एवं आत्मभिरूचि की शिक्षा में बच्चों की निरन्तर बढ़ती हुई आवश्यकताओं को और से मुँह मोड़ लिया जाता है। स्कूलों का दैनिक कार्यक्रम इतने कठोर बंधनों में घाबड़ा होता है कि बच्चों को उसके प्रति रूचिमान भी प्रकट नहीं होता है : "बच्चों की धारोक्ति क्रियाशीलता की, उनके सृजनात्मक तथा सामाजिक भावों की, उनकी कुछ करने की, किसी चीज का निर्माण करने की, अपने चारों ओर की चीजों को लेकर कोई नया प्रयोग करने की इच्छा का जो दमन किया जाता है, उसके विरुद्ध उनकी प्रत्येक सहज-प्रवृत्ति पुकार-पुकार कर दुहाई देती है।"

इस प्रकार की शिक्षा भारत के भावी नागरिकों की राजनैतिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सफल नहीं हो सकती है। अतः देश के शिक्षा-विशेषज्ञों के समक्ष यह समस्या उपस्थित हुई कि स्कूलों के कार्य का पुनर्गठन कुछ इस प्रकार से किया जाय कि उनके प्रति बच्चों का दृष्टिकोण

ry instinct in their being cries out against the repression of their physical activity, their creative and social their desire for doing, for construction, for with the environment."—K. R. Salyi-



धील वातावरण के लिये बच्चों को शिक्षा दे ।<sup>१</sup>” राजनैतिक परिवर्तन के कारण हमारे समाज, हमारे समुदाय के तकाजें भी बदल गये हैं, अतः यह अनुभव किया गया है कि देश के विद्यालयों और उनकी शिक्षा को उन तकाजों के अनुकूल बनाया जाय । स्कूलों को सामुदायिक जीवन से घृष्ट कर रख कर संदेह इस बात का भय रहेगा कि एक जड़ औपचारिकता उन पर छा जाय और वर्तमान वास्तविकताओं का स्थान भतीत की प्रेक्षात्माएँ ले लें । अतः सरकार ने घोषित किया है कि “हमारी समस्त शिक्षा-संस्थाएँ सामुदायिक कर्म-केन्द्र होयी ।<sup>२</sup>”

## ६. जनता कलिज

भारत ग्रामों का देश है । १९५१ की जनगणना के अनुसार इस देश की ८३ प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है । हमारे ग्रामीण जनता कितनी विछड़ी हुई दशा में है, इसका उल्लेख करना निरर्थक है । जब तक इन व्यक्तियों को शिक्षित करके इनमें नेतृत्व के गुणों का विकास नहीं किया जायगा तब तक भारत की राजनैतिक तथा आर्थिक उन्नति की कल्पना करना अर्थ है । ग्रामीणों को शिक्षित करने का कार्य अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और समाज-शिक्षा द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है । उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करने के लिये ‘जनता कलिजों’ की स्थापना की गई है । साधारणतः लोगों का विचार है कि जनता कलिज उच्च शिक्षा के केन्द्र हैं, परन्तु ऐसा नहीं है । वस्तुतः ये प्रशिक्षण—स्थानीय नेतृत्व के प्रशिक्षण—के केन्द्र हैं और यह प्रशिक्षण केवल ग्राम-निवासियों को दिया जाता है । इन कलिजों में भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय साहित्य, आर्थिक समस्याओं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख बातों की शिक्षा दी जाती है<sup>३</sup> । चार मास का प्रशिक्षण प्राप्त करके ग्राम निवासी अपने-अपने ग्रामों को लौट जाते हैं और वहाँ समाज शिक्षा के कार्य-क्रम में जुट जाते हैं । इस प्रकार ग्रामों की जाती है कि उनके प्रवासों के फलस्वरूप हमारे ग्रामों के निवासियों का उत्थान अल्प समय में हो हो सकेगा ।

१. के० जी० सेपरेन : शिक्षा की पुनर्रचना, पृष्ठ ६३
२. “All our institutions will be communities at work.”  
Radio Broadcast by Dr. Zakir Husain, published in *The Future of Education, A Symposium*.
३. *Teachers' Handbook of Social Education*, pp. 74-75.

## १०. शिक्षा का जनतंत्रीकरण

भारतीय जीवनान के अनुसार देश के सभी व्यक्तियों का सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक व्याप प्राप्त है। भारत में 'धर्म-निरासेन सोचउत्पादक गणराज्य' की स्थापना की गई है। अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। इस प्रकार जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर व्यक्तियों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। इन बातों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये हमें गावर्नरनिक विद्यालयों के द्वार सभी व्यक्तियों के लिये खोल दिये गये हैं। शिक्षा का जनतंत्रीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। निपेन परन्तु योग्य छात्रों को शिक्षा का लाभ उठाने के लिये छात्रवृत्तियाँ देना प्रारम्भ कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित धार्मिक जातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को विशेष रूप से छात्रवृत्तियाँ प्रदान करके शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

## ११. प्रौढ़-शिक्षा

राष्ट्रीय जीवन में प्रौढ़-शिक्षा का अत्यधिक महत्व होता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व तो प्रौढ़-शिक्षा केवल बाँझनीय तथा आवश्यक प्रतीत होनी की देश के नेता जानते थे कि 'जन-साधारण' के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक स्तर में बहुत काफी ऊँचा उठाये बिना वे किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते थे। स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरान्त प्रौढ़-शिक्षा जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गई है। उसको उपेक्षा करके प्रपचा उसे स्थापित करके भारत अपने लिये बहुत बड़ा उत्तरा मोल लेगा। "यदि हम एक ऐसी व्यावहारिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें बहुमत की तर्कसंगत इच्छा की प्रधानता रहे, तो क्या इस बात का आश्वासन कर लेना आवश्यक नहीं है कि यह इच्छा विवेकपूर्ण हो और प्रपकारी उद्देश्यों तथा लक्ष्यों पर आधारित न होकर उपकारी उद्देश्यों तथा लक्ष्यों द्वारा प्रेरित हो। अधिदित लोगों का महज ही स्वार्थी लपकाओं की तिकड़मों का शिकार हो जाते हैं और अपना सुखी जीवन के लिये किसी भी दूसरी शासन-पद्धति की प्रपेक्षा अधिक कर सकता है।"

"ऊपर बताई गई बातों से ज्ञात होता है कि यदि पहिले प्रौढ़-शिक्षा मह-पूर्ण थी, तो अब वह जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गई है। हमें जनता में जो को परखने की क्षमता, आलोचनात्मक शक्ति और सामाजिक भावना का

विकास करने में योग देना चाहिये ताकि वे कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट तथा विकृष्ट के बीच, ज्ञान के क्षेत्र में सब धीरे झूठ के बीच धीरे साचरण के क्षेत्र में भले धीरे धुरे के बीच घन्तर कर सकें। जब तक उनके जीवन को इन सभी दिशाओं में काफ़ी उन्नत नहीं बनाया जायगा, तब तक हम उनसे सुसंस्कृत, सामाजिक दृष्टि से व्यापपूर्ण और समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करने में अपनी भूमिका अत्यन्त ढंग से निभाने की आशा नहीं कर सकते हैं।<sup>११</sup> प्रौढ़-शिक्षा की इसी आवश्यकता का अनुभव करके भारत-सरकार ने समाज-सिखा का व्यापक कार्यक्रम अदम्य उत्साह तथा स्फूर्ति से क्रियान्वित किया है।

## १२. शारीरिक-शिक्षा

शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। मानसिक विकास के साथ-साथ उसका शारीरिक विकास भी होना आवश्यक है। स्वस्थ नागरिक देश के दृढ़ स्तम्भ हैं। राजनैतिक परिवर्तन के कारण भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसको सुरक्षित रखने का भार देश के नवयुवकों के कंधों पर है। वर्तमान राजनैतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में जब विश्व के ऊपर युद्ध के काले बादल मँडरा रहे हैं, इन नवयुवकों की शारीरिक शिक्षा की उपेक्षा करना एक महान् भूल होगी। इसलिये हमारी राष्ट्रीय सरकार ने उनके लिये शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद की विशेष तथा उत्तम व्यवस्था की है।

शारीरिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं एवं केंद्रों के विकास के लिये निर्मित की गई 'राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन योजना' को क्रियान्वित कर दिया गया है। विभिन्न कार्यक्रमों के मध्य समन्वय स्थापित करने और सरकार को परामर्श देने के लिये एक 'केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श मण्डल' की स्थापना की जा चुकी है।

खेल-कूद के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये अप्रामाणिक उपाय किये गये हैं :—(१) 'महिल भारतीय खेल-कूद परिषद्' की स्थापना, (२) विभिन्न राज्यों में 'राज्य खेल-कूद परिषदों' की स्थापना, और (३) 'राजकुमारी खेल-कूद शिक्षण योजना' के अन्तर्गत देश में भारतीय एवं विदेशी खेल-कूद विशेषज्ञों की देखभाल में शिक्षण-केन्द्रों की स्थापना।

## १३. युवक कल्याण

युवक राष्ट्र की समृद्ध सम्पत्ति हैं। आज जब कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक वातावरण विषाक्त हो रहा है और एक देश दूसरे के विरुद्ध जहर उगल रहा



है, भारतीयों की भाँखें अपने इन्हीं युवकों की ओर लगी हुई हैं। यही कारण है कि सरकार 'युवक कल्याण' ( Youth Welfare ) की योजनाओं का निर्माण करने में व्यस्त है। इन योजनाओं में अग्रलिखित उल्लेखनीय हैं :—  
 (१) प्रति वर्ष अन्तर्विश्वविद्यालय सामारोह आयोजित किये जाते हैं तथा एक-कालेज सामारोह सगाठत करने के लिये विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाती है,  
 (२) युवा-नेतृत्व प्रशिक्षण-शिविर लगाये जाते हैं, (३) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों की यात्रा करने के लिये युवकों को वित्तीय सहायता दी जाती है, और (४) युवकों में शारीरिक श्रम के प्रति प्रतिष्ठा-भाव जाग्रत करने का प्रयास किया जा रहा है।<sup>१</sup>

## १४. शिक्षा में सदाचार

राजनैतिक परिवर्तन के फलस्वरूप दासता से मुक्त होकर स्वतन्त्र भारत ने 'समाजवादी आदर्श के समाज' की स्थापना की घोषणा की है। इसमें सफलता तभी प्राप्त हो सकेगी जब नागरिकों में सहयोग तथा सहकारिता की भावनाओं का विकास किया जा सकेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये यह वांछित समझा गया है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों में सदाचार और सामाजिक गुणों का विकास किया जाय। यह अधिकाधिक अनुभव किया जाने लगा है कि यदि शिक्षा में इन बातों पर विशेष ध्यान न दिया गया तो छात्र नागरिकों के रूप में 'समाजवादी आदर्श के समाज' में उपयुक्त स्थान न ले सकेंगे। इस विषय पर हाल में एक विशेष समिति ने विचार किया था। उसकी सिफारिशों को 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' ने स्वीकार कर लिया है और आदेश दिया है कि उनके अनुसार ऐसी पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराये जायें, जिन्हें पढ़कर सदाचार और सामाजिक आदर्शों में बालकों का विश्वास दृढ़ हो तथा उनकी रूचि बढ़े।<sup>२</sup>

## १५. हिन्दू का विकास

पण्डिता महात्मा गाँधी का कथन था : "यदि हम एक राष्ट्र कहलाने के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो हम में समान रूप से अनेक बातें होनी चाहिये। हमारे विभिन्न सम्प्रदायों तथा उपसम्प्रदायों में समान संस्कृति मिलती है। हमारी अर्न्धतायें समान हैं। हमें एक समान भाषा की भी आवश्यकता

१. भारत (वार्षिक संदर्भ-ग्रन्थ) पृष्ठ ८४

२. तीसरी पंचवर्षीय योजना : प्रारम्भिक कवरेज, पृष्ठ १०२

है।<sup>१</sup> राजनैतिक परिवर्तन के फलस्वरूप १९४७ में भारत ने एक स्वतन्त्र राष्ट्र का रूप धारणा किया और महात्मा गांधी के कथनानुसार एक समान भाषा का अनुभव किया। विभिन्न भाषा-भाषी देश होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों में जो पारंपरिक दृष्टिगत हो रहा है, उसका अन्त करने के लिये और उनमें एक भाषा द्वारा सम्पर्क स्थापित करके अविच्छेदता की वृद्धि करने के लिये तथा इस प्रकार सम्पूर्ण भारत को एक राजनैतिक सूत्र में बाँधने के लिये यह अनिवार्य समझा गया कि सम्पूर्ण देश को एक राष्ट्र भाषा हो। महात्मा गांधी तो हिन्दुस्तानी को इस पद पर घासीन करना चाहते थे, परन्तु कतिपय कारणों से यह पद हिन्दी को प्रदान किया गया है। केन्द्रीय सरकार हिन्दी के प्रचार एवं विकास सम्बन्धी कितनी ही विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर चुकी है और कर रही है।

उपरिनिर्दिष्ट तथ्यों के आधार पर हम यह निरसंकोच रूप से कह सकते हैं कि स्वतन्त्र भारत में शिक्षा पर प्रबल राजनैतिक संघात हुआ है और इस संघात के प्रभाव से शिक्षा का कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं बना है। वस्तुतः शिक्षा-जगत् में अनेक परिवर्तन किये जा सके हैं और कितने ही अनेक परिवर्तनों के किये जाने की स्पष्ट सम्भावना है।

## सारांश

शिक्षा तथा समाज दोनों अविच्छिन्न रूप से परस्पर जुड़े हुये हैं। यदि किन्हीं राजनैतिक कारणों से समाज में परिवर्तन होता है, तो शिक्षा में भी अवश्य ही परिवर्तन होता है। जब योक्ष में पुनः जागरण के कारण नवयुग का सूत्रपात हुआ, तब शिक्षा-व्यवस्था में राजनैतिक शक्ति का हस्तक्षेप प्रारम्भ हुआ। फ्रांस की राज्य-कृति के परिणामस्वरूप शिक्षा को पूर्णतया राज्य के अधीन करके उसका कार्याकल्प किया गया। नेपोलियन ने फ्रांस में सत्ताशुद्ध होकर शिक्षा के रूप को पुनः परिवर्तित कर दिया।

ब्रिटिश शासन-काल में शिक्षा पर राजनैतिक संघात—ब्रिटिश शासन-

1. "If we are to make good our claim as one nation, we must have several things in common. We have a common culture running through a variety of creeds and sub-creeds. We have common disabilities. We need also a common language."—M. K. Gandhi : *India of my Dreams*, p, 203.

British rule in India and describe their impact on  
education.  
Write a short essay on : 'Political impact upon education  
in 1905-1947.'  
Give a brief account of the political impact upon educa-  
tion in free India.

— • —

## अध्याय १०

### शिक्षा में परीक्षा

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारतीय आत्मा को उसकी गहराई तक हिला दिया था। भारतीय अंग्रेजों के अमानुषिक प्रत्याचार, अन्यायपूर्ण व्यवहार, साम्राज्यवादी नीति एवं देश के लोपण की देखकर क्रान्तिकारी भावनाओं से भर गये थे। परन्तु महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने विध्वंसात्मक नीति का अनुसरण न करके अहिंसात्मक नीति का प्रातिगन किया। उन्हीं के पथ-प्रदर्शन में भारत के निवासियों ने अंग्रेजी राज्य की जड़ों को निर्बल बनाने के अभिप्राय से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और राष्ट्रीय शिक्षा की माँग का नारा बुलन्द किया। शिक्षित भारतीय अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली को देश के लिये अहितकर समझने लगे थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि राष्ट्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा की परियोजनाओं को कार्यान्वित करके और इस प्रकार नवपुत्रकों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करके ही विशाल ब्रिटिश साम्राज्य से, जिसमें सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, लोहा लिया जा सकता था। इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं की आधारशिलायें रखी गईं और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परीक्षण किये गये। प्रस्तुत अध्याय का विषय इनमें से कतिपय प्रमुख परीक्षाओं का वर्णन करना है। जिन परीक्षणों पर हम अपना ध्यान केन्द्रीकृत करेंगे, वे निम्नलिखित हैं :

- (१) बेसिक शिक्षा—
- (२) विश्व-भारती—
- (३) अरविन्द-आश्रम—

Basic Education  
Vishwa Bharti  
Arvind Ashram  
२२७

४) गुरुकुल—

(२) बनारसी विद्यापीठ—

१. बेसिक शिक्षा

भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अविनाशमिगम् के अनुसार बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया "अंतिम और सबसे अधिक मूल्यवान उद्धार है।" देश को स्वतंत्र दिलवाने तथा एक नवीन सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का निर्माण करने के प्रयास में महात्मा गांधी ने बहुत समय पूर्व यह बात भली-भाँति समझ ली कि व्यक्तियों के उद्वान के बिना मानव-जाति का उत्थान नहीं किया सकता है और केवल उत्तम शिक्षा ही उत्तम स्त्री-पुरुषों का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार महात्मा जी का दृढ़ विश्वास था कि सब प्रकार की तथा सुधार का एकमात्र उपाय उत्तम शिक्षा है। भारत का भ्रमण करते उन्होंने तत्कालीन भारतीय शिक्षा का गूढ़म अध्ययन किया और वे इस पर पहुँचे कि भारतीय बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा घनेको दोषापूर्ण है।

## तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के दोष

भारत की तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के जिन दोषों के प्रति महात्मा गांधी ने संकेत किया, वे अधोलिखित हैं :—

१. हमारी शिक्षा-पद्धति में पुस्तकों का प्रमुख स्थान है और वह पूर्ण-तया पुस्तकीय, साहित्यिक तथा शास्त्रीय है।
२. वह हमें ज्ञान तो देती है, पर हमें जीवन से उसका सम्बन्ध नहीं बताती है। हमारे ज्ञान में तो वृद्धि होती है, परन्तु हमारी बुद्धि तथा समझ में कोई उन्नति नहीं होती है।
३. ज्ञान भी अति कृत्रिम रूप से दिया जाता है, क्योंकि उसे घनेको असम्बद्ध विषयों में विभाजित कर दिया जाता है। इससे हम बातों को जानने तो लगते हैं, परन्तु उनको समझते नहीं हैं।
४. हमारी शिक्षा व्यावहारिक कार्यकुशलता की व्यवहेलना करती है और उसमें सामाजिक निपुणता के विकास के लिये कोई स्थान नहीं है।

1. "The last and the most precious gift."—T. S. Avinash-lingam : *Understanding Basic Education*, p. 1.
2. Hans Raj Bhatia : *What Basic Education Means*, p. 7.

५. हमारी शिक्षा भिन्नभाव तथा सहयोग के स्थान में प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिद्वन्द्विता की भावना को प्रोत्साहित करती है।

६. इसका भारतीय संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

७. इसमें अंधे जी के पढ़ने-पढ़ाने को सर्वोत्तम स्थान दिया जाता है और मातृभाषा के प्रयोग को गौण स्थान दिया जाता है।

८. यह शिक्षा मँहगी है।

९. इसने शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के मध्य भेदभाव उत्पन्न कर दिया है।

१०. इस शिक्षा का लाभ कुछ ही व्यक्ति उठा रहे हैं, क्योंकि यह जन-साधारण की शिक्षा की अवहेलना करती है।

११. इसमें अव्यय की मात्रा बहुत अधिक है। पहली कक्षा में प्रवेश करने वाले छात्रों में से केवल कुछ ही छात्र पाँचवीं कक्षा में पहुँचते हैं, और जो थोड़ा-सा ज्ञान वे प्राप्त करते हैं, वह जीवन में उनके काम नहीं आता है।

### महात्मा गांधी के शिक्षा-विषयक विचार

तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों को देखकर महात्मा गांधी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उससे देश तथा उसके निवासियों का कल्याण होना असम्भव है। अतः उन्होंने 'हरिजन' में उस शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त करना प्रारम्भ किया, जो भारत के लिये उपयुक्त हो सकती थी। ३१ जुलाई, १९३७ के 'हरिजन' में उन्होंने अपने शिक्षा-विषयक विचारों को अधोलिखित शब्दों में व्यक्त किया :—

“राष्ट्र के रूप में हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं कि यदि हमने शिक्षा का यह कार्य-क्रम धन पर आधारित किया, तो हम राष्ट्र के प्रति शिक्षा के अपने उत्तरदायित्वों को इस पीढ़ी में थोड़े समय में निर्वाह करने की आशा नहीं कर सकते हैं। अतः मैंने अपनी दृष्टान्तमय योग्यता की रक्षा को संकट में डालकर यह प्रस्ताव करने का साहस किया है कि शिक्षा आत्म-निर्भर होनी चाहिये। शिक्षा से मेरा अर्थ है बच्चे एवं मनुष्य की सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास। साक्षरता न तो शिक्षा का अन्त है और न आदि। यह तो अनेकों साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एवं स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है। अतः मैं बच्चे की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखा कर और जिस समय से वह अपनी शिक्षा प्रारम्भ करता है, उसी समय से उसे उत्पादन करने योग्य बनाकर प्रारम्भ करना चाहता हूँ। इस प्रकार यदि राज्य विद्या-

में निमित्त वस्तुओं को लेने का उत्तरदायित्व में है, तो प्रत्येक शिक्षक अपने-निर्भर बनाया जा सकता है।"

प्रति भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन

गंधी जी के शिक्षा-विषयक विचारों ने देश में हलचल मचा दी। उनके अनुसार शिक्षा-संशोधन के उभय पक्षों को लेकर विचारकों में घमासान का-विवाद प्रारम्भ हो गया। अतः गंधी जी ने देश के शिक्षा-समर्थकों द्वारा प्रस्तुत योजना को जीव कराना निश्चित किया। उस समय महात्मा जी वर्षों में के। वही २२ और २३ फरवरी १९३७ को मारवाड़ी हाई स्कूल की रक्त-जन्म का समारोह होने वाला था। इस अवसर पर भारत के विभिन्न भागों से शिक्षा-विशेषज्ञ, राष्ट्रीय नेताओं एवं समाज-गुणधारकों को आमंत्रित किया गया और 'प्रगत-भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन', जिसे 'वर्षा शिक्षा-सम्मेलन' भी कहते हैं, का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में गंधी जी ने सभापति का स्थान ग्रहण किया। उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने वाले शिक्षा-विचारकों के समक्ष अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचार व्यक्त किये। गम्भीर विचार-विमर्श के उपरान्त सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये, जो वैश्विक शिक्षा-योजना के आधार हैं :

१. राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे को सात वर्षों तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाय।

1. As a nation we are so backward in education that we cannot hope to fulfil our obligations to the nation in this respect in a given time during this generation, if this programme is to depend on money. I have, therefore, made bold, even at the risk of losing a reputation for constructive ability, to suggest that education should be self-supporting. By education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit. Literacy is not the end of education nor even the beginning. It is only one of the means whereby man and woman can be educated. Literacy in itself is no education. I would, therefore, begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. Thus every school can be made self-supporting, the condition being that the State takes over the manufacture of the "schools." Harijan, July 31, 1937.

National Education Conference,

२. शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो ।
३. इस सम्पूर्ण अवधि में शिक्षा किसी हस्त एवं उत्पादक कार्य के माध्यम से दी जाय । अन्य विषय इस केंद्रीय कार्य से सम्बन्धित रहे जायें । बच्चों की अन्य सभी योग्यताओं का विकास या उसको दिया जाने वाला निष्कल, उसके वातावरण से पूर्णतः सम्बन्धित हो ।
४. सम्मेलन को प्राणा है कि धनैः-धनैः शिक्षा की इस प्रणाली से धन्यापकों का वेतन निकलने लगेगा ।<sup>१</sup>

### जाकिर हुसेन समिति<sup>२</sup>

उपरिनिर्दिष्ट प्रस्तावों को पारित करने के उपरान्त सम्मेलन ने जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली, के प्राचार्य डा० जाकिर हुसेन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की । इसे 'जाकिर हुसेन समिति' के नाम से पुकारा जाता है । इस समिति का उद्देश्य वर्षा शिक्षा-सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के अनुसार एक विस्तृत पाठ्य-क्रम तैयार करना था । इस समिति ने दिसम्बर १९३७ और अप्रैल १९३८ में दो रिपोर्टें प्रस्तुत कीं । प्रथम रिपोर्ट में वर्षा शिक्षा-योजना के आधारभूत सिद्धान्तों, उद्देश्यों, शिक्षकों तथा उनके प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन एवं निरीक्षण और कढ़ाई-बुनाई के विस्तृत पाठ्य-क्रम इत्यादि का विस्तृत वर्णन किया । द्वितीय रिपोर्ट में समस्त विषयों के पाठ्य-क्रम एवं उनको आधारभूत हस्त तथा उत्पादक कार्य से सम्बन्धित करने के उपायों पर अपना मत प्रकट किया ।

इसी बीच 'जाकिर हुसेन समिति' की प्रथम रिपोर्ट फरवरी १९३८ में हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में विचार विनिमय के लिये रखी गई और भारतीय शिक्षा को पुनर्संगठित करने के लिये उसे कांग्रेस की योजना स्वीकार कर लिया गया । इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये अप्रैल १९३९ में सेवाश्रम में 'मजिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्'<sup>३</sup> की स्थापना की गई । इस परिषद् को 'हिन्दुस्तानी तालिमी संघ'<sup>४</sup> भी कहा जाता है । कारण यह है कि गान्धी जी इस नवीन शिक्षा को 'नई तालीम'<sup>५</sup> के नाम से पुकारते थे ।

1. Hindustani Talimi Sangh, Educational Reconstruction, p. 82.
2. Zakir Husain Committee.
3. All-India National Education Board,
4. Hindustani Talimi Sangh.
5. Nai Talim.



## प्रथम खेर समिति

बेसिक शिक्षा योजना को १९३८ में भारत के उन प्रान्तों में मंत्रिमंडल से, क्रियान्वित कर दिया गया। जब केन्द्रीय सरकार में प्रान्तीय सरकारों की अभिरुचि देखी, तो उसने भी इस वि-  
क्रियात्मक पग उठाने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से सलाहकार बोर्ड<sup>१</sup> ने १९३८ में बम्बई के मुख्यमंत्री बी० जी० धता ने 'वर्धा शिक्षा-योजना' की जाँच करने के लिये एक समिति की। इस समिति को 'खेर समिति' के नाम से पुकारा जाता है। नियुक्त की गई 'प्रथम खेर समिति' ने बेसिक शिक्षा-योजना का करके निम्नलिखित सुझाव दिये :

१. सर्व प्रथम बेसिक शिक्षा की योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश दिया जाय।
२. बेसिक शिक्षा ६ वर्ष से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये बाध्य हो; परन्तु ५ वर्ष की आयु वाले बच्चे भी बेसिक प्रवेश ले सकते हैं।
३. बेसिक स्कूलों को छोड़कर अन्य प्रकार के विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चों को सभी दी जाय; जब वे ५ वी कक्षा पास कर ५ वर्ष से अधिक आयु के हों।
४. छात्रों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाय।
५. बेसिक विद्यालय का पाठ्य-क्रम समाप्त करने वाले छात्रों के लिये बाह्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये विद्यालय की ही परीक्षा ही पर्याप्त होगी। उसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को पत्र प्रदान किये जायें।<sup>२</sup>

## द्वितीय खेर समिति

'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' ने 'प्रथम खेर समिति' को सिफारिश स्वीकार कर लिया और १९३९ में 'द्वितीय खेर समिति' की नियुक्ति की। इस समिति का उद्देश्य बेसिक शिक्षा-प्रणाली और उच्च शिक्षा में समन्वय करना था। इसके लिये समिति ने अधोलिखित सिफारिशें कीं :

1. Central Advisory Board of Education.
2. Report of the Committee of the C. A. B. E. appo.

१. बेसिक शिक्षा का शिक्षा-काल ८ वर्ष का हो। ६ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयु तक के बच्चे इस शिक्षा को ग्रहण करें।
  २. ८ वर्ष की इस अवधि को दो प्रक्रमों (Stages) में विभाजित किया जाय—(अ) प्रथम प्रक्रम या जूनियर स्टेज, और (ब) द्वितीय प्रक्रम या सीनियर स्टेज। प्रथम में ५ वर्ष का और द्वितीय में ३ वर्ष का शिक्षा-काल हो।
  ३. जब विद्यार्थी जूनियर स्टेज की शिक्षा समाप्त कर लें; पर्याप्त जब वे ५ वीं कक्षा पास कर लें, तभी उनको उत्तर-प्राथमिक (Post-primary) शिक्षा के अन्य किसी विद्यालय में प्रविष्ट होने की भाजा दी जाय।<sup>१</sup>
- ‘केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड’ ने उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकृत किया और ‘साबैन्ट-शिक्षा-योजना’ में उनको क्रियान्वित किया गया।

### योजना की रूप-रेखा

बेसिक शिक्षा-योजना की रूप-रेखा निम्नलिखित प्रकार से है :

१. बेसिक शिक्षा की अवधि ८ वर्ष की है। यह शिक्षा ६ से १४ वर्ष तक की आयु के बालकों और बालिकाओं के लिये नि:शुल्क एवं अनिवार्य है।
२. शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा है और अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी जाती है।
३. सम्पूर्ण शिक्षा का सम्बन्ध किसी आधारभूत शिल्प (Basic Craft) से होता है, जिसे बच्चों की योग्यता तथा स्थान की आवश्यकताओं को देख कर चुना जाता है।
४. चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वह बच्चों की उत्तम शिल्पी बना देती है, और जो वस्तुएँ वे बनाते हैं, ऐसी होती हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है या उनको बेच कर विद्यालय के खर्च के कुछ भाग की पूर्ति की जा सकती है।
५. इस शिल्प की शिक्षा यांत्रिक विधि से न दी जाकर इस प्रकार दी जाती है कि छात्र उसके सामाजिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व से परिचित हो जाते हैं।<sup>२</sup>

1. *Report of the Second Wardha Education Committee of C. A. B. E. 1939, together with the Decision of the Board thereon, P. 7.*
2. K. G. Saiyidain in *Year Book of Education* (Evans Bros) 1940, p. 503.

## पाठ्य-क्रम

बैसिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में निम्नलिखित विषय होते हैं:

१. गृहभूत शिल्प—प्रचलित आधारभूत शिल्पों में से को-  
नसा है :—(क) टुपि; (ख) कताई-बुनाई; (ग) लकड़ो का  
मिट्टी का काम; (ङ) घमड़े का काम; (च) मछली पालना,  
साक एवं उद्यान-कर्म; (ज) बालिकाओं के लिये गृह वि-  
कोई अन्य शिल्प, जिसके लिये स्थानीय तथा भौगोलिक व  
प्रयुक्त हों।

२. मातृ-भाषा।

३. गणित।

४. सामाजिक अध्ययन—इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र।

५. सामान्य विज्ञान—(प) प्रकृति अध्ययन; (ब) वनस्पति शास्त्र; (स)  
शास्त्र; (द) रसायन-शास्त्र; (र) स्वास्थ्य विज्ञान; (ल) नक्षत्रों  
(व) महाद् वैज्ञानिकों एवं अन्वेषकों की कहानियाँ।

६. कला—रेखा-चित्रण एवं संगीत प्रावि

७. हिन्दी (जहाँ मातृ-भाषा नहीं है)

८. शारीरिक शिक्षा ( व्यायाम एवं खेल-कूद )

पंचवीं कक्षा तक सह-शिक्षा है और बालकों तथा बालिकाओं के  
समान पाठ्य-क्रम है। इसके उपरान्त दोनों के लिये पृथक् विद्यालयों  
व्यवस्था की गई है। ६ ठी और ७ वीं कक्षाओं में बालिकाएँ आधारभूत  
के स्थान पर गृह-विज्ञान में उच्च पाठ्य-विषय ले सकती हैं। शिक्षा का मा-  
मातृभाषा है, परन्तु राष्ट्रभाषा अर्थात् हिन्दी का अध्ययन सब छात्रों के  
प्रनिवार्य है। हिन्दी देवनागरी लिपि में पढ़ाई जाती है। जिन प्रांतीय  
भाषा हिन्दी नहीं है, वहाँ उन स्थानों की प्रादेशिक भाषा पाठ्य-क्रम में प्र-  
भाषा के रूप में रहती है। पाठ्य-क्रम में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान न  
दिया गया है।

## अध्यापन-विधि

बैसिक शिक्षा में अध्यापन विधि सामान्य शिक्षण-पद्धति से सर्वथा भिन्न  
है। बैसिक शिक्षण-प्रणाली में अध्यापन का कार्य, क्रियाओं एवं अनुभवों के  
माध्यम से किया जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षण-विधि इतनी व्यावहारिक  
होती है कि बच्चे विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में धारित करते हैं।  
साथ ही उन्हें यह ज्ञान अन्य समय में ही उपलब्ध हो जाता है। विस्तार का  
से प्रत्येक कक्षा में शिक्षा निम्नादिष्ट प्रकार से प्रयुक्त होती है।

प्रथम कक्षा में बच्चों को अपनी मातृभाषा का मौखिक ज्ञान कराया जाता है। तदनन्तर बच्चे पढ़ना और उसके बाद लिखना सीखते हैं। जिस समय वे लिखना सीखते हैं, उस समय किसी आधारभूत शिल्प की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों बच्चे बाने की कक्षाओं में पहुँचते हैं, वे विभिन्न विषयों के ज्ञान का भर्जन करते हैं। परन्तु उनको इन विषयों की शिक्षा स्वतन्त्र रूप से प्रदान न की जाकर किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जाती है। यणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान आदि के शिक्षण में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी विषय का कोई भाग आधारभूत शिल्प के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो उसे किसी अन्य विधि से पढ़ा दिया जाता है। पाठ्य-क्रम के समस्त विषय परस्पर-सम्बन्धित ज्ञान-क्षेत्रों के रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार ८ वर्ष के अन्त में बच्चों को सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। साथ ही उन्हें आधार-भूत शिल्प की इतनी प्रबुद्धी जानकारी हो जाती है कि उसकी सहायता से वे अनौपार्जन करने लगते हैं।

### अध्यापक

बैसिक शिक्षा-प्रणाली में अध्यापकों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्यालयों के लिये उनका चुनाव करते समय उन अध्यापकों को परीयता दी जाती है, जो उस क्षेत्र के निवासी होते हैं जहाँ विद्यालय स्थित है। शिक्षण कार्य के लिये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिमान (Preference) दिया जाता है।

बैसिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किये जाते हैं। प्रशिक्षण विद्यालयों में वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं, जो या तो मेट्रोकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों या बर्नाबूलर फ़ाइनल परीक्षा पास करने के उपरान्त कम से कम दो वर्ष तक किसी विद्यालय में अध्यापन कार्य कर चुके हों। प्रशिक्षण-विद्यालयों में दो प्रकार का पाठ्य-क्रम होता है—(१) दीर्घ-कालीन प्रशिक्षण, और (२) अल्पकालीन प्रशिक्षण। प्रथम में प्रशिक्षण की अवधि ३ वर्ष है और द्वितीय में एक वर्ष। इस अवधि में छात्राध्यापकों को बैसिक विद्यालयों के सभी विषयों की शिक्षण-विधि का ज्ञान प्रदान किया जाता है।

### नामकरण के कारण

यहाँ यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस शिक्षा का नाम 'बैसिक शिक्षा' क्यों रखा गया है। 'बैसिक' (Basic) शब्द का हिन्दी सान्तर

## पाठ्य-क्रम

बेसिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में निम्नलिखित विषय होते हैं:

१. आधारभूत शिल्प—अग्रलिखित आधारभूत शिल्पों में से कोई एक चुना जाता है :—(क) कृषि; (ख) कटाई-बुनाई; (ग) लकड़ी का काम; (घ) मिट्टी का काम; (ङ) चमड़े का काम; (च) मदली पालना; (छ) फल-शाक एवं उद्यान-कर्म; (ज) बालिकाओं के लिये गृह विज्ञान; (झ) कोई अन्य शिल्प, जिसके लिये स्थानीय तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हों।
२. मातृ-भाषा।
३. गणित।
४. सामाजिक अध्ययन—इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र।
५. सामान्य विज्ञान—(अ) प्रकृति अध्ययन; (ब) वनस्पति शास्त्र; (स) प्राणि-शास्त्र; (द) रसायन-शास्त्र; (र) स्वास्थ्य विज्ञान; (त) नक्षत्रों का ज्ञान; (थ) महान् वैज्ञानिकों एवं धन्येयों की कहानियाँ।
६. कला—रेखा-चित्रण एवं संगीत आदि
७. हिन्दी (जहाँ मातृ-भाषा नहीं है)
८. शारीरिक शिक्षा ( व्यायाम एवं खेल-कूद )

पाँचवीं कक्षा तक सह-शिक्षा है और बालकों तथा बालिकाओं के लिये समान पाठ्य-क्रम है। इसके उपरान्त दोनों के लिये पृथक् विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। ६ ठी और ७ वीं कक्षाओं में बालिकाएँ आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह-विज्ञान में उच्च पाठ्य-विषय ले सकती हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, परन्तु राष्ट्रभाषा अर्थात् हिन्दी का अध्ययन सब छात्रों के लिये अनिवार्य है। हिन्दी देवनागरी लिपि में पढ़ाई जाती है। जिन प्रांतों की भाषा हिन्दी नहीं है, वहाँ उन स्थानों की प्रादेशिक भाषा पाठ्य-क्रम में प्रमुख भाषा के रूप में रहती है। पाठ्य-क्रम में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है।

## अध्यापन-विधि

बेसिक शिक्षा में अध्यापन विधि सामान्य शिक्षण-पद्धति से सर्वथा भिन्न है। बेसिक शिक्षण-प्रणाली में अध्यापन का कार्य, क्रियाओं एवं अनुभवों के माध्यम से किया जाता है। दूसरे शब्दों में शिक्षण-विधि इतनी व्यावहारिक होती है कि बच्चे विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही समय में अर्जित करते हैं। साथ ही उन्हें यह ज्ञान प्रत्येक समय में ही उपलब्ध हो जाता है। विस्तार रूप से प्रत्येक कक्षा में शिक्षा निम्नांकित प्रकार से प्रदान की जाती है :

प्रथम कक्षा में बच्चों को अपनी मातृभाषा का मौखिक ज्ञान कराया जाता है। तदनन्तर बच्चे पढ़ना और उसके बाद लिखना सीखते हैं। जिस समय वे लिखना सीखते हैं, उस समय किसी आधारभूत शिल्प की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े की कक्षाओं में पहुँचते हैं, वे विभिन्न विषयों के ज्ञान का भर्जन करते हैं। परन्तु उनको इन विषयों की शिक्षा स्वतन्त्र रूप से प्रदान न की जाकर किसी आधारभूत शिल्प के माध्यम से दी जाती है। गणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान आदि के शिक्षण में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी विषय का कोई भाग आधारभूत शिल्प के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो उसे किसी अन्य विधि से पढ़ा दिया जाता है। पाठ्य-क्रम के समस्त विषय परस्पर-सम्बन्धित ज्ञान-क्षेत्रों के रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार ८ वर्ष के अन्त में बच्चों को सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। साथ ही उन्हें आधारभूत शिल्प की इनकी प्रवृत्ति जानकारो हो जाती है कि उसकी सहायता से वे धनोपार्जन करने लगते हैं।

### अध्यापक

बैसिक शिक्षा-प्रणाली में अध्यापकों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्यालयों के लिये उनका चुनाव करते समय उन अध्यापकों को परीयता दी जाती है, जो उस क्षेत्र के निवासी होते हैं जहाँ विद्यालय स्थित है। शिक्षण कार्य के लिये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक प्राथमिकता (Preference) दिया जाता है।

बैसिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किये जाते हैं। प्रशिक्षण विद्यालयों में वे ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं, जो या तो मेट्रोकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों या बर्निक्यूलर फ़ाइनल परीक्षा पास करने के उपरान्त कम से कम दो वर्ष तक किसी विद्यालय में अध्यापन कार्य कर चुके हों। प्रशिक्षण-विद्यालयों में दो प्रकार का पाठ्य-क्रम होता है—(१) दीर्घ-वालीन प्रशिक्षण, और (२) अल्पकालीन प्रशिक्षण। प्रथम में प्रशिक्षण की अवधि ३ वर्ष है और द्वितीय में एक वर्ष। इस अवधि में छात्राध्यापकों को बैसिक विद्यालयों के सभी विषयों की शिक्षण-विधि का ज्ञान प्रदान किया जाता है।

### नामकरण के कारण

यहाँ यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि इस शिक्षा का नाम 'बैसिक शिक्षा' क्यों रखा गया है। 'बैसिक' (Basic) शब्द का हिन्दी रूपान्तर

‘माधारभूत’। इसी प्रसङ्ग में ‘बैसिक शिक्षा’ के नामकरण के निर्माहित कारणों को समझा जा सकता है :

यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सम्पदा, संहति एवं शिक्षा-समयन का आधार होगी।

प्रत्येक भारतीय बच्चे को, यदि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य नहीं है, यह माधारभूत शिक्षा, अनिवार्य रूप से प्रदान की जायगी।

यह माधारभूत शिक्षा प्रत्येक भारतीय-पुरुष भयवा स्त्री, धनी घरवा दरिद्र, हिन्दू भयवा मुसलमान, हरिजन भयवा ब्राह्मण की सामान्य सम्पत्ति होगी।

इसका बच्चे की माधारभूत आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों से अनिवार्य सम्बन्ध होगा।

यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के माधारभूत आवश्यकता से सम्बन्धित होगी। यह शिक्षा सभी भारतीयों को ऐसा माधारभूत ज्ञान प्रदान करेगी, जो उनको अपने वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने एवं प्रयोग करने में सहायक सिद्ध होगा।

इस शिक्षा का मन्त्र बिन्दु कोई माधारभूत सिद्धांत होगा, जिसका प्रयोग व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन-निर्वाह के लिये किया जा सकता है।

### यह शिक्षा के माधारभूत सिद्धांत

बैसिक शिक्षा के माधारभूत सिद्धांत निम्नांकित हैं:

१. जनजागरण की शिक्षा—गान्धीजी का कथन था कि “जनजागरण को या भारत का पाद धीरे कलजु है। धनः उसका धन करना आवश्यक” जब भारत में जनसम्य प्रजापति की स्थापना की गई, तब गान्धी जी के की गरिबा का अनुभव किया गया। उनको सहन नया। क लिए वह एक समय था कि देश का प्रत्येक सभ्य अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त है। शिक्षा स्वयं ज्ञान ज्ञान करने का ही दो नही, बल्कि वह जीवन एवं कला का ही ज्ञान है। कालक शिक्षा सभ्य एवं राष्ट्र के लिए ही सहायक है। धनः वह शिक्षा समूह राष्ट्र के लिए रखी गई है और जनजागरण की एक ही प्रजापति के रूप में बाह्य निकाला जायगा।

"Mass education is India's only real chance and must be made a reality." Dr. K. Subramanian: *India of my Dreams*, p. 153.

२. **घनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा**—गांधी जी को भारत के लिए घनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा में हृदय विद्यमान था ।<sup>१</sup> पराधीन भारत अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की शिक्षा भी व्यवस्था करने में असफल रहा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ६ से १४ वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को घनिवार्य बनाने का निश्चय किया गया । इस शिक्षा को बेसिक शिक्षा का रूप दिया गया है ।

३. **हस्त-शिल्प की शिक्षा**—भारत के लिए नवीन शिक्षा की रूप-रेखा प्रस्तुत करते हुए गांधी जी ने ३१ जुलाई, १९३७ के 'हरिजन' में लिखा था : "साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है । अतः मैं बच्चे की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्त-शिल्प सिखा कर, और जिस समय से वह अपनी शिक्षा प्रारम्भ करता है, उसे उत्पादन करने योग्य बना कर प्रारम्भ करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि ऐसी शिक्षा-प्रणाली से ही मस्तिष्क तथा चारमा का सर्वोच्च विकास हो सकेगा । आवश्यकता केवल इस बात की है कि प्रत्येक हस्त-शिल्प की शिक्षा वैज्ञानिक ढङ्ग से दी जाय, न कि केवल यांत्रिक विधि से जैसा कि वर्तमान समय में किया जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक बालक को 'क्यों और कैसे' का ज्ञान कराया जाय ।"<sup>२</sup> गांधी जी के इसी दृष्टिकोण ने प्रेरित होकर बेसिक शिक्षा-प्रणाली में हस्तशिल्प को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है और समस्त विषयों की शिक्षा उसी के माध्यम से दी जाती है ।

४. **स्वावलम्बी शिक्षा**—नवीन शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए गांधीजी का कथन था कि "शिक्षा को स्वावलम्बी होना चाहिए; अर्थात् शिक्षा से पूँजी के अतिरिक्त वह सब धन मिल जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करने

1. "I am a firm believer in the principle of free and compulsory Primary Education for India." M. K. Gandhi : *India of my Dreams* p. 187.
2. "Literacy in itself is no education. I would, therefore, begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. I hold that the highest development of of the mind and the soul is possible under such a system of education. Only every handicraft has to be taught not merely mechanically as it done to-day but scientifically, i.e. the child should know the why and the wherefore of every process." *Ibid*, p. 186.



में व्यय किया गया है।" अतः बेसिक शिक्षा में इस 'स्वावलम्बी' पहलू प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। बेसिक शिक्षा में यह स्वीकार किया जा रहा है कि यदि हस्तशिल्प की योजना को सावधानी से बनाया जाय, तो बच्चे बनाई हुई वस्तुओं को बेचकर स्कूल का कुछ व्यय निकाला जा सकता है। "स्वावलम्बन बेसिक शिक्षा की तेजाबी जाँच है। बापू भारत की निर्धन को शिक्षा-प्रसार में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। इसे दूर करने के लिए उन्होंने यह योजना रखी कि शिक्षा के माध्यम-स्वरूप जो उद्योग जुटा जाय वह उत्पादक हो, अर्थात् उससे कुछ अधिक लाभ प्रकट हो। इस उपार्जन से पाठशाला का कुछ खर्च चल सकता है और शिक्षा स्वावलम्बी हो सकती है। बच्चे भी उद्योग-विशेष में निपुण होंगे और शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त आत्मनिर्भर बन सकेंगे।"

५. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा—“बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। इतिहास हमें बताता है कि यदि किसी देश की संस्कृति को मिटाया हो, तो उसका साहित्य मिटा देना चाहिये। इसी सिद्धान्त पर विदेशियों ने हमारे देश में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा। पर बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा स्वाभाविक रूप तथा स्वतन्त्रता से दी जा सकती है।”

६. शिक्षा में शारीरिक धर्म—बेसिक शिक्षा में शारीरिक धर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इससे हमारे ऐसे निर्धन देश के लिये दो लाभ होंगे। प्रथम, इससे बच्चों की शिक्षा का व्यय निकल आयेगा। द्वितीय, इससे उन्हें एक व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त होगी, जिसके द्वारा इच्छा होने पर वे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा में शारीरिक धर्म को स्थान देकर बच्चों को आत्म-विश्वास बनाया जा सकेगा। राष्ट्र का सबसे अधिक पतन अभी होता है, जब हम शारीरिक धर्म से दूर होना सीख लेते हैं।

1. All education to be true must be self-supporting, that is to say, in the end it will pay its expenses excepting the capital which will remain intact" M. K. Gandhi : *India of my Dreams* pp. 188-189.
2. मर्त्यता तथा मर्त्यता : बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त, पृष्ठ ७
3. "The introduction of manual training will serve a double purpose in a poor country like ours. It will pay for the education of our children and teach them an occupation on which they can fall back in after-life, if they choose, for earning a living. Such a system must make our children self-reliant. Nothing will demoralize the nation so much as that we should learn to despise labour."

—M. K. Gandhi : *op. cit.*, p. 189.

७. सामाजिक शिक्षा—बेसिक शिक्षा का अन्तिम आधारभूत सिद्धान्त है प्रत्येक प्राणी में सहानुभूति एवं प्रेम उपस्थित करना, पनी और निर्धन व्यक्तियों का भेद समाप्त करना और उच्च तथा निम्न वर्गों में समता लाना। इस प्रकार बेसिक शिक्षा के द्वारा एक ऐसे नवीन समाज की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है जो शोषणविहीन हो, जिसका आधार न्याय हो और जिसका मूलमंत्र सहिष्णुता तथा सत्य हो। इस प्रकार बेसिक शिक्षा द्वारा ऐसी सामाजिक शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई है जिससे समाज को नवीन जीवन प्रदान करने के लिये सजीव, स्वावलम्बी एवं उत्साही व्यक्तियों का निर्माण हो।

**बेसिक शिक्षा के उद्देश्य**

बेसिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

१. नागरिकता के गुणों का विकास—प्रजातन्त्र-शासन-व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के प्रति उसके कर्त्तव्य बढ़ जाते हैं। साथ ही उसे अपने अधिकार भी प्राप्त हैं। वह इन कर्त्तव्यों तथा अधिकारों का निर्वाह ठीकी कर सकता है, जब वह इनके प्रति सजग हो। इसके लिये ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो उसमें नागरिकता के गुणों का विकास करे। बेसिक शिक्षा में इस बात की धोर पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। जाकिर हुसेन समिति ने इस विषय में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है : “भाषुनिक भारत में नागरिकता देश के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में विस्तार से प्रजातांत्रिक होनी है। नई पीढ़ी को कम से कम इस बात का अवसर प्रवर्धन मिलना चाहिये कि वह अपनी समस्याओं, अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को समझे।”

२. नैतिक विकास—भाषुनिक समाज का उत्तरोत्तर नैतिक पतन होता जा रहा है। धार्मिक जीवन को प्रमुखता देने वाले व्यक्ति अपने स्वार्थों की दृष्टि में अपने कर्त्तव्यों, सिद्धान्तों तथा आदर्शों को विस्मृत कर चुके हैं। समाज की इस पतनोन्मुख दशा को देखकर गांधी जी ने शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति में नैतिकता को समाविष्ट करना बताया। उनके अनुसार : “मैंने सब से ऊँचा स्थान हृदय की संस्कृति या चार्निजक निर्माण को दिया है और मुझे

1. “In modern India citizenship is destined to become increasingly democratic in social, political, economic and cultural life of the country. The new generation must at least have an opportunity of understanding its own problems and rights and obligations.” *Educational Reconstruction*, p. 95.

धनुभव हुआ है कि सब को समान रूप से नैतिक शिक्षा दी जा सके। बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि उनकी धातु और पालन-पोषण में भिन्न क्यों न हो।”

बेसिक शिक्षा में नैतिक विकास की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया। को कर्तव्य-निराकरणता, दूसरों के अधिकारों के प्रति सम्मान, सहयोग और शान्ति एवं सत्यता के मार्ग का अनुसरण करने की जाती है।

३. सांस्कृतिक उद्देश्य—प्रचलित शिक्षा-प्रणाली का एक मुख्य दोष यह है कि उसमें भारतीय संस्कृति का पाठ न पढ़ाया जाकर बच्चों को पाश्चात्य में रंगा जाता है। वे अपनी परम्परागत संस्कृति से दूर हो जाते हैं। इसकी वृत्ति हानि के सम्बन्ध में गांधी जी ने लिखा है : “यदि किसी स्थिति में जाकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयत्नों से बिल्कुल अचेत हो जाते हैं, अपनी संस्कृति पर लज्जा करने लगती है, तो वह नष्ट हो जाती है।” गांधी जी ने अक्षरज्ञान से अधिक महत्त्व शिक्षा के सांस्कृतिक पहलू को दिया है। इसीलिये बेसिक शिक्षा में भारतीय शिल्पों को स्थान दिया गया है और को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया है।

४. त्रिविध विकास—प्रचलित शिक्षा-प्रणाली में केवल बुद्धि के विकास पर बल दिया जाता है और शारीरिक तथा आत्मिक विकास को पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। अतः इस प्रकार व्यक्ति का केवल एकांगी विकास होता है, विकास नहीं। बेसिक शिक्षा में मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक विकास को पूरा ध्यान दिया गया है। पाठ्य-क्रम के लिये इस प्रकार के विषय चुने गये हैं जिनसे तीनों प्रकार का विकास होना निश्चित हो जाता है।

५. आर्थिक उद्देश्य—बेसिक शिक्षा में आर्थिक उद्देश्य के दो अभिप्राय हैं। प्रथम, बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से विद्यालय के व्यय की भांति

1. “I had given the top place to the culture of the heart and the building of character, and I felt confident that moral training could be given to all alike, no matter how different their ages or upbringing.”—Mahatma Gandhi : *Autobiography*, p. 408.

2. “If at any stage one generation goes completely out of touch with the effort of its predecessors or in anywise is ashamed of itself or its culture, it is lost.”—*Young India*, March 20, 1924,

पूति करना। द्वितीय, बेसिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् बालकों का बड़े होकर किसी उद्योग के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूति करना।

६. सर्वोदय समाज—समाज का भौतिकवादी समाज स्वार्थसिद्धि की नीति की नींव पर खड़ा है। समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित है—धनवति और धनहीन। दोनों ही वर्ग विकृत हैं। एक की विकृति का कारण धन की अधिकता है और दूसरे की विकृति का कारण धन का अभाव। धनवति शोषण की चिता पर खड़े होकर जीवन के आनन्द सूट रहे हैं। धनहीन व्यक्तियों को भर-पेट भोजन और तन ढकने लिये कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं।

बेसिक शिक्षा का उद्देश्य इस विकृत समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना करना है। सर्वोदय समाज में स्वार्थ का स्थान परमार्थ, संग्रह की वृत्ति का स्थान त्याग की वृत्ति और शोषण का स्थान सेवा लेती है। इस समाज में धर्म की महत्ता होगी, ईर्ष्या की नहीं, और सहयोग तथा स्नेह की भावनाएँ होंगी, ईर्ष्या और द्वेष की नहीं। इस समाज के निर्माण के लिये बेसिक शिक्षा इस बात पर बल देती है कि बच्चे सामूहिक तथा सहयोगी जीवन व्यतीत करें। इसीलिये बेसिक शिक्षा बच्चों में त्याग, आत्मविश्वास, समाजसेवा, प्रेम आदि की उच्च भावनाओं को कूट-कूट कर भरने का प्रयत्न करती है।

## बेसिक शिक्षा की विशेषतायें

बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषतायें निम्नांकित हैं:

१. मनोवैज्ञानिक आधार—बेसिक शिक्षा-प्रणाली का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें पाठ्य-विषयों की प्रपेक्षा बालक की प्रधानता दी जाती है। बालक की हस्त-शिल्प का ज्ञान कराया जाता है, जिससे उसकी व्यावहारिक क्षमता को विकसित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। बालक का प्राकृतिक विकास किसी कार्य के द्वारा ही हो सकता है। इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर बेसिक शिक्षा में हस्तशिल्प को प्रमुखता दी गई है।

२. सामाजिक आधार—बेसिक शिक्षा-प्रणाली का आधार सामाजिक है, क्योंकि इसमें बालक के सामाजिक गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। इसी उद्देश्य से बेसिक शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान पर बल नहीं दिया जाता है। शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के चारों ओर केन्द्रित रहती है। इस प्रकार बालकों को एक व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। साथ ही हस्त-शिल्प द्वारा उनमें आत्म-संयम, आत्मा-यासन, सहयोग, सहिष्णुता आदि

गुणों का विशाल विषय जाता है। इन गुणों के फलस्वरूप वे समाज के उत्तम सदस्य बनते हैं और उमरी प्रगति में योग देते हैं।

३. **घासिक साधारण**—बेतिक शिक्षा-प्रणाली का साधारण घासिक है। इसके पक्ष में दो तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं। प्रथम, बेतिक विद्वानों के विचारों को किसी शिक्षा की शिक्षा दी जाती है। उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचकर विद्यालय और शिक्षा का ध्येय यदि पूर्णरूप से नहीं तो घासिक रूप से प्रत्यक्ष निकल आता है। इनके बालकों को शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। भारत जैसे निर्धन देश के लिये घासिक शिक्षा-प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण थी कि साधारण घासिक स्थिति के बालक उसमें लाभ नहीं उठा पाते थे। द्वितीय, बालक हस्तशिल्प को सीख कर और उसमें प्रवीणता प्राप्त कर स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। इसमें उनके भावी जीवन की घासिक समस्याओं का समाधान हो जाता है।

४. **हस्तधर्म का महत्व**—बेतिक शिक्षा में बालक हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और हस्तधर्म का महत्व समझते हैं। हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था सदैव जात-पात के भेदभाव से धीत-प्रोत रही है और छोटे तथा बड़े व ऊँच तथा नीचे का भेद जीवन एवं कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होता है और स्वीकार किया जाता है। उच्च जातियों के व्यक्ति हाथ से काम नहीं करते हैं। इसके विपरीत, निम्न जातियों के व्यक्ति सदैव करते हैं। यही कारण है कि मानसिक कार्य थोड़ा और हाथ का काम निकुष्ट समझा जाता है। "इस प्रकार के विचार और भेदभाव धात काल के नये प्रजातन्त्रवादी वातावरण में नहीं चल सकते हैं और प्रजातन्त्रवादी संस्थाओं की वृद्धि और विकास में बाधा डालते हैं। हमें ऐसा समाज पैदा करना है, जिसमें जाति, सम्प्रदाय और रंग के संकुचित भेदभाव न रहें। जहाँ सब को बराबर सुविधायें मिलें और जिसमें सब लोगों से यह धाना की जाय कि वे राष्ट्र और देश की उन्नति और कल्याण के लिये प्रयत्नशील रहें। कितनी सेवा कोई देश की कर सकता है उसकी सामाजिक स्थिति पर ही नहीं बल्कि मानसिक धर्म पर भी निर्भर रहता है। हमें देश के उत्पादन में हाथ बटाना है, उसमें वृद्धि करनी है, सम्पत्ति बढ़ नहीं है, जो हम भोगते हैं बल्कि वह बढ़ाना है, जो हम पैदा करते हैं और नये निजाम में हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों का कोई स्थान नहीं है। काम ही हमारी पूजा है और सबको अपने हाथों से काम करना सीखना चाहिये।" इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर

बेसिक शिक्षा-प्रणाली में हाथ के काम को पर्याप्तिक महत्व दिया गया है। जब छात्र स्वयं अपने हाथों से काम करना सीखते हैं, तब उन्हें हस्तधर्म के प्रति पूर्ण नहीं रह जाती है और वे उसकी महत्ता को समझने लगते हैं।

५. विद्यालय, गृह और समाज के जीवन में सामंजस्य—वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का सर्वभ्रष्ट दोष यह है कि उसके द्वारा विद्यालय, गृह और समाज के जीवन में सामंजस्य नहीं उपस्थित किया जाता है। बेसिक शिक्षा-प्रणाली इस दोष का निवारण करती है। शिक्षा का अभिप्राय केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं है। सच्ची शिक्षा वही है, जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यावहारिकता ही शिक्षा का प्राण है। हस्तशिल्प की शिक्षा प्राप्त करके बालक के व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है और वह अपने को विद्यालय, गृह और समाज में प्रायः समान वातावरण में पाता है।

६. सहसम्बद्ध शिक्षण बेसिक शिक्षा में अपनाई गई शिक्षण-विधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकतम है। इस विधि में बालक की समस्त शिक्षा का माध्यम कोई हस्तशिल्प भ्रषवा क्रिया है। कृषि, कटाई-बुनाई, लकड़ी, मिट्टी भ्रषवा चमड़े के काम आदि में से बालक एक कार्य का चयन करके उसको करता है। सरलशब्दों में बालक को उस कार्य से सम्बन्धित मन्द ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार उसे हस्तकार्य भ्रषवा अन्य क्रियाओं आदि के माध्यम से भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, कला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती है। विभिन्न विषयों की हस्तशिल्प भ्रषवा क्रिया के माध्यम से शिक्षा देने की विधि को 'सहसम्बद्ध शिक्षण' (Correlated Teaching) कहते हैं। इस विधि का आधार मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है। 'सहसम्बद्ध शिक्षण' का आधार केवल हस्तकार्य भ्रषवा कला-कौशल ही नहीं हैं, अपितु शिक्षण को बालक के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से भी सम्बद्ध किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा केवल विद्यालय की चतुर दीवारी तक ही सीमित नहीं रहती है, अपितु उसका सम्बन्ध विद्यालय के बाहर के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से भी स्थापित हो जाता है।

७. ज्ञान एक अभिन्न-अखंड समष्टि—'बेसिक शिक्षा में ज्ञान एक अभिन्न अखंड समष्टि है और उसका अनेक असम्बद्ध, और कई बार, परस्पर अभिव्यक्त विषयों में विभाजन निषिद्ध है।'<sup>१</sup> प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के

1. "In Basic Education knowledge is treated as one unified whole and its division into a number of unrelated, and at times mutually exclusive subjects is not favoured."  
—H. R. Bhavia : *What Basic Education Means*, p. 17.



भावश्यक होता है।<sup>१</sup>”

बालक के प्रति वैज्ञानिक शिक्षा का यह दृष्टिकोण नवीन नहीं है। रूसो (Rousseau), पेस्टालोजी (Pestalozzi), फ्रोबेल (Froebel), एवं हर्बर्ट (Herbart) शिक्षा-शास्त्रियों ने बालको के व्यक्तित्व को सच्चा सम्मान दिया। उन्होने कहा कि शिक्षा किसी भावी काल के लिये नहीं होती है, अपितु बालक का अपना निजी महत्व इसी समय तथा इसी काल में होता है। “हमारे अपने युग में अमेरिका के बड़े दार्शनिक और शिक्षा-शास्त्री जॉन ड्यूई (John Dewey) ने बालक-प्रधान शिक्षा की लहर को दार्शनिक रूप और बल दिया जो आज ‘नई शिक्षा’ (New Education) अथवा ‘आधुनिक स्कूल’ (Modern School) के नाम से प्रचलित है तथा ड्यूई के विचारों से प्रेरित और प्रोत्साहित है। स्कूल में बालकों के व्यक्तित्व का उतना ही आदर होना चाहिये, जितना बड़ों के व्यक्तित्व का समाज में होता है।<sup>२</sup>”

वैज्ञानिक शिक्षा ने इसी सिद्धान्त को स्वीकार दिया गया है और साथ ही ‘आधुनिक बाल-अध्ययन-आन्दोलन’ (Modern Child-Study Movement) के इस सिद्धान्त को भी स्वीकार किया गया है कि बालक बालकों में स्वभावगत विभिन्नताएँ होती हैं, अतः शिक्षा-प्रणाली, पाठ्य-वस्तु और माता-पिता को उनके स्वभाव के अनुकूल बनाया जाय। वैज्ञानिक शिक्षा-प्रणाली में बालकों की अभिरूचियों, भावनाओं तथा मानसिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनकी शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक शक्तियों का विकास किया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक शिक्षा बालक का सर्वाङ्गीण विकास करने का प्रयास करती है।

६. क्रिया-प्रधान शिक्षा—वैज्ञानिक शिक्षा क्रिया-प्रधान है। इसमें सम्पूर्ण ज्ञान का आधार अनुभव माना गया है। इस अनुभव को प्राप्त करने का माध्यम कोई हस्तशिल्प होता है। बालक इस केन्द्रभूत हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए और भी सम्बन्धित अनुभवों को प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ, कातना, सीलते समय बालक कपास, उसकी छेती, छेत के लिये मिट्टी व पानी, भारत में सूती उद्योग-धन्धों का व्यापार, व्यापार के सम्बन्ध में धंधेजों का भारत-यागमन, सूत के पोतों का गितना आदि बातों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस

1. “In the Basic system the centre of education is the child ..... The Basic system regards the child as ‘the educational customer’ whose needs must be studied and understood, catered to and fulfilled.”—Hans Raj Bhatia : *op. cit.*, p. 13.

2. हंसराज भाटिया : वैज्ञानिक शिक्षा क्या है, पृष्ठ १०



प्रकार उसे कताई के साथ कृषि, भूगोल, रसायन-शास्त्र, इतिहास, गणित आदि के अनुभव प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि हस्तशिल्प में लगे हुए बालक बौद्धिक ज्ञान अथवा मानसिक अनुभव भी प्राप्त करते हैं। शिक्षा में यह सिद्धान्त 'करो और सीखो' (Do and Learn) कहा जाता है। पश्चिम के प्रगतिशील देशों में इस सिद्धान्त को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। अमेरिका के शिक्षा-शास्त्री जान ड्यूई (John Dewey) ने इसी सिद्धान्त के आधार पर 'क्रिया-प्रधान विद्यालय' (Activity School) स्थापित किया। किडरगार्टन, फ्रोबेल एवं मांटेसरी स्कूल भी इसी सिद्धान्त पर आधारित हैं। बेसिक शिक्षा-पद्धति में भी इसी सिद्धान्त का पालन किया जाता है।

यह सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बालक के स्वभाव के अनुकूल है। वह सदैव कुछ न कुछ करते रहना चाहता है। उसके अन्तर में जिज्ञासा, रचना, संवय आदि अनेकों नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। बेसिक शिक्षा-प्रणाली में कुछ करने और बनाने पर बल दिया जाता है। अतः इससे बालक की इन नैसर्गिक प्रवृत्तियों और भीतरों भाँगे की पूर्ति होती है। परिणामस्वरूप यह इस शिक्षा के प्रति आकर्षित होता है और बेसिक शिक्षा एवं बालक के जीवन में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार की शिक्षा अधिक आशय-पूर्ण और सप्रयोजन रूप धारण कर लेती है।

१०. शिक्षा का माध्यम : आधारभूत शिल्प—बेसिक शिक्षा का माध्यम कोई आधारभूत शिल्प होता है। यही शिल्प सभी विषयों के माध्यम का माध्यम होता है। आधुनिक युग के सभी शिक्षा-विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते हैं कि बालकों को किसी उत्पादक कार्य के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिये क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा जीवन से वास्तविक सम्बन्ध स्थापित करती है। शिल्प के कार्य में ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों को एक साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। बालक ईमानदारी से परिश्रम करने का मूल्य समझने लगता है और उसको व्यावहारिक बुद्धि तथा कुशलता का विकास होता है। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा के महत्व को व्यक्त करते हुए अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि इस शिक्षा से बालक का मनोवैज्ञानिक हित होगा। उसे साहित्यिक तथा सैद्धान्तिक प्राचीन शिक्षा-प्रणाली से, जिनके विरुद्ध उसकी आत्मा सदैव विद्रोह किया करती है, मुक्ति प्राप्त होगी। इस शिक्षा के द्वारा बालक केवल साधर ही नहीं होगा, बल्कि उसकी पारिरीक, बौद्धिक तथा रचनात्मक क्षमताओं का भी विकास होगा। इसका अर्थ होगा उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा।

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि बेसिक शिक्षा में शिल्प को स्थान देने का उद्देश्य बालकों को कारीगर बनाना है। इन आधाररहित तर्कों का उत्तर देते हुए जाकिर हुसेन समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है : “इन नवोन शिक्षा-पद्धति का प्रधान उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि बालकों को ऐसे कारीगर बना दिया जाय कि वे यत्रवत् कार्य करते रहें वरन् इसका उद्देश्य यह है कि शिल्प में निहित साधनों को शिक्षा के लिए उपयोग किया जा सके।” अतः शिल्प में तीन गुणों का होना आवश्यक है :— (१) शिल्प अपना उत्पादन कार्य ऐसा हो जिसका सम्बन्ध शिक्षा-विज्ञान से हो, (२) इस शिल्प का सम्बन्ध छात्र की क्रियाशो, रुचियों और भावी जीवन से हो, और (३) शिल्प ऐसा हो जिसमें पाठ्य-क्रम के सम्पूर्ण अङ्गों का समावेश किया सके।

११. स्वतन्त्रता-प्रधान प्रणाली—बेसिक शिक्षा-प्रणाली में अध्यापकों तथा छात्रों को कार्य करनेकी अधिक स्वतन्त्रता रहती है। “जब शिक्षा का लक्ष्य यह समझा जाता है कि नवयुवक स्वच्छन्द और रचनात्मक भावप्रक्रियाशीलता द्वारा पूर्णतम सम्भव वृद्धि और विकास पायें, तो छात्रों की पूरी स्वतन्त्रता रहनी चाहिए कि वे अपने भाव सोचें, अपने काम का नज़ारा अपनी रुचि और इच्छा से बनायें और अपनी शक्ति और रसदार से उस नवोद्यम योजना को कार्य रूप में परिणत करने की चेष्टा करें।” वर्तमान शिक्षा-पद्धति का प्रमुख दोष यह है कि उसमें धारम-अभिव्यक्ति तथा रचनात्मक कार्य सम्भव नहीं हैं, क्योंकि उसमें केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के सङ्कुचित लक्ष्य से रटने तथा निश्चित प्रवृत्ति में तथ्यों पर अधिकार कर लेने पर बल दिया जाता है। बेसिक स्कूलों में छात्रों को कार्य करने का, कार्य में रुचि लेने का और कार्य करके लाभप्रद ज्ञान के अर्जन करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। उनकी व्यक्तिगत भावों को पूर्ण किया जाता है और वे अनुभव करते हैं कि स्कूल का निर्माण उन्हीं के सिधे हुआ है और वह उन्हीं के हित में कार्य कर रहा है। परन्तु उनकी स्वतन्त्रता का अर्थ यह नहीं है कि वे स्कूल में जिस प्रकार चाहें कार्य करें। उनकी स्वतन्त्रता को दो महत्वपूर्ण बातें नियमित करती हैं—उनके अपने प्रयोग तथा प्रयोजन और उनकी कक्षाओं के अन्य छात्रों का हित। जब छात्र किसी एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में कार्य करने का प्रयास करते हैं और जब वे अन्य विद्यार्थियों से मिल-जुलकर, और उनकी रुचि तथा हित को अपने समक्ष रख कर कार्य करते हैं, तब उनकी स्वतन्त्रता, धारम-संयम और भावमन्यन्य मे परिणत हो जाती है। बेसिक शिक्षा में अनुशासन का अभिप्राय बाह्य प्रतिबन्ध

१. हुंटराज भाटिया : बेसिक शिक्षा क्या है, पृष्ठ ४७।

तथा दबाव से उत्पन्न की गई व्यवस्था नहीं है, बलितु उसका कार्य है स्वतन्त्रता का विवेकपूर्ण प्रयोग।

बेसिक शिक्षा में अध्यापकों को भी पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। उन्हें न तो कोई घटल पाठ्यक्रम ही चलाना पड़ता है और न कोई नियमबद्ध पाठ हो जाने पड़ता है। उन्हें न तो पुस्तकों को समाप्त करने की विन्ता होती है और उन्हें परीक्षाओं का भय होता है। वे अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग तथा शिक्षण कर सकते हैं और ऐसी विधियों एवं उपायों पर विचार कर सकते हैं जहाँ उन्हें काम में ला सकते हैं, जो उनके मस्तिष्क तथा योग्यता के विकास के लिए आवश्यक हों और जिनसे स्कूल की आवश्यकता पूर्ण हो सकें। वे संचित अनुभव के आधार पर अपने कार्य की विधि में जिस प्रकार का परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं। सम्पूर्ण पाठ्य-क्रम पर उनका अधिकार है। अन्य साधारण स्कूलों के अध्यापकों के समान वे इस बात का अनुभव करते हैं कि वे केवल दूसरों के हाथ की कठपुतली हैं और पाठ्य-क्रम तैयार करने, पुस्तकों के चयन करने, कार्य-क्रम निश्चित करने तथा परीक्षा उनका कोई हाथ नहीं है। इससे संदेह नहीं कि बेसिक स्कूल में पाठ्य-क्रम तैयार करने, परन्तु उनके कार्य एवं प्रयत्न में इतना लचीलापन, एवं विस्तार होता है कि अध्यापक अपने कार्य में अपनी इच्छा से कर सकते हैं जिससे उनका कार्य उनके जीवन का एक अङ्ग बन जाता है।

## शिक्षा के दोष

शिक्षा-योजना के जिन दोषों की ओर संकेत किया गया है, वे निम्नलिखित हैं :

शिक्षा-योजना विशेष रूप से ग्रामों के लिये है, न कि नगरों के लिये।

शिक्षा में उत्पादित-सिद्धान्त (Principle of Productivity)

नहीं है। अतः इसका अनुसरण करने से बेसिक विद्यालय कुटीर-प्रणाली में परिणत हो जायेंगे।

शिक्षा-सिद्धान्त से अध्यापकों का नैतिक पतन हो जायगा, क्योंकि वे अपने-अपने छोटे-छोटे क्षेत्रों एवं विद्यालयों को धनीपार्जन करने के साधन समझेंगे।

साधुयानों एवं ब्रह्मों का है और विज्ञानों की प्रति तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसे युग में कठार्थ और बुनार्थ के समान मध्यकालीन प्रयोग का उपदेश करके भारत की औद्योगिक प्रगति अवरोधित होगी।

५. आधारभूत शिल्प द्वारा समस्त विषयों को शिक्षा दी जानी एक सम्भव बात है ।
६. आधारभूत शिल्प की सहायता से न तो बच्चों का सर्वतोमुखी विकास करना सम्भव होगा और न उन्हें सामान्य शिक्षा ही दी जा सकेगी, क्योंकि वर्धा-शिक्षा-योजना में व्यावसायिक तथा बौद्धिक शिक्षा में उचित संतुलन का अभाव है ।
७. तकली द्वारा कलाई पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया है । क्योंकि इस कार्य द्वारा अधिक उत्पादन होना सम्भव नहीं है, अतः इसमें विद्यार्थियों का समय नष्ट होगा और उनके लिये शिक्षा भंगूगी पड़ेगी ।
८. वर्धा-शिक्षा-योजना में भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने की ओर पूर्ण ध्यान दिया गया है, पर धर्म की शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया गया है । अतः धर्मविहीन वैज्ञानिक शिक्षा उसी प्रकार की होगी, जिस प्रकार की भारमाविहीन बुद्धि ।
९. वैज्ञानिक विद्यालय एक वर्ष में २८८ दिन खुलेंगे । इतने अधिक कार्य दिवस रख कर बच्चों को अत्यधिक थम करने के लिये बाध्य किया जायगा ।
१०. पाठ्य-क्रम के विभिन्न विषयों के लिये समय का विभाजन अत्यन्त नुटि-पूर्ण है । शारीरिक-शिक्षा के लिये प्रतिदिन केवल १० मिनट दिये गये हैं, जबकि आधारभूत शिल्प के लिये ३ घंटे २० मिनट का समय निर्धारित किया गया है ।
११. प्राथमिक शिक्षा पर आवश्यकता से अधिक धन दिया गया है और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की उपेक्षा की गई है ।

अन्त में हम कह सकते हैं कि "यह योजना काल्पनिक है, एक अनावश्यक विद्वांस है, एक मनःसृष्टि है और वास्तविक व्यवहार से परे है । इस योजना में एक सुस्थित शिक्षा-दर्शन की अपेक्षा भावुकता अधिक है । इसे गांधी जी की महानता से प्रभावित व्यक्तियों ने भावुकतावश ही स्वीकार किया है ।"

### उपसंहार

वैज्ञानिक-शिक्षा-योजना के उपर्युक्त गुण-दोषों के विवेचन के आधार पर हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिये कि भारत जैसे निर्धन देश के

लिये वर्षा-विद्या-योजना आवश्यक कृपाएँ करायी गइयों। बन्धुज  
देश के लिए हमने अधिक उगम विद्या-योजना की कल्पना करना ही  
है। इस योजना की महानत्व देन है 'उत्पादक क्रिया का निदान'।  
योजना गांधीजी की दूरदर्शिता की प्रतीक और उनकी देश-सेवा तथा वास्तव  
धनुषम फल है। हमें यह विश्वास है कि जिस प्रकार उनकी राजनीतिक  
नामों में इस देश की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिये  
तीय शक्ति विद्यमान रहती थी, उसी प्रकार उनकी वर्षा-विद्या-योजना में  
की समस्त विद्या-समस्याओं को हल करने की पूर्ण क्षमता है।

## २. विश्व-भारती

श्रीमती व्यासकाई श्रेष्ठ ने एक पत्र में रवीन्द्रनाथ टैगोर को लिखा था :  
"हम धनुषम करते हैं कि यदि हम आपकी सस्था में न गये होते, तो हमारा  
भारत-यात्रा का कार्य पूर्ण न हुआ होता।" जिन सस्था का श्रीमती श्रेष्ठ ने  
उल्लेख किया है, वह है 'विश्व-भारती'।

### विश्व-भारती की स्थिति एवं स्थापना

कवि-सम्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर ने १८६१  
में बंगाल प्रान्त में बोलपुर नामक स्थान के समीप भगवान के भक्तों के लिये  
एक धार्मिक की स्थापना की। यह स्थान बोलपुर रेलवे स्टेशन से दो मील और  
कलकत्ते से लगभग १०० मील दूर है। हावड़ा से यहाँ की यात्रा में तीन घण्टे  
लगते हैं। कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने १९०१ में इस धार्मिक को एक विद्यालय  
का रूप प्रदान किया और इसका नाम 'शान्तिनिकेतन' रखा। ६ मई १९२२  
को इस शिक्षण संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिणत करके, कवि  
टैगोर ने इसका नाम 'विश्व-भारती' रखा। १९५१ में केन्द्रीय धारा-सभा ने  
एक अधिनियम पारित करके इसको केन्द्रीय सरकार के संरक्षण में रख  
दिया है।

### टैगोर के शैक्षिक विचार

शान्तिनिकेतन प्रणाली विश्व-भारती की स्थापना के कारणों को खोजने  
के लिये हमें कवि टैगोर के शैक्षिक विचारों का विहंगावलोकन करना  
पड़ेगा। रवीन्द्रनाथ अपने प्रारम्भिक विद्यार्थी जीवन से ही वर्तमान  
शिक्षा-प्रणाली से असंतुष्ट थे। उनका यह विश्वास था कि यह शिक्षा  
बालकों की नैसर्गिक शक्तियों को कुंठित कर देती है। उनके मतानुसार यह

शिक्षा न केवल अपूर्ण धरितु व्यर्थ भी थी, क्योंकि इससे बालकों की प्राकृतिक शक्तियों के विकास में बाधा पहुँचती है। इस शिक्षा में बालकों के शरीर, मन तथा आत्मा का समुचित विकास करने की क्षमता नहीं है। टैगोर भी अन्य शिक्षा-शास्त्रियों के समान कृत्रिम बातावरण के विरोधी एवं स्वतन्त्रता के समर्थक थे। उनका प्रबल विश्वास था कि बालकों को वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रदान करके ही उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किया जा सकता है। नियंत्रण इस विकास में बाधा उपस्थित करता है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिये बाध्य न करे। सच्ची शिक्षा वही है, जो विद्यार्थियों को आत्म-प्रभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करे। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है, न कि उनको पाठ्य-पुस्तकों को कठस्थ कराके उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को कुंठित करना।

टैगोर प्रकृति के अनन्य उपासक और सच्चे भक्त थे। उनके विचारानुसार प्रकृति ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। मानव भी उसी ब्रह्म का अङ्ग है। अतः उनका कथन था कि प्रकृति और मानव में प्रबल सम्बन्ध है। उनकी धारणा थी कि प्रकृति के माध्यम से ही मानव को सत्य का आभास हो सकता है। इसीलिये उन्होंने अपनी शिक्षा में प्राकृतिक बातावरण को सर्वोपरि रखा। इस बातावरण में रहकर ही प्रकृति तथा मनुष्य में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। उनके मतानुसार प्राकृतिक बातावरण में रहकर छात्रों के हृदयों में स्वयं ही सौन्दर्य की भावना का संचार हो जाता है, जिससे आत्मा की कालिमा घुल जाती है और छात्र निष्कपट होकर धर्म-धर्म-उच्चतर जीवन की ओर प्रवृत्त होते हुए अन्त में ईश्वर और उसी सत्ता का अनुभव करते हैं।

टैगोर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के पुजारी थे। वे पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का भी सम्मान करते थे। किन्तु समकालीन अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली ने भारतीयों को पाश्चात्य आचार-विचारों से इतना भतिरंजित कर दिया था कि वे उस शिक्षा के प्रबल विरोधी हो गये थे। तत्कालीन शिक्षा पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है : "व्यापक भूमिका से भ्रष्ट यह शिक्षा अत्यधिक अस्वच्छ तथा असम्पूर्ण है। केवल उसके धर्म्यस्त हो जाने के कारण हमें इस बात का अनुभव नहीं होता है। जब हम धर्म्य देशों के साथ अपने देश की शिक्षा की तुलना करते हैं, तो हमें केवल सामने दिखाई देने वाले हृदय-अंधा ही दिखाई देते हैं। धर्म्य अंध का हम कोई हिसाब नहीं रखते हैं। हम केवल यह देखते हैं कि धर्म्य देशों में भी विश्वविद्यालय हैं और हमारे देश में भी हैं।" विदेशी शिक्षा-प्रणाली का यह बिज्र अङ्कित करने का उनका अभिप्राय यही था कि उस शिक्षा से भारत का हित नहीं हो सकता था। यह क्यों

इसका स्वीकारण करते हुए टेंगोर ने प्राप्ति लिखा है : "अंग्रेजी भाषा के घूँघट में छिपी हुई शिक्षा स्वभाव से ही हमारे हृदय की सहवर्तिनी होकर नहीं चल सकती है। यही कारण है कि हम में से अधिकांश व्यक्तियों को जितनी शिक्षा प्राप्त है, उतना ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हमारे गृह तथा विद्यालय के मध्य द्राम प्रवृत्ति पाँवगाड़ी चलती है, परन्तु हृदय नहीं चलता है। नोटबुकों के शासन से हम मुक्त नहीं हो पाये हैं। शिक्षा के साथ देश के हृदय का सहज स्वाभाविक तादात्म्य कराने की तैयारियाँ आज तक नहीं की गई हैं।"

शिक्षा के प्रति स्वयं टेंगोर का क्या दृष्टिकोण था, इसका भाषास हों उनका "मेरा विद्यालय" ( My School ) पढ़ कर हो जाता है। वे लिखते हैं :

"मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चों की अष्ट-चेतन बुद्धि उनकी चेतन बुद्धि से अधिक शक्तिशाली होती है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण पाठों की अधिक मात्रा हमको इसके द्वारा सिखाई गई है। अस्वस्थों पीढ़ियों के अनुभव हमारे स्वभाव में इसके द्वारा धीरे-धीरे प्रवेश करा दिये गये हैं, और यह न बिना किसी प्रकार की शकान उत्पन्न किये, अपितु हमको आनन्द देकर। ज्ञान की यह स्वाभाविक मानसिक शक्ति हमारे जीवन का पूर्ण अङ्ग हो जाती है। यह एक तालटन के समान नहीं है, जो बाहर से जलाई जा सकती है और जिसकी बत्ती बाहर से काटी जा सकती है, पर यह जुगनु के प्रकाश के समान है, जिसे वह अपने जीवन-क्रम के कारण रखता है।

"हम इस संसार में प्राप्ति हैं, इसे धनाने के लिये, केवल इसे जानने के लिये नहीं। हम ज्ञान से शक्ति भले ही प्राप्त कर लें, परन्तु हम में परिपूर्णता सहानुभूति से ही आ सकती है। अस्वस्थ शिक्षा वह है, जो हमें भुवना का भंडार न बनाकर, हमारे जीवन एवं स्थिति को एकलपता प्रदान करती है।

"स्कूलों में सहानुभूति की शिक्षा की आवश्यकता रूप से उपेक्षा ही नहीं की जाती है, बल्कि उसका कठोरतापूर्वक दमन भी किया जाता है। हम भूगोल की शिक्षा देने के लिये बालक को मिट्टी से दूर हटाते हैं, व्याकरण की शिक्षा देने के लिये उसको भाषा को उससे छिनेते हैं। बालक का स्वभाव अपनी सम्पूर्ण शक्ति से इस पर्यावरण का विरोध करता है, परन्तु अन्त में दब के भय से चुन हो जाता है।"

अपने विद्यार्थी-जीवन का वर्णन करते हुए टेंगोर ने लिखा है : "हम लोग किसी घमायबपर में रखी हुई निरन्तर बस्तुओं के समान कला में बैठे रहते थे और पढ़ाये जाने वाले पाठों की, पुण्यों पर दोनों के समान, बर्षों की जानी दो। शिक्षा जीवन के परिवेश से दूर भटक गई थी। प्रकृति के स्वभाव एवं

पूर्णता की घोर अप्रसर करने वाले प्रभावों से उसका सम्बन्ध समाप्त हो गया था ।" इस प्रकार की शिक्षा, जिसका जीवन-प्रवाह से कोई तादात्म्य नहीं है, पूर्णतया अस्वाभाविक एवं निरर्थक है ।

वैश्वकालीन शिक्षा के उपरोक्त दोषों का अवलोकन करके घोर अपने ऐतिसिक विचारों को भूर्त रूप प्रदान करने के लिये टैगोर १९०१ में शान्ति निकेतन में केवल १० छात्रों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना नवीन परीक्षण करने के लिये प्रवृत्त हुए । उन्हें अपने इस कार्य में इतनी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई कि १९२२ में इस साधारण विद्यालय ने 'विश्व-भारती' के नाम से एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण किया ।

### विश्व-भारती का वातावरण

यह संस्था नगर के कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में एक मनोरम स्थान में है । यह विश्वविद्यालय साधारण विश्वविद्यालयों के समान दीवारों से घिरा हुआ, इमारतों की भीड़-भाड़ का दृश्य उपस्थित नहीं करता है । वस्तुतः यह सामान्य अर्थ में एक विश्वविद्यालय का चित्र प्रस्तुत न करके एक आश्रम का दृश्य उपस्थित करता है । प्रकृति के जिस हृदयाकर्षक एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में विश्वभारती स्थित है, उसका वर्णन स्वयं टैगोर के शब्दों में ही किया जा सकता है । उन्होंने लिखा है : "निर्विरोध, निर्विकार वातावरण है इस शान्ति-निकेतन आश्रम के चारों ओर । कहीं-कहीं झाड़ियाँ निकल आई हैं । इसके मध्य में ऊँचे ढाड़ के वृक्ष, काली जामुन के विटप, नये पीपे और खोदियों के घरोदों दृष्टिगत होते हैं । एकाकी खेतों के मध्य में एक पतली पगडंडी सितज के घाँवल में बसे गाँव की ओर बल खाती चली गई है । घास का मृदुर उठाये संघाल मुकतियाँ कभी-कभी उबर से निकल जाती हैं । इस प्रशान्त स्थली के मध्य निर्विकार साल वृक्षों का कुंज है जिसके सपन पत्तों के वातायन से किर्त पक्षि को मन्दिर के कलश के अग्रभाग की झाँकी मिल सकती है । इस घास-घामलक कुंज में साल और महुए के घाँवल में बसा है हमारा शान्ति निकेतन ।" वस्तुतः सौन्दर्य की पराकाष्ठा है । तनिक कल्पना कीजिये उस तावण्य-पूर्ण वातावरण की तथा वृक्षों की छाया में चाँद, चाँदनी, सितारों की चमक, उन्मुक्त विहंगों के कसरव का रसास्वादन करते हुए प्रकृति के स्पन्दन में परमात्मा के अंश का संचार नहीं देख



इसका स्पष्टीकरण करते हुए टैगोर ने प्रागे लिखा है : "घरेलू भाषा के घुँघट में छिपी हुई शिक्षा स्वभाव से ही हमारे हृदय की सहचरिनी होकर नहीं चल सकती है। यही कारण है कि हम में से अधिकांश व्यक्तियों को बिना शिक्षा प्राप्त है, उतना ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हमारे गृह तथा विद्यालय के मध्य द्राम प्रत्यवा पाँवगाड़ी चलती है, परन्तु हृदय नहीं चलता है। नोटबुकों के शासन से हम मुक्त नहीं हो पाये हैं। शिक्षा के साथ देश के हृदय का सर्व स्वाभाविक तादात्म्य कराने की तैयारियाँ आज तक नहीं की गई हैं।"

शिक्षा के प्रति स्वयं टैगोर का क्या दृष्टिकोण था, इसका आभास हमें उनका "मेरा विद्यालय" ( My School ) पढ़ कर हो जाता है। वे लिखते हैं :

"मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चों की भ्रष्ट-चेतन बुद्धि उनकी चेतन बुद्धि से अधिक शक्तिशाली होती है। हमारे सबसे महत्वपूर्ण पाठों की अधिक भाषा हमको इसके द्वारा सिखाई गई है। असंख्यों पीढ़ियों के अनुभव हमारे स्वभाव में इसके द्वारा धीरे-धीरे प्रवेश करा दिये गये हैं, और यह न बिना किसी प्रकार की थकान उत्पन्न किये, अपितु हमको आनन्द देकर। ज्ञान की यह स्वाभाविक मानसिक शक्ति हमारे जीवन का पूर्ण अङ्ग हो जाती है। यह एक लालटेन के समान नहीं है, जो बाहर से जलाई जा सकती है और जिसकी बत्ती बाहर से काटी जा सकती है, पर यह जुगनू के प्रकाश के समान है, जिसे वह अपने जीवन-क्रम के कारण रखता है।

"हम इस संसार में भाये हैं, इसे भपनाने के लिये, केवल इसे जानने के लिये नहीं। हम ज्ञान से शक्ति भले ही प्राप्त कर लें, परन्तु हम में परिपूर्णता आनुभूति से ही आ सकती है। अष्टतम शिक्षा वह है, जो हमें सूचना का संसार न बनाकर, हमारे जीवन एवं स्थिति को एकलपता प्रदान करती है।

"स्कूलों में आनुभूति की शिक्षा की व्यवस्थित रूप से उपेक्षा ही नहीं की जाती है, बल्कि उसका कठोरतापूर्वक दमन भी किया जाता है। हम भूगोल की शिक्षा देने के लिये बालक को मिट्टी से दूर हटाते हैं, व्याकरण की शिक्षा देने के लिये उसकी भाषा को उससे छीनते हैं। बालक का स्वभाव अपनी सम्पूर्ण संस्था का विरोध करता है, परन्तु अन्त में दण्ड के भय से चुप

के लिये

पड़ेगा।

शिक्षा-प्रणाली

बालकों की नसों

करते हुए टैगोर ने लिखा है : "हम लोग

के समान कक्षा में बैठे रहते थे

बर्षा की जाती

सहकारिता, स्वयं-शासन, सामूहिक जीवन, स्वतंत्रता, धानन्दानुभूति, प्रकृति से सम्पर्क, पारस्परिक सहभावना और छात्रों तथा अध्यापकों की निकटता पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे छात्रों में मानवता का उचित रूप में विकास हो सके। इस विद्यालय में साहित्यिक, सामाजिक, हस्तशिल्प, कला, और संगीत से सम्बन्धित कार्यक्रमों की उत्तम व्यवस्था है। फलस्वरूप छात्रों को भाषा-प्रतिभाषित एवं भाष्य-प्रकाशन का अवसर प्राप्त होता है। वस्तुतः इस विद्यालय में छात्रों की सात्विक अनुभव प्राप्त होता है।

२. शिक्षा-भवन—यह एक कॉलेज है, जिसमें उच्च शिक्षा दी जाती है। इसमें इन्टर पार्ट्स और साइन्स की शिक्षा की व्यवस्था है।

३. विद्या-भवन—यह स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा का कॉलेज है। इसमें विद्यापियों के लिये बी० ए०, एम० ए० और पी० एच०डी० की शिक्षा का प्रवर्ण है। इसमें अनुसंधान-कार्य की भी सुविधा है। अनुसन्धान-कार्य भारतीय दर्शन, बौद्ध धर्म और हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, उर्दू, फारसी, अरबी, बंगला आदि भारतीय भाषाओं पर किया जाता है। विद्या-भवन की स्थापना १९१८ में की गई थी।

४. कला-भवन—इसमें तलित कलाओं, विशेष रूप से चित्र-कला और शिल्प-कला की शिक्षा दी जाती है। इनके प्रतिरिक्त काठना, पिरोना, बुनना, धपड़े का काम, आदि कलाएँ सिखाई जाती हैं। इसमें अध्ययन करने वाले छात्र 'क्राइन पार्ट एन्ड क्राफ्ट' में डिप्लोमा तथा सार्टीफिकेट की परीक्षाएँ देते हैं। यह भवन १९१९ में स्थापित किया गया था।

५. ग्रन्थ भवन—यहाँ विभिन्न प्रकार के कुटीर-उद्योगों तथा हस्त-कौशलों की शिक्षा दी जाती है और 'डिप्लोमा कोर्स' की परीक्षाएँ ली जाती हैं। इसकी स्थापना १९२१ में हुई थी।

६. संगीत-भवन—इसमें संगीत, नृत्य एवं अभिनय की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है।

७. चीन-भवन—इसमें भारतीय छात्रों को चीन की संस्कृति और चीन के छात्रों को भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

८. विनय-भवन—यह अध्यापकों के प्रशिक्षण का कॉलेज है। इसमें बी० एड० की डिग्री प्रदान की जाती है।

९. कीनिफेक्शन—यहाँ छात्रों में धर्मों का पुनर्संज्ञकन करने के कार्य में अभिरुचि उत्पन्न की जाती है। इसके उद्देश्य सभोक्तित्व हैं।

## विश्व-भारती के उद्देश्य

विश्व-भारती की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई है:

1. विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किये गये सत्य के विभिन्न रूपों के ज्ञान के उद्देश्य से मानव-मस्तिष्क का अध्ययन करना।
2. प्राच्य संस्कृतियों में मानवस्य स्थापित करके उनमें घनिष्टता उत्पन्न करना।
3. पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का समरूप अध्ययन करना।
4. एशिया में व्याप्त जीवन-दर्शन एवं एशियाई विचार को दृष्टिकोण में रखकर पाश्चात्य देशों से सम्पर्क बढ़ाना।
5. पूर्व तथा पश्चिम में निकट सम्पर्क स्थापित करके विश्वदान्ति की दशाओं को जन्म देना।
6. मह-बन्धुत्व की भावना का विकास करके पूर्व और पश्चिम के देशों को एकता के सूत्र में प्रारब्ध करना।
7. पूर्व और पश्चिम के विचारों के आदान-प्रदान द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे विश्व-बन्धुत्व को सम्भव हो सके।
8. इन आदर्शों को दृष्टिकोण में रखते हुए विश्व-भारती में एक ऐसे सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करना जहाँ धर्म, साहित्य, विज्ञान, इतिहास, एवं हिन्दू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, और अन्य सम्प्रदायों की कला को खोज तथा अध्ययन किया जा सके, जहाँ इन कलाओं का पश्चिमी देशों की कलाओं से सामंजस्य स्थापित किया जा सके, जहाँ उपयुक्त वातावरण में रह कर विभिन्न दार्शनिकों तथा विचारकों में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया जा सके और जहाँ मानव को ब्रह्म की अनुभूति कराके पूर्णता की ओर ले जाया जा सके।

इन श्रेष्ठ आदर्शों, दार्शनिक विचारों और उच्च उद्देश्यों की पृष्ठ-भूमि में विश्वभारती का सिलान्यास किया गया था।

## विश्वभारती की संस्थाएँ

विश्वभारती विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षण संस्थाएँ हैं :

1. पय-भवन—यह अपने ढंग का एक प्रगतिशील विद्यालय है। इसमें प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें अध्ययन करने वाले छात्रों की प्राप्ति साधारणतः ६ वर्ष से १६ वर्ष तक की होती है। इस विद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान के विस्तार के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसमें सहयोग,

सहकारिता, स्वयं-शासन, सामूहिक जीवन, स्वतंत्रता, ध्यानानुभूति, प्रकृति से सम्पर्क, पारस्परिक सद्भावना और छात्रों तथा अध्यापकों की निकटता पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे छात्रों में मानवता का उचित रूप में विकास हो सके। इस विद्यालय में साहित्यिक, सामाजिक, हस्तशिल्प, कला, और संगीत से सम्बन्धित कार्यक्रमों की उत्तम व्यवस्था है। फलस्वरूप छात्रों को आत्म-प्रतिबिम्बित एवं आत्म-प्रकाशन का अवसर प्राप्त होता है। वस्तुतः इस विद्यालय में छात्रों को सात्विक अनुभव प्राप्त होता है।

२. शिक्षा-भवन—यह एक कॉलेज है, जिसमें उच्च शिक्षा दी जाती है। इसमें इंटर पार्ट्स और साइन्स की शिक्षा की व्यवस्था है।

३. विद्या-भवन—यह स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा का कॉलेज है। इसमें विद्यापियों के लिये बी० ए०, एम० ए० और पी० एच०डी० की शिक्षा का प्रबन्ध है। इसमें अनुसंधान-कार्य की भी सुविधा है। अनुसंधान-कार्य भारतीय दर्शन, बौद्ध धर्म और हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, उर्दू, पंजाबी, मराठी, बंगला आदि भारतीय भाषाओं पर किया जाता है। विद्या-भवन की स्थापना १९१८ में की गई थी।

४. कला-भवन—इसमें ललित कलाओं, विशेष रूप से चित्र-कला और शिल्प-कला की शिक्षा दी जाती है। इनके प्रतिरिक्त काढ़ना, पिरोना, बुनना, चमड़े का काम, आदि कलाएँ सिखाई जाती हैं। इसमें अध्ययन करने वाले छात्र 'फ्राइन आर्ट एंड फ़ाउण्ड' में डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेट की परीक्षाएँ देते हैं। यह भवन १९१९ में स्थापित किया गया था।

५. शिल्प-भवन—यहाँ विभिन्न प्रकार के कुटीर-उद्योगों तथा हस्त-कीमती की शिक्षा दी जाती है और 'डिप्लोमा कोर्स' की परीक्षाएँ ली जाती हैं। इसकी स्थापना १९२१ में हुई थी।

६. संगीत-भवन—इनमें संगीत, नृत्य एवं अभिनय की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है।

७. चीन-भवन—इसमें भारतीय छात्रों को चीन की संस्कृति और चीन के छात्रों को भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

८. विनय-भवन—यह अध्यापकों के प्रशिक्षण का कॉलेज है। इसमें बी० एड० की डिग्री प्रदान की जाती है।

१९२४

मे धर्मों का पुनर्संज्ञान करने के कार्य में उद्देश्य अभिविहित है:

१. ग्रामों की समस्याओं का अध्ययन करना और देश की जनता को सचेत प्रति जागरूक करना ।
  २. ग्रामी की समस्याओं का समाधान करने में ग्राम-निवासियों की सहूलता करना और इस प्रकार उनके स्नेह, सहानुभूति और भिन्नता को दूर करना ।
  ३. ग्राम-निवासियों के समस्त स्वास्थ्य, सफाई तथा सहकारिता के कार्यों को प्रस्तुत करना और उन्हें कृषि की उत्तम विधियाँ तथा कुटीर-उद्योग धर्मों की शिक्षा देकर उनके जीवन को अधिक सुगम तथा स्वस्थ करना ।
  ४. स्कूलों के छात्रों तथा प्रशिक्षण के माध्यम पर ग्रामों में शैक्षणिक शिक्षा की सुविधाओं को उत्तम बनाना और ग्राम निवासियों को उत्तम नागरिकता के लाभ बताना ।
  ५. शिक्षालय के छात्रों में ग्रामों के प्रति सेवा तथा सहानुभूति की भावना को उत्पन्न करना और उन्हें कृषि, पशु-पालन, दुग्ध-शाला, मृगी-पालन, कटाई, बुनाई, सुहार का काम, बड़ई का काम, चमड़े का काम आदि विषयों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना ।
- उपयुक्त के प्रतिरिक्त विश्वभारती में 'हिन्दी भवन' तथा 'इस्लामी प्रमुख-भवन' भी हैं ।

### विश्व-भारती के विभाग

विश्व-भारती में निम्नांकित विभाग हैं:—

१. कृषि-विभाग—यह विभाग कृषि की वैज्ञानिक तथा उन्नत विधियों की प्रदर्शन द्वारा शिक्षा प्रदान करता है । इस विभाग से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र कृषि को अपना व्यवसाय बनाते हैं ।
२. दुग्धशाला-विभाग—यह विभाग विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये शुद्ध दूध और ताजा भक्षण की व्यवस्था करता है । यह पशु-प्रजनन तथा पशु-पालन की आधुनिकतम विधियों का प्रचार करता है ।
३. कुटीर-उद्योग विभाग—इस विभाग में कुटीर उद्योग-धर्मों का कार्य सिखाया जाता है । प्रमुख कुटीर उद्योग हैं—कटाई, बुनाई, चमड़े का काम लकड़ी का काम, बर्तन बनाने का काम, लाख का काम और जिल्दसाजी ।
४. ग्राम-कल्याण विभाग—इसके द्वारा ग्रामवासियों के लाभ के लिये सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है । यह विभाग ग्रामीण जनता को भौतिकालय, रात्रि-पाठशालाओं एवं सचल पुस्तकालय की भी सुविधा प्रदान करता है ।

१. पुस्तकालय विभाग—विश्वभारती में विभिन्न संस्थाओं के लिये विभिन्न विभागीय पुस्तकालय हैं। एक केन्द्रीय पुस्तकालय भी है जिसमें विभिन्न भाषाओं तथा विषयों की लगभग डेढ़ लाख हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है।

### विश्वभारती का कार्यक्रम

विश्वभारती का कार्यक्रम अधोलिखित है :

नागरण	४.३० बजे प्रातः
भाषास भाङना	४.५०
शारीरिक व्यायाम	४.५५
स्नान	५.३०
कलेवा	५.५५
उपासना	६.१५
पठन-पाठन	६.३०—१०.३०
प्रक्षालन	१०.३०
मध्याह्न-भाहार	१०.५०
मध्याह्न विधाम	१२.१५
व्यक्तिगत शिक्षण	१.५—२
पठन-पाठन	२—४
भाषास शुद्धि	४.१५
जलपान	४.२५
उपस्थिति लेसन	४.४०
खेल-कूद	४.५५—५.५५
संध्या-प्रक्षालन	६ बजे सायं
उपासना	६.२०
अध्ययन एवं व्याख्यान	६.२०—७.४५
रात्रि-भोजन	८
विश्राम	९ बजे रात्रि

उपरिलिखित कार्यक्रम किस प्रकार चलाया जाता है, इसका विस्तृत वर्णन करते हुए भारत-स्थिति भ्रमरीकी राजदूत बेस्टर बोल्स की पुत्री लिविया बोल्स ने अपनी पुस्तक "भारत मेरा घर" में लिखा है : "लगभग ६ बजे प्रातःकाल हम बड़े से भोजन-कक्ष में कलेवा करते थे। नीची-नीची लकड़ी के मेजों के सामने हम पल्लवी बेंचों पर बैठते थे। कलेवे में कोको के साथ ताजा



वास है। छात्रों एवं छात्राओं के लिये घलग-घलग छात्रावास बने हुए हैं। सभी छात्रावासों में रहने वाले बालकों तथा बालिकाओं के आराम, भोजन तथा स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखा जाता है।

**कक्षाएँ**—विश्वभारती में सामान्य विश्वविद्यालयों के समान दीवारों से घिरी हुई कक्षाएँ नहीं हैं। विद्याभ्यसन खुले मैदान में या वृक्षों के नीचे किया जाता है। यदि विद्यार्थी चाहता है, तो वह वृक्षों की छातियों में भी बैठ कर पढ़ सकता है। वहाँ शिक्षक किस प्रकार अध्यापन कार्य करते हैं और छात्र किस प्रकार विद्या का धर्जन करते हैं, इसका आभास हमें 'मेरा विद्यालय' में स्वयं टेंगोर के वर्णन से प्राप्त होता है। सतीशचन्द्र राय नामक एक शिक्षक के सम्बन्ध में लिखते हुए, वे कहते हैं : "उसके साथ छात्रों ने इस बात का कभी अनुभव नहीं किया कि वे एक पढ़ाने वाली कक्षा की सीमा के अन्दर बन्द थे। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि उनको पढ़ैव सब स्थानों पर था। जब वसन्त ऋतु में खान के वृक्ष पूर्णतया फूलों से सज जाते थे, तब वे उसके साथ जंगल को जाते थे, और वहाँ वह भावना से उन्मत्त होकर उनको अपनी जुनो हुई कविताएँ सुनाता था। वह उनके सामने शेक्सपीयर (Shakespeare) और ब्राउनिंग (Browning) की कविताएँ पढ़ा करता था; और अपनी बोलने की आश्चर्यजनक शक्ति से उनको बंगला में समझाता था। वह बालकों की समझने की शक्ति में कभी भविष्यवासी नहीं करता था। वह जानता था कि बालकों के लिये असरदा: और ठीक-ठीक समझना बिल्कुल आवश्यक नहीं था, अपितु यह कि उनके मस्तिष्क को जागृत करना चाहिये। वह अन्य शिक्षकों के समान केवल पाठ्य-पुस्तकों में लिखी बातें पढ़ाने वाला नहीं था। वह अपनी शिक्षा को व्यक्तिगत बनाता था; वह स्वयं उसका स्रोत था, और इसलिए उसकी शिक्षा में जीवन से सम्बन्धित वे बातें होती थीं, जो जीवित मानव-स्वभाव द्वारा सरलता पूर्वक समझी जा सकती हैं।"

**पाठ्य-क्रम**—विश्वभारती का पाठ्य-क्रम प्रति विस्तृत रखा गया है। उसमें सामान्य विषयों के अतिरिक्त, जिनकी शिक्षा भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में दी जाती है, संगीत, नृत्य, शिल्प, चित्रकला आदि का समावेश किया गया है। ऐसा करने का अभिप्राय केवल यह है कि छात्र अपनी अभियोग्यताओं तथा अभिरुचियों के समान विषयों का अध्ययन कर सकें जिससे कि उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो।

**सामूहिक जीवन**—विश्वभारती में सामूहिक जीवन पर विशेष बल दिया जाता है। वे साथ-साथ खाते, खेलते और पर्यटन करते हैं। सामूहिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिये अभिनय, गीतियों आदि भी व्यवस्था की गई है।



मक्खन लगी हुई रोटियाँ, जिन पर शक्कर बुरकी हुई होती थी या पूरियाँ एक हरी सन्जी मिलती थी। रोज कलेवे के बाद एक छोटी सी गायन-प्रार्थना सभा होती थी। छात्रों के अलग-अलग दल एक सप्ताह उसका नेतृत्व किया करते थे। प्रार्थना चुप-चाप होती थी और टैगोर के लिखे गीत गाये जाते थे। भोजन के बाद दो-तीन घण्टे आराम और पढ़ने का समय होता था। तीसरे पहर फिर कलासों होती थीं। कलासों के बाद दो घण्टे खेल होते थे। सात बजे शाम हजारी के लिये छात्रावास पहुँचना पड़ता था। उसके बाद हम पढ़ते थे या नृत्य और वाद्य-वादन का अभ्यास करते थे या लेक्चर, सभा, नाटक आदि देखने जाते थे। लगभग ८-३० पर भोजन होता था। बुधवार को शान्तिनिकेतन में साप्ताहिक छुट्टी रहती थी।”

**विश्वभारती का विवरण एवं विशेषतायें**  
प्रवेश एवं अध्ययन की सुविधायें—विश्वभारती साक्षात् एवं सह-शिक्षा की संस्था है, और यहाँ न केवल भारत के अपितु सुदूर एशिया तथा यूरोप से भी छात्र एवं छात्रायें अध्ययन करने आते हैं। इस विश्वविद्यालय में भारत के सभी भागों के शिक्षक हैं। यहाँ के विद्यापियों को एक विशेष सुविधा यह है कि वे विश्वविद्यालय की एक शिक्षण-संस्था में प्रवेश लेकर अन्य संस्थाओं के विद्याल से लाभ उठा सकते हैं और उन्हें इसके लिये कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। परन्तु इस सुविधा से वे ही छात्र लाभ उठा सकते हैं जो अन्य शिक्षा-संस्थाओं के अध्यापन के विषयों में विशेष रुचिका प्रमाण दें। विश्वभारती नियमित और आकस्मिक (Regular and Casual) दोनों प्रकार के छात्रों को प्रवेश देता है और इनका शिक्षण योग्य अध्यापकों के द्वारा किया जाता है।

**शिक्षकों तथा छात्रों के सम्बन्ध—**प्राचीन भारत में गुरु एवं शिष्य में घनिष्ठ सम्बन्ध था। कवि टैगोर ने विश्वभारती में इन परम्परा को पुनर्जीवित किया। वहाँ शिक्षकों तथा छात्रों में घनिष्ठ निकट सम्बन्ध है। उनमें परस्पर स्नेह और सहोदाय्य की भावना पाई जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का विद्यापियों पर उच्च प्रकार अधिकार है जैसा कि मात-पिता को अपने बालकों पर होता है। इस अनिच्छा के साथ साथ कवि ने पश्चिमी स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों का लाभ-लाभ स्थापित करने का प्रयास किया है।

**छात्रावास—**विश्वभारती विश्वविद्यालय में विभिन्न जातु के छात्रों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था है। प्रारम्भिक कक्षाओं के छात्रों के लिये, उच्च गणित के लिये तथा अनुशासन करने वाले छात्रों के लिये पृथक्-पृथक् छात्रा-

ख है। छात्रों एवं छात्राओं के लिये अलग-अलग छात्रावास बने हुए हैं। सभी छात्रावासों में रहने वाले बालकों तथा बालिकाओं के आचरण, भोजन तथा आस्व्य का पूर्ण ध्यान रखा जाता है।

**कलाएँ—**विश्वभारती में सामान्य विश्वविद्यालयों के समान दीवारों से ढकी हुई कलाएँ नहीं हैं। विद्याभ्यसन सुले मैदान में या वृक्षों के नीचे किया जाता है। यदि विद्यापी चाहता है, तो वह वृक्षों की छाँटियों में भी बैठ कर पढ़ सकता है। वहीं शिक्षक किस प्रकार प्रशिक्षण कार्य करते हैं और छात्र किस प्रकार विद्या का अध्ययन करते हैं, इसका आभास हमें 'मेरा विद्यालय' में एवं टैगोर के वर्णन से प्राप्त होता है। सतीशचन्द्र राय नामक एक शिक्षक के स्मरण में लिखते हुए, वे कहते हैं : "उसके साथ छात्रों ने इस बात का कभी अनुभव नहीं किया कि वे एक पढ़ाने वाली कक्षा की सीमा के अन्दर अन्दर थे। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि उनकी पहुँच सब स्थानों पर थी। जब वसन्त ऋतु में खान के वृक्ष पूर्णतया फूलों से लदे जाते थे, तब वे उसके साथ जंगल में जाते थे, और वहाँ वह भावना से उत्पन्न होकर उनकी अपनी चुनौती हुई कविताएँ सुनाता था। वह उनके सामने शेक्सपियर (Shakespeare) और ब्राउनिंग (Browning) की कविताएँ पढ़ा करता था; और अपनी गीतों की धाराधर्यजनक दृष्टि से उनको बगला में समझाता था। वह बालकों से समझने की दृष्टि में कभी प्रविष्टि नहीं करता था। वह जानता था कि बालकों के लिये अक्षरजः और ठीक-ठीक समझना बिल्कुल आवश्यक नहीं था, बल्कि यह कि उनके मस्तिष्क को जागृत करना चाहिये। वह अन्य शिक्षकों के समान केवल पाठ्य-पुस्तकों में लिखी बातें पढ़ाने वाला नहीं था। वह अपनी शिक्षा को व्यक्तिगत बनाता था; वह स्वयं उसका स्रोत था, और इसलिए उसकी शिक्षा में जीवन से सम्बन्धित वे बातें होती थीं, जो जीवित मानव-जगत् द्वारा सरलता पूर्वक समझी जा सकती हैं।"

**पाठ्य-क्रम—**विश्वभारती का पाठ्य-क्रम प्रति विस्तृत रखा गया है। उसमें सामान्य विषयों के प्रतिरिक्त, जिनकी शिक्षा भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में भी जाती है, संगीत, नृत्य, शिल्प, चित्रकला आदि का समावेश किया गया है। ऐसा करने का प्रथमप्रायः केवल यह है कि छात्र अपनी अभियोग्यताओं तथा अभिरुचियों के समान विषयों का अध्ययन कर सकें जिससे कि उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो।

**सामूहिक जीवन—**विश्वभारती में सामूहिक जीवन पर विशेष बल दिया जाता है। वे साथ-साथ खाते, खेलते और पर्यटन करते हैं। सामूहिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिये प्रतिस्पर्धा, गोष्ठियों आदि की व्यवस्था की गई है।

इसी उद्देश्य से प्रत्येक छात्र को प्रार्थना में भाग लेने के लिये कहा जाता है। परन्तु किसी भी विद्यार्थी को भगवान् का ध्यान करने के लिये बाध्य नहीं किया जाता है। उसको यह अवश्य सिखाया जाता है कि वह धान्त रहे, जिससे दूसरों के ध्यान में बाधा न उत्पन्न हो।

समाज-सेवा—विश्वभारती में छात्रों में समाज-सेवा की भावना को विकसित किया जाता है। वहाँ के छात्र निर्बल, रोगी तथा दुखी विद्यार्थियों को देख-भाल करते हैं। इसके प्रतिरिक्त वे सभीपवर्ती ग्रामों में निवास करने वाले व्यक्तियों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं और निराश्रित जनों के हृदयों में आशा का संचार करते हैं।

ग्रन्थ विशेषतायें—विश्वभारती में विद्यार्थियों के अपने डेरी-क्वार्टर्स, प्रयोगशाला, मन्दिर और कारखाने हैं। वहाँ १९२२ में विश्वभारती मुद्राणालय की स्थापना हुई, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय अपने मुद्रण का कार्य स्वयं कर रहा है। विश्वभारती टैगोर के निचारों का प्रचार करने के लिये दो पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है; एक ग्रंथजो की ओर एक हिन्दी की—विश्वभारती क्वार्टरली और विश्वभारती पत्रिका। वहाँ के हिन्दी-भवन का शिलान्यास जनवरी, १९३७ में सी० एफ० एण्ड्रयूज (C. F. Andrews) ने किया था। विश्वविद्यालय में उद्योग-धंधों से सम्बन्धित शिक्षा भी दी जाती है। कपड़ा बुनने के कार्य भी हैं। पुस्तकालय में ग्रंथस्य पुस्तकें हैं। फल एवं जमनी ने पुस्तकें भेंट की हैं। विभिन्न लेखक अपनी पुस्तकें वहाँ भेजते हैं। वहाँ के छात्रों को ग्राम-उत्थान के लिये कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। वे ग्रामों में जाकर धान-उत्थान के हरिजनों के लिये कंधायें चलाते हैं। विश्वभारती में विद्यार्थियों के अपने व्याख्यान हैं। वे ही दण्ड देते हैं, पर शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता है।

### उपसंहार

स्वतन्त्र भारत में विश्वभारती ही ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय था, जिसका अपना स्वयं का प्रादर्श एवं विचार था। आज भी यह अपने ढंग का एक निराशा शिक्षा-केन्द्र है। यह वास्तव में एक स्वयं-शासित संस्था है। जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर कबीन्द्र रवीन्द्र ने इस सरस्वती-मन्दिर की आधार-शिला रखी थी, वे आज भी वहाँ के वातावरण में दृष्टिगत होते हैं। यद्यपि विश्वभारती टैगोर के संरक्षण से वकित हो चुका है, परन्तु उनके व्यक्तित्व की छाप उस पर लगी हुई है। उस संस्था की भूमि पर वसार्ण करने वाले व्यक्तियों को उनकी यत्नात उत्पत्ति का अनुभव होता है और वहाँ के काव्य-मय जीवन से उनकी संगीतपूर्ण कविताओं की अनुभूति होती है। विश्व के

भौतिक कोलाहल से दूर अन्तर्राष्ट्रीय बंधुत्व के संदेश को प्रसारित करता हुआ सरस्वती का यह पावन मन्दिर मानव-सम्पत्ता के उन्नयन में अपूर्व योग प्रदान कर रहा है। प्राच्य एवं पश्चात्य संस्कृतियों का यह संगम-स्थल विश्व को सत्य की दिशा में अग्रसर होने के किये प्रेरणा दे रहा है। भारतीय शिक्षा-परम्पराओं का पोषक बनकर भी यह आधुनिकतम अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मंजा प्राप्त करने का अधिकारी है।

किन्तु खेद है कि विश्व-बन्धुत्व एवं प्राच्य और पश्चात्य संस्कृतियों के संतुलित संपिप्पल के रूप में यह विश्वविद्यालय उस सत्य को प्राप्त नहीं कर पाया है और सम्भवतः प्राप्त नहीं कर पायेगा, जिससे प्रेरित होकर कवि सम्राट् टैगोर ने इसकी आधारशिला रखी थी। कारण यह है कि सरकार द्वारा समर्पित बन कर इसका शिक्षण एवं पाठ्य-क्रम बहुत कुछ अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के समान हो गया है और इसका लक्ष्य नवीन पाठ्य-क्रम का पूरा करना हो गया है। स्पष्ट रूप से मानास होने लगा है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य की अधोनता में यह अपने सांस्कृतिक उद्देश्य को पूर्ति में सफल न हो सकेगा।

### ३. अरविन्द-आश्रम

भारत के मुद्दर घटीत में आध्यात्मिक एवं सात्विक आदर्शों पर आधारित एक महान् संस्कृति का निर्माण किया। देश की पावन भूमि पर जन्म लेने वाले अधियों-मुनियों ने इस संस्कृति के पथ को प्रशस्त बनाकर उसकी प्रगति में योग प्रदान किया है। इन्हीं के सतत प्रयास के फलस्वरूप आज भारतीय संस्कृति को मानव-वाद का आधार स्वीकार किया जाता है। श्री अरविन्द योग की भी इन्हीं महात्माओं में गणना है।

#### श्री अरविन्द योग

श्री अरविन्द का जन्म १८७२ में कलकत्ता में एक धनी बंगाली परिवार में हुआ था। प्रारम्भ से ही उनको सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षा दी गई। पाँच वर्ष की आयु में उन्हें वारजिलिंग के एक इंगलिश स्कूल में विद्याभ्ययन के लिए भेज दिया गया। दो वर्ष उपरान्त उन्हें ज्ञान का अर्जन करने के लिये इंग्लैण्ड को खाना कर दिया गया। वहाँ उन्होंने सेण्ट पॉल स्कूल और केम्ब्रिज विश्व-विद्यालय में अध्ययन किया। सोढ़ वर्ष तक पश्चात्य सम्पत्ता तथा संस्कृति के मध्य में जीवन व्यतीत करने के कारण वे पश्चात्य परम्पराओं से पूर्णतया



कर जीवन का महान् उन्नयन करने वाला विचार और मानव-जीवन का घोषित अन्तिम सत्य बताया गया है। यह समस्त विचार का सार और समस्त धर्म का आधार है। ये सब बातें भारतीय सभ्यता को आध्यात्मिक संस्कृति के सर्वोच्च स्थान पर प्रसीन कर देती हैं। यह सत्य भारतीय विचार की विशेषता नहीं है। सर्वत्र इसे देखा गया है और इसका अनुसरण किया गया है, परन्तु जब कि अन्य देशों में यह केवल कुछ ही विचारकों का वास्तविक पथ-प्रदर्शक रहा है, भारत में यह सर्व-साधारण का पथ-प्रदर्शक रहा है। भारतीय संस्कृति ने सत्य की अपनी निरन्तर खोज से वह कार्य करने में सफलता प्राप्त की है, जो किसी अन्य संस्कृति द्वारा नहीं प्राप्त की गई है। इसी बात में सत्ता की अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता है। इसने धर्म पर वास्तविक आध्यात्मिकता के आदर्श की व्याप लगा दी है। यह कहना ही बिल्कुल प्रसन्न है कि भारत के सामान्य धार्मिक व्यक्ति ने भारतीय धर्म को उच्चतम आध्यात्मिक प्रपञ्च आत्मविद्या के सत्यों को नहीं समझा है। इसके विपरीत, भारतीय दर्शन के प्रमुख आध्यात्मिक सत्य, धर्मियों के सामान्य भस्तिष्क पर प्रकट कर दिये गये हैं। माया, लोला आत्मा की प्रसरता और भौतिक वस्तुओं की निरर्थकता के विचारों से सामान्य मनुष्य और मन्दिर के उपासक उठने हैं परिचित हैं, जितना कि एकान्त में रहने वाला दार्शनिक, अपने मठ में रहने वाला साधु और अपने कुटी में रहने वाला सन्यासी।

भारतीय धर्मों के सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए श्री आर्यभट्ट ने लिखा है कि समस्त भारतीय धर्मों का एक सामान्य आधारभूत विचार है। ये सब एक सर्वोच्च प्राणी प्रपञ्च ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं वह भस्तिष्क, जीवन और शरीर से परे है। वह पूर्ण और अनन्त है। वह एक जीवित आध्यात्मिक सत्य, एक सत्ता, एक शक्ति और एक वास्तविकता है अपनी योग्यता की मात्रा के अनुसार सभी व्यक्ति उसकी खोज कर सकते हैं उसे जीवन में और जीवन के उपरान्त अपने-अपने विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। उस सर्वोच्च शक्ति को जानना और उसकी खोज करना भारतीय धर्म

1. "The ideas *Maya, Lila*, divine Immanence are as familiar to the man in the street and the worshipper in the temple as to the philosopher in his seclusion, the monk in monastery and the saint in his hermitage. The spiritual reality which they reflect, the profound experience which they point has permeated the religion, the literature, the art, even the popular religious songs of a whole people."—Sri Aurobindo : *The Unity of Indian Religion*



यह शिक्षा जीवन एवं मानव-जाति के मन तथा आत्मा से और उस समस्त मानवता के मन तथा आत्मा से जिसका कि वह एक अंश है, सत्य सम्बन्ध की स्थापना में सहायता देती है ।”

श्री धरविन्द के मतानुसार अन्तःकरण अथवा मानस शिक्षा का प्रमुख अंग है । उन्होंने अन्तःकरण के चार स्तर बताये हैं :—चित्त, मनस, बुद्धि तथा ज्ञान । उनके विचारानुसार मानव की इन शक्तियों में क्रमिक विकास होता रहा है । अतः शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये कि वह इन शक्तियों को विकसित कर सके । केवल ज्ञान की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है । सच्ची शिक्षा यही है जिसमें मानव का पूर्ण विकास करने की क्षमता हो ।

- मानव का पूर्ण विकास क्या है ? इस सम्बन्ध में श्री धरविन्द के विचार निम्नांकित हैं :

१. मानव का प्राध्यात्मिक विकास करके उसमें दिव्यता को कुसमित करना ।
२. मानव की समस्त व्यक्तिगत क्षमताओं एवं विलक्षणताओं को विकसित करके उसमें दिव्य प्रकाश भरना और उसे मानव के स्तर से ऊँचा उठाकर दिव्य पुरुष बनाना ।
३. मानव में अन्तर्निहित प्रेम, प्रतिभा एवं सार्वभौमिकता को विकसित करके उसे सृष्टि के सम्पूर्ण सौन्दर्य तथा आनन्द को अनुभूति कराना ।

श्री धरविन्द ने अपनी शिक्षा में किसी ऐसे विषय की उपेक्षा नहीं की, जिसमें धार्मिक अभिव्यक्ति तथा जीवन की क्रियाशीलता के गुण विद्यमान थे । यही कारण है कि उनकी शिक्षा में राजनीति, समाज, व्यापार, साहित्य, कविता, वास्तु-कला और मूर्ति-कला को उचित स्थान प्रदान किया गया । उनका एकमात्र उद्देश्य था, इन सभी विषयों में जीवन का नया संचार करके उनको एक नवीन रूप प्रदान करना । वे इनको इतना अधिक विकसित कर देना चाहते थे कि उनके माध्यम से अर्ध-मानवता तथा आत्मा की पूर्णता का प्रकाश बिल्कुल स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो सके । इस प्रकार उनकी शिक्षा का परम लक्ष्य सम्पूर्ण मानव-जाति का सर्वांगीण विकास करके प्राध्यात्मिक आचार पर विश्व के समस्त राष्ट्रों की स्थापना करना था ।

श्री धरविन्द का कथन था कि शिक्षा में बालक पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये, बल्कि उसे पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहने देना चाहिये । उनका विश्वास था कि शिक्षा का बालक के स्वभाव के अनुकूल होना आवश्यक है । बालक एक जड़ पदार्थ नहीं है जिसे शिक्षक बिधर भी बाँध ले जाय । वह सभी व्यक्तियों के समान एक स्वयं-विकसित होने वाला प्राणी है । अतः





यह शिक्षा जीवन एवं मानव-जाति के मन तथा आत्मा से और उस समस्त मानवता के मन तथा आत्मा से जिसका कि वह एक घस है, सत्य सम्बन्ध की स्थापना में सहायता देती है ।”

श्री भरविन्द के मतानुसार भन्तःकरण भयवा मानस शिक्षा का प्रमुख अंग है । उन्होंने भन्तःकरण के चार स्तर बताये हैं :—चित्त, मनस, बुद्धि तथा ज्ञान । उनके विचारानुसार मानव की इन शक्तियों में क्रमिक विकास होता रहा है । भन्तः शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये कि वह इन शक्तियों को विकसित कर सके । केवल ज्ञान की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है । सभी शिक्षा वही है जिसमें मानव का पूर्ण विकास करने की क्षमता हो ।

मानव का पूर्ण विकास क्या है ? इस सम्बन्ध में श्री भरविन्द के विचार निम्नांकित हैं :

१. मानव का प्राध्यात्मिक विकास करके उसमें दिव्यता को कुसमित करना ।
२. मानव की समस्त व्यक्तिगत क्षमताओं एवं विलक्षणताओं को विकसित करके उसमें दिव्य प्रकाश भरना और उसे मानव के स्तर से ऊँचा उठाकर दिव्य पुरुष बनाना ।
३. मानव में भन्तर्निहित प्रेम, प्रतिभा एवं सार्वभौमिकता को विकसित करके उसे सृष्टि के सम्पूर्ण सौन्दर्य तथा आनन्द की अनुभूति कराना ।

श्री भरविन्द ने अपनी शिक्षा में किसी ऐसे विषय की उपेक्षा नहीं की, जिसमें शैक्षिक अभिव्यक्ति तथा जीवन की क्रियाशीलता के कुछ विद्यमान थे । यही कारण है कि उनकी शिक्षा में राजनीति, समाज, व्यापार, साहित्य, कविता, वास्तु-कला और मूर्ति-कला को उचित स्थान प्रदान किया गया । उनका एकमात्र उद्देश्य था, इन सभी विषयों में जीवन का नया संचार करके उनको एक नवीन रूप प्रदान करना । वे इनको इतना अधिक विकसित कर देना चाहते थे कि उनके माध्यम से थोड़े मानवता तथा आत्मा की पूर्णता का प्रकाश बिस्तृत स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो सके । इस प्रकार उनकी शिक्षा का प्रथम लक्ष्य सम्पूर्ण मानव-जाति का सर्वाङ्गीण विकास करके प्राध्यात्मिक प्राधान्य पर विश्व के समस्त राष्ट्रों की स्थापना करना था ।

श्री भरविन्द का कथन था कि शिक्षा में बालक पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया चाहिये, अपितु उसे पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रहने देना चाहिये उनका विश्वास था कि शिक्षा का बालक के स्वभाव के अनुकूल होना आवश्यक है । बालक एक जड़ पदार्थ नहीं है जिसे शिक्षक जिधर भी चाहे ले जाय । बालक एक स्वयं-विकसित होने वाला प्राणी है । भन्तः

माता-पिता और शिक्षक का कर्तव्य कि वे बालक को अपनी मानसिक, वैतिक और व्यावहारिक क्षक्तियों को स्वयं तथा स्वतन्त्र रूप में विकसित करने में सहायता दें।<sup>१</sup>

### श्री धरविन्द के शिक्षा-सिद्धान्त

श्री धरविन्द ने निम्नांकित मनोवैज्ञानिक शिक्षा-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया:

१. शिक्षा का माध्यम—शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा होनी चाहिये।

२. शारीरिक पुष्टि—शिक्षा प्राप्त करने वाले की शारीरिक पुष्टि के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये, क्योंकि शरीर के द्वारा ही मानव-धर्म तथा उसके समस्त उद्देश्यों की पूर्ति होती है और शरीर ही मानव को इसी जीवन एवं साम्प्रदायिक जीवन के स्तर पर पहुँच सकता है।

३. ज्ञानेन्द्रियों का विकास—बालकों की ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा (Training of the senses) पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिये। इस शिक्षा के साधन स्नायु-शुद्धि (Nerve purification) चित्त-शुद्धि एवं मानस-शुद्धि हैं, जो योग-साधन ही के रूप में हैं। इस प्रकार की नियमित शिक्षा प्रदान करके बालकों की ज्ञानेन्द्रियों का विकास किया जा सकता है।

४. मानसिक क्षमताओं का विकास—श्री धरविन्द ने मानसिक क्षमताओं के अन्तर्गत स्मृति, निर्णय-शक्ति, तर्क, कल्पना, चिन्तन आदि को स्थान दिया है। उनके मतानुसार बालकों की ज्ञानेन्द्रियों के विकास के पश्चात् उनकी मानसिक क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिये। इस विकास का आधार बालकों की अभिरूचियाँ होनी चाहिये। जब तक उनकी विभिन्न अभिरूचियों के अनुसार उनकी शिक्षा प्राप्त करने का व्यवस्था नहीं मिलेगा, तब तक उनकी मानसिक क्षमताओं का विकास नहीं होगा। यदि शिक्षा को बालकों की अभिरूचियों के अनुकूल बना दिया जाय, तो वह 'स्व-शिक्षा' (Self-Education) का रूप धारण करके बालकों का महान् हित कर सकती है।

५. स्व-शिक्षा की आवश्यकता—बालकों के लिए या पालन-द्वारा निर्वा-

1. "Each human being is a self-developing soul and the business of both parent and teacher is to help the child to educate himself, to develop his own intellectual, moral, aesthetic and practical capacities and to grow freely as an organic being, not to be kneaded and pressured into form like an inert plastic material." Sri Aurobinda

रित किया जाय, वह रोचक होना चाहिये। उसमें जिन विषयों को स्थान दिया जाय, उनमें बालकों को आकृष्ट करने की शक्ति होनी चाहिये। बालक इस प्रकार के विषयों का सलोनीता से अध्ययन करेंगे और फलस्वरूप उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करेंगे। शिक्षक का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह सर्व प्रथम जीवन, जीवन की क्रियाओं तथा विद्वद-ज्ञान में बालकों की रुचि उत्पन्न करे। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के पश्चात् ही वह बालकों के ज्ञान-प्राप्ति के साधनों का विकास करे और उन्हें भाषा का सम्पूर्ण ज्ञान कराये। इन परिस्थितियों में ज्ञान तथा अध्ययन की वृद्धि स्वतः ही तीव्र गति से होती चली जायेगी।

१. **अध्यापक का स्थान**—श्री धरविन्द के मतानुसार शिक्षा में अध्यापक को निर्देशक, पथ-प्रदर्शक और सहायक के रूप में कार्य करना चाहिये। वह भीन रूप से बालकों की अभिरूचियों का अध्ययन करके और उन अभिरूचियों के अनुसार बालकों के लिये शिक्षा की सामग्री का संकलन तथा प्रस्तुतिकरण करे। उसे स्वयं बालकों को ज्ञान देने का प्रयास नहीं करना चाहिये और न उन पर बाह्य ज्ञान को लादना ही चाहिये। उसे तो यह प्रयत्न करना चाहिये कि बालक अपनी अभिरूचियों के अनुसार ज्ञान का भर्जन करते हुए 'स्व शिक्षा' के पथ पर अग्रसर हों। इस प्रकार श्री धरविन्द ने अध्यापक की शिक्षा में गौण स्थान दिया है।

७. **बालक का स्थान**—श्री धरविन्द ने बालक को शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया है। उनके विचारानुसार बालक का विकास उसकी प्रकृति, अभिरूचि, स्वभाव तथा धर्म के अनुकूल ही किया जाना चाहिये। वह शिक्षा बालक के लिये निरर्थक है जो पूर्व निर्धारित गुणों, पाद्यों, मान्यताओं एवं विशेषताओं के अनुसार आयोजित की जाती है। कारण यह है कि प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत क्षमताएँ तथा विलक्षणताएँ होती हैं। यदि इनकी प्रवृत्ति करना करके एक पूर्व सूची के अनुसार बालकों में किन्हीं गुणों एवं पाद्यों को उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है, तो यह कार्य बालक के लिये अध्यापपूर्ण तथा अहितकर होता है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये—बालकों की अभियोग्यताओं, अभिरूचियों तथा अंतर्हित क्षमताओं की खोज करके उनको पूर्ण रूप से विकसित करना। यदि शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है, तो वह सच्ची शिक्षा कह जाने की अधिकारिणी नहीं है।

८. **अन्तःकरण का विकास**—श्री धरविन्द के मतानुसार अन्तःकरण अथवा मानस शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। अन्तःकरण के चार स्तर हैं : चित्त, मनस, बुद्धि तथा ज्ञान। 'चित्त' में मानव-जीवन के गते तथा वर्तमा

धनुष्यो का गन्ध होता है। सारा सारा म हन 'गन्ध' का 'सुन्धि' को कहते हैं। यिष्ठा एगी बानी बाहिज, विनक झाग घनःकरत की विगानाथी विनायोनता का विनयित तथा ममुप्रत बनाया आ मके। मनीविज्ञान के धनुषार 'मनस' आदि की घटी जानाग्रह है। यह सवाय करता है धीर बजाना, चिन्तन, मनस घादि का घाधार है। यिष्ठा प्रकार की होनी बाहिज विनय 'मनस' का विनयित करने की मायस्य है 'मनस' घनो विनायो को 'बुद्धि' द्वारा व्यापक करता है। उदाहरणार्थ—यिष्ठा धागोबना, व्याख्या, निर्णय, निरोधाल, निष्कर्ष, मायाव्योकरत घादि या गिक विनायो की घमिन्धित बुद्धि के द्वारा होती है। यिष्ठा का उद्देश्य विनायो को परिमावित करके गुण तथा माय कव प्रदान करना है। 'आमानव की वह दार्ति है जिसे हम साधारण सव्यो से दिव्य-दृष्टि घववा घन दृष्टि या सत्य का घान्तरिक द्यन कह सकते हैं। दान के विज्ञान में मानव का विकास हुआ है। घनः ज्ञान की विवर्धित करना भी विज्ञा न सक्य है। साराय म यिष्ठा का प्रमुत कर्तव्य मानव के घनःकरत का विकास करना है, क्योंकि इसका विकास करने से हमके भारों स्तरों—चित्त, मनस बुद्धि तथा ज्ञान का स्वयः ही विकास हो जायगा।

६. नैतिकता का विकास—धी घरविन्द का घन्तिम विज्ञा-विज्ञान यह है कि यिष्ठा की मानव की नैतिकता का विकास करना चाहिये। मनुष्य की नैतिकता से सम्बन्ध रखने वाली तीन मुख्य बातें हैं—उसकी प्रवृत्ति (Nature), उसकी घादतें (Habits), और उसकी भावनायें (Emotions)। यिष्ठा का उद्देश्य इन तीनों बातों को गुण तथा मुन्दर बनाकर मानव के हृदय का परिवर्तन करना है। हृदय-परिवर्तन का यह कार्य मोक्षिक विज्ञा तथा भाषणों के द्वारा सम्पन्न न किया जाकर केवल सुभाष (Suggestion) द्वारा ही किया जा सकता है। घम्यापक का कार्य बातको को प्रवक्ष तथा घप्रत्यक्ष रूप से सुभाष देना है। घतः घावश्यक है कि वह ऐसे घादतों का घनुसरण करे और ऐसा थोष्ठ जीवन घ्यतीत करे कि उसके घान प्रतिपल उससे प्रेरणा प्राप्त करके जीवन की उच्चतर घवस्थामो को प्राप्त होते रहें। भारत के प्राचीन गुरुभो का उदाहरण हमारे समक्ष है। यदि वर्तमान समय के शिक्षक उनके पद-चिन्हो का घनुगमन करें तो वे घति सरलता पूवक घपने छात्रो की नैतिकता को थोष्ठतर बनाने में योग प्रदान कर सकते हैं। परन्तु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके घतिरिक्त छात्रों के लिये सत्संग तथा घामिक विज्ञा की व्यवस्था भी करनी होगी। घामिक विज्ञा से धी घरविन्द का घभि-प्राय किसी विशेष घर्म पर आधारित संकीर्ण घामिक विज्ञा से न होकर,

पन्थ व्यक्तियों, सम्पूर्ण मानवजाति, देश, विश्व तथा सर्व व्यापक ईश्वर की सेवा में जीवन को समर्पित करना है।

### भरविन्द-माधम

भरविन्द उपरिलिखित आदर्शों तथा उद्देश्यों को साकार रूप प्रदान करने के लिये श्री भरविन्द ने १९१० में पांडेवेरी में एक 'आध्यात्मिक पुनर्जन्म केन्द्र' की स्थापना की, जो 'भरविन्द माधम' के नाम से प्रख्यात है। आरम्भ में आध्यात्म-वासियों की संख्या केवल ८ थी, परन्तु धीरे-धीरे इस संख्या में वृद्धि होती चली गई और वह १९२६ में ८०० हो गई। यद्यपि आध्यात्म-वासियों के बच्चों के लिये १९४० से शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई थी, तथापि इसको सुनिश्चित शिक्षा-संस्था की सजा नहीं प्रदान की जा सकती है। इस माधम के विकास में श्री रा. रिचर्ड नामक एक फ्रांसीसी महिला का विशेष हाथ रहा है। इन्हें 'दी मदर' (The Mother) कहा जाता है और ये यहाँ १९२० से हैं। वस्तुतः माधम को सुसंगठित तथा विकसित करने का ध्येय इन्हीं को प्राप्त है।

'भरविन्द माधम' सन्ध्यासियों का मठ नहीं है और न यहाँ रहने वाले येषमा येषवा इन्ग कोई विशेष पोशाक ही धारण करते हैं। यह तो आध्यात्मिक शान्ति के दृष्टिकोण जिज्ञासुओं का एक केन्द्र है, जहाँ वे साधकों के रूप में आध्यात्मिक जीवन से सामान्वित होने के लिये अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वे पृथक्-पृथक् स्थानों पर तपस्या नहीं करते हैं, बल्कि एक परिवार के सदस्यों के समान श्री भरविन्द के आदर्शों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किसी भी जाति, वर्ग, लिंग, राष्ट्र, धर्म, तथा वर्ण का व्यक्ति इस परिवार का सदस्य बन सकता है। शर्त केवल यह है कि 'मदर' को इस बात का विश्वास हो जाना चाहिये कि प्रवेश चाहने वाला व्यक्ति श्री भरविन्द के आदर्शों का पालन करने वाला है और उसे आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की आन्तरिक प्रेरणा प्राप्त हो चुकी है। मात्र इस माधम में विभिन्न राष्ट्रों तथा जातियों के स्त्री एवं पुरुष पाये जाते हैं। उन सब का श्री भरविन्द के आदर्शों के अनुसार 'मदर' के द्वारा वय-प्रदर्शन किया जाता है। सभी साधकों का जीवन आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित है। वे मन, वचन, कर्म से इसी जीवन में 'देवी जीवन' की प्राप्ति के लिये प्रयास करते हैं। प्रत्येक साधक का 'देवी जीवन' में दृढ़ विश्वास है और वह योग-साधन द्वारा उसकी प्राप्ति में दत्तचित्त रहता है।

साधकों के जीवन का मूल-मंत्र निःस्वार्थ सेवा-भावना से कार्य करना है।

वे जो कुछ भी करते हैं उसे भगवान् को समर्पित करते हैं। सभी साधकों को अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ कार्य करना होता है। इस कार्य के प्रतिरिक्त उन पर अन्य कोई बन्धन नहीं है। उन्हें अपनी रुचि तथा क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्हें सब कार्य स्वयं करने पड़ते हैं, क्योंकि आश्रम में सेवक रखने का निषेध है।

आश्रम का मूल रूप वही है जो प्राचीन भारत में ऋषियों के आश्रमों में था, केवल उसको कुछ माधुनिक ढंग दे दिया गया है। आश्रम के केन्द्र में एक भवन है जिसमें 'मन्दर' एवं कुछ अन्य प्रमुख साधक रहते हैं। अन्य साधकों के निवास के लिये पृथक् भवन हैं। ये सभी भवन छान्त एवं स्वस्थ वातावरण में हैं। आश्रम वासियों को सभी प्रकार की सुविधायें हैं। उनके लिये पुस्तकालय, वाचनालय, भोजनालय, चिकित्सालय, बैंक, लाइब्रेरी, डेरी, प्रेस, इंजीनियरिंग वर्क-शाप, आदि हैं। इन सब का प्रबन्ध 'मन्दर' के निर्देशन में साधकों द्वारा किया जाता है। आश्रम में कुटीर-उद्योगों, कताई-नुनाई, काष्ठ-कला आदि की व्यवस्था है। इनका संचालन साधकों के द्वारा ही किया जाता है। ये बातें प्रमाणित करती हैं कि यद्यपि आश्रम आध्यात्मिक चिन्तन का स्थान है, तथापि इसमें सांसारिक जीवन की उपेक्षा नहीं की गई है।

### आश्रम-स्कूल

श्री भरविन्द ने १९४० में आश्रम के साधकों के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। १९४३ में 'आश्रम स्कूल' की स्थापना करके इस कार्य को सुसंगठित रूप प्रदान किया गया। भारत में इसमें केवल ३२ छात्र थे, परन्तु आज इसमें ३०० से अधिक छात्र तथा छात्राये हैं। ये विभिन्न जातियों, वर्गों, वर्णों तथा राष्ट्रों के हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या गुजराती एवं बंगाली छात्रों की है। सभी की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। उनको शिक्षा देने वाले आश्रम के साधक ही हैं। इन अध्यापकों को वेतन के रूप में भत्ता नहीं दिया जाता है, अपितु उनका और उनके परिवारों का भरण-पोषण आश्रम के द्वारा किया जाता है।

स्कूल में सभी सामान्य विषयों के शिक्षण की व्यवस्था है, यथा—गणित, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, चित्रकला आदि। भाषाओं में प्रपञ्ची, संस्कृत, साम्प्रदायिक, फ्रेंच, जर्मन आदि के शिक्षण की व्यवस्था है। इसके लिये भी इन भाषाओं को सीखने का प्रबन्ध किया गया है। प्रवेश देने वालों में नियमित (Regular) तथा सामयिक (Casual) दोनों प्रकार के छात्र हैं। शिक्षा का माध्यम फ्रेंच है। भाषाओं के शिक्षण के लिये छात्रों

को उनके ज्ञान के स्तर के अनुसार विभिन्न समूहों में विभक्त किया जाता है। समान विशेषताओं वाले छात्रों को एक समूह में रखा जाता है और उन्हें उसी प्रकार की विशेषताओं वाले अध्यापक के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार स्कूल के छात्र मनकों समूहों के विभाजित हैं। परिणामस्वरूप उनको शिक्षा देने के लिये साधारण स्कूलों की प्रपेक्षा कहीं अधिक अध्यापक है। विज्ञान में प्रयोगात्मक कार्य करने के लिये उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाएँ हैं। कला एवं सजीव के शिक्षण के लिये भी उत्तम व्यवस्था है। इस स्कूल की शिक्षा का स्तर हमारे देश के हाई स्कूल के स्तर के बराबर है।

प्राथम-स्कूल में सामान्य त्रैमासिक, छह-वार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। अध्यापक समय-समय पर छात्रों के टेस्ट लेते रहते हैं और उन्हीं की रिपोर्टों के आधार पर छात्रों की एक कक्षा से दूसरी कक्षा को उन्नति की जाती है। यदि कोई छात्र भारत के 'हाई स्कूल', फ्रांस के 'बैका-मोरियेट' अथवा इंग्लैंड के 'सीनियर केम्ब्रिज' की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसको अपना उन्हें प्राप्त करने में शिक्षण की विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार के कुछ छात्र प्रतिवर्ष हो जाते हैं और उन्हें अपनी परीक्षाओं से सम्बन्धित सभी पाठ्य-विषयों की शिक्षा दी जाती है।

श्री भरविन्द शिक्षा ग्रहण करने वाले बालक की स्वतन्त्रता के प्रबल समर्थक थे। प्राथम-स्कूल में इसी सिद्धान्त का पालन किया जाता है। इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाता है कि बालक स्वतन्त्र वातावरण में विद्याभजन करता हुआ अपने व्यक्तित्व तथा भात्मा का पूर्ण विकास करने में सफल हो। हम ऊपर लिख चुके हैं कि प्राथम-स्कूल छात्रों के बच्चों को शिक्षा देने के लिये है। अतः स्वाभाविक है कि वे बच्चे अपने माता-पिता के पास रहते हैं। इनके व्यक्तिगत स्कूल में कुछ बाहर के छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता है। यदि छात्र पोंडिचेरी के हैं, तो वे नगर में अपने अभिभावकों के साथ रहते हैं। यदि वे किसी अन्य स्थान के होते हैं, तो उन्हें बालकों के उपनिवेश में स्थान दे दिया जाता है। सभी छात्रों का पत्र-प्रदर्शन 'मदर' के द्वारा किया जाता है और वे स्वयं उन्हें फॉच की शिक्षा देती हैं।

प्राथम-स्कूल भारत की प्राचीन परम्पराओं पर आधारित एक प्राधुनिक विद्यालय है। इसमें प्रायः सभी प्राधुनिक शिक्षा-वस्तुओं को स्थान दिया गया है। इसमें धर्म को कोई स्थान नहीं प्राप्त है। छात्रों को धार्मिक वस्तुओं तथा कर्म-वाणियों को करने का निषेध है जिससे कि उनका दृष्टिकोण संकुचित हो जाय। देश के विभाजन के समय से, जब इस पर मुसलमानों ने आक्रम



किया था, इसमें शारीरिक व्यायाम पर विशेष बल दिया जाने लगा है। स्कूल के छात्रों को ही नहीं, अपितु माध्यम के सभी साधकों को व्यायाम में निरमित रूप से भाग लेना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'माध्यम-स्कूल' गिला में एक नवीन परीक्षण है और यह कहना प्रतिशयोक्ति न होगी कि इस परीक्षण को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

### श्री भरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र

१९५० में श्री भरविन्द के निधन के पश्चात् उनके शिक्षा-सम्बन्धी आदर्शों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया। १९५१ में एक विशेष सम्मेलन (Convention)। निश्चय किया गया कि महायोगी भरविन्द की पुण्य स्मृति में तथा 'मदर' के उद्देशन में एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय जहाँ श्री भरविन्द : आदर्शों के अनुसार मानव जाति को दिव्य-प्रकाश प्राप्त हो सके। ६ जनवरी, १९५२ को इस विश्व-विख्यात शिक्षा-केन्द्र का शिलान्यास किया। वस्तुतः यह 'माध्यम स्कूल' का ही विकसित रूप है, जिसकी स्थापना १९४३ में की गई थी। यह केन्द्र तीन शैक्षिक विभागों—प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च में विभाजित है। इसमें निम्नांकित पाठ्य-क्रमों के शिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था है :

१. शिशु-शिक्षा—शिशु-शिक्षा की व्यवस्था उन बच्चों के लिये है जो चार वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं। शिशुओं को तीन वर्ष तक मान्दसरी तथा अन्य प्रतिभाशालि वयस्त्रियों से शिक्षा दी जाती है और उनकी अभिरचियों को समुपद्रित विकसित करने की चेष्टा की जाती है।

२. प्राथमिक शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा की अवधि चार वर्ष की है। इसकी वस्था ७ से ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये की गई है। छात्रों को गीत, मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेज, सामान्य विज्ञान, गणित, नागरिक अध्ययन

"Sri Aurobindo International University Centre.

"This Convention resolves that with the purpose of realising one of the most cherished ideals of Sri Aurobindo and of giving concrete shape to what he regarded as one of the best means of preparing humanity to receive the Supernatural Light, an International University on the lines approved by the Master, and under her guidance and control, be established in Pondicherry as a fitting memorial to the Master."

घौर चित्रकला की शिक्षा दी जाती है। खेल, फ़िल्म शो, संगीत आदि कार्य कम विशेष रूप से आयोजित किये जाते हैं। शिक्षण-कार्य में अध्यापकों को पूर्ण स्वतन्त्रता है।

३. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा—इस शिक्षा की अवधि साठ वर्ष की है। पाठ्य-विषयों में मातृभाषा, अंग्रेज़ी, फ़ॉन्ट, गणित, भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान (वनस्पति-विज्ञान, जीव-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, स्वास्थ्य-विज्ञान, भूमिकी(Geology)), सामाजिक अध्ययन और चित्रकला को स्थान दिया गया है। इन विषयों के प्रतिरिक्त प्रत्येक छात्र को व्यावसायिक विषयों में से किसी एक विषय का अध्ययन भी करना पड़ता है।

४. विश्वविद्यालय-शिक्षा—विश्वविद्यालय की सामान्य शिक्षा का काल तीन वर्ष है। उसके उपरान्त उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिये दो वर्ष और व्यतीत करने पड़ते हैं। अध्ययन के विषय हैं—विश्व-एकीकरण (World Integration) अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (International Relations), भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन, मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र, सम्यता का इतिहास, अंग्रेज़ी साहित्य, जीवन का विज्ञान (Science of Life), गणित, भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, विज्ञान का इतिहास और फ़ॉन्ट साहित्य। अन्तिम दो वर्ष विषयों की शिक्षा फ़ॉन्ट के माध्यम से घौर शेष की अंग्रेज़ी के माध्यम से दी जाती है।

५. व्यावसायिक शिक्षा—व्यावसायिक शिक्षा अधाकित विषयों में दी जाती है—काष्ठ-कला, सामान्य मेकेनिकल और एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोटोग्राफी, चित्रकारी, अभिनय, आशुलिपि (Short-hand), टंकन (Type-writing), व्यावसायिक पत्र-व्यवहार (Commercial Correspondence) सूची-शिल्प-कार्य (Embroidery) सिलाई, कुटीर-उद्योग, शिल्प-कला सम्बन्धी ट्राईंग, भारतीय और यूरोपीय संगीत, नृत्य, उपचारण (Nursing)।

६. व्यवस्था-शिक्षा—व्यवस्था के लिये अंग्रेज़ी, फ़ॉन्ट, जर्मन, हिन्दी, संस्कृत और तमिल की शिक्षा की व्यवस्था है।

'अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र' का उद्देश्य छात्रों के शरीर, मस्तिष्क और जीवन का अनुमूर्खी विकास करना और उन्हें 'देवी जीवन' के स्तर पर पहुँचाना है। इसलिये योग पर विशेष बल दिया जाता है। केन्द्र में किसी विशेष धर्म से सम्बन्धित धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है और न विभिन्न धर्मों के

निवन्धी का पापन जाने को धाका है। केन्द्र मई-जून तक का प्रयोग करता है कि छात्रों को नैतिक-वैज्ञानिक को विवर्तन करके उन्हें पुनः मानवता और धर्मपर विचार कराए।

केन्द्र का द्वार सभी भाषियों, नर्सी, गण्डू, पक्षी, घोर वृत्तों के साथ तथा बालिकाओं के लिये खुला हुआ है। उनमें छात्रों का कोई दुष्प्रभाव निया जाता है। केन्द्र में गृह-विद्या का प्रचलन है। इस मन्दर बड़ी मन्द १०० विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में अधिक गण्डू पाठ्यापी को है। सभी छात्रों लिये छात्रावास की समुचित व्यवस्था है। इन छात्रों में से अधिकांश छात्र पाठियों को गतान है। इनको वर्ष के अन्त में कोई परीक्षा नहीं देखी जाती है। इनके वैयक्तिक कार्य और शिक्षकों के निर्णय के आधार पर इनको प्रकाश में दूसरी में उन्नति दे दी जाती है। विद्यार्थ्यन समाप्त करने के बाद इनको कोई किसी व्यवस्था उपाधि नहीं प्रदान की जाती है।

केन्द्र में १९० में अधिक प्रख्यात है। वे सभी छात्रों के प्रत्यक्ष विद्यार्थी में १८ भारतीय हैं और वे १४ विभिन्न राष्ट्रों के हैं। इनको केन्द्र नहीं दिया जाता है, पर इनको और इनके परिवारों के सभी सदस्यों की व्यवस्थाओं की पूर्ण व्यवस्था के द्वारा की जाती है। इनके लिये छात्रावास प्रदत्त है।

केन्द्र का प्रचालन एक शैक्षिक-प्रधान (Academic Head) के अधीन उसकी सहायता के लिये सहयोगी उप-प्रधान कार्यकर्ता हैं। वे सभी 'मन्दर' निर्देशन में कार्य करते हैं। केन्द्र कार्यालय के समस्त कार्य का भार प्रिन्सिपल पर है। पाठ्य-विषयों का निर्धारण करने के लिये समितियाँ हैं। इसी प्रकार केन्द्र में सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिये भी समितियाँ बनी हुई हैं। प्रख्यात-वर्ग की प्रति मास एक सभा होती है और उसमें अनुशासन, पाठ्य-परीक्षण आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

प्रायः सभी विषयों के लिये पुष्कल कला है। विज्ञान-भवन का निर्माण अभी कुछ ही समय पूर्व किया गया है। उसमें प्राधुनिक बङ्ग की घोर उपकरणों से सुसज्जित भौतिक विज्ञान एवं रसायन-शास्त्र की प्रयोगशाला हैं। इसी प्रकार जीवन-विज्ञान, सङ्गीत, नृत्य आदि कला भी हैं। इसके अतिरिक्त एक विशाल भवन और है जिससे बड़ी-बड़ी प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। छात्रों को धर्मनिरपेक्ष करने तथा सोचने के लिये एक मिनेटर भी है। केन्द्र के विशाल पुस्तकालय में प्रायः सभी भाषाओं के प्रबुद्ध तथा प्रमत्त ग्रन्थों का सुन्दर संकलन है। छात्रों के लिये एक चित्रकला तथा नर्सिंग हॉल भी है।

## उपसंहार

‘बी. ओरिन्ड भन्तर्पिष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र’ शिक्षा के क्षेत्र में तथा महत्वपूर्ण परीक्षण है। वहाँ माइन्डर तथा दिखाने का कोई नहीं है। जिन महान् भारतीय योगी के नाम पर इस केन्द्र की स्थापना की गई है, उनका नाम इमारत के किसी भाग पर भी अंकित नहीं है। परन्तु वहाँ उनके आदर्शों, उपदेशों, उद्देश्यों और सिद्धान्तों को पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। वहाँ भारतीय शिक्षा, संस्कृति तथा साधना को पुनर्जीवित करके बराबर पर प्रतिष्ठित किया गया है। सम्पूर्ण जीवन की शिक्षा प्रदान करता हुआ, छात्रों को विश्व-वन्द्य तथा पूर्ण मानवता को धीरे-धीरे बनाने वाला हुआ और बी. ओरिन्ड के शिक्षा दर्शन को व्यावहारिक रूप देता हुआ यह केन्द्र सम्पूर्ण विश्व में प्रकाश एवं अभ्यासवाद की किरणों को विकीर्ण कर रहा है।

५: गुरुकुल शिक्षा प्रणाली

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति तथा सम्पत्ता और सभ्यता के उत्थान के लिये अनिवार्य है। भारतवासियों ने शिक्षा के इस महान् महत्व को समझ लिया था। इसी के फलस्वरूप भारत के गुरुकुल प्रणाली में भी गुरुकुलों में शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था की गई थी। वेदों से ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि उस समय भी भारत में संगठित रूप में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। छान्दोग्य उपनिषद् से ज्ञात होता है कि बालक गुरु-गृह में रहकर विद्याभ्यास करते थे।

### प्राचीन गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली

जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, प्राचीन समय में बालक गुरु के गृह अथवा कुल में रहकर विद्याभ्यास करते थे। इन गुरुकुलों की प्राचीन विद्यालयों के समान मध्य प्रारम्भिक कार्य नहीं होती थीं। ये तो अनपढ़ के कोलाहल से दूर, नैसर्गिक सौन्दर्य के सुरभित घने वन, प्रकृति के गुरुमुख कक्ष तथा मनोरम पर्वतों की कन्दराओं में स्थित होते थे। वहाँ नील नम के नील वितान के लोके भक्तियों, ध्यान, ऋषियों-मुनियों से उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। सत्ता-पता-परि-वेष्टित ऋषि-प्राप्त्यर्थ ही प्रकाश की पवित्र एवं दिव्य रश्मियों को प्रसारित करते थे।

ये गुरुकुल ही भारतीय संस्कृति के केन्द्र थे। इसीलिये कवि-सम्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि भारतीय संस्कृति के निर्भर नवरत्नों में नहीं, अपितु

भारत के वनों में बहते हैं। वैदिक एवं बौद्ध काल में भारतीय संस्कृति का विकास राजप्रासादों तथा सचिवालयों में नहीं हुआ, वरन् प्रकृति के नैसर्गिक वैभव के मध्य इन्हीं गुरुकुलों में हुआ। यह संस्कृति धर्मः धर्मः भारत के प्रत्येक कोने तक फैल गई।

प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली का आधार भारतीय संस्कृति थी। इस शिक्षा का मानव-जीवन के प्रति वही दृष्टिकोण था, जो भारतीय संस्कृति का था। इसका प्रमुख उद्देश्य आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण और आत्म-ज्ञान तथा आत्मा की परिपूर्णता की प्राप्ति थी। यह व्यक्ति की लौकिक से पारलौकिक की ओर ले जाती थी। यह उसे आत्मा का दर्शन और परब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बताती थी। यह विश्व में जो प्रद्युम्ण है उसे पहिचानने तथा उसे प्राप्त करने में व्यक्ति की सहायता करती थी। अतः विद्या ज्ञान में बाह्य ज्ञान की अपेक्षा आत्म-विद्या अथवा आत्म-ज्ञान पर ही विशेष बल दिया जाता था।

प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में व्यक्ति ही शिक्षा का केन्द्र था। शिक्षा का परम लक्ष्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करके उसे पारवर्त सत्य का साक्षात्कार कराना था। उसका परम ध्येय था व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करके उसे इस योग्य बनाना कि वह अपने अन्तर में महान् सत्य का दर्शन कर सके और अन्त आत्मा का भ्रम मनने में सफल हो सके।

गुरुकुलों के छात्रों का जीवन गुरुह अनुशासन से पूर्ण होता था। उन्हें अपने सम्पूर्ण शिक्षा-काल में ब्रह्मचर्य-जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उनकी शारीरिक प्रसाधन सामग्री, मेसला, मृगवर्म और लम्बे केस थे। दण्ड और कण्डल उनके आध्यात्मिक चिह्न थे। उनके लिये एक निश्चित दिनचर्या का विधान था। उन्हें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता था। उन्हें गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। वे उसकी गीर्षों को चराते थे। उसके लिये लक्ष्मियाँ एकत्रित करके लाते थे। छात्रों को नित्य-प्रति अपने भोजन के लिये भिक्षाटन करने जाना पड़ना था। गुरु तथा छात्र में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होता था और गुरु प्रत्येक प्रकार से अपने छात्रों का ध्यान रखता था।

शिक्षा धार्मिक रूप से दी जाती थी। गुरु अपने छात्रों को वेदों की शिक्षा देते थे और उनके मन्यों की व्याख्या करते थे। शिष्य अपनी संशयों का समाधान करने के लिये गुरु से प्रश्न पूछते थे। तर्क तथा वाद विवाद की शिक्षण में विशेष महत्त्व प्रदान किया जाता था। इस प्रकार इन्द्रिय-सदम और पूजा-पाठ करते हुए छात्र गुरु के गृह में रहकर विद्या का उपार्जन करते थे।

कठोर काल ने भारतीय संस्कृति के इन केन्द्रों को पद-दक्षित कर डाला। मुस्लिम शासकों ने भारतीय शिक्षा के उच्च प्रादशों पर बख़्शप्रहार किया। शिक्षा की प्राचीन संस्थाएँ धनस्त में विलीन होने लगीं और उसकी रूप-रेखा बदलती चली गई। घंघ्रों के आगमन ने भारतीय शिक्षा और उसकी संस्थाओं के प्रयोगों को सदैव के लिये धरती पर से हटा दिया। शिक्षा की रूप-रेखा और उसके उद्देश्यों में पूर्ण परिवर्तन हो गया। विद्या का अर्थ जीवन-यापन के लिये किया जाने लगा। भारत के निवासियों को गुरुकुलों से दी जाने वाली शिक्षा एक कहानी बन गई। पाश्चात्य संस्कृति में सराबोर वे अपनी शिक्षा के उच्च प्रादशों से अनभिज्ञ हो नहीं भ्रमिष्ठ विमुख भी हो गये। भारतीय संस्कृति से उनका सम्बन्ध समाप्त हो गया।

### आधुनिक काल में गुरुकुलों की स्थापना

एक लम्बे समय के बाद भारतीयों के नेत्रों के आगे से पाश्चात्य संस्कृति का आवरण हटा। बीसवीं शताब्दी का उषा-काल उनके लिये गुण-प्रवर्धक सिद्ध हुआ। कांग्रेस ने राजनैतिक क्षेत्र में हलचल उत्पन्न कर दी। समाज-सुधारकों ने समाज के प्रत्येक अंग को दोष रहित करने के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किये। कतिपय देश-प्रेमियों ने तत्कालीन शिक्षा के विदेशी स्वरूप की प्रति कटु आलोचना की। उन्होंने उसके दोषों की व्याख्या करके उसे देश के लिये स्पष्ट रूप से अहितकर बताया। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा तथा राष्ट्रीय विद्यालयों के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया। इसी के फलस्वरूप गुरुकुलों की स्थापना की गई और उनमें वैदिक मन्त्रों को मधुर धनियाँ भारत के अतीत की गौरवभाषा गुंजरित करने लगी।

### गुरुकुलों के लिये आन्दोलन

बीसवीं शताब्दी के उषा-काल में भारत में जिन राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्रान्तियों का आविर्भाव हुआ, उन्हीं के मध्य गुरुकुलों के निर्माण के आन्दोलन का जन्म हुआ। इसका अर्थ स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्राप्त है। भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म के प्रबल समर्थक होने के कारण उन्होंने समकालीन शिक्षा-पद्धति की तीक्ष्ण आलोचना की। उनका कथन था कि यह पद्धति पाश्चात्य संस्कृति से सराबोर होने के कारण भारतीय संस्कृति तथा भारतीय धर्म को समूल नष्ट करने का प्रयास कर रही है। घंघ्रों की शिक्षा के उपासक बनकर इस देश के निवासी अपनी प्राचीन परम्पराओं से दूर होते जा रहे हैं। इस शिक्षा में चरित्र निर्माण का कोई स्थान न होने के कारण भारतीयों के चरित्र का निरन्तर पतन हो रहा है। उन्होंने कोपित किया कि यदि

देश की पतनोन्मुख होने से रक्षा करनी है तो वेदों की शिक्षा की धोर पु-  
जाना पड़ेगा और प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली को जीवित कर-  
होगा। यद्यपि उनके समय में प्रचलित मरुट पाठशालायें भारत की शिक्षा-  
प्रणाली के अनुसार ज्ञान का प्रसार कर रही थी, परन्तु उन्होंने उनको अनु-  
प्राप्त बताया। इस बात में अपने कारणों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा :

१. इन पाठशालायों के अध्यापक प्राचीन गुरुओं के समान स्वामी और  
तपस्वी नहीं हैं।
२. इन पाठशालायों के प्रति छात्रों का कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि  
इनकी शिक्षा से उन्हें कोई लाभ नहीं होता है।
३. इनमें अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।
४. इनमें केवल संस्कृत के अध्ययन तथा अध्यापन पर बल दिया जाता है  
और इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, चिकित्सा आदि के शिक्षण पर विशेष  
ध्यान नहीं दिया जाता है।
५. इनमें योग्य तथा अनुभवी गुरुओं का प्रायः पूर्ण अभाव है।

तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा-व्यवस्था तथा संस्कृत-पाठशालायों के उपरोक्त  
दोषों का विस्तेरण करने के पश्चात् स्वामी दयानन्द ने अपने देशवासियों के  
समक्ष प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के आदर्श को उपस्थित किया।

### गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली की रूप-रेखा

स्वामी दयानन्द ने जिस शिक्षा-प्रणाली का समर्थन किया वह प्राचीन  
आश्रम-प्रणाली के आदर्शों पर आधारित होते हुए भी उससे कुछ भिन्न थी।  
इसका प्रमुख कारण यह था कि स्वामी जी शिक्षा की देश की परिवर्तित परि-  
स्थितियों के अनुकूल बनाना चाहते थे। संक्षेप में उनके द्वारा प्रतिपादित  
गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की रूप-रेखा इस प्रकार थी :

१. आठ वर्ष की आयु के पश्चात् बालकों तथा बालिकाओं को घर पर न  
रखकर गुरुकुलों में विद्याध्ययन के लिये भेज दिया जाय।
२. बालकों एवं बालिकाओं के लिये धृष्ट गुरुकुलों की स्थापना की जाय।
३. इन गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य-जीवन व्यतीत किया जाय।
४. इनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के प्रति समान व्यवहार किया  
जाय और उनमें किसी प्रकार का कोई भेद न समझा जाय।
५. गुरुकुलों की स्थापना जनपद कीलाहल से दूर प्रकृति के सुख्य कक्ष में की  
जाय।
६. गुरुओं और शिष्यों के मध्य बहुत समीप का सम्पर्क हो।

७. गुरुकुलों के पाठ्य-क्रम में संस्कृत के साथ-साथ अंग्रेजी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा आदि की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाय।

८. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।

### गुरुकुल-संस्थाओं का निर्माण

श्री श्री दयानन्द के शिक्षा-सम्बन्धी आदर्शों से प्रेरित होकर भारत में विभिन्न भागों में गुरुकुलों की स्थापना की गई। इनमें से प्रमुख गुरुकुल यहाँ लिखित हैं :

१. गुरुकुल कांगड़ी—इसकी स्थापना १९०३ में पंजाब में स्वामी दयानन्द के द्वारा की गई थी। १९२४ में इसे उठाकर कांगड़ी (हरिद्वार) ले आया गया। इसके प्रबन्ध तथा संचालन का भार भार्य-प्रतिनिधि सभा पर है। प्रारम्भ में यह एक छोटी सी संस्था थी, परन्तु आज इसने विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया है। इसमें छात्रावली: ६ से ९ वर्ष तक की छात्रों के बालक प्रवेश करते हैं। इसमें शिक्षा की अवधि १४ वर्ष की है। उच्च शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् छात्र को 'स्नातक' (Graduate) की उपाधि दी जाती है। दो वर्ष और अध्ययन करके वह 'मास्टर' (M. A.) की उपाधि प्राप्त कर सकता है।

छात्रों को होम, यज्ञ, संध्या, उपासना आदि करने पड़ते हैं। उनके लिए शारीरिक व्यायाम अनिवार्य है। पाठ्य-क्रम के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दू संस्कृति तथा प्रागुर्वेदिक चिकित्सा की शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था है। यह शिक्षा भारतीय आदर्शों के अनुसार दी जाती है और उसका रूप विदेश नहीं होने दिया जाता है। समस्त शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। प्रागुर्वेदिक शिक्षा का स्तर पर्याप्त रूप में ऊँचा है और प्रागुर्वेदिक उपाधियों को भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। इस शिक्षा की अवधि ५ वर्ष की है और १५-१६ वर्ष तक की आयु के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

२. गुरुकुल वृन्दावन—इसकी स्थापना १९०२ में विक्रमराव में की गई थी। १९११ में इसे वहीं से उठाकर मथुरा के निकट कृष्ण भगवान् की जन्म-भूमि वृन्दावन ले आया गया। इसका प्रबन्ध तथा संचालन उस प्रदेश की भार्य-प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है। यह भी आज गुरुकुल कांगड़ी के समान एक विश्वविद्यालय है और इसमें सामान्य तथा प्रागुर्वेदिक शिक्षा की व्यवस्था उसी प्रकार की है जिस प्रकार की गुरुकुल कांगड़ी में है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त उपरोक्त दोनों गुरुकुलों को आशाशील उन्नति



हुई है और भारतीय नेताओं ने इनकी मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है। इन दोनों विश्वविद्यालयों में न केवल भारत के विभिन्न भागों से अपितु एशिया और अफ्रीका से भी विद्यार्थी आने करने के अभिलाषी छात्र आते हैं।

३. कन्या-गुरुकुल—गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व दिये जाने के कारण सह-शिक्षा का नियम है। अतः बालकों के समान बालिकाओं के लिये भी गुरुकुलों का निर्माण किया गया है। कन्या-गुरुकुलों में तीन गुरुकुल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—(१) कन्या-गुरुकुल, बेहराइन। यह गुरुकुल कांगड़ी की शाखा है। (२) कन्या-गुरुकुल, सातनी (उत्तर प्रदेश) और (३) माधव कन्या-महाविद्यालय, बड़ोदा। इसमें शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है।

उपरिलिखित तीनों कन्या-गुरुकुलों के उद्देश्य एवं विशेषताएँ लगभग वही हैं जो बालकों के गुरुकुलों की हैं। छात्राओं को सोलह वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन और प्रविवाहित रहना पड़ता है। उन्हें हिन्दू धर्म के अनुसार स्त्री-धर्म तथा स्त्री-कर्तव्य की विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है।

गुरुकुल-शिक्षा के उद्देश्य

जिन उद्देश्यों, सिद्धान्तों एवं धारणों को सम्मुख रख कर भारत में गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति की पुनर्स्थापना की गई है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :—

१. बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा कम से कम आठ वर्ष की आयु से गुरुकुलों में होना।
२. गुरुकुलों को नगर के कोलाहल से दूर सुन्दर प्राकृतिक वातावरण में स्थापित करके छात्रों तथा छात्राओं को नागरिक जीवन की कुरूप छाया से दूर रखना।
३. छात्रों को प्राचीन भारतीय धारणों के अनुसार शिक्षा देना।
४. छात्रों को प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं हिन्दू धर्म की विशेषताओं का समुचित ज्ञान प्रदान करना।
५. उपरोक्त विशेषताओं के छात्रों के जीवन में व्यावहारिक रूप में प्रतिबिम्बित करना।
६. छात्रों का सांस्कृतिक एवं धार्मिक विकास करके, उनमें प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं तथा धारणों के शौर्य से परिपूर्ण बनाना।
७. छात्रों में ब्रह्मचर्य, अथ, तप, उपासना आदि के द्वारा काम-वृत्ति पर अधिकार प्राप्त करने की शक्त उत्पन्न करना।

८. छात्रों की नैसर्गिक प्रतिभाओं तथा शक्तियों का विकास और उनके चरित्र का उत्थान करना ।
९. छात्रों को विभिन्न विषयों की शिक्षा देकर उनका मानसिक विकास करना ।
१०. उनको व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करके सामाजिक जीवन के अनुकूल बनाना ।
११. छात्रों में जन्म, वंश या वर्ण के कारण भेदभाव न करके उनमें समानता और सहयोग की भावना तथा मानवजाति की एकता की चेतना को जागृत करना ।
१२. छात्रों को कठोर तथा अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करके उनमें सहन-शक्ति का निर्माण करना ।
१३. गुरु तथा शिष्य के मध्य निकट सम्बन्ध स्थापित करना ।
१४. सामूहिक शिक्षण के स्थान में व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना ।
१५. संस्कृत भाषा के साथ-साथ हिन्दी, अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान की शिक्षा देना ।
१६. भारतीय इतिहास तथा ग्रन्थ विषयों में अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहित करना ।

### गुरुकुल-शिक्षा की विशेषतायें

भारत के नवनिर्मित गुरुकुलों की शिक्षा की विशेषतायें प्रायः वही हैं, जो प्राचीन गुरुकुलों की शिक्षा की थी । केवल आधुनिक परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रख कर उनमें थोड़ा-सा हेर-फेर कर दिया गया है ।

छात्रों को नगर के विलास-पूर्ण जीवन से दूर किसी शान्त स्थान में निर्मित गुरुकुल में दुरुह मर्यादों से युक्त साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता है । उन्हें धूम तथा मदिरा-पान और मांस-सेवन का निषेध होता है । उनकी पोशाक सादा होती है और उन्हें शिक्षा-काल में ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना पड़ता है । उनके लिये एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित होता है । उसके अनुसार उन्हें प्रातःकाल उठना, व्यायाम करना तथा होम और उपासना में भाग लेना पड़ता है ।

छात्रों के चरित्र-निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । उनमें कठोरता सहन करने और सहनशीलता तथा सहानुभूति के गुणों को उत्पन्न किया जाता है । उनमें सामुदायिक जीवन, साम्य तथा सहयोग की भावनाओं का विकास किया जाता है । उनमें भारतीय संस्कृति की प्रेरणा बूढ़-बूढ़ कर

भर दी जाती है। उनका घपने शिक्षकों से निश्चय सम्पर्क होता है। विद्यालय के साथ साथ विभिन्न प्राथमिक तथा पाठ्यक्रम ज्ञान-विज्ञान के देकर उनका बौद्धिक विकास किया जाता है। उनके आध्यात्मिक विविध बल दिया जाता है।

गुरुकुल छात्रावास शिक्षा-संस्थाएँ हैं। उनमें मह-विद्या का प्रचलन नालको तथा बालिकाओं के लिये गुरुकुल है। उनमें कल्पित कला शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। शिक्षा निःशुल्क है और माध्यम हिन्दी है। पाठ्य-क्रम में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ-साथ प्राथमिक प्राप्ति तथा विज्ञानों को स्थान दिया गया है। शोध-कार्य के पर्याप्त सुविधायें हैं।

### उपसंहार

प्राथमिक भारत के गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तथा सफल परी है। वे भारत की प्राचीन संस्कृति तथा शिक्षा के महान् उद्देश्यों को पुनर्जी करने में संलग्न हैं। वे भारतीय दर्शन, साहित्य तथा विज्ञानों के संरक्षण प्रसार में अभिनन्दनीय योग प्रदान कर रहे हैं। वे छात्रों को आत्म-निर्भरता और सेवा की दीक्षा देकर उन्हें भारत की नवीन सामाजिक संरचना लिये उपयुक्त बनाने में प्रयत्नशील हैं। वे पाठ्यक्रम संस्कृति की क्षेत्रों में जहाँ हुए भारतीयों में छात्रों का नव-संदेश प्रसारित कर रहे हैं। वे वस्तुतः भारतीयों के बौद्धिक तथा सांस्कृतिक जागरण के लिये शताब्दीय कार्य कर रहे हैं।

## ५. बनस्थली विद्यापीठ

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा का आन्दोलन भी प्रारम्भ किया गया। देश के नेताओं ने प्रचलित शिक्षा-प्रणाली से असन्तुष्ट होकर राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था के लिये राष्ट्रीय विद्यालयों का निर्माण प्रारम्भ किया। इन्हीं विद्यालयों में बनस्थली विद्यापीठ का स्थान है।

### विद्यापीठ की स्थिति एवं स्थापना

राजस्थान में बनस्थली नामक एक ग्राम है। यह जयपुर से ४५ मील है। १९२६ में राजस्थान के कुछ कार्यशील कार्यकर्ता श्री होरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में इस ग्राम में रह कर समाज-सेवा का कार्य कर रहे थे। वहाँ उन्होंने विद्यालय के लिये 'जीवन-कुटीर' नामक एक आश्रम बना लिया था। यहाँ

को अपना केन्द्र बनाकर वे लोग ग्राम के निर्धन कृषकों, धर्मिकों और हरिजनों के उत्थान के लिये रचनात्मक कार्य कर रहे थे।

पं० हीरालाल घास्मी की एक पुत्री थी, जिसका नाम शान्ताबाई था। १९३४ में जब शान्ताबाई बारह वर्ष की थी, तब एक दिन उसने यह इच्छा प्रकट की कि वह बालिकाओं की शिक्षा के लिये एक विद्यालय स्थापित करेगी। दुर्भाग्यवश १९३५ में अकस्मात् ही उसकी मृत्यु हो गई और उसकी इच्छा पूर्ण न हो सकी। अपनी एक मात्र पुत्री की अपूर्ण अभिलाषा को पूर्ण करने के उद्देश्य से पं० हीरालाल घास्मी ने अक्टूबर, १९३५ में 'जीवन कुटीर' में एक 'शिक्षा-कुटीर' को जन्म दिया। १९३६ में इस 'शिक्षा-कुटीर' का नाम 'राजस्थान बालिका-विद्यालय' रखा गया और १९४२ से यह 'बनस्पती विद्यापीठ' के नाम से विख्यात हुआ।

### छात्रायेँ तथा भवन

१९३५ में इस विद्यालय का शिक्षण कार्य ६ बालिकाओं से प्रारम्भ किया गया था। आज इसमें लगभग ७०० छात्रायेँ हैं। वे देश के विभिन्न भागों, वर्गों तथा जातियों की हैं। प्रारम्भ में विद्यालय के सभी भवन कच्चे थे। परन्तु गत वर्षों से वहाँ बहुउद्देशीय विद्यालय, हाई-स्कूल, शिक्षा-भवन, कला-भवन, छात्रावास तथा कुछ अध्यापकों के निवास-स्थान पक्की ईंटों के बन गये हैं। प्रतिवर्ष कुछ नए भवनों का निर्माण हो जाता है। विद्यापीठ के लिये बिजली, पोस्ट-ऑफिस, पानी के नलों एवं टेलीफोन की व्यवस्था कर दी गई है। विद्यापीठ की स्थापना के समय बनस्पती में जीवन व्यतीत करना कठिन था, परन्तु आज वहाँ सभी आवश्यक वस्तुयें अति सुगमता से मिल जाती हैं और जयपुर तथा निवाई स्टेशन तक, जो बनस्पती से पाँच मील है, यातायमन की उत्तम सुविधायेँ उपलब्ध हो गई हैं। विद्यापीठ का वार्षिक व्यय तीन लाख रुपये से अधिक है।

### विद्यापीठ के शिक्षा-विभाग

बनस्पती विद्यापीठ बालिका-शिक्षा का अखिल भारतीय केन्द्र है। इसमें प्रिन्सिपल-शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था है। विभिन्न स्तरों की शिक्षा प्रदान करने के लिये विद्यापीठ में निम्नांकित शिक्षा-विभाग हैं :

१. प्राथमिक विभाग—इसमें २ कक्षायेँ प्राथमिक शिक्षा की हैं। प्राथमिक पाठशाला से सम्बन्धित एक प्रिन्सिपल-कक्षा भी है। इस विभाग का पाठ्यक्रम स्वतन्त्र रूप से निर्धारित किया जाता है।

२. संस्कृता विभाग—इस विभाग में विद्यापीठ द्वारा परीक्षा-प्रमाण पत्र चाहने वाली बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था है। यह माण-पत्र कक्षा ८ के बाद दिया जाता है।

३. माध्यमिक शिक्षा-विभाग—माध्यमिक शिक्षा के लिये दो प्रकार के विद्यालय हैं :—(१) सामान्य हाई स्कूल, और (२) बहुउद्देशीय विद्यालय। ८ वी कक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त छात्रायाँ दोनों में से किसी भी विद्यालय में प्रवेश कर सकती हैं।

४. सामान्य हाई स्कूल—इसमें कक्षा ९ और १० हैं। इस स्कूल में अध्ययन करने वाली छात्रायाँ राजस्थान बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होती हैं।

५. बहुउद्देशीय विद्यालय—यह विद्यालय भारत-सरकार द्वारा संचालित हैं। इसमें कक्षा ९, १० और ११ हैं। छात्राओं को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का अनुसरण करना पड़ता है। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संगीत, कला, हस्तकला और गृह-विज्ञान की शिक्षण की व्यवस्था है। इस विद्यालय की छात्रायाँ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् बी० ए० में प्रवेश करती हैं। उनके लिये बी० ए० का पाठ्य-क्रम समाप्त करने की प्रवृत्ति तीन बर्षों है।

६. कनिष्ठीय शिक्षा विभाग—कनिष्ठीय शिक्षा के अन्तर्गत इन्टर, बी० ए० और एम० ए० स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। ये परीक्षायाँ राजस्थान बोर्ड तथा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती हैं। विद्यापीठ में केवल इन्टर पार्ट्स की व्यवस्था है। एम० ए० स्तर की शिक्षा केवल इतिहास और धर्मशास्त्र में ही जाती है।

७. अन्य शिक्षा विभाग—अन्य शिक्षा विभागों में संगीत ( वाद्य तथा गायन) चित्र-कला एवं पारोरिक शिक्षा का समुचित प्रबंध है। जो छात्रायाँ इनमें से किसी शिक्षा के पाठ्य-क्रम का अध्ययन करती हैं, उनकी परीक्षा स्वयं विद्यापीठ द्वारा ली जाती है और उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं की डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। इन डिप्लोमा परीक्षाओं का पर्याप्त सम्मान है। विद्यापीठ के लक्ष्य एवं उद्देश्य

जनसभों विद्यापीठ बालिका-शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुपम परीक्षण है। इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नांकित हैं :

१. प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा धारणों के आधार पर बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके उनका अनुपम विकास करना।
२. बालिकाओं का पारोरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना।

३. विभिन्न प्रकार के गृह-कार्यों की शिक्षा देकर बालिकाओं को स्वावलम्ब बनाना ।
४. बालिकाओं में सहयोग, समाज-सेवा, नागरिकता, देश-प्रेम की भावनाओं का समावेश करना ।
५. बालिकाओं में स्त्री-स्वातंत्र्य-भावना का विकास करके उन्हें पदों तथा अधिकारों से मुक्त करना ।
६. शिक्षा को बाह्य परीक्षाओं एवं बंधनों से मुक्त करके बालिकाओं को स्वतन्त्र रूप से अपना संतुलित विकास करने का अवसर प्रदान करना ।
७. पूर्व की आध्यात्मिक विरासत और पश्चिम की सफलताओं के समन्वय लिये प्रयत्न करना ।
८. बनस्पती विद्यापीठ के उद्देश्य को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है :  
 "विद्यापीठ का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में विज्ञान, प्रज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व का संबन्धोमुखी शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास करने वाली ऐसी सर्वांगपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है, जिसके परिणामस्वरूप गतिशील जीवन के अनुरूप सुसंयोजित, सुयोग्य और कार्यकुशल नागरिक का निर्माण किया जा सके । छात्राओं को सफल नागरिक तथा साथ-साथ सफल गृहिणी और माताएँ दोनों बन सकें । इस उद्देश्य को लेकर बनस्पती विद्यापीठ प्रायेण धाया है ।"

### विद्यापीठ की विशेषतायें

बनस्पती विद्यापीठ की कतिपय अनोखी विशेषतायें हैं, जिन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं :

१. शिक्षा सर्वांगीण, स्वतन्त्र तथा प्रगतिशील है ।
२. भारतीय परम्पराओं के अनुसार मर्यादा-पालन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय किया गया है ।
३. छात्राओं का जीवन सादा और सरल है ।
४. छात्राओं द्वारा कानूनों का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाता है ।
५. छात्राओं तथा अध्यापकों के लिये खट्टर पहिना आवश्यक है ।
६. छात्राओं को अपना निजी एवं घरेलू कार्य स्वयं करना पड़ता है जिसे उन्हें भावी जीवन में नौकरी का सहारा न खोजना पड़े । ६ ठी कक्षा के ऊपर की समस्त छात्राओं को भोजन बनाने के कार्य में सहायता दी जाती है ।

७. छात्रागों को सामाजिक तथा सामुदायिक कार्य करना अनिवार्य है।
८. छात्रागों के जीवन का भेदभाव किये बिना छात्रावास में सामुदायिक जीवन व्यतीत करती है।
९. छात्रावास का प्रबंध सभी बालिकागों के सहयोग से किया जाता है।
१०. विद्यापीठ केवल बालिकागों की शिक्षा-संस्था है। उसमें कोई भी बालक प्रवेश नहीं ले सकता है।
११. बालिकागों की सर्वतोमुखी शिक्षा देने के विचार से पाठ्य-क्रम के विषयों के अतिरिक्त भोजन बनाना, धरेलू कार्य करना, पोसना आदि भी अनिवार्य रखा गया है।
१२. बालिकागों को शारीरिक शिक्षा प्रदान करके निडर तथा पुस्त बनाने का प्रयास किया जाता है।
१३. सब बालिकागों का धन एक सम्मिलित कोष में रखा जाता है और सभी बालिकागों को उसमें से अपनी आवश्यकतानुसार व्यय करने का अधिकार होता है।
१४. छात्रागों के संरक्षकों से सम्पर्क रखने के लिये प्रति वर्ष 'संरक्षक-सम्मेलन' आयोजित किया जाता है।
१५. "विद्यापीठ उस मार्ग की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है, जहाँ परोक्षागों, पाठ्य-क्रमों, पाठ्य-पुस्तकों, अति निश्चित तथा कठोरता से चलाये जाने वाले दैनिक कार्य-क्रमों और घण्टों की अनुचित प्रधानता न हो एवं शिक्षा वास्तव में घर के से सहयोगी, ऊँचा उठाने वाले और प्रभुता बनाने वाले वातावरण में व्यतीत किये जाने वाले जीवन-क्रम का रूप ले ले।"

### पंचमुखी शिक्षा

बनस्पती विद्यापीठ की एक अनुपम विशेषता है, उसको पंचमुखी शिक्षा। यह बालिकागों का सर्वतोमुखी विकास करने के लिए एक मनोनी शिक्षा-योजना है। इस योजना के अनुसार उनको निम्नलिखित प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का आयोजन किया गया है :

१. शारीरिक शिक्षा
२. बौद्धिक शिक्षा
३. प्रायोगिक शिक्षा
४. कला की शिक्षा

## १. नैतिक शिक्षा

१. धारीरिक शिक्षा—इस शिक्षा का उद्देश्य बालिकाओं को स्वस्थ, साहसी और निर्भीक बनाना है। इस शिक्षा के कार्य-क्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के धारीरिक व्यायामों और खेलों को स्थान दिया गया है। उदाहरणार्थ सैनिक योग्या (Military Drill), धारीरिक योग्या (Physical Drill) लोदी तलवार, माला और बल्लम चलाना, लेजिम, गदका डम्बल, जोड़ी. योधिक घासन, बालीबाल, रिंगबाल, बास्केटबाल, हैडबाल, बाजबाल, हाकी, बेडमिंटन फुटबाल, सांग जम्प, हाई जम्प, मार्लिकिन चलाना, घुड़सवारी करना, नाव चलाना, तैरना इत्यादि।

२. बौद्धिक शिक्षा—इस शिक्षा का उद्देश्य छात्राओं का बौद्धिक, मानसिक एवं ज्ञानात्मक विकास करना है। विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विषयों का शिक्षण देते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि छात्राओं का मानसिक विकास एकांगी तथा संकीर्ण न होकर विद्यात एवं व्यापक रूप में हो। इसके प्रतिरिक्त इस बात पर बल दिया जाता है कि बालिकाओं में स्वयं विचार करने की शक्ति का विकास हो, जीवन तथा संसार के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्ण एवं वैज्ञानिक हो, पुस्तकीय ज्ञान पर आश्रयकता से अधिक बल न दिया जाय और बालिकाओं का व्यक्तित्व पुस्तकों एवं परीक्षाओं ने दब न जाय। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बालिकाओं को प्रारम्भ से ही समाज शास्त्र एवं विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। भारतीय तथा विश्व इतिहास के शिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। भ्रष्टाचारी की शिक्षा कथा से प्रारम्भ कर दी जाती है। बालिकाओं की विभिन्न विधियों से भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का समुचित ज्ञान दिया जाता है।

३. प्रायोगिक शिक्षा—इस शिक्षा का उद्देश्य बालिकाओं को गृह-कार्य में दक्ष बनाना और उनमें धारीरिक श्रम के प्रति सम्मान उत्पन्न करना है। इस शिक्षा के अन्तर्गत अप्रतिष्ठित कार्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने पर बल दिया जाता है :—अनाज छानना, साक करना और पीसना, भोजन बनाना,

मँगोड़ी बनाना, कतना, कुनना, घीना, कसीदा

तेल, साबुन और वेसलीन बनाना, बर्तनों पर

परेषु धिक्करा करना; जिम्दारी,

धम के कार्य।

गठित करके उसमें धागे निचे लकीन

गई है—मोखा, बनियान, चाक, स्लेट,

और पाउडर बनाना; धर्तों, काँचोई,



हाथ के करवे की बुनाई, कपड़े की छपाई, सलमे-सितारे घोर की  
किनारी का काम ।

४. कला की शिक्षा—इन शिक्षा का उद्देश्य छात्राओं में साधारण  
वृत्ति का विकास करना और उनमें माधुर्य, सौन्दर्य एवं मुहूर्ति उत्पन्न करना  
है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये बालिकाओं को विभिन्न कलाओं से परिचित  
कराया जाता है । उदाहरणार्थ, कक्षा १ से कक्षा ५ तक को छात्राओं के लिये  
सज्जीन तथा चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है । कक्षा ६ से ऊपर  
इन दोनों विषयों में से केवल एक का अध्ययन करने का अधिकार है । सरीस के  
पुस्तकें बाघ एवं गायन दोनों की व्यवस्था है । बालिकाओं के लिये नृत्य  
सीखने का समुचित प्रबंध है ।

५. नैतिक शिक्षा—विद्यापीठ का प्रमुख उद्देश्य छात्राओं का चरित्रिक  
निर्माण करना है । यतः हमी उद्देश्य की पूर्ति के लिये नैतिक शिक्षा की  
व्यवस्था की गई है । इन शिक्षा का कला-आधारित है । व्याख्यानों तथा  
उपदेशों द्वारा चरित्र-निर्माण के कार्य को प्रोत्साहित नहीं हो जानी है । इनके  
विरुद्ध सामूहिक प्रार्थना, साप्ताहिक विचार-विनिमय, छात्र-संवादन, रस-  
वातावरण एवं सामूहिक जीवन द्वारा बालिकाओं के चरित्र का निर्माण करने  
का प्रयत्न किया जाता है ।

### विद्यापीठ के विविष्ट शैक्षिक कार्य-क्रम

विद्यापीठ में कतिपय विविष्ट शैक्षिक कार्य-क्रमों का आयोजन किया गया  
है । इनका उद्देश्य बालिकाओं को विभिन्न क्षमताओं तथा अभिरुचियों का  
विकास करके उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास करना है । ये कार्य-क्रम  
निम्नादि हैं ।

१. वाद-विवाद परिषद तथा बालिकायोग—विद्यापीठ में विभिन्न विषयों  
की वाद-विवाद परिषदें हैं । विद्यालय की छात्राओं के लिये एक बालिकायोग  
भी है । इनके द्वारा उन्हें प्रकृत्य की सेवा, धारण की विधिविता, ज्ञानार्जन की  
विद्याया, विज्ञान की धर्म तथा नर्तक को प्रेरणा को प्रवृत्त करने का प्रयत्न  
किया जाता है ।

२. अखिल एक कला-प्रदर्शन—अखिल एक कला-प्रदर्शन की योजना  
किया गया है । इनके द्वारा बालिकाओं में साप्ताहिकता, जनसमता तथा  
सौन्दर्य प्रत्येक की महत्त्वों का विकास किया जाता है ।

३. अन्तर्-परिषद—छात्राओं के लिये का'द्वय, अन्तर् तथा अन्तर्-परिषद  
की परिषदें आयोजित की गई हैं । इनके माध्यम से उनकी प्रकृतिक अभिरुचि एवं  
विचार-प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है ।

४. समाज-सेवा—छात्राओं को समाज-सेवा के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें स्वयं की प्राप्ति के लिये राजि-पाठशालाओं संचालित की जाती है। छात्राओं द्वारा उनमें ब्यस्त स्त्रियों को शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त वे समाज-शिक्षा के अन्य कार्य-क्रमों में भी भाग लेती हैं।

५. पाठ्य-बाह्य-क्रियाएँ—विद्यापीठ में पाठ्य-बाह्य-क्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है। इन क्रियाओं में भ्रमण, यात्रा, पर्व एवं त्यौहार समारोह, शिक्षण-प्रयोजनों, वार्षिक बालमेला और अभिनय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

### उपसंहार

बनस्पती विद्यापीठ बालिका-शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय तथा सफल परीक्षण है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में यह संस्था अपने ढङ्ग को निराली है। इसमें बालिकाओं को पाश्चात्य विषयों की शिक्षा भारतीय भावों के अनुसार दी जाती है। इस बात का अत्यन्त प्रयास किया जाता है कि छात्राएँ अपने भावी जीवन में देश की उत्तम नागरिक बनकर समाज में अपना उचित स्थान ग्रहण कर सकें। भारतीय परम्पराओं तथा भारतीय संस्कृति से अवगत कराके उन्हें स्त्रियों के उच्च दायित्वों तथा कर्तव्यों की भावना से सज्जित कर दिया जाता है। उनकी शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, व्यावहारिक, सामाजिक तथा सांसारिक क्षमताओं का उन्नयन करके उनके व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास किया जाता है। सारांश में बनस्पती की शिक्षा भारतीय नारी-जीवन के पुनर्निर्माण की एक पूर्ण तथा सराहनीय योजना है।

## सारांश

### ✓ १. बेसिक शिक्षा

तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था के दोष—(१) पूर्णतया पुस्तकीय, साहित्यिक तथा छात्रीय, (२) बुद्धि तथा मनः में कोई उन्नति नहीं, (३) ज्ञान का असम्बद्ध विषयों में विभाजन, (४) व्यावहारिक कुशलता की अवहेलना, (५) प्रतिस्पर्धा तथा प्रतिद्वन्द्विता की भावना को प्रोत्साहन, (६) भारतीय संस्कृति का कोई स्थान नहीं, (७) अंग्रेजी का सर्वोच्च स्थान, (८) मातृभाषा का गौण स्थान, (९) शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के मध्य भेदभाव, (१०) जन-साधारण की शिक्षा की अवहेलना, और (११) अर्थव्यवस्था पर अभाव।

**बैसिक शिक्षा का काम और कार्यान्वयन**—शिक्षा के सम्बन्ध में गाँधी जी के विचार मोतिक थे। शिक्षा से उनका धर्म या बच्चे एवं मनुष्य की सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा धार्मिक शक्तियों का सर्वतोमुखी विकास। १९१७ में वर्षों में 'प्रथम भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन' हुआ और गाँधी जी उसके समस्त धपनी योजना प्रस्तुत की। यही योजना 'बैसिक शिक्षा-योजना' के नाम से विख्यात हुई। 'जाकिर हुसेन समिति' ने इस योजना के लिये पाठ्यक्रम तैयार किया। 'प्रथम और द्वितीय छेर समिति' ने केन्द्रीय सरकार को इसके सम्बन्ध में सुझाव दिये। १९३८ में 'बैसिक शिक्षा-योजना' का कार्यान्वयन किया गया।

**बैसिक योजना को कपरेखा**—(१) ६ से १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य, (२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, (३) सम्पूर्ण शिक्षा का किछी आधारभूत शिल्प से सम्बन्ध, (४) पाठ्य विषयों में आधारभूत शिल्प, मातृभाषा, हिन्दी, गणित, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान और कला तथा (५) प्रध्यापन का कार्य क्रियाशील एवं अनुभवों के माध्यम से।

**बैसिक शिक्षा के सिद्धान्त**—(१) जनसाधारण की शिक्षा, (२) अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, (३) हस्तशिल्प की शिक्षा, (४) स्वावलम्बी शिक्षा, (५) शिक्षा में शारीरिक धर्म, और (६) सामाजिक शिक्षा।

**बैसिक शिक्षा के उद्देश्य**—(१) नागरिकता के गुणों का विकास, (२) नैतिक विकास, (३) सांस्कृतिक उद्देश्य, (४) विविध विकास, (५) प्राथमिक उद्देश्य, और (६) सर्वोदय समाज।

**बैसिक शिक्षा की विशेषताएँ**—(१) मनोवैज्ञानिक आधार, (२) सामाजिक आधार, (३) प्राथमिक आधार, (४) हस्तधन का महत्व, (५) विद्यालय, गृह और समाज के जीवन में सामंजस्य, (६) सहसम्बद्ध शिक्षण, (७) ज्ञान एक अभिन्न प्रवाह समष्टि, (८) बालक-प्रधान शिक्षा, (९) क्रिया-प्रधान शिक्षा, (१०) शिक्षा का माध्यम आधारभूत शिल्प, और (११) स्वतंत्रता प्रधान प्रणाली।

**बैसिक शिक्षा के दोष**—(१) विशेष रूप से ग्रामों के लिये, (२) उत्पादित सिद्धान्त पर अत्यधिक बल, (३) विज्ञान के प्राधुनिक युग में मध्यकालीन उद्योगों के प्रयोग की निरर्थकता, (४) प्राथमिक शिक्षा का अभाव, (५) विभिन्न विषयों के लिये समय का अतिरिक्त विभाजन, और (६) प्राथमिक शिक्षा पर अत्यधिक बल।

## २. विश्व-भारती

यह विश्वविद्यालय कलकत्ता से लगभग सौ मील दूर बोलपुर रेलवे स्टेशन से सौ मील है। १८६३ में महर्षि देवेन्द्र नाथ टैगोर ने यहाँ भगवान् के भक्तों के लिये एक ग्राम्यम स्थापित किया था। १९०१ में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा में एक नवीन परीक्षण करने के लिये यहाँ 'शांतिनिकेतन' नामक एक विश्व-ग्राम स्थापित किया। १९२२ में उन्होंने इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करके इसका नाम 'विश्वभारती' रखा। यह धान्त बातावरण में स्थित है।

टैगोर के शैक्षिक विचार—टैगोर वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से असंतुष्ट थे। उनके मतानुसार यह बातों की प्राकृतिक शक्तियों के विकास में बाधा पहुँचाती थी। वे कृत्रिम बातावरण के विरोधी और स्वतंत्रता के समर्थक थे। वे शिक्षा द्वारा छात्रों को आत्म-प्रभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि प्रकृति के माध्यम से ही मानव को सत्य का आभास हो सकता है। वे भारतीय संस्कृति के पुजारी और पाश्चात्य संस्कृति का सम्मान करते थे। परन्तु वे पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों के लिये उपयुक्त नहीं समझते थे। उनका विश्वास था कि बच्चों की भद्र-चेतन बुद्धि उनकी चेतन बुद्धि से अधिक शक्तिशाली होती है। वे स्कूलों में बच्चों के प्रति सहानु-भूति का व्यवहार चाहते थे।

विश्वभारती के उद्देश्य—(१) अनुभव किये गये सत्य को विभिन्न रूपों की परिज्ञान के उद्देश्य से मानव मस्तिष्क का अध्ययन करना, (२) प्राच्य संस्कृतियों में सार्थकत्व स्थापित करना, (३) पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का समरूप अध्ययन करना, (४) पूर्व तथा पश्चिम में निकट सम्पर्क स्थापित करना, (५) एशियाई विचार को दृष्टिकोण में रख कर पाश्चात्य देशों से सम्पर्क बढ़ाना, (६) सहबन्धुत्व की भावना का विकास करना, (७) विश्व-शांति की दशाओं को जन्म देना, और (८) सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करना।

(२) शिक्षा-भवन, (३) विद्या-

.. (७) चीन-भवन,

.. (२) दुग्धशाला विभाग, (३)

(४)

६ बजे

रात्रि तक, (२) छावास एवं सह-विद्या विश्वविद्यालय, (३) शिस्तों तथा छात्रों में धनिष्ठ सम्बन्ध, (४) छात्रों तथा छात्राओं के तिवे पृथक् छात्रागार, (५) खुले मैदानों या वृक्षों के नीचे कलायें, (६) विस्तृत पाठ्य-क्रम, (७) सामूहिक जीवन, (८) समाज-सेवा का भावना, (९) स्वयं साहित्य संस्था, (१०) बेरो कामें, भस्माल, मुद्रालय, मन्दिर कारखाने, (११) कुटीर उद्योगों को शिक्षा, (१२) विद्यार्थियों के न्यायालय, (१३) भण्डारी एवं हिन्दी की परि-कार्य, और (१४) ग्राम-उत्थान का कार्य ।

### ३. अरविन्द-आश्रम

श्री अरविन्द के धर्म तथा संस्कृति-सम्बन्धी विचार—श्री अरविन्द को भारतीय धर्म तथा संस्कृति में हृदय आस्था थी । उनके विचारानुसार धार्मिक संस्कृति के रूप में भारतीय सभ्यता का सर्वप्रथम स्थान है । भारत में महानतम धार्मिक सत्य को अधिकतम व्यापकता से देखा जाता है । भारतीय संस्कृति ने सत्य की निरन्तर खोज की है । इतने धर्म पर भारतीय धार्मिकता के भावों की छाव लगा दी है । भारतीय दर्शन के प्रमुख धार्मिक सत्य व्यक्तियों के सामान्य मस्तिष्क पर प्रकट कर दिये गये हैं । समस्त भारतीय धर्म एक सर्वोच्च प्राणी प्रपञ्च ईश्वर के प्रतिष्ठान में निवास करते हैं । ईश्वर एक सर्वोच्च वास्तविकता है । भारतीय दर्शन और धर्म की अनेककृतता अतः भारतीय धार्मिक संस्कृति का चिह्न है ।

श्री अरविन्द के शिक्षा-सम्बन्धी विचार—श्री अरविन्द के शिक्षा-सम्बन्धी विचार धार्मिकता, साधना, ब्रह्मचर्य और योग पर आधारित हैं । उनका विश्वास था कि इन प्रकार की शिक्षा से मानव का पूर्ण विकास हो सकता है । उनके मतानुसार अतःकरण प्रपञ्च मानव शिक्षा का प्रमुख अङ्ग है । केवल ज्ञान की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है । यन्त्रों शिक्षा नहीं है, विषयों मानव का पूर्ण विकास करने की क्षमता हो । उन्होंने किसी ऐसे विषय को उपाय नहीं की, जिसमें वैयक्तिक व्यक्तिगत तथा जीवन को व्यापकता के गुण विद्यमान हैं । उनका कथन था कि शिक्षा में बालक को गुणों स्वतन्त्र होनी चाहिये । शिक्षा बालक के स्वभाव के अनुकूल होनी चाहिये । बालक एक बड़े पदार्थ नहीं है, बल्कि शिक्षा और और भी बड़े से बड़ा । बालक को अपनी मानविक, वैयक्तिक और व्यावहारिक व्यक्तियों को स्वयं तथा स्वतन्त्र रूप से विकसित करने में सहायता दी जानी चाहिये ।

श्री अरविन्द के शिक्षा-विचार—(१) शिक्षा का आध्यात्मिक अनु-धारा, (२) वास्तविक ज्ञान पर विचार आधार, (३) मानविकता का विकास, (४) मानविक

समताओं का विकास, (५) पाठ्य-क्रम की रोचकता, (६) शिक्षक बालक का निर्देशक, पथ-प्रदर्शक तथा सहायक, (७) बालक का शिक्षा में प्रमुख स्थान, (८) मन्तःकरण का विकास, और (९) नैतिकता का विकास ।

**धरविन्द धामधम**—यह धामधम पट्टिचेरी में १९१० में स्थापित किया गया । प्रारम्भ में इसमें केवल ८ साधक थे । १९२६ में यह संस्था ८०० हो गई । इसमें १९४० में धामधम के बालकों के लिये शिक्षा की व्यवस्था की गई । १९२० से इसका संचालन एक फ्रांसीसी महिला जिन्हें 'दी मदर' कहते हैं, कर रही हैं । यह धामधम धार्मिक शान्ति के इच्छुक जिज्ञासुओं का एक केन्द्र है । सब साधक एक परिवार के सदस्यों के समान कहते हैं । श्री धरविन्द के भादसों का पालन करने वाला कोई भी स्त्री या पुरुष धामधम का सदस्य बन सकता है । इनका पथ-प्रदर्शन 'मदर' के द्वारा किया जाता है । साधकों का जीवन धार्मिक अनुशासन पर आधारित है । वे मन, वचन, कर्म से इसी जीवन में 'दैवी जीवन' प्राप्त करने का प्रयास करते हैं । साधकों के जीवन का मूल-मन्त्र निस्स्वार्थ सेवा-भावना से कार्य करना है ।

**धामधम स्कूल**—यह स्कूल १९४३ में स्थापित किया गया । प्रारम्भ में इसमें ३२ छात्र थे, परन्तु अब ३०० से अधिक हैं । शिक्षा निःशुल्क दी जाती है । धामधमों को वेतन नहीं दिया जाता है । शिक्षा के विषय-गणित, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, रसायन-शास्त्र, चित्रकला आदि हैं । भाषाओं में संस्कृत, संस्कृत, तामिल, फ्रेंच, जर्मन आदि के शिक्षण की व्यवस्था है । स्कूल का शिक्षा का स्तर हमारे देश के 'हाई स्कूल' के समान है । वार्षिक परीक्षाएँ नहीं होती हैं । छात्र स्वतन्त्र पाठावरण में विद्या का अभ्यस करते हैं । शिक्षा में धर्म का कोई स्थान नहीं है ।

**श्री धरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय केन्द्र**—इसकी स्थापना ६ जनवरी, १९५२ को की गई थी । इसमें धरविन्द पाठ्य-क्रमों के शिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था है—(१) शिशु शिक्षा, (२) प्राथमिक शिक्षा, (३) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, (४) विश्व-विद्यालय शिक्षा, (५) व्यावसायिक शिक्षा, और (६) वयस्क शिक्षा । केन्द्र का उद्देश्य छात्रों के शरीर, मस्तिष्क और जीवन का समुचित विकास करना है । सह-शिक्षा का प्रचलन है । किसी जाति, धर्म और राष्ट्र का बालक प्रवेश ले सकता है । वर्ष के अन्त में परीक्षा नहीं होती है । कोई द्विती प्रवृत्ति उपार्जित नहीं दी जाती है । लगभग ५०० छात्र और १२० अध्यापक हैं । केन्द्र का प्रशासन एक वैश्विक प्रबंधन करता है । सभी विषयों के लिये पृथक् कक्षा हैं ।



गृहकुल-शिक्षा को विशेषतायें—(१) छात्रों का साधारण जीवन, (२) निश्चित कार्य-क्रम, (३) सामुदायिक जीवन, (४) सह-शिक्षा का निषेध, (५) सलित कक्षाओं की शिक्षा का निषेध, (६) शिक्षा का माध्यम हिन्दी, (७) सभी प्राधुनिक विषयों का अध्ययन, और (८) शोध-कार्य की सुविधा।

## ५. बनस्पती विद्यापीठ

बनस्पती विद्यापीठ जयपुर से ४५ है। इसकी स्थापना पं० होराला छात्रों ने १९३५ में अपनी एकमात्र पुत्री छात्राबाई की स्मृति में की थी। प्रारम्भ में इसका नाम 'राजस्थान बालिका-विद्यालय' था। १९४२ से 'बनस्पती विद्यापीठ' के नाम से प्रख्यात है।

शिक्षा-विभाग—(१) प्राथमिक विभाग, (२) संस्कृता विभाग, (३) माध्यमिक शिक्षा-विभाग, (४) सामान्य हाईस्कूल, (५) बहुउद्देशीय हाई स्कूल (६) कॉलेजिय शिक्षा-विभाग, और (७) अन्य शिक्षा-विभाग।

सम्य एवं उद्देश्य—(१) प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुसार प्राधुनिक शिक्षा, (२) बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास (३) गृह-कार्यों की शिक्षा, (४) बालिकाओं में सहयोग, समाज-सेवा, नागरिकता देश-प्रेम एवं स्वस्थ राष्ट्रीयता की भावनाओं का समावेश, (५) बालिकाओं की स्वातन्त्र्य-भावना का विकास, (६) शिक्षा को बाह्य परीक्षाओं से मुक्त कर (७) प्राच्य आध्यात्मिक विरासत एवं पाश्चात्य सफलताओं का समन्वय, एवं (८) बालिकाओं के व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास।

विशेषतायें—(१) स्वतन्त्र एवं प्रगतिशील शिक्षा, (२) व्यक्तिगत स्वतन्त्र एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का समन्वय, (३) सादा और सरल जीवन, (४) कठना और लक्ष्मर पहिना, (५) छात्राओं द्वारा निजी एवं घरेलू कार्य' कि जाना, (६) सामाजिक एवं सामुदायिक कार्य, (७) शुद्ध बालिका विद्यालय (८) सर्वतोमुखी शिक्षा, (९) शारीरिक शिक्षा, (१०) बालिकाओं का समितित कोष, (११) संरक्षकों से सम्पर्क, और (१२) शिक्षा की दैनिक कार्य-क्रम के बन्धन से मुक्ति।

पंचमुखी शिक्षा—(१) शारीरिक शिक्षा, (२) बौद्धिक शिक्षा, (३) प्राथमिक शिक्षा, (४) कला की शिक्षा, और (५) नैतिक शिक्षा।

विशिष्ट शिक्षा कार्य-क्रम—(१) वाद-विवाद परिषदें तथा पालियामे (२) संगीत एवं कला परिवर्द्ध, (३) अन्य परिषदें, (४) समाज-सेवा (५) पाठ्य-बाह्य क्रियायें।



## सहायक पुस्तकों की सूची

1. T. S. Avinashlingam : *Understanding Basic Education*.
2. Hans Raj Bhatia : *What Basic Education Means*.
3. M. K. Gandhi : *India of my Dreams*.
4. Mahatma Gandhi : *Autobiography*.
5. Rabindranath Tagore : *Personality*.
6. Rabindranath Tagore : *My Reminiscences*.
7. Sri Aurobindo : *The Unity of Indian Religion*.
8. Sri Aurobindo and The Mother : *On Education*.
9. Sri Aurobindo : *The Supernatural Manifestation*.
10. Sri Aurobindo : *The Life Divine*.
11. *Report of the Zakir Husain Committee*.
12. *Educational Reconstruction* (Hindustani Talimi Sangh).
13. *Report of the Committee of the C. A. B. E. appointed to consider the Wardha Scheme of Education*.
14. *Report of the Second Wardha Education Committee of C. A. B. E., 1939, together with the Decisions of the Board thereon*.
15. *Year Book of Education* (Evan Bros.).
16. *Visva Bharti Prospectus*.
17. *Directory of Institutions for Higher Education, 1960*.
18. *Physical Education in Aurobindo Ashram*.
19. *Integral Education* (Sri Aurobindo Ashram).
20. *Sri Aurobindo International University Centre* (Sri Aurobindo Ashram).
२१. मलैया तथा मलैया : बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त ।
२२. हंसराज भाटिया : बेसिक शिक्षा क्या है ।
२३. झिगरन और शर्मा : हमारे शिक्षा-प्रतिवेदन ।
२४. सिधिया बोस्स : भारत मेरा घर ।
२५. शान्ति निकेतन ( टेंगोर प्रकाशन ) ।
२६. भार० धार० दिवाकर : महायोगी
२७. बनस्पती विद्यापीठ, २२ वाँ कार्य-विवरण
२८. बनस्पती विद्यापीठ विवरण पत्रिका, १९५६-६०
२९. बनस्पती विश्वविद्यालय की कल्पना, १९५५
३०. हमारी विचारधारा ( बनस्पती प्रकाशन

## TEST QUESTIONS

Describe in detail the fundamental features of Basic Education, explaining the importance of a 'basic craft' and 'self-supporting' aspect of the education.

Write a reasoned criticism of it.

"The ..."

"... children ?

Write notes on :—(a) Arvind Ashram (b) Ashram School, and (c) Sri Aurobindo International University. Compare the ancient and modern systems of Gurukul education.

Describe briefly the aims and chief characteristics of Gurukul education.

Write a note on the Brindavan or the Kangri Gurukula.

"... ali Vidyapeeth founded ? What are its chief characteristics of the education ?

## सहायक पुस्तकों की सूची

1. T. S. Avinashlingam : *Understanding Basic Education.*
2. Hans Raj Bhatia : *What Basic Education Means.*
3. M. K. Gandhi : *India of my Dreams.*
4. Mahatma Gandhi : *Autobiography.*
5. Rabindranath Tagore: *Personality.*
6. Rabindranath Tagore : *My Reminiscences.*
7. Sri Aurobindo : *The Unity of Indian Religion.*
8. Sri Aurobindo and The Mother : *On Education.*
9. Sri Aurobindo : *The Supernatural Manifestation.*
10. Sri Aurobindo : *The Life Divine.*
11. *Report of the Zakir Husain Committee.*
12. *Educational Reconstruction (Hindustani Talimi Sangh)*
13. *Report of the Committee of the C. A. B. E. appointed to consider the Wardha Scheme of Education.*
14. *Report of the Second Wardha Education Committee of C. A. B. E., 1939, together with the Decisions of the Board thereon.*
15. *Year Book of Education (Evan Bros.)*
16. *Visva Bharti Prospectus.*
17. *Directory of Institutions for Higher Education, 1960.*
18. *Physical Education in Aurobindo Ashram.*
19. *Integral Education (Sri Aurobindo Ashram)*
20. *Sri Aurobindo International University Centre (Sri Aurobindo Ashram).*
२१. मल्लिका तथा मल्लिका : बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त ।
२२. हंसराज भाटिया : बेसिक शिक्षा क्या है ।
२३. भिन्नरत्न भोर दर्मा : हमारे शिक्षा-प्रतिवेदन ।
२४. सिधिया बोस्त : भारत मेरा घर ।
२५. छान्ति निकेतन ( टैगोर प्रकाशन ) ।
२६. घर० घर० दिवाकर : महायोगी
२७. बनस्पती विद्यापीठ, २२ -दिवंगत
२८. बनस्पती विद्यापीठ
२९. बनस्पती
३०. हमारे

## अनुक्रमणिका

धनिवार्य शिक्षा—१, ५-१०	एन्द्रयूज—२६०
धम्बेदकर—८	भौद्योगिक क्रान्ति—१५५
धर्मपथ—१५, २८, ३४, ६१	भारतीय विद्यालय—३६
धर्मरोषन—१५, ३८	भारतीय राज्य में भौद्योगिक
धर्मशास्त्रकार्य—१४	शिक्षा—१५४
धर्मविन्द-भाष्य—२६६	कर्म—४, ५३
धर्मिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा	कौगड़ी—२७६
समिति १८६	कन्या गुरुकुल—२८०
धर्मिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा	कला का शिक्षा—२८८
सम्मेलन—२३०	मोखले—७
धर्मम-स्कूल—२७०	गुरुकुलो के लिये भान्दोलन—२७५
धर्मार्थ नरेंद्रदेवसमिति—१२०, १२१	गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की
धर्मनिकतम भौद्योगिक	रूपरेखा—२७८
गतिविधियाँ—१६३	गुरुकुल संस्थाओं का निर्माण—२७९
धर्मिक परिवर्तनों का शिक्षा पर	गुरुकुल कौगड़ी—२७६
प्रभाव—१७६	गुरुकुल वृन्दावन—२७६
धर्मपत्र—( १८१३ ) ३	गुरुकुल शिक्षा के उद्देश्य—२८०
धर्मनिक युग में स्त्री-शिक्षा—५१	गुरुकुल-शिक्षा की विशेषताएँ—२८८
धर्मनिक विषय—१२२	विष्णुलाल सोलनबाद—६
धर्मनिक काल में गुरुकुलों की	छात्रवृत्तियाँ—१६४
स्थापना—२७७	जनता के कर्तव्य—७२
इस्लामी रहस्यलुक्ता—६	जाकिर हुसेन समिति—२३१
इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स—१६२	जीविकोपार्जन शिक्षक—१४६
इंडियन सोशल रिफॉर्मर—१८१	जीवन-कुटीर—२८२
ईश्वरचन्द विद्यासागर—१८४	सत्कालीन शिक्षा पद्धति के बोध—२९
एडम—६	साराचन्द समिति—१२१
एनी बेसेन्ट—५४	देसाई—२०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—३७  
 दक्षिणी शिक्षा-समिति—५२  
 दस्तकारी के स्कूल—१५६  
 दयानन्द—२७७  
 द्वितीय खेर समिति—२३२  
 नटराजन—५१, १५७  
 नामकरण के कारण  
 (बैसिक शिक्षा)—२३५  
 निस्पन्दन सिद्धान्त—२०३  
 नैतिक शिक्षा—२८८  
 पारि-विधि—२१  
 पाठ्य-क्रम—४३  
 पाठ्य-क्रम का विभिन्नोकरण—११८  
 पाठ्य-क्रम (बैसिक शिक्षा)—२३४  
 पंचमुखी शिक्षा—२८६  
 प्लासी का युद्ध—२  
 प्रथम खेर समिति—२३२  
 प्राथमिक शिक्षा—२, ५  
 प्राचीन काल में प्रौद्योगिक  
 शिक्षा—१५३  
 प्राच्य-पारचार्य शिक्षा-विवाद—२०३  
 प्रायोगिक शिक्षा—२८७  
 प्रौढ़ शिक्षा का धर्म एवं  
 परिभाषा—८०  
 प्रौढ़-शिक्षा की नवीन धारणा—८१  
 प्रौढ़-शिक्षा तथा समाज-शिक्षा में  
 अन्तर—८२  
 प्रौद्योगिक शिक्षा की  
 आवश्यकता—१५२  
 प्रौद्योगिक शिक्षा की प्रगति—१६४  
 प्रौद्योगिक शिक्षा की समस्याएँ—१६५  
 प्रोबं प्राग्भेदान—१३४  
 बनस्पती विद्यापीठ—२८२  
 बड़ौदा नरेश—७  
 बरनिवार—१५४  
 बहुउद्देशीय विद्यालय का धर्म—१३२  
 बहुउद्देशीय विद्यालय के  
 उद्देश्य—१३३  
 बहुउद्देशीय विद्यालयों की  
 प्रवृत्ति—१३५  
 बहुउद्देशीय विद्यालयों की  
 आवश्यकता—१३०

बहुउद्देशीय विद्यालयों के लाभ—१३६  
 बहुउद्देशीय विद्यालयों की समस्याएँ  
 और उनका समाधान—१४१  
 बाल-विवाह—४१, ४४  
 बाउनिंग—२५६  
 ब्रिटिश शासन-काल में शिक्षा पः  
 सामाजिक-धार्मिक सघात—  
 ब्रिटिश शासन-काल में शिक्षा पः  
 राजनैतिक सघात—२०१  
 बैसिक पाठ्य-क्रम—३२  
 " योजना—२३३  
 " पाठ्य-क्रम—२३४  
 " धर्म्यापन विधि—२३४  
 " धर्म्यापक—२३५,  
 " शिक्षा के सिद्धान्त—२  
 " शिक्षा के उद्देश्य—२३६  
 " " की विशेषताएँ—२४१  
 " " के दोष—२४८  
 बैटिक—१४५  
 बैप्यून—५२  
 बोडिक शिक्षा—२८७  
 बग-भंग—५  
 भारत-सरकार अधिनियम—२०६  
 भारतीय शिक्षा-धायोग—४, ५१,  
 १५६, १८४, २०५  
 भारतीय बयस्कता अधिनियम—५७  
 भारतीय विद्वत्विद्यालय धायोग—२०६  
 महात्मा गांधी—७४  
 महात्मा गांधी के शिक्षा-विषयक  
 विचार—२२६  
 माध्यमिक शिक्षा-धायोग—  
 १६, १२१, १३६  
 मार्ग-प्रदर्शन धायिकारी—१४५  
 मुकद्दमी—१४०  
 मुनरी—५२  
 मुस्लिम-युव म स्त्री-शिक्षा—१०  
 मुस्लिम-काल में प्रौद्योगिक  
 शिक्षा—१५४  
 म्नायित्त बाधी—७६  
 रास्कन—१  
 राखंड प्रचार—६५

राष्ट्रीय जीवन में समाज-शिक्षा

का स्थान—७६

बुद्ध का बोधरात्रि—३

आवसायिक शिक्षा—५४

बिनागोट—६

विभिन्न पाठ्य-क्रम की कुरुरेखा—१२२

विभिन्न पाठ्यक्रम की

आवश्यकता—१२४

विभिन्न पाठ्य-क्रम का महत्त्व—१२७

विज्ञान मंदिर—१६३

विश्वभारती—२५०

विश्वभारती की स्थिति व

स्थापना—२५०

विश्वभारती का वातावरण—२५३

विश्वभारती के उद्देश्य—२५४

विश्वभारती की समस्याएँ—२५४

विश्वभारती के विभाग—२५६

विश्वभारती का कार्य-क्रम—२५७

विश्वभारती का विवरण एवं

विशेषताएँ—२५८

विद्यापीठ की स्थिति व स्थापना—२८२

विद्यापीठ की छात्राएँ व भवन—२८३

विद्यापीठ के शिक्षा-विभाग—२८३

विद्यापीठ के लक्ष्य व उद्देश्य—२८४

विद्यापीठ की विशेषताएँ—२८५

विद्यापीठ के विशिष्ट शैक्षिक

कार्य—२८८

बैकल्पिक विषय—१२३

बुद्धावन—२७६

छात्रीय शिक्षा—२८७

छान्दाबाई—२८३

शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी

प्रस्ताव—५, ५४

शिक्षा-कर—८

शिक्षा-परिपक्व—५२

शिक्षा पर प्रौद्योगिकीय संघात—१५१

शिक्षा पर सामाजिक-धार्मिक

संघात—१७४

शिक्षा पर राजनैतिक संघात—२००

शिक्षा में परीक्षण—२२७

शेक्सपीयर—२५६

शैक्षिक प्रधान—२७४

श्री धरविन्द घोष—२६१

श्री धरविन्द घोष के पुत्र तथा स-

म्बन्धी विचार—२६२

श्री धरविन्द घोष के शिक्षा-सम्ब-

न्धित विचार—२६४

श्री धरविन्द घोष के शिक्षा-

सिद्धान्त—२६६

श्री धरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-

विद्यालय केन्द्र—२७२

सरकार के कर्तव्य—६४

सह-शिक्षा—५४

सहायता-अनुदान—३

स्त्रियों के कर्तव्य—७४

समाज-शिक्षा—७६

समाज-शिक्षा का धर्म एवं

परिभाषा—८२

समाज-शिक्षा का कार्य-क्रम—८४

समाज-शिक्षा के उद्देश्य—८४

समाज-शिक्षा के लक्ष्य—८५

समाज शिक्षा की आवश्यकता—१

समाज-शिक्षा की समस्याएँ—६५

समाज-शिक्षा की समस्याओं का

समाधान—१००

समाज-शिक्षा का इतिहास—१०६

स्वतन्त्र भारत में प्रौद्योगिक शिक्षा

के प्रति दृष्टिकोण—१५८

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा पर प्रौद्यो-

गुणात्मक—१५६

सामाजिक परिवर्तनों का शिक्षा पर

प्रभाव—१७४

स्वतन्त्र भारत में सामाजिक-धार्मिक

परिवर्तन—१६०

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा पर सामा-

जिक-धार्मिक संघात—१६३

स्वतन्त्र भारत में राजनैतिक

परिवर्तन—२११

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा पर राजनै-

तिक संघात—२१३









